

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भारत, इंग्लैंड और रूस

का

आर्थिक विकास

(Economic Development of India,
England & Russia)

(Specially meant for 1st year Degree Arts
B A & B Com Students)

लेखक

गोपालकृष्ण गुप्ता एम ए, एम कॉम
प्राध्यापक प्रयोगास्त्र विभाग
राजकीय महानिधानय कोटा



प्रकाशक

दी स्टूडेंट्स बुक कम्पनी

जयपुर

जोधपुर

१९६०

मूल्य ४)

प्रकाशक :

दी स्टूडेन्ट्स बुक कम्पनी

जयपुर

जोधपुर

निवेदन और आभार प्रदर्शन

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् विश्व की परिस्थितियों में इतने परिवर्तन हुए हैं कि उन्हें एक रूप में कान्ति के वर्ण कहा जा सकता है। यहाँ हमें केवल आर्थिक क्षेत्र में हुई उपल-पुल का ही अध्ययन करना है और इस क्षेत्र में भी हमारा ध्येय भारत, इंग्लैंड और रूस के आर्थिक विकास पर ही प्रकाश डालना है, मुख्यकर भारतीय होने के नाते भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् हो रहे आर्थिक परिवर्तनों का दिग्दर्शन करना। प्रत्येक समझदार नागरिक को अपने देश की अर्थव्यवस्था का उचित व सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें वह देश की विभिन्न समस्याओं के समाधान में अपना सहयोग देने में समर्थ हो सके। अधिकतर यह देखा जाना है कि देश की आर्थिक परिस्थितियों का समुचित ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति अपने सङ्चित दृष्टिकोण अथवा राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने के हेतु विचार करते हैं, जिससे सामान्य नागरिक को भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अपने देश की आर्थिक व्यवस्था तथा उसके साथ इंग्लैंड तथा रूस जैसे उन्नत राष्ट्रों के अभूतपूर्व आर्थिक विकास की रूपरेखा देने का यह तुच्छ प्रयास है।

देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के हेतु Three Year Degree Course के प्रारम्भ होने को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। गत वर्ष राजस्थान युनिवर्सिटी के द्वारा इस कोर्स के अन्तर्गत परीक्षा हुई। इस कोर्स के विद्यार्थियों को इस विषय में किसी मान्यता प्राप्त तथा समुचित पुस्तक, जिसमें भारत, इंग्लैंड और रूस तीनों देशों के आर्थिक विकास का वर्णन हो, के अभाव में अति कठिनाई का अनुभव हुआ। मैं इस विषय को पढ़ाता हूँ अतः विद्यार्थियों के समान ही मुझे भी कुछ कठिनाई हुई और काफी परिश्रम करना पड़ा। गत वर्ष कुछ छात्रों ने बलास में दिये गए लेक्चर्स की पुस्तक के रूप से प्रकाशित करने का अनुरोध किया, जिससे आने वाले छात्रों को लाभ हो सके। परन्तु कुछ तो M. A. Classes के कार्य की अधिकता तथा कुछ बड़े लेखकों की अपेक्षा अपनी शुद्धता के कारण इस ओर अप्रसर होने का साहस न हुआ।

इस वर्ष भी वही समस्या आई—अधिक विस्तृत स्तर पर, अपना योगदान, की संस्था में वृद्धि के कारण और दूसरे एक दो पुस्तक जो भी प्रकाशित हुईं उससे छात्रों को पूर्ण सन्तोष नहीं हुआ और वे सदैव मेरे नोट्स को पुस्तक का रूप देने की प्रेरणा करते रहे।

मेरा यह प्रथम प्रयास है और आशा की जा सकती है कि विद्यार्थीवृन्द जिनकी प्रेरणा से यह पुस्तक लिखी गई है, इससे लाभान्वित होंगे और इस प्रकार किसी समुचित पुस्तक के अभाव का अभियोग न लगा सकेंगे । अपने गुरुजनों की आभार प्रदर्शन करना मैं अपना प्रमुख कर्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने अर्थशास्त्र और सम्बन्धित मामलों में अपूर्व प्रेरणा प्रदान की थी । इनमें प्रमुख हैं Dr. R. N. Bagchi M. A. Ph. D. (Lon), Director of Eco-Industrial Survey Rajasthan, Dr. B. K. Tandon M. A., B. Com., Ph. D. Head of Econ. Deptt., Govt. College, Beawar and Prof. S. C. Tella M. A., Head of Econ. Deptt., Govt. College Ajmer अन्त में मैं Dr. R. P. Singh M. A., B. Com., Ph. D. Vice-Principal & Head of Econ. Deptt., Govt. College, Kotah का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस और कार्य करने का अवसर प्रदान किया । अपने सहयोगी और आदरणीय Prof. M. L. Gupta तथा R. S. Sharma द्वारा भी समय समय पर दिये गए सुझावों का मैं कृतज्ञ हूँ । अपने समस्त विद्यार्थियों का, जिन्होंने मुझे इस और कार्यरत करने की प्रेरणा दी, मैं आभारी हूँ । पाठकों से अनुरोध है कि पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाने हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव देने का कष्ट करें ।

कोटा

१५-८-१९६०

विनीत

गोपालकृष्ण गुप्ता

विषय-सूची

प्रथम भाग

भारत का आर्थिक विकास

अध्याय	पृष्ठसंख्या
१. परिचय	१
२. भौगोलिक वातावरण और आर्थिक विकास के साधन	३
३. जनसंख्या	२४
४. सामाजिक व धार्मिक मर्यादा	३२
५. कृषि	३७
६. कृषि जोतें	४२
७. भूमि अधिकार प्रणालियाँ	४७
= सिंचाई व्यवस्था	५२
८. कृषि सुधार और विकास के राजकीय कार्यक्रम	५४
९. कुटीर उद्योग	६४
१०. श्रम सन्निधिम	६८
११. यातायात में विकास	७३
१२. भारतीय प्रशुक्क नीति	८३
१४. भारत में मुद्रा विकास	८६
१५. भारत में बैंकिंग व्यवस्था	९१

द्वितीय भाग

इंग्लैंड का आर्थिक विकास

अध्याय	पृष्ठसंख्या
१. प्रारम्भिक	१०३
२. कृषि उद्योग और कृषिकान्ति	१०५
३. औद्योगिक क्रान्ति	११६
४. प्रमुख उद्योग	१२४
५. यातायात और वस्त्र विकास	१३०
६. श्रमिक संघ	१३८
७. सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा	१४१

८. स्वतन्त्र व्यापार नीति
९. बैंकिंग और राजस्व

१४४

१४८

तृतीय भाग

रूस का आर्थिक विकास

अध्याय

१. रूस के आर्थिक विकास की महत्ता
२. राज्यक्रान्ति के पूर्व की स्थिति
३. रूस की राज्यक्रान्ति (१९१७)
४. नवोन आर्थिक नीति
५. कृषि विकास
६. औद्योगिक स्थिति
७. रूसी योजनाएं और उनसे शिक्षा

१५४

१५६

१६०

१६४

१६७

१७०

१७३

भारत का आर्थिक विकास

अध्याय

१. परिचय
२. भौगोलिक वातावरण और आर्थिक विकास के साधन
३. जनसंख्या
४. सामाजिक व धार्मिक मर्यादाएँ
५. कृषि
६. कृषि जोतें
७. भूमि अधिकार प्रणालियाँ
८. सिंचाई व्यवस्था
९. कृषि सुधार और विकास के राजनैतिक कार्यक्रम
१०. कुटीर उद्योग
११. श्रम सन्निधन
१२. यातायात में विकास
१३. भारतीय प्रशुल्क नीति
१४. भारत में मुद्रा विनिमय
१५. बैंकिंग व्यवस्था



वर्तमान समय में अर्थशास्त्र का अध्ययन विशेष आवश्यक समझा जाता है। अब अर्थशास्त्र केवल एक भेदान्तरिक विषय के रूप में ही नहीं, अपितु व्यावहारिक रूप में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी देश की वास्तविक उन्नति हम उसकी आर्थिक समस्याओं के अध्ययन द्वारा जान सकते हैं। इस पुस्तक के इस खण्ड में भारत के आर्थिक विकास का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के अध्ययन को बहुधा 'भारतीय अर्थशास्त्र' (Indian Economics) का नाम दिया जाता है। वास्तव में यह नाम ठीक नहीं है क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के नए सिद्धान्तों की विवेचना न कर अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धान्तों को ही भारतीय आर्थिक स्थिति की दृष्टभूमि में लागू किया गया है। भारत की राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टभूमि में भारत का आर्थिक जीवन किस प्रकार विकसित होता गया उसकी आर्थिक समस्याएँ तथा उनको हल करने के उपाय एवं योजनाओं के अध्ययन को हम भारत का आर्थिक विकास कह सकते हैं।

कुछ व्यक्ति इस अध्ययन से भारतीय आर्थिक विचारधारा के विकास का अर्थ समझते, परन्तु भारत में जीवन के आर्थिक क्षेत्र का महत्त्व नगण्य सा ही रहा है, अतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पश्चात् इस विषय पर भारतीय विचारधारा नहीं के बराबर है, और विज्ञान के विकास में हमारा कोई विशेष भाग नहीं है। इस प्रकार भारतीय अर्थशास्त्र के स्थान पर 'भारतीय अर्थव्यवस्था' शब्द का प्रयोग अधिक उचित होगा।

इस अध्ययन के अन्तर्गत हम देश की भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक सम्पदा, सामाजिक समस्याएँ, जनसंख्या, कृषि, उद्योग आदि समस्याओं का विधिवत् अध्ययन करते हैं। अतः अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बहुत विस्तृत है इसके अन्तर्गत देश की समस्त आर्थिक समस्याओं का अध्ययन होता है।

इस प्रकार का अध्ययन किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यन्त उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा उसको उसकी निर्धनता के कारण, जीवनस्तर को उन्नत करने तथा देश की धार्मिक स्थिति में सुधार करने का समुचित ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त अपने देश की आर्थिक स्थिति की तुलना, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति, देशों के आर्थिक विकास, आदि के अध्ययन से हमें पथ-प्रदर्शन व प्रेरणा मिल सकती है। आज देश के सम्मुख उत्पादन में निरन्तर वृद्धि, राष्ट्रीय आय का उचित वितरण व जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के ध्येय हैं, जिनको पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना अनिवार्य है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

१. प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता के साथ निर्धनता:—भारत के प्राकृतिक साधनों में उपजाऊ भूमि, विविध जलवायु, खनिज पदार्थ व शक्ति के साधन सम्मिलित हैं। इन प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग नहीं किया गया। परिणामस्वरूप देश में निर्धनता का राज्य है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् सरकार इस ओर प्रयत्न कर रही है और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है।

२. बड़ी जनसंख्या:—१९५१ की जनगणनानुसार भारत की कुल जनसंख्या ३६.२ करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या के चेरोबगामी, निम्न जीवनस्तर, प्रति व्यक्ति कम आय तथा कम जीवन अवधि अवश्यम्भावी परिणाम हैं।

३. असंतुलित तथा अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था:—कुल जनसंख्या का लगभग ६७% भाग कृषि में लगा हुआ है, जिससे भूमि पर बहुत अधिक भार है। खेत छोटे छोटे और छिटे हुए हैं और प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है।

४. यातायात के साधनों की कमी—मुख्यतः गांवों में सड़क यातायात की अत्यन्त शोचनीय दशा है। भारत के आर्थिक विकास में ग्रामों का विकास प्रमुख महत्व रखता है। गांवों की उपज मरिदियों तक सुगमतापूर्वक ले जाने के समुचित साधन सुजम होना आवश्यक है।

५. धार्मिक व सामाजिक प्रवृत्तियाँ:—देश के आर्थिक विकास के मार्ग में सामाजिक रीति-रिवाज तथा धर्म बाधक रहा है। जातिप्रथा, उत्तराधिकार के नियम, भाग्यवादिता आदि। अतः प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की स्थापना करना आवश्यक है।

६. आय की असमानता:—संपत्ति का वितरण अनुचित है और प्रति व्यक्ति की आय बहुत कम है।

७. कुशल भ्रम, यान्त्रिक ज्ञान व पूंजी का अभाव:—भ्रम की पूर्ति को अधिक है परन्तु भूमि में कार्यक्षमता की कमी है क्योंकि औद्योगिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कुशल इन्जीनियरों तथा विशेषज्ञों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। पूंजी की कमी के कारण खेती का यन्त्रीकरण सम्भव नहीं हो पाया तथा उद्योगों का भी आधुनिकीकरण नहीं हो सका है।

देश के स्वतन्त्र होने के बाद से अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 'कल्याणकारी राज्य' के लक्ष्य की निर्धारित कर तथा सांख्यिक क्षेत्र की विस्तृत कर सरकार प्रगतिशील समाजवादी दृष्टि के समाज की स्थापना की ओर अग्रसर है। इस भ्येय की प्राप्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं ने नया गत-संचार करना आरम्भ कर दिया है। इन सब बातों का अध्ययन आगे के अध्यायों में किया गया है।

(३) दक्षिणी पठारी प्रदेश :—इसका आकार त्रिकोण है । इसके पूर्व और पश्चिम में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तथा उत्तर में विन्ध्याचल पर्वत हैं । यह प्रदेश पठारी है तथा इसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियाँ बहती हैं । ये नदियाँ यातायात तथा सिंचाई के लिए अनुपयुक्त हैं । यहाँ वर्षा कम होती है, परन्तु पाली मिट्टी पाये जाने के कारण कपास अधिक होती है । कपास के अतिरिक्त यहाँ तिलहन, पड़पा, तम्बाकू, चावल आदि उत्पन्न होते हैं ।

जलवायु

भारत की जलवायु मुख्यतः मानसूनी और उष्ण कटिबंधीय है । भारत के विभिन्न भागों में जलवायु भी भिन्न भिन्न है । उत्तरी भारत तथा पहाड़ियों पर जलवायु ठण्डा है, मैदानों में गर्म और शुष्क और दक्षिण-पश्चिम में गर्म और नम है । भारत में तीन ऋतुएँ प्रधान हैं :—

(१) शीत ऋतु—अक्टूबर से फरवरी तक ।

(२) ग्रीष्म ऋतु—मार्च से जून तक ।

(३) वर्षा ऋतु—जुलाई से सितंबर तक ।

विविध जलवायु का देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है ।

(१) विभिन्न फसलें :—विभिन्न भागों में भिन्न जलवायु के कारण यहाँ विविध प्रकार की फसलें उगती हैं । विभिन्न वनों में भी विभिन्न प्रकार की लकड़ी पाई जाती है ।

(२) कृषि की महत्ता :—भारत की उर्वर भूमि एवं अनुकूल जलवायु के कारण लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है ।

(३) रहन-सहन :—भारतीय जनवायु अनुप्य को कम से कम आवश्यकताओं की ओर प्रेरित करती है—खान-पान, वस्त्र और आवास व्यवस्था में भारतीय को अधिक चिन्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती । लोगों में सन्तोष की भावना प्रबल है ।

(४) कार्यक्षमता :—भारतीय जनवायु लोगों की आलसी बनावी तथा निरलसहित करती है, जिससे भारतीय श्रमिक का कार्यक्षमता निम्न कोटि का है ।

हमें जलवायु के प्रभाव की अविवेकित न देखनी चाहिए और इसकी अपनी आर्थिक अवस्था का कारण न मानना चाहिए, क्योंकि इन श्रमिकताओं के होते हुए भी प्राचीन काल में हमने अभूतपूर्व प्रगति की थी । देश का कार्यक्षमता, वैभव, शान अनुकरणीय था ।

वर्षा :—भारत के कृषिप्रधान देश होने के कारण वर्षा का उचित मात्रा में होना तथा समान वितरण आवश्यक है । वर्षा के समय पर तथा उचित मात्रा में न होने से किसानों को ही नहीं, अविश्व व्यापार, उद्योग और सरकार को भी भारी क्षति होती है । भारत के भूतपूर्व वित्त सचिव ने भारतीय बजट को वर्षा पर निर्भर बुझा (A gamble in Rains) बताया था, जो कि वास्तव में सत्य है ।

भारत में वर्षा कुछ निश्चित भागों में ही होती है । वर्षा करने वाली हवाओं की मानसूनी अथवा मोसमी हवाएँ बहते हैं । मानसूनी हवाएँ दो होती हैं :—

(२) **लैटराइट मिट्टी**—यह मिट्टी मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा के कुछ भाग तथा पूर्वी और पश्चिमी घाटों के समुद्रतट पर पाई जाती है। यह बहुत कम उपजाऊ है। यह चाय, कद्वा, नारियल आदि के लिए उपयुक्त है।

(३) **काली मिट्टी**—यह ज्वालामुखी पहाड़ के विस्फोट (लावे) से बनी है। वर्षा के पानी को रोक रखने की क्षमता के कारण यह कपास के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। कपास के अतिरिक्त इसमें चकार, बाजरा, गेहूँ व दालें भी उगाई जाती हैं। यह बम्बई, मध्य प्रदेश और आंध्र में पाई जाती है।

(४) **लाल मिट्टी**—यह मध्यम श्रेणी की है। यह मद्रास, मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा दक्षिण बंगाल में मिलती है।

भूमि-चरण

मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ कणों को पानी द्वारा बह जाने अथवा हवा द्वारा उड़ जाने से भूमि की जो क्षति होती है, उसे मिट्टी का कटाव या भूमि का चरण कहते हैं।

भारत में भूमि-चरण तीन प्रकार से होता है :—

(१) **समान कटाव**—पानी द्वारा सारी भूमि की ऊपरी उर्वर मिट्टी बहने और नीचे की भूमि समान किन्तु बेकार रहने को एक सा कटाव कहते हैं।

(२) **बिछारदार कटाव**—तेज वर्षा अथवा बाढ़ के कारण भूमि में गहरे गड्ढे अथवा बिछार बन जाते हैं, भूमि जगह जगह कट जाती है। इसे बिछारदार कटाव कहते हैं।

(३) **वायु से कटाव**—सूखे मांगों में जब वायु बड़े वेग से चलती है तो यह अपने साथ मिट्टी के ऊपरी परत के कणों को उठा ले जाती है।

भूमि-कटाव के कारण

(१) **घनों का त्रिनाश**—आंधी और पानी की शक्तियों द्वारा मिट्टी को उड़ा या बहा ले जाने से वन भूमि की रक्षा करते हैं। पहाड़ी ढलानों से वनस्थिति के नष्ट होने से वर्षा के पानी द्वारा भूमि के मूल्यवान् स्तर नष्ट हो जाते हैं। जूझों से आंधियों की शक्ति कम होती है, परन्तु आंधी से रेतीली मिट्टी उठने लगती है। इस प्रकार राजस्थान का मरुस्थल पिछले २० वर्षों से लगभग आधा मील प्रति वर्ष की गति से फैलता आ रहा है।

(२) **कृषि के दोषपूर्ण तरीके**—सेतों पर प्रचलित भूमि उपयोग के दोषपूर्ण तरीकों से भी मिट्टी का कटाव होता है। ढलावदार खमीन पर समानान्तर हल खोदना, पशुओं का उचित देखरेख आदि उपायों का प्रयोग न करना भी मिट्टी के कटाव का कारण है।

मिट्टी-कटाव का उपचार

मिट्टी-कटाव को नियंत्रित करने और भूमि की उत्पादन-क्षमता पुनः लाने के

भारत के प्राकृतिक साधनों में वन-सम्पत्ति का अधिक महत्व है। यहा वनों का कुल क्षेत्रफल २.८१ लाख वर्ग मील है, जो समस्त भारत के क्षेत्रफल का २२% है। राष्ट्रीय वन नीति (१९५२) के अनुसार भारत में कुल भू-क्षेत्र का १/३ भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। हमारे वनों का क्षेत्र आवश्यकता से कम है। इसके साथ ही वनों का विभिन्न राशियों में वितरण भी असमान है।

वनो के प्रकार

देश में विभिन्न जलवायु, भूमि तथा अन्य तत्वों के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाये जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं —

(१) सदाबहार वन — ये हिमालय व पश्चिमी घाट पर जहाँ वर्षा ८० इंच से अधिक होती है, पाये जाते हैं। ये वन बहुत ही घने और गिन्नाल होते हैं। इन वनों की सघनता के कारण यातायात की कठिनाई होती है, अतः इनकी व्यावसायिक उपयोगिता कम होती है। इन वनों के मुख्य वृक्ष ताड़, बांस, बेंत, महुआ, सिनकोना, फर्न आदि हैं।

(२) पतझड़ वाले वन — इनकी पत्तियाँ झड़कर नये छिरे से आती हैं। ये वन उन प्रदेशों में पाये जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा ४० इंच से ८० इंच के बीच में होती है। ऐसे प्रदेश हिमालय के निचले भाग, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं— साल, साल, रीछम आदि। ये वन सदाबहार वनों की भाँति घने नहीं होते तथा इनके वृक्षों की लकड़ी उपयोगी होती है।

(३) पर्णतीय वन — यह हिमालय पर वर्षा होने के कारण भिन्न-भिन्न ऊँचाई पर अलग-अलग प्रकार के पाये जाते हैं, जैसे— देवदार, पाइन, श्वेत सनोकर तथा ओक आदि।

(४) समुद्रतटीय वन:—ये वन समुद्र और नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में हैं। इनमें गंगा के सुन्दर वन प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा ताड़, नारियल आदि के वृक्ष हैं। इन वनों में पाई जाने वाली लकड़ी ईंधन के काम आती है और छात्र चमड़ा रंगने के काम आती है। इनसे नान भी बनाई जाती है।

(५) शुष्क प्रदेश के वन — ये वन सूखे प्रदेश जहाँ २० इंच से भी कम वर्षा होती है, पाये जाते हैं, जैसे राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, मध्य प्रदेश आदि। इनमें मुख्य वृक्ष हैं— बूढ़, करील, काटेदार भाँवियाँ आदि। इन वृक्षों की छाल चमड़ा रंगने और लकड़ी हल, बैलगाड़ी आदि बनाने के काम आती है।

वनो का आर्थिक महत्व

वन प्रकृति की देन है और इस प्रकार बहुमूल्य सम्पत्ति है। वनों के सामानों को दो भागों में बाँट सकते हैं — (१) प्रत्यक्ष लाभ और (२) अत्यक्ष लाभ।

(३) वे वन, जो साधारण लकड़ी, ईंधन व चारा आदि देते हैं ।

(४) चरागाह अर्थात् पशु चराने के स्थान, जो केवल नाममात्र में ही वन हैं, वास्तव में नहीं ।

यह नीति यद्यपि उपयुक्त जान पड़ती है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है ।

(१) इस नीति के अनुसार स्थायी गेती के लिए वनों को नष्ट किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को इमारती लकड़ी और ईंधन की कमी हुई और मोबर जैसी खाद को बनाने लगे । इसके अतिरिक्त भूमि-कृषि के विरुद्ध कोई उपाय न रहा ।

(२) स्थानीय जनसंख्या को वन की उपज पर अधिक अधिकार दिये गये जो राष्ट्र-हित में नहीं थे ।

(३) इस वन-नीति में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित नहीं किया गया, जो एक समुचित नीति में होना आवश्यक है । ये निम्नलिखित हैं:—

(i) वन क्षेत्र को बढ़ाने के उपाय नहीं बताये गये ।

(ii) इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि वनों से सदा ही निश्चित उपज तथा आय प्राप्त हो ।

(iii) वन्य जीवन की रक्षा, वनों के प्रदूषण व नियन्त्रण, वन विज्ञान तथा वन-अन्वेषण की व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कहा गया ।

उपयुक्त दोषों को दूर करने के लिए उचित नई वन नीति की घोषणा मई, १९५२ में की गई । अब यह माना जाने लगा कि वन कृषि की कटाव दाखी नहीं, परन्तु उसके अनिवार्य मित्र और उपमाता हैं तथा कृषि-भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं । वनों की महत्ता की दृष्टिकोण से सन् १९५० में श्री के. एम. मुन्शी द्वारा 'वन-महोत्सव' अथवा 'अधिक वृक्ष उगाओ' आन्दोलन आरम्भ किया । श्री मुन्शी के शब्दों में "वन महोत्सव कृषि-कल्याण की उत्पत्ति नहीं है, यह समरक्षणी उत्सव नहीं है, यह भूमि के रूप-परिवर्तन में अत्यन्त प्रभावपूर्ण बदल है । वन महोत्सव सुवर्ण का उत्सव है, मणिष्य का उत्सव है, आशा का उत्सव है ।"

१९५२ की नई नीति में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया :—

(१) गेसी, अण्डानी, का, रिफल, रिफ, न्या, रिफो, दर, पम्पर की, भूमि, नल, प्रदेण, ये, लाई आप जिसमें यह अधिकतम उत्पादन करे और कम से कम भूमि का अपभ्रंश हो ।

(२) निम्नलिखित को रोकने के लिए विशेष ध्यान देना :—

(i) पर्वतीय वनों के विनाश को रोकना, क्योंकि इससे नदियों को सदा पानी मिलता है और नदी क्षेत्र ही सबसे अधिक उपजाऊ होते हैं ।

(ii) बड़ी नदियों के तटवर्ती किनारों की भूमि पर जो कटाव होता आ रहा है और जिससे आसपास की भूमि भी उर्वरता नष्ट होती आ रही है, उसको रोकना ।

(iii) समुद्री रेत तथै की ओर बढ़ती आ रही है, जिससे राजस्थान के मरुस्थल में बालू के टीले बनते जा रहे हैं, उनका निवारण करना ।

(iv) देश की जलवायु तथा प्राकृतिक अवस्थाओं में सुधार के लिए जहाँ सम्भव हो वृक्ष लगाये जायें ।

(v) चरागाह तथा कृषि-श्रीजारों की लकड़ी की उचित व्यवस्था करना । ईंधन की लकड़ी का विशेष रूप से प्रबंध करना, जिससे गोबर का खाद के लिए प्रयोग किया जा सके और खाद-उत्पत्ति में वृद्धि हो ।

(vi) सुरक्षा, यातायात तथा उद्योग के लिए लकड़ी तथा अन्य वन की उपजों की पूर्ति का प्रबंध करना ।

(vii) उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने हुए अधिकतम वार्षिक आय की प्राप्ति करना ।

वनो का वर्गीकरण

वनो को निम्नलिखित चार वर्गों में बाटा जा सकता है :—

(1) सुरक्षित वन :—जो पूर्ण रूप से राज्य के अधिकार में हैं और जिन्हें जलवायु तथा प्राकृतिक दृष्टिकोण से लगाना आवश्यक है । इनमें से केवल पुराने वृक्ष ही काटे जा सकते हैं ।

(ii) रक्षित वन :—ये वे वन हैं, जिनसे टीक, साल तथा अन्य व्यावसायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं । इसका संगठन व प्रबंध राज्य सरकारों द्वारा होता है ।

(iii) असुरक्षित सामान्य वन :—जिनको ईंधन के वन भी कहते हैं । इनसे आसपास के गावों को बलाने की लकड़ी, कृषि-श्रीजार बनाने की लकड़ी, पशुओं का चारा आदि मिलते हैं । इन वनों का प्रबंध इस उद्देश्य से होना चाहिये कि ये स्थानीय जन-संख्या की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ।

(iv) वृक्षभूमि :—ये क्षेत्र नियमित वनों के अंग नहीं हैं, परन्तु देश की प्राकृतिक दशाओं को सुधारने के लिए वह आवश्यकता है कि लोगों को वृक्षों के बारे में सचेत बनाया जाय और ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षभूमि को बढ़ाया जाय ।

इस प्रकार के वर्गीकरण का उद्देश्य वनों के असतत उपयोग व अत्यधिक कटाव को रोकना है तथा उनके उत्पादन में वृद्धि करना है । वन अभिनारियों की शिक्षा के लिए वन श्रवण सभा तथा महाविद्यालय देहरादून और कोयम्बटूर का प्रबंध है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में वन

इस योजना में वनों पर कुल ११.७ करोड़ रु० (२ करोड़ ५० केन्द्र द्वारा तथा ६७ करोड़ ५० राज्यो द्वारा) व्यय का अनुमान था । मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित निर्धारित किये गये :—

(१) वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए बेकार भूमि तथा नहरों और सड़कों के किनारे वृक्ष लगाये जायेंगे।

(२) औद्योगिक महत्व वाले वनों को विशेष रूप से लगाया जायगा; जैसे चागौन, दियासलाई की लकड़ी के वृक्ष आदि।

(३) वनों के प्रदेशों में यातायात के साधन सुनम किये जायेंगे, जिसमें लकड़ी सुगमतापूर्वक निर्यात जा सके।

(४) केन्द्रीय वन प्रमोदन यह बताए कि प्रत्येक राज्य में वनों के नीचे कितना क्षेत्रफल होना चाहिये। वन उसी समय काटने की आज्ञा देनी चाहिए, जब वे आवश्यकता से अधिक हों या काटे गए क्षेत्र के बराबर नये क्षेत्र पर वन लगाए जा सकें।

(५) जमींदारी की समाप्ति के पश्चात् जो राज्य सरकारों के पास ४ करोड़ एकड़ भूमि आ गई है, उसमें अधिकतम भूमि पर वनों का पुनःस्थापन किया जाय।

(६) वृद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए अधिक काटे गए वनों की निर से लगाना चाहिए।

(७) जिन स्थानों पर मिट्टी-कटाव अधिक है वहां वृक्ष लगाये जायें।

(८) लकड़ी की पूर्ति बढ़ाने के लिए काम में न आने वाली लकड़ियों का रासायनिक द्रव्य से शोधन किया जाय।

(९) विभिन्न गांवों में उद्यानों का विकास किया जाय।

(१०) राज्यों की नीतियों में सामंजस्य करने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अपनी योजना वनों के महानिरीक्षक के पास भेजनी चाहिए तथा समय समय पर राज्यों के अधिकारियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए।

इस योजनाकाल में ७५,००० एकड़ भूमि पर नये वन लगाये गए तथा ३,००० एकड़ प्रतिवर्ष की दर से दियासलाई की लकड़ी के पेड़ लगाए गए और ३,००० मील लम्बी वन की सड़कों को बनाया गया। २ करोड़ एकड़ से भी अधिक वनभूमि को सरकार ने अपने नियन्त्रण में लिया। राजस्थान के रेव की आगे बढ़ने से रोकने के लिए सन् १९५२ में एक मरस्थान बनारोवरण तथा शोध केन्द्र घोषपुर के पास खोला।

द्वितीय योजना में वन कार्यक्रम

वन विकास के लिए कुल २३ करोड़ रु० रखे गए, जिसमें निम्न कार्यक्रम सम्मिलित किए गये :-

(१) ३०० लाख एकड़ पर के वनों का पुनःस्थापन किया जायगा, जिससे वन-क्षेत्र में वृद्धि होगी।

(२) व्यापारिक महत्व के वनों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायगा। ५०,०००

एकड़ पर टीक आदि के वृक्ष, १३,००० एकड़ पर नीला गोंद आदि तथा ५०,००० एकड़ पर दियासलाई की लकड़ी के वृक्ष उगाये जायेंगे।

(१) वनों की सड़कों को उन्नत करने तथा हमारती लकड़ी को अच्छे ढंग से प्राप्त करने के प्रयत्न किए जायेंगे।

(४) वन-संपत्ति के विकास व नियोजन के लिए वनों का सर्वेक्षण करके आवश्यक आंकड़े एकत्र किए जायेंगे।

(५) वन्य जीवन की सुरक्षा के लिये १८ राष्ट्रीय पार्क तथा दिल्ली में एक सिद्धिघा-पर छोला जामगा।

(६) वन अन्वेषण का कार्य बड़ाया जायगा।

(७) वन शिक्षा देने की अधिक सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

(८) वन के कर्मचारियों तथा अभिकों की दशाओं को सुधारने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे।

(९) वनों के कुछ छोटे उत्पादन, जैसे कड़ी वृष्टियों के उत्पादन में वृद्धि की जायगी।

(१०) राज्यों की वन योजनाओं में समन्वय स्थापित करना केन्द्र का काम होगा।

भारत में खनिज

औद्योगिक विकास के लिए खनिज-संपदा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत की खनिज संपत्ति का अभी पूरा सर्वेक्षण नहीं हो सका है। वाणिज्य की दृष्टि से खनिज पदार्थों का तीन वर्गों में अध्ययन किया जा सकता है।

(१) ऐसे खनिज जो निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसे अभ्रक, मैंगनीज, कच्चा लोहा, मैगनेजाइट, लाक, बिस्मथ आदि।

(२) ऐसे खनिज जो देश की आवश्यकता की देखते हुए पर्याप्त हैं, जैसे कोयला, नमक, ब्वाक्साइट, ग्रेफाइट, बेरियम आदि।

(३) ऐसे खनिज जिनका आयात करने की आवश्यकता है, जैसे तेल, ताँबा, सीसा, खरता, टिन, गंधक, चीनी, मिट्टी, निकल आदि।

भारत के मुख्य खनिज पदार्थ

(१) लोहा — किसी भी देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला लोहा है। कच्चे लोहे की अच्छी विरम तथा कोयला खानों की निश्चयता के कारण भारत बहुत कम लागत पर लोहा बना सकता है। भारत के कुछ लोहे के मण्डार तो संसार भर में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। इनमें ६० से ७०% तक धातु रहती है और फास्फोरस तथा गंधक कम होते हैं। भारत में कच्चे लोहे की एशिया में सबसे बड़ी खान है। अनुमान है कि भारत की खानों में लगभग २१०० करोड़ टन लोहा विद्यमान है, जो कि संसार के कुल लोहे के भण्डार का एक-चौथाई है।

वितरण— भारत में अच्छा लोहा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास, बम्बई तथा मैसूर में पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा बंगाल, बिहार और उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। सिन्धुभूमि, कच्छ, बोनाई, मयूरभंज, बंगाल, मैसूर में लोहे के अटूट भण्डार हैं। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे लोहा खनिकार उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, आंध्र के कुरनूल और दक्षिणी भारत के भागों में मिलते हैं।

भारत में कच्चे लोहे का औसत वार्षिक उत्पादन ३५ लाख टन है। द्वितीय योजना में कच्चे लोहे का उत्पादन १९६०-६१ में १०५ लाख टन हो जाएगा, जिसमें से २० लाख टन निर्यात हो सकेगा। अभी तक भारत में विश्व का १%, फ्रांस का १/१० तथा अमेरिका का १/५० कच्चा लोहा उत्पन्न होता है।

(२) मैंगनीजः— यह एक बहुत ही बहुमूल्य धातु है, जो बीलाइ बनाने, रासायनिक पदार्थों, प्लास्टिक, कानिथ और शुष्क टैट्री आदि में काम देता है। इस कारण ही इसको *Jack of all trades* (हरपन मौला) सब व्यवसायों का सहायक करते हैं।

यह मुख्यकर मध्यप्रदेश के झिडवाड़ा नागपुर, बलाघाट और भंडारा जिलों में आंध्र के विशाखापट्टनम, बम्बई के कुछ भागों में, मैसूर, मद्रास, बिहार और उड़ीसा में मिलता है। सबसे अच्छी बिस्म मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बहा देश के कुल उत्पादन का ७०% भाग निकाला जाता है। रूस और गोल्डफेल्ड के बाद मैंगनीज उत्पन्न करने वाले देशों में भारत का स्थान है।

संसार के कुल उत्पादन का ३०% भाग भारत में उत्पन्न होता है, किंतु अधिक भाग विदेशों की निर्यात कर दिया जाता है। भारत में विदेशी विनिमय को प्राप्त करने का यह प्रमुख साधन है। द्वितीय योजना के अनुसार सन् १९६०-६१ में २० लाख टन मैंगनीज निकाला जाएगा, जिसमें से १५ लाख टन निर्यात कर दिया जाएगा। लोहा, इस्पात तथा अन्य धातुओं का देश में विकास होने से इसकी परेल् मांग अवश्य बढ़ जायेगी।

(३) अभ्रकः— यह भी बहुत ही उपयोगी खनिज पदार्थ है जिसका उपयोग मुख्यकर बिजली के उद्योगों तथा तार, टेलीफोन, वेतार के तार, रेडियो, वायुयान, रोगन, फागन, तेल व रबर उद्योगों में किया जाता है।

भारत में दुनिया के सब देशों से अधिक अभ्रक उत्पन्न होती है और विश्व की ७० से ८०% आवश्यकता की पूर्ति होती है। यह मुख्यत बिहार में हजारीबाग व आंध्र में नैलोर में पाया जाता है। केवल बिहार में ही कुल उत्पादन का ६०% भाग निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त यह अजमेर, मारवाड़, द्रावणकोर, मैसूर आदि में भी उपलब्ध होता है। देश के उत्पादन का लगभग सम्पूर्ण भाग निर्यात कर दिया जाता है। द्वितीय योजना में उत्पादन का लक्ष्य २ लाख टन प्रतिवर्ष रखा गया है।

(४) स्वावसाइट — यह अरयूमीनियम बनाने के काम आता है, जिसे वर्तमान युग की अद्भुत धातु मानी जाती है। यह विशेषकर वायुयान उद्योग में बहुत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल साफ करने तथा विशेष प्रकार की सीमेंट तैयार करने में भी आवश्यक होता है।

भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, असम आदि स्थानों में पाया जाता है। इसका कुल अनुमान २५ करोड़ टन है, जिसमें से अच्छे प्रकार की धातु केवल ३५ करोड़ टन के बराबर है।

(५) जिप्समः—देश के औद्योगिक विकास में लोहे और कोयले के बाद इसका स्थान है। इसका उपयोग सीमेंट व खाद बनाने के काम आता है।

भारत में यह मुख्यतः राजस्थान, सौराष्ट्र, बच्छ तथा मद्रास और थोड़ी मात्रा में हिमाचल प्रदेश तथा काश्मीर में मिलता है। इस प्रकार देश के कुल भण्डारों का अनुमान २०० मिलियन टन के लगभग है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १८६ लाख टन जिप्सम प्राप्त करने की योजना है। देश में सीमेंट और सिंटी के खाद के कारखानों के खुलने के साथ साथ जिप्सम की मांग फिर बढ़ रही है तथा भविष्य में और बढ़ने की आशा है।

(६) क्रोमाइट — यह खनिज युद्ध के काम आने के कारण एक महत्वपूर्ण धातु हो गया है। इसके अतिरिक्त विमान तथा मोटरगाड़ियों में भी इसका उपयोग होता है। यह मुख्यकर बिहार, मैसूर, बम्बई, मद्रास और उड़ीसा में पाई जाती है। इसका कुल भण्डार १३२ लाख टन है।

(७) सोनाः—यह बहुमूल्य धातु मुद्रा और अभूषणों के लिए प्रयोग की जाती है। भारत में सोना बहुत कम होता है। यह केवल मैसूर राज्य के कोलार क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ मात्रा में आंध्र तथा बम्बई में भी निकाला जाता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में रेत से भी सोना प्राप्त किया जाता है। सन् १९५७ में लगभग १७९ हजार औंस सोना निकाला गया।

(८) थोरियम — यह एटम शक्ति उत्पन्न करने के प्रयोग में आता है और भारत के केवल केरल राज्य में बड़ी मात्रा में मिलता है।

(९) नमकः—हमारे नमक के साधन पर्याप्त हैं। समुद्रतटीय राज्यों—जैसे बम्बई, मद्रास, केरल, आंध्र आदि में समुद्र के पानी को सुलाकर नमक बनाया जाता है। इस प्रकार ७०% नमक इस ही साधन से प्राप्त होता है। देश के आन्तरिक भागों में मुख्यकर राजस्थान में सागर जैसी खारी झीलों से पानी से नमक बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मण्डी स्थान पर पहाड़ी संधा नमक बहुत कम मात्रा में निकलता है। इस नमक का मुख्य स्रोत पाकिस्तान में है।

(१०) तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, निकल आदि — तांबा—इसकी खानें मुख्यकर बिहार के सिंहरूमि स्थान पर हैं जहां तांबा पट्टी ८० मील तक फैली हुई है। थोड़ी मात्रा में

(६) कुछ महत्वपूर्ण खनिजों को जो निर्यात के लिए निकाले जाते हैं, उनको तैयार अथवा अर्ध-तैयार अवस्था में बाहर भेजना ।

(७) निम्न प्रकार के खनिज पदार्थों का अन्वेषण करके शान प्राप्त करना ।

उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर सन् १९५२ में राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई ।

प्रथम योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए १ करोड़ ४० की व्ययराश की गई, जिसके बाद में २५ करोड़ ४० तक बढ़ा दिया गया । द्वितीय योजना में औद्योगीकरण पर विशेष महत्व देने का कारण खनिज विकास पर ७३ करोड़ ४० व्यय करने का अनुमान किया गया ।

शक्ति के साधन

औद्योगिक विकास और आर्थिक उन्नति के लिए शक्ति के साधनों का प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है । शक्ति के विभिन्न साधन हैं—मनुष्य, पशु, वायु, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम तथा जल, परमाणु शक्ति तथा सूर्य शक्ति आदि ।

मनुष्य व पशु शक्ति के बारे में आगे वर्णन किया जायगा । वायु का भारत में शक्ति के रूप में अभी प्रयोग नहीं होता । लकड़ी के बारे में हमें पहले से ही शत है कि हमारे वन इतने कम हैं कि उन्हें शक्ति-उत्पादन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता । वर्तमान औद्योगिक विकास के लिए कोयला, पेट्रोलियम तथा जल विशेष महत्वपूर्ण हैं ।

कोयला

लोहे के साथ कोयला औद्योगीकरण के लिए आवश्यक है । यह कहा गया है कि कोयला वर्तमान संयोग चन्धों की अनेक रूप में सेवा करता है ।

विश्व में कोयला उत्पन्न करने वाले देशों में भारत का शुद्ध स्थान है । परन्तु हमारे देश में घटिया किरम का कोयला ही अधिकतर मिलता है क्योंकि इसमें अत्यधिक राख और नमी पाई जाती है । भारत में कुल कोयले का भण्डार १६५० में ३०,००० मिलियन टन आँका गया था और बाद में कुल कोयला शक्ति का अनुमान ६५०० करोड़ टन लगाया गया था ।

भारत में कोयला क्षेत्रों का वितरण असमान है । कुछ उत्पादन का ८०% भाग केवल बिहार तथा बंगाल से प्राप्त होता है । कुछ कोयला मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा हैदराबाद में मिलता है । इन खानों से पश्चिमी क्षेत्रों तक कोयला पहुँचाने में यातायात-व्यय अधिक होता है ।

इस समय भारत में ८०० कोयले की खानें हैं । पिछले कुछ वर्षों से कोयले का उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है । अधिकतर कोयला रानीगंज व झरिया की खानों से निकाला जाता है ।

इस प्रकार भारत में कोयला कम पाया में है । सन् १९३७ में भारतीय कोयला समिति ने यह बताया था कि भारत में कोयला १०० वर्ष तक तथा साधारण कोयला ६२ वर्ष तक चलेगा । अभी ज्ञान ही यह कहा गया कि अच्छे कोयले का अभाव इसी सदी के अन्त तक हो जाएगा । इस कारण उद्योग-धन्यों की उन्नति के लिए कोयले पर निर्भर बहुत समय तक नहीं रहा जा सकता ।

भारत में कोयले खोदने के दम में बड़े अमन्तीकरण हैं । बहुत सा कोयला खोदने में ही नष्ट हो जाता है । यह आवश्यक है कि कोयला ठीक प्रकार से निगाला जाय तथा उसका अधिक से अधिक लाभदायक कार्यों में उपयोग किया जाय ।

१९५२ में कोयला खान संरक्षण तथा सुरक्षा नियम के पास हो जाने से सरकार को विस्तृत अधिकार मिल गए । इस विधान के अन्तर्गत एक केन्द्रीय मण्डल तथा परामर्श दायी समिति स्थापित की गई ।

योबना आयोग ने सुझाव दिया कि कोयले के खानों का पता लगाना जाय, उग्रता उचित वर्गीकरण किया जाय और कोयले का उचित दम से बेचाया गया जाय । सन् १९५५ में सरकार ने कोयले की खानों का एकीकरण करने के लिए एक समिति नियुक्त की ।

द्वितीय योजना में खनिज विकास की महत्वपूर्ण स्थान दिया गया । वृत्तरी योजना के अन्त में ६ करोड़ टन कोयले की माग होगी ।

पेट्रोलियम

वर्तमान युग में पेट्रोलियम की विशेष श्रौंगिक महत्ता है । परन्तु भारत में यह नाम मात्र की ही निकलता है । बर्मा और पकिस्तान के पृथक् होने से हमारे देश की यह तेल रिदेरी से मगाना पड़ता है । देश की आवश्यकता का केवल १०% पेट्रोल ही देश में उत्पन्न होता है । पट्टान केन अरब के डिगरोद, बाप्पाय सपा हापाय स्थानों पर मिलता है । अब इस खनिज तेल की देश के अन्य क्षेत्रों में खोज की जा रही है ।

द्वितीय योजना में तेल खानों का पता लगाने के लिए ११.५ करोड़ रु० निर्धारित किये गए हैं । आधुनिक मशीनों से तेल की खोज का काम पश्चिमी बंगाल और पंजाब के ज्वालामुखी स्थानों में आरम्भ हो गया है । सम्मात प्रदेश में तो तेल मिल भी गया है । ५० बंगाल, अरब और राबन्धान के बैकनमेर क्षेत्र में सरकार विदेशी निरोपों की सहायता से सर्वेक्षण का कार्य कर रही है । इस प्रकार डा० एम० एन० कृष्णन् के अनुसार यह आशा की जा सकती है कि भारत अगले १० वर्षों में तेल में आत्मनिर्भर हो जाएगा ।

इसके साथ ही आयात किये हुए कच्चे तेल की मात्रा करने ■■■ लिए हाल ही में तीन तेल कंपनियों द्वारा देश में तेल काज करने के तीन करारनाएँ—दो ट्राम्पे में और एक मिथिलापट्टम के पास स्थापित किये गए हैं । ये तीन विदेशी कंपनियाँ ये हैं —

(१) अमरीका की स्टैण्डर्ड त्रकुअम आयल कम्पनी, सन् १९५४ में ।

(२) इंग्लैण्ड की बर्माशैल कम्पनी, सन् १९५५ में ।

(३) अमरीका की कालटेक्स कम्पनी, सन् १९५७ में ।

इन तीन कम्पनियों की तेल साफ करने की क्षमता ३७ लाख टन प्रतिवर्ष है । सरकार अब सरकारी तेल के साफ करने के कारखाने को स्थापित करने की योजना बना रही है—एक असम में तथा दूसरा बिहार में । इसके अतिरिक्त पेट्रोल की कमी को चीनी के शीरे से शक्ति अल्कोहल तथा कोयले से कृत्रिम तेल बनाकर भी पूरा किया जा सकता है । इस ओर राज्य की ओर से एक कारखाना खोलने का निश्चय है, जो प्रतिवर्ष ३ लाख टन सिन्थेटिक तेल उत्पन्न करेगा ।

जल-विद्युत् शक्ति

भारत में शक्ति के साधनों में जलशक्ति का विशेष स्थान है । कोयला तथा पेट्रोल के कम पाये जाने के कारण विद्युत् शक्ति पर ही निर्भर रहा जा सकता है । बिजली द्वारा सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं । आधुनिक जीवन बिजली पर इतना आश्रित है कि लोगों के रहने-सहने के स्तर का माप बिजली के उपयोग की मात्रा से लगाया जाता है । इसका पारिवारिक उपयोग विभिन्न रूपों में है—रोयनी करना, पका खलाना, हीटर चलाना, रेडियो, टेलीवीन आदि ।

बिजली कृषि के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है क्योंकि इससे व्यूबैल द्वारा सिंचाई तथा खेती के नए औजारों का प्रयोग किया जा सकता है ।

छोटे छोटे उद्योग घरों के लिए बिजली अत्यन्त उपयोगी है और इसी कारण जापान तथा स्विट्जरलैंड जैसे देश सम्पन्न राष्ट्र बन गए । इसके अतिरिक्त विशालस्तरीय उद्योगों के लिए भी बिजली बहुत उपयुक्त सिद्ध हुई है । इसके द्वारा उद्योगों का विकेन्द्रीकरण सम्भव हो सकता है, जिससे बहुत सी सामाजिक, नैतिक व आर्थिक बुराइयाँ को दूर किया जा सकता है और स्थानीय भ्रम, शक्ति, कच्चे माल, बाजार और खुले स्थान का लाभ उठाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त यातायात के साधनों की समस्या बिजली की रेलों द्वारा सुलभ सकती है और इस प्रकार कोयले की बचत हो सकती है । इस प्रकार भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में बिजली द्वारा अभूतपूर्व सहायता मिल सकती है ।

भारत में जल-शक्ति के साधन

भारत में बिजली की शक्ति का अनुमान ३५ करोड़ किलोवाट लगाया गया है परन्तु यहाँ ५ लाख किलोवाट से अधिक शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकी है । इसका कारण यह है कि बिजली के कारखाने स्थापित करने में अधिक धन की आवश्यकता होती है ।

भारत में एक वर्ष में जितनी बिजली का उपयोग होता है उतनी अमेरिका में केवल एक सप्ताह में ही उपयोग में ले ली जाती है । यहाँ कुल उपयोग का ४२% भाग बर्बाद और

कलकत्ता के नाम आ जाता है । हमारे देश में प्रति व्यक्ति बिजली का प्रयोग केवल २५ किलोवाट घण्टे वार्षिक है, जबकि इंग्लैंड में ६८६, अमेरिका में २६१६ तथा कनाडा में ३५३६ किलोवाट है ।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् सरकार जल को घन का रूप देने की ओर प्रयत्नशील है और वर्तमान समय में समस्त देश में लगभग १६० योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनके पूर्ण होने से २५ करोड़ एकड़ भूमि अतिरिक्त सींची जा सकेगी, ५०-६० लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न होगा और १ करोड़ किलोवाट बिजली बनेगी ।

प्रथम योजना में १३ लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य था, परन्तु योजनाकाल में वृद्धि केवल ११ लाख किलोवाट की ही हुई । बिजली योजनाओं के लिए २६० करोड़ ८० की व्ययपथा की गई थी । द्वितीय योजना में बिजली उत्पादन का अनुमान ३५ लाख किलोवाट का लगाया गया और सार्वजनिक क्षेत्र पर कुल ४२७ करोड़ २० के व्यय की सम्भावना की गई । तृतीय योजना में बिजली के लिए ६ अरब २० की 'प्रारम्भिक राशि' निर्धारित की गई है ।

भारत के मुख्य जल-विद्युत् केन्द्र

(१) बम्बई राज्य :—बिजली उत्पादन में देश में सर्वप्रथम है । यहाँ राज्य के बिजली के ३ कारखाने हैं :— (i) लोनावाळा, (ii) आग्रम घाटी और (iii) नीलामूला । इन केन्द्रों से राज्य के लगभग १८०० मील क्षेत्र को बिजली मिलती है ।

(२) महाराष्ट्र :—यहाँ ३ मुख्य विद्युत् केन्द्र हैं :—

(i) पाहारा—सन् १९३२ में पाहारा नदी के प्रपात से बिजली उत्पन्न कर इसकी स्थापना की गई । इसके द्वारा ६०% कपड़े की मिलों तथा १५% अन्य औद्योगिक कारखानों की होती है ।

(ii) मैटूर—कावेरी नदी पर बाध बना कर मैटूर स्थान पर सिंचाई की नहरें तथा बिजली उत्पन्न करने की व्यवस्था की गई ।

(iii) पापानाशम्—यह योजना १९४४ में पूर्ण हुई । इसकी क्षमता २१००० किलोवाट घूनिट है ।

मैसूर में महात्मा गांधी जल विद्युत् केन्द्र का नाम १९४२ में पूरा हुआ था । पहले इसका नाम भोगशक्ति योजना था ।

पञ्जाब में मण्डी जल-विद्युत् योजना के अन्तर्गत भोगेन्द्रनगर स्थान पर बिजलीघर बनाया गया है ।

काश्मीर में जेठम नदी पर बारामूला स्थान पर कारखाना स्थापित किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में, जल-विद्युत् गगानहर विद्युत् संगठित कम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती है । इससे प्राप्त विद्युत् एह बनाये जा चुके हैं । प्रथम योजना में दो जल-विद्युत् योजनाएँ—पथरी तथा शारदा पूरी हो चुकी हैं ।

(४) मचकुण्ड योजना.—आन्ध्र प्रदेश में विद्यासापत्तनम् जिले में यह बांध बनाया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस बांध के पास बने बिजलीघरों की क्षमता १ लाख २ हजार किलोवाट हो जायगी। इस पर अनुमानित व्यय २७.३२ करोड़ ६० है।

(५) मयूराक्षी योजना (प० प्रगाल) —यह बांध १९५५ में तैयार हो चुका है और इसके पास बने विद्युत घर से ४००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। अनुमानित लागत १६.११ करोड़ ६० है।

(६) कोसी योजना.—उत्तरी बिहार को इस नदी की बाढ़ के कष्ट से बचाने के लिए यह योजना बनाई गई है, जिस पर सन् १९५५ में काम आरम्भ हो गया था। कुल ४६ करोड़ ६० के व्यय का अनुमान है और द्वितीय योजना के अन्त तक इस बांध के पूरे होने की आशा है।

(७) कोयना योजना (बम्बई)—यह १९५४ में आरम्भ की गई थी और आशा है १९६० के अन्त तक इससे बिजली मिलने लगेगी।

(८) नागार्जुन सागर योजना (आंध्र प्रदेश) :—आंध्र राज्य में कृष्णा नदी पर बांध बनाया जायगा, जिसकी कुल लागत का अनुमान १२२ करोड़ ६० है। इसके द्वारा ७५००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी।

(९) रिहन्द बांध (उत्तर प्रदेश) :—उत्तर प्रदेश में रिहन्द नदी पर दिसम्बर १९४७ में इस योजना पर कार्य आरम्भ हो गया था। योजना की कुल लागत का अनुमान ४५.२६ करोड़ ६० है और उससे २.५ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी।

(१०) चम्बल योजना—यह १९५३ में आरम्भ की गई थी। इसपर अनुमानित व्यय ७१.६६ करोड़ ६० होगा और इससे २ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। इसके अन्तर्गत गांधी सागर बांध, यणाप्रताप सागर बांध, कोटा बांध और कोटा बैरेज बनाने का कार्यक्रम है।

इन योजनाओं के अतिरिक्त और भी कई योजनाएँ देश के विभिन्न भागों में चलती जा रही हैं।

प्रश्न

१. भारत के प्राकृतिक साधनों पर प्रकाश डालिये। क्या उनका उचित विकास हुआ है? यदि नहीं तो उन्नति के मुद्दा पर दीजिये।
२. “मानसून के अतिरिक्त कदाचित ही कोई दूसरा कारण भारत की ग्राम्य व्यवस्था पर इतना प्रभाव डालता है।” इस बारे में अपने विचार दीजिये।
३. भारत में मिट्टी कितने प्रकार की गई जाती है? मिट्टी कृषि को कैसे रोका जा सकता है?

- ४ भारत के मुख्य खनिज पदार्थों का वर्णन करिय और उनका औद्योगिक महत्व बताइये ।
- ५ भारत में शक्ति के विभिन्न साधनों का विवरण दीजिये । कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी-घाटी योजनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिये ।
- ६ भारत की जन-सम्पत्ति का आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है ?
- ७ भारत एक धनी देश है, परन्तु इसके निवासी निर्धन हैं । इसको समझाइये ।



किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान है । कल्याणकारी राज्य की आकांक्षा की पूर्ति के लिये तथा आर्थिक नियोजन के समय जनसंख्या के आकार, रचना तथा कार्यक्षमता का अध्ययन आवश्यक है ।

भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है । सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या वम्बू, कश्मीर और असम के कबायली क्षेत्र सहित ३६ करोड़ १८ लाख के लगभग थी । इस दृष्टि से विश्व में चीन के बाद भारत का ही स्थान है । सन् १९५८ में अनुमान लगाया गया था कि भारत की जनसंख्या ३६.७५ करोड़ है । १९४१ से १९५१ में जनसंख्या में वृद्धि की दर १३.४ प्रतिशत रही है । यह वृद्धि बहुत अधिक है ।

विभिन्न राज्यों में जनसंख्या की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, जहाँ ६३२ लाख थी । इसके बाद बम्बई ४८० लाख, बिहार ३८८ लाख आदि हैं । जनसंख्या की वृद्धि दर भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रही है । सबसे अधिक बम्बई (२०.८%) की वृद्धि हुई, जबकि पश्चिम में ५% घटी है ।

जनसंख्या का घनत्व

औसत रूप में एक वर्गमील में जितनी जनसंख्या होती है, उसी को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं । देश की कुल जनसंख्या में उसके कुल क्षेत्रफल का भाग देकर जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है । भारत में जनसंख्या का घनत्व ३१२ प्रति वर्ग मील है । देश के विभिन्न भागों में घनत्व भिन्न भिन्न है । दिल्ली प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व ३०१७ है जो सबसे अधिक है ।

जनसंख्या के घनत्व में अन्तर होने के अनेक कारण हैं ।

(१) प्राकृतिक दशाः—जिन क्षेत्रों में पहाड़ियाँ या पठार हैं, वहाँ की जनसंख्या कम और मिट्टर, कर, बम्बी, होती है । इसके विपरीत मैदानी भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है । भारत में गंगा के मैदान में दक्षिण के पठार तथा हिमाचल प्रदेश, असम आदि पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व अधिक है ।

(२) जलवायुः—जिन स्थानों पर जलवायु स्वास्थ्यप्रद और सक्रियकारी होगी, वहाँ अधिक लोग रहेंगे और जहाँ जलवायु हानिकारक होगी वहाँ कम । जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि में घनत्व अधिक है और असम तथा हिमाचल की तराई में कम है ।

(३) वर्षा.—जिन प्रदेशों में वर्षा उचित मात्रा व उचित समय पर होती है वहां कृषि अच्छी प्रकार हो सकती है। अतः यहाँ प्रति वर्गमील अधिक जनसंख्या होती है। ऐसे प्रदेश हैं—बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि। असम में वर्षा तो अत्यधिक होती है, परन्तु जलवायु अस्वास्थ्यकर होने से घनत्व कम है। राजस्थान और पंजाब में वर्षा की न्यूनता के कारण घनत्व कम है।

(४) सिंचाई की सुविधा —जिन स्थानों में वर्षा की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ कृषि उत्पादन के बढ़ने के कारण ही जनसंख्या का घनत्व अधिक हो जाता है। सिंचाई के कारण ही पंजाब का घनत्व अधिक हो गया, यद्यपि वहाँ वर्षा होती है। विविध बहुउद्देशीय योजनाओं के पूर्ण होने से वहाँ के घनत्व में वृद्धि होने की आशा है।

(५) भूमि की उर्वरता —भूमि के अधिक उपजाऊ होने के कारण अधिक उपज प्राप्त हो सकती है और इस प्रकार घनत्व बढ़ जाता है। बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश आदि में जनसंख्या का घनत्व इसी कारण अधिक है। राजस्थान तथा दक्षिणी पठार की भूमि कम उपजाऊ है इसलिए वहाँ घनत्व कम है।

(६) औद्योगिक वृद्धि —बंगाल और बम्बई राज्य औद्योगिक उन्नति के कारण हो घने बसे हुए हैं। दूसरी ओर पंजाब और राजस्थान औद्योगिक विकास के अभाव में कम घने बसे हुए हैं।

(७) सुरक्षा —किसी क्षेत्र की जनता की संख्या वहाँ पर लोगों की जान और माल की सुरक्षा पर भी बहुत कुछ निर्भर रहती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है क्योंकि वहाँ किसी भी समय आक्रमण हो सकता है।

उपरोक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि जनसंख्या के घनत्व के अन्तर का कोई एक निश्चित कारण नहीं है—विभिन्न कारण एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभाव डालते हैं।

भारत की जनसंख्या के घनत्व की तुलना अन्य देशों से करें तो शायद होगा कि औद्योगिक राष्ट्रों की अपेक्षा हमारे देश का औसत घनत्व कम है। भारत का घनत्व ३१२, इंग्लैंड का ५३६, बेल्जियम ६५४, जर्मनी ४४३ और जापान का ५७६। कुछ कृषिप्रधान देशों का घनत्व कम है, जैसे फ्रांस का १६३, चीन का १२३, कनाडा और आस्ट्रेलिया का ३।

जन्म व मृत्यु दर.—इसका तात्पर्य यह होता है कि किसी देश में एक वर्ष में प्रति १००० व्यक्तियों के पीछे कितने बच्चे जन्म लेते व कितने व्यक्ति मरते हैं। इन दोनों के अन्तर को वृद्धि की दर कहते हैं। भारत में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही सड़ार में सबसे ऊँची है।

देश

जन्मदर

मृत्युदर

भारत

३६.६

२७.४

(१९५१ की जनगणना के कमिशनर
के अनुमान के अनुसार)

इंग्लैंड	१५.६	११.४
अमेरिका	२४.७	६.६
चीन	३.७	१.७
जापान	२१.५	८.६

भारत में बन्मदर के अधिक होने के कारण —

(१) भ्रूण आयु में विवाह —भारत में ८०% लड़कियों का विवाह १५ से ३० वर्ष की आयु में हो जाता है, जबकि ब्रिटेन में इस आयु वर्ग में केवल ४१% का विवाह होता है। बाल विवाह के प्रचलन के कारण है—बलवायु का सप्य होना तथा सामाजिक रीति-रिवाज। इस प्रकार पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारत में बन्मदर अधिक है।

(२) अज्ञानता तथा अन्धविश्वास —अनपढ़ होने के कारण अधिकतर लोग मायवादी हैं और बच्चों को भगवान की देन समझते हैं तथा जीवनस्तर ऊँचा उठाना नहीं चाहते, जिससे परिवार का आकार बढ़ता जाता है।

(३) निर्धनता—निर्धन होने के कारण छोटे बच्चों को भी कामाने की ओर प्रेरित किया जाता है और इस प्रकार अधिक बच्चे होना अच्छा समझा जाता है। इसी प्रकार घन के अभाव में गर्भ निरोधक कृत्रिम साधनों का प्रयोग भी नहीं हो पाता।

(४) अधिक मृत्युदर —मृत्युदर अधिक होने के कारण (मुख्यकर बाल-मृत्यु) यह निश्चित नहीं हो पाता कि उनके कितने बच्चे जीवित रह पायेंगे और इस प्रकार मृत्यु के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा करने के लिए अधिक बच्चे उत्पन्न करते हैं।

(५) गर्भ निरोधक साधनों का जैसा पश्चिमी देशों में प्रचलन है, भारत में नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोग निर्धन, मायवादी व निरक्षर हैं।

मृत्युदर के ऊँचे होने का कारण बाल व स्त्री-मृत्यु की अधिकता है। भारत में सन् १९५० में बालमृत्यु दर १३७ प्रति हजार थी, जबकि अमेरिका में २६.२, इंग्लैंड में २५.८। बालमृत्यु की अधिकता के कई कारण हैं—बालविवाह, मातृत्व का अज्ञान, दूध व दवाइयों का अभाव, शिथिल दाइयों व नर्सों की कमी, निर्धनता, रोगों का गिरा हुआ स्वास्थ्य आदि।

इसके अतिरिक्त रोगों की मृत्यु दर भी बहुत ऊँची है। यह भारत में २० है, जबकि इंग्लैंड में केवल २.६ प्रति १०००। इस ऊँची मृत्युदर के कारण ये हैं—बालविवाह, मातृत्व सम्बन्धी अज्ञान, पुष्टिकारक भोजन का अभाव, शिथिल दाइयों की कमी आदि।

लोगों की सम्पन्नता बढ़ने तथा चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाओं के प्रसार के साथ साथ मृत्युदर भी कम हो रही है परन्तु बन्मदर लगभग स्थिर ही है।

सन्तानोत्पत्ति की दर—इस दर का सिद्धान्त श्री कुनिन्सकी ने प्रतिपादित किया। इसके अनुसार यदि १००० स्त्रियों ने १००० लड़कियों को जन्म दिया जो सन्तानोत्पत्ति की आयु तक जीवित रहें तो इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक पीढ़ी नई पीढ़ी को जन्म दे रही है और सन्तानोत्पत्ति का औसत एक हुआ। यदि १००० लड़कियों से अधिक उत्पन्न हुईं तो औसत एक से अधिक होगा। यह दर निकालने के लिए यह मानना पड़ता है कि प्रत्येक स्त्री सन्तानोत्पत्ति—काल तक जावित रहती है और फिर परिणाम को मृत्यु-तालिका से ठीक किया जाता है।

हुल का विषय है कि सन्तानोत्पत्ति का ठीक औसत निकालने के लिए हमारे पास उचित आँकड़े नहीं हैं। डा० घाफ के अनुसार यह औसत १.१ है, जबकि राष्ट्रीय योजना समिति के अनुमान के अनुसार १.४५ है।

लिंग अनुपात

भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति १००० पुरुषों के पीछे ९४७ स्त्रियाँ थीं। उड़ीसा, मद्रास, केरल और कर्णाट राज्यों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक थी। दूसरी ओर दिल्ली में १००० पुरुषों के पीछे ५६८ स्त्रियाँ तथा अन्धमान निकोबार में केवल ६२५ स्त्रियाँ थीं।

जीवन की अवधि

भारत में अन्य देशों की तुलना में जीवन की अवधि बहुत कम है। इसका कारण बाल व स्त्रियों की अधिक मृत्युसंख्या तथा निधनता है। सन् १९३१ में औसत आयु (पुरुष की) २७ वर्ष थी जो बढ़कर १९५१ में ३२ वर्ष ५ मास हो गई। स्त्रियों की औसत आयु सन् १९३१ में २६ ५६ वर्ष से १९५१ में ३१ ६६ हो गई। दूसरे देशों में दीर्घ जीवन के कारण अधिक उन्नति हुई है। कुछ देशों के लोगों की जीवन अवधि इस प्रकार है—

(१) हंगेरी ६६ ३६ वर्ष (२) कनाडा ६५ १८, (३) आस्ट्रेलिया ६६, (४) स्वीडन ६७ ०६ जबकि भारत की ३२ ४५।

इस प्रकार भारत में लोग अपने जीवन की उस प्रभात बेला में ही मर जाते हैं, जबकि वे समाज के कल्याण में अपना सबसे अधिक योग दे सकें। अतः भारत का निर्धन होना इस कारण से अधिक है।

व्यवसाय की दृष्टि से जनसंख्या का वितरण

इस प्रकार के अध्ययन से देश की आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का ६६.५% शहरी पर निर्भर था, जबकि हंगेरी में ६%, अमेरिका में १६%, कनाडा २६% तथा आस्ट्रेलिया में १६%। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में कृषिप्रधान उद्योग है और इन्हीं पर अधिकतर लोग निर्भर हैं।

भारत में खानों, उद्योगों और व्यापार में केवल १६% भाग लगा हुआ है, जबकि अमेरिका में ४५.६% और इंग्लैंड में ५५.५% भाग लगा हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि भारत उद्योग-धन्यो में कितना पिछड़ा हुआ है।

भारत की जनसंख्या का ८२.७% भाग गांवों में और १७.३% भाग नगरों में रहता है। पश्चिमी देशों में स्थिति यद्वा से विपरीत है; जैसे इंग्लैंड में ८० प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है तथा फ्रांस में ५२ प्रतिशत। अन्य राज्यों की अपेक्षा बर्माई तथा प० बंगाल में कुल जनसंख्या का ३१ और २४.८ प्रतिशत नगरों में रहा हुआ है। गत वर्षों से नगरों में बसने की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है। परन्तु फिर भी इतने बड़े देश में नगरों की संख्या बहुत कम है। इससे ज्ञात होता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था कितनी अवनत है। १९५१ में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ७३ थी। प्राचीन जनता अधिकतर अशिक्षित, भाग्यवादी तथा अमंगलशील होती है। इसके विपरीत नगरवासी प्रगतिशील तथा शिक्षित होते हैं। इस प्रकार किसी देश में नगरों की अधिकता वहां के भौतिक विकास की चेतक है।

भारत में जनसंख्या की समस्या

भारत में जनसंख्या देशके साधनों के दृष्टिकोण से अधिक है अथवा नहीं—यह प्रश्न विचारणीय है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम भारत में जनसंख्या में वृद्धि के कुछ तथ्यों का विवेचन करेंगे। १९२१ से १९५१ तक ३० वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि की दर ३६% रही है। यद्यपि कुछ वर्षों से जन्मदर में कमी आई है, लेकिन मृत्युदर में इससे अधिक गिरावट आई है, जिसके कारण जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है। इस प्रकार एक ओर तो जनसंख्या में इस गति से वृद्धि है और दूसरी ओर न तो छायापन का संसाधन ही बढ़ा है और न जनता के रहन-सहन के स्तर में ही सुधार दृष्टिगोचर होता है। यह इस बात को सिद्ध करते हैं कि भारत के सामने अति जनसंख्या की समस्या है।

कुछ लोगों के अनुसार भारत में अधिक जनसंख्या नहीं है। इस विचार के पक्ष में उनका कहना है कि (१) हमारे प्राकृतिक साधन बहुत हैं और उनके उचित उपयोग से देश अधिक जनसंख्या का बोझ उठाने में समर्थ हो सकता है। (२) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की वृद्धि इस बात की साक्षी है कि हमारी जनसंख्या अधिक नहीं है। (३) भारत में भूमि की कमी भी इस बात की दृष्टि करती है कि भारत की जनसंख्या अधिक नहीं।

परन्तु वास्तविकता कुछ और है। प्राकृतिक साधनों का बितना उपयोग इस समय किया जा सकता है उसको देखते हुए जनसंख्या अधिक ही है। दूसरे लोगों की चारुतिक आय में वृद्धि नहीं हुई है और तीसरे अशिक्षित मजदूरों की कमी नहीं, परन्तु शिक्षित भूमि की वास्तव में कमी है। इस प्रकार यह सहज ही निष्कर्ष निष्पत्ता जा सकता है कि हमारे देश में जनसंख्या अधिक है और इस जनसंख्या को समझने का प्रयत्न करने आवश्यक है। मात्स्य का जनसंख्या का विद्वान्त हमारे देश में पूर्ण रूप से ज्ञात होता है।

मात्स्य के सिद्धान्त के अनुसार किसी देश की जनसंख्या खाद्य सामग्री की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है—यदि किसी प्रकार के अवरोध न हों। ये अवरोध दो प्रकार के हैं—(१) प्राकृतिक प्रतिबन्ध—जैसे अकाल, महामारी, युद्ध आदि। (२) निवारक प्रतिबन्ध—जैसे सयम अथवा गर्भ निरोधक उपाय। भारत में जनसंख्या को रोकने के लिए निवारक उपायों का प्रयोग नहीं होता, जबकि प्राकृतिक प्रतिबन्ध बिना किसी रुकावट के अपना कार्य कर रहे हैं। इसी कारण से भारत में मृत्युदर विश्व के अन्य देशों से बहुत अधिक है।

जनसंख्या के आधुनिकतम सिद्धान्त 'आदर्श जनसंख्या' (Optimum Population) के अनुसार भी भारत अतिविकाशित देश है, क्योंकि लोगों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत कम है। यद्यपि आबड़ों से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय निरन्तर बढ़ती जा रही है, परन्तु हमें मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना चाहिये। इस हिसाब से हमें शक होगा कि प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः यह सर्वविदित है कि भारत में अति जनसंख्या की गम्भीर समस्या है। इसके अतिरिक्त नवविषय में भी जनसंख्या के बढ़ने की प्रवृत्ति है। द्वितीय योजना की रिपोर्ट के अनुसार १९६१ से १९७० के बीच जनसंख्या की वृद्धि की दर १३.३% का अनुमान है और १९७१ से १९८० के लिए १४% की वृद्धि दर को माना है। इन दरों के आधार पर सन् १९८१ में देश की जनसंख्या ५४ करोड़ हो जायेगी।

जनसंख्या को सीमित करने के उपाय

देश की इस तेजी से बढ़ती जनसंख्या की वृद्धि की गति कम करना एक अत्यन्त आवश्यक राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या के सुलझाने के लिए निम्न उपायों को बताया जा सकता है—

(१) देर में विवाह—कुछ नगरों में शिक्षा के प्रचार से और आर्थिक कारणों से अब विवाह देर से होने लगे हैं। परन्तु अधिकांश विवाह अल्प आयु में ही हो जाते हैं, जिससे यहाँ की जन्मदर अधिक है।

(२) नैतिक सयम—जनसंख्या को सीमित करने का सबसे सरल और सादा उपाय आत्मसंयम है जिसकी महत्त्वा गांधी ने भी उपयुक्त बताया है। परन्तु व्यावहारिक रूप में इसकी उपयोगिता कम है और इस प्रकार बर्ध-कंट्रोल के साधन ही अधिक आवश्यक हैं।

(३) शिक्षा—शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता है, जिससे लोग भली प्रकार से अपने अपने परिवार के और समाज के उत्तरदायित्व को समझने लगें। इस प्रकार शिक्षा से परिवार के आकार को सीमित रखने में परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा।

(४) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें—लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और अधिक धन उत्पन्न होगा। यद्यपि अधिक चिकित्सा की सुविधाओं से आरम्भ में तो मृत्युदर घटेगी, परन्तु अन्त में जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगेगी। क्योंकि ऊँची बालमृत्यु दर के भय से लोग अधिक बच्चे उत्पन्न करते हैं।

(५) 'देशान्तर-गमन'—एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक देश से दूसरे देश को अतिरिक्त जनसंख्या भेजने का सुझाव युक्तिसंगत नहीं मानी जा रहा है। क्योंकि राजनैतिक, परिस्थितियों के कारण दक्षिणी अफ्रीका, अलबानिया आदि में पहले से ही बड़े हुए भारतीयों पर अनेक अत्याचार हो रहे हैं। दूसरे जनसंख्या की अधिकता तथा भूमि की कमी सभी राज्यों में है।

(६) अधिक उत्पादन—समस्या का सामाजिक समाधान देश में अधिक जन उत्पादन करना है, जिससे लोगों की आय बढ़े और जीवनस्तर उच्च हो सके। नियोजित रूप से देश के प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास उसके देश की कृषि तथा उद्योगों की स्थिति में वृद्धि करना आवश्यक है। यह एवं का नियम है कि वैश्वीय खाद्य मंत्री भी एस. के. पाण्डे ने अभी हाल ही यह घोषणा की है कि देश तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भर हो जायगा। इसके अतिरिक्त अब औद्योगीकरण को सम्पन्नता का सूचक मान लिया है और औद्योगिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है।

(७) परिवार नियोजन (Family Planning) — इस उपाय के अन्तर्गत लोगों को अपने परिवार सीमित करने के महत्त्व तथा साधनों का ज्ञान कराना आवश्यक है। जनसंख्या में वृद्धि को सामान्य रूप में केवल मरुति-निरोध के उचित तरीकों को अपना कर ही रोकना जा सकता है। परन्तु इस कार्यक्रम में कुछ कठिनाइयाँ हैं, जैसे जनता का अज्ञान व अग्रगण्यता, दानि रहित व सस्ते मरुति-निग्रह के साधनों का अभाव और लोगों की निर्धनता। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों को लोकप्रिय बनाने के लिए स्वयं सक्रिय हो।

योजना आयोग ने भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता व महत्त्व पर जोर दिया है। प्रथम योजना में इस कार्यक्रम के लिए ६५ लाख २० की व्यवस्था की गई थी, और रिचर्ड स्टोन के Dr Stone को इस ओर प्रकाश डालने के लिए आमन्त्रित किया था।

दूसरी योजना में इस कार्यक्रम के लिए ५ करोड़ २० निर्धारित भिजे गये थे। नगरों में ३००० और गाँवों में २००० परिवार नियोजन केन्द्र खोलने का विचार किया गया। इनके द्वारा लोगों को परिवार नियोजन की महत्ता तथा बर्तमान-वर्तमान के दमित साधनों का ज्ञान कराया जायगा। इसके अतिरिक्त चिकित्सा तथा बीमारियों के सम्बन्ध में अन्वेषण भी किया जायगा।

इस प्रकार ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि सरकार परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने में सक्रिय प्रयत्न कर रही है। परन्तु इतना सब होने पर भी व्यवहार में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसका जितना प्रचार हुआ है, उतना वास्तविक कार्य नहीं हुआ। जनता के सहयोग बिना जनसंख्या की समस्या हल नहीं हो सकती।

प्रश्न

- (१) जनसंख्या के घनत्व से क्या अभिप्राय है ? भारत में भिन्न भिन्न राज्यों में घनत्व भिन्न भिन्न क्यों है ?
- (२) क्या भारत में जनसंख्या अधिक है ? यदि है तो इस समस्या को हल करने के लिए सुझाव दीजिये ।
- (३) भारत की वर्तमान जनसंख्या का सही रूप क्या है ? आपकी दृष्टि में जनसंख्या सम्बन्धी नीति क्या होनी चाहिये ?
- (४) परिवार नियोजन से क्या तात्पर्य है ? इस ओर राज्य की ओर से क्या किया जा रहा है ?
- (५) भारत में जनसंख्या के पेशेवर वितरण का आर्थिक महत्व बताइये ।

यहां सभी भाई अपनी पत्नियों और बच्चों सहित अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति मुखिया या कर्त्ता होता है, सभी सदस्यों की आय एक साथ मिला ली जाती है और चौका-चूल्हा भी एक ही होता है तथा उनकी सम्पत्ति भी सम्मिलित होती है।

लाभ

(१) इसका सबसे उत्तम गुण यह है कि यह परिवार के सभी सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था तथा विधवा होने पर उनका जीवन-निर्वाह सुचारु रूप से चलता है।

(२) समुक्त परिवार का अपेक्षाकृत कम आय में काम चल जाता है और इस प्रकार खर्च में बचत हो जाती है। इसके विपरीत पृथक्-पृथक् रहने से एक घर के स्थान पर बहुत से घर चलाने पड़े और इस प्रकार व्यय अधिक करना पड़े।

(३) इस प्रणाली द्वारा कृषि-भूमिका उपविभाजन और लक्ष विभाजन नहीं हो पाता।

(४) इस व्यवस्था से परिवार के सदस्यों में त्याग और सहयोग की भावना का विकास होता है। प्रत्येक अपनी शक्ति के अनुसार कमाता है और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलता है। इस प्रकार वे आपस में सहयोग करते हैं और एक दूसरे के हितों को बढ़ाने से लिए त्याग करते हैं।

हानियां

(१) इससे आलस्य की भावना को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि बिना परिश्रम किये भी जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं परिवार के सम्मिलित साधनों से मिलती रहती हैं। इस प्रकार स्वावलम्बन के स्थान पर दूसरों पर आश्रित होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ने की साहसी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है।

(२) परिवार की आय तथा व्यय सम्मिलित रूप में होने के कारण अधिक कमाने के प्रयत्न नहीं किये जाते और पूर्ण सक्रिय नहीं हो पाती, जिससे विद्यालय उद्योगों की स्थापना सम्भव नहीं होती।

(३) इस प्रथा के अन्तर्गत भ्रम की गतिशीलता भी कम हो जाती है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक स्थान पर ही रहना चाहते हैं।

(४) इस प्रथा से बहुधा परिवार का वातावरण अस्थिर रहता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष और कलह रहती है।

पतन

वर्तमान परिस्थितियाँ इस प्रथा के अनुकूल नहीं हैं और अब इसका शनैः शनैः हास होता जा रहा है। इसके पतन के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(१) रेल आदि यातायात के साधनों के विकास के कारण लोग बाहर जाकर नये व्यवसाय आरम्भ करने की प्रेरणा पाते हैं।

(२) पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक शिक्षा ने व्यक्तिवाद की भावना को हमारे देश में पैलाया और संयुक्त परिवार प्रणाली को बर्बाद किया दी।

(३) जनसंख्या की अधिकता, बेकारी और आय की कमी के कारण भी लोग जीविका की खोज में परिवारों से पृथक् होने को विवश हुए।

इन आर्थिक शक्तियों के कारण यह प्रथा अब शीघ्रता से लुप्त होती आ रही है। परन्तु यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत परिवार प्रणाली को अपनाते हुए हम पारस्परिक सहानुभूति और सहयोग को न त्यागें।

उत्तराधिकार के नियम

इंग्लैंड आदि पश्चिमी देशों में पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा लड़का सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। परन्तु भारत में उत्तराधिकार नियम के अनुसार उत्तराधिकारियों की संख्या अधिक होती है। हिन्दू समाज में उत्तराधिकार की दो श्रेणियाँ हैं—(१) मिताक्षर और (२) दाय भाग।

(१) मिताक्षर :—बंगाल को छोड़कर सारे देश में लागू है। इसके अन्तर्गत पुरखों की सम्पत्ति पर परिवार के सब सदस्यों का अधिकार समान होता है। पिता सम्पत्ति का बटवारा कर सकता है। पिता सम्पत्ति को अपने पुत्रों की इच्छा बिना नहीं बेच सकता।

(२) दाय भाग :—यह नियम बंगाल में प्रचलित है, जिसके अन्तर्गत परिवार की सम्पत्ति पर परिवार के कर्तों का पूरा अधिकार होता है। वह उसकी देखभाल करता है और इच्छानुसार बेच सकता है। पिता की मृत्यु के पश्चात् ही सम्पत्ति का बटवारा उसके पुत्रों में होता है।

सन् १९५६ के हिन्दू उत्तराधिकार नियमों के अन्तर्गत अब सम्पत्ति का विभाजन केवल लड़कों में ही न होकर लड़कियों, मा, विधवाओं आदि में भी होसकेगा।

मुस्लिमों के अनुसार सम्पत्ति केवल लड़कों में ही नहीं, बल्कि लड़कियों में भी विभाजित की जाती है।

गुण

(१) परिवार के प्रत्येक सदस्य की जीवन के आरम्भ में ही कुछ न कुछ सम्पत्ति मिल जाती है जिससे उसकी जीविका चलाने का साधन प्राप्त हो जाता है।

(२) इसके द्वारा सम्पत्ति का अधिक व्यापक वितरण होता है और इस प्रकार सम्पत्ति की असमानता को कम करता है।

(३) प्रत्येक को सम्पत्ति में अथ कम मिलने से आगे परिश्रम और आर्थिक उन्नति करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

दोष

(१) इस नियम से देश की कृषि को बहुत हानि पहुँचती है। खेतों के छोटे छोटे भाग तय बिलर हुए होने का यही कारण है।

(२) सभ्यता का बहुत से उत्तराधिकारियों में वितरण होने से पूर्वी निर्माण में बाधा पड़ सकती है।

(३) प्रपदमेवाभी को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे धन तथा समय का अप्रत्यय होता है।

धर्म और उसका आर्थिक प्रभाव

बहुत से लोगोंने का मत है कि भारत की निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण हिन्दू लोगों में धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था है। पश्चिम में लोग मर्यादादी और सांसारिक सुखों की ओर अधिक रुत हैं, जबकि हमारे देश के लोग भाग्यवादी तथा पारलौकिक कल्याण के लिए त्याग की भावना से जीवन यापन करते हैं।

यह मत सर्वथा सत्य नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीनकाल में भारत ने आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक आदि सभी क्षेत्रों में बहुत उन्नति की थी। धर्म ने उन्नति के मार्ग में कोई बाधा नहीं उत्पन्न की। हमारा धर्म हमें निष्क्रिय नहीं, परन्तु स्वार्थ त्याग कर भौतिक परलोक के उपार्जन की शिक्षा देता है। अतः भारतीय धर्म देश की उन्नति में बाधक नहीं, सहायक है।

वास्तव में देश की निर्धनता के दूरे कारण हैं। सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि देश गत दो शताब्दियों में विदेशी राज्य की दागता में रहा, जिससे देश का खूब आर्थिक शोषण हुआ, और इस समय में ही पश्चिमी देशों ने औद्योगिक क्रान्ति तथा विविध वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप तीव्र गति से उन्नति कर ली और भारत बहुत पीछे रह गया। इसके अतिरिक्त हमारे देश की जनजाति विभग है, जिसमें कई प्रकार की महामारियाँ फैलती हैं जिससे मनुष्य की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही हमारे देश में सगव समय पर अकाल और बाढ़ आती हैं। इस प्रकार की कठिनाइयों के कारण ही लोग निराशावादी हो गए और भाग्य में विश्वास करने लगे। देश में कुछ राजनैतिक स्थिति तथा एकता के अभाव में पूर्वी का निर्माण न हो सका और बड़े उद्योग स्थापित न हो सके। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश आर्थिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है और लोगों की मनोदशा में भी प्रबल परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे आशा है कि भारत फिर से एक उन्नत राष्ट्र हो सकेगा।

प्रश्न

1. भारत के सामाजिक ढांचे की मुख्य विशेषताएँ बताइये। उनका हमारे आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?
2. जाति-प्रथा के आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालिए। इस व्यवस्था के पतन के मुख्य कारण क्या हैं ?
3. उद्युक्त परिवार प्रणाली का उद्योगों की स्थापना और वृद्धि के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है ?

यह सर्वविदित है कि भारत एक कृषिप्रधान देश है और इस उद्योग में जनसंख्या का ७० प्रतिशत भाग लगा हुआ है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग ४७ प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। खाद्य सामग्री को उपभोग करने के अतिरिक्त कृषि से हमारे बहुत से उद्योगों को अच्छा माल मिलता है; जैसे रई, जूट, गन्ना, तिलहन, तम्बाकू आदि। इसी से हम विभिन्न वस्तुएँ निर्यात कर विदेशी विनिमय प्राप्त करते हैं। कृषि उद्योग द्वारा रेलों को भारी आय होती है। इस प्रकार देश का बजट कृषि की स्थिति पर ही निर्भर रहता है।

परन्तु कृषि का इतना महत्व होते हुए भी इसकी वर्तमान स्थिति बड़ी असन्तोषजनक है। हमारे देश में प्रति एकड़ उत्पादन दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम है। अतः देश की निर्धनता को हटाने के लिए प्रति एकड़ उपज को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

खेती की पिछड़ी हुई दशा के निम्नलिखित कारण और उपाय हैं:—

(१) भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार.—भारत की जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि के कारण तथा खेती पर अधिक लोगों के निर्भर रहने से भूमि उनका अच्छी तरह से भरण-पोषण नहीं कर सकती।

इस बढ़ते हुए भूमि पर दबाव को कम करने के लिए उद्योग-धर्मों और कुटीर-धर्मों को विकसित करना आवश्यक होगा। द्वितीय योजना के अन्तर्गत देश के औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी गई है।

(२) वर्षा की कमी और अनिश्चितता:—कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा के कम आने या ठीक समय पर न आने से कृषि की प्रति एकड़ उपज कम हो जाती है। इसलिए ही भारत के बजट को 'मानसून का जुआ' (Gamble in Monsoons) कहते हैं। राजस्थान तथा पंजाब के कुछ भाग में वर्षा बहुत कम होती है, अन्य भागों में वर्षा अनिश्चित होती है, जिससे कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

वर्षा की कमी को दूर करने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास आवश्यक है। प्रथम योजना में ६६१ करोड़ रु० सिंचाई और शक्ति योजनाओं में व्यय का निर्धारण था। द्वितीय योजना में केवल सिंचाई पर ३८१ करोड़ रु० के व्यय का अनुमान किया गया था।

विभिन्न बहुउद्देश्यीय नदी-राटी योजनाएँ इस ओर काफी प्रगति पर हैं। तीसरी योजना में सिंचाई के लिए ६॥ अरब रु० की प्रारम्भिक राशि निर्धारित की गई है। (नवम्बर १९६०, २० मार्च १९६०)

कृषि की प्राचीन प्रणालियाँ — खेती के वे ही पुराने ढंग हैं—पुराने औजार, अपर्याप्त खाद, घटिया बीज, उपज की बिक्री की दोषपूर्ण प्रणाली, दुर्बल पशु और कीटों द्वारा खेती का विनाश आदि।

इन दोषों को मिटाने के लिए सस्ते, उपयुक्त और आधुनिक कृषि यन्त्रों को किसानों को उपलब्ध कराना सरकार तथा सहकारी समितियों का कर्तव्य है। सरकारी फार्मों पर प्रदर्शन द्वारा कृषि के आधुनिक तरीकों का ज्ञान कृषक को कराना आवश्यक है। कृषि अनुसन्धान संस्था द्वारा उत्तम प्रकार के बीज का अन्वेषण करना तथा ऐसे बीजों को सरकारी गोदामों द्वारा किसानों को दिलाना चाहिये। गोबर, हरी खाद तथा रासायनिक खाद के उपयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये। सिंद्री खाद कारखाने के अतिरिक्त तीन और ऐसे कारखाने (नागपुर, रुरकेला और दक्षिण अर्काट) खुलने की सम्भावना है। पशुओं की दशा सुधारने के लिए उनकी उचित चिकित्सा व चारे की व्यवस्था करना आवश्यक है। हानिकारक कीटों से खेती की रक्षा करनी चाहिये। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए यातायात के साधनों में सुधार तथा सहकारी बिक्री आदि उपाय लाभदायक हैं।

— (४) खेतों का उपविभाजन और अपखण्डन — भारत में कृषि की पिछड़ी दशा का एक प्रमुख कारण खेतों का छोटा होना तथा बिखरे हुए होना है। इससे आधुनिक मशीनों का उपयोग सम्भव नहीं हो पाता।

इस दोष को दूर करने के लिए खेतों की चक्कन्दो, अधिक बोट का निर्माण, सहकारी खेती आदि मुख्य उपाय हैं।

(५) दोषपूर्ण भूमि-अधिकार प्रणाली:— जमींदारी प्रथा के अन्तर्गत किसान का शोषण होता है और भूमिहीन किसानों की समस्या आती है। इस प्रकार खेतों में स्थायी सुधार नहीं हो पाता।

इस का निपट है कि जमींदारी प्रथा अब लगभग सभी राज्यों में समाप्त हो गई है और किसान तथा राज्य के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाने से लगान सम्बन्धी दोष निवृत्त जा रहे हैं।

— (६) किसानों की अशिक्षा, अन्धविश्वास और अज्ञानता — अशिक्षित व अज्ञानी होने से किसान आधुनिक तरीके से कृषि नहीं कर पाते। सामाजिक कुरीतियों तथा पैतृक श्रृंखला के कारण किसान 'श्रृंखला में बन्ध लेता है, श्रृंखला में रहता है और श्रृंखला में ही मृत्यु की ग्रास होता है।' किसान सदैव महाजन के चपुल में ही फँसा रहता है।

किसानों में विशेषकर कृषि शिक्षा का प्रसार, नये यन्त्रों का ज्ञान और सहकारी साख समितियों का खुलना आवश्यक है।

(७) मुकदमेबाजी —अनपढ़ व सकुचित विचारों के होने से किसान छोटी छोटी बातों के लिए आपस में झगड़ बैठते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी में अपना अमूल्य समय और धन का अपव्यय करते हैं।

शिक्षा व सहकारिता की भावना के प्रचार तथा ग्रामपंचायतों की स्थापना द्वारा झगड़े आसानी से निपटाये जा सकते हैं।

भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा जलवायु पाये जाने के कारण सभी महत्वपूर्ण फसलें यहाँ उगाई जाती हैं।

पंचवर्षीय योजना के विवरण के अनुसार भारत का भौगोलिक क्षेत्र ८० ६३ करोड़ एकड़ माना जाता है, जिसमें से आठवें केवल ७१ ६७ करोड़ एकड़ के ही उपलब्ध हैं। इसमें से कृषि योग्य भूमि ३६ ६६ करोड़ एकड़ है तथा ३२ ०७ करोड़ एकड़ भूमि पर कृषि की जाती है और ४८७ करोड़ एकड़ भूमि वज्र है। बोये हुए क्षेत्र में से ८०% में खाद्य फसलें और शेष २० प्रतिशत में दूसरी फसलें उगाई जाती हैं।

(From "India, 1959")

भारत की मुख्य फसलें

(१) गेहूँ —उत्तरी भारत के लोगों का यह मुख्य खाद्य है। भारत में गेहूँ का प्रति एकड़ उत्पादन (४८४ पौंड) बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका में ६०६ और १०७६ पौंड है। १९४७-४८ में गेहूँ उगाने का क्षेत्र ३०० लाख एकड़ था और कुल उत्पादन ७९ ५ लाख टन था। गेहूँ उत्पन्न करने वाले मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य-प्रदेश, बिहार आदि हैं। विमाजन के फलस्वरूप गेहूँ के उत्पादन में कमी हो गई, जिससे प्रतिवर्ष गेहूँ का आयात करना पड़ता है। सन् १९४८ में २६७ लाख टन गेहूँ का आयात किया गया था।

(२) चावल — यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यह अधिकांश जनता का प्रमुख भोजन है। यह अधिक पानी वाली नीची भूमि पर पैदा होता है। भारत में प्रति एकड़ उपज १०४८ पौंड है, जबकि जापान में ३३२१ पौंड है। १९४७-४८ में चावल का क्षेत्र ७६० लाख एकड़ तथा कुल उत्पादन २४८ लाख टन था। देश में उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार जापानी पद्धति को प्रोत्साहन दे रही है। मुख्य उत्पादन क्षेत्र मद्रास, बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, बम्बई, आसाम आदि हैं।

(३) मोटे अनाज — ज्वार, बाजरा — ये निर्धन लोगों का मुख्य खाद्य है। इसका उत्पादन देश के विभिन्न भागों में होता है—मुख्यकर बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। सन् १९४७-४८ में ज्वार का क्षेत्र ४१४ लाख एकड़ और

उत्पादन ८० लाख टन था, जबकि बाजरे का क्रमशः २७४ ५ लाख एक्ड़ तथा ३५ ६ लाख टन था।

(४) मक्का — यह भी निर्वन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण खाद्य है। मुख्य उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और बिहार में होता है। औसत प्रति एकड़ उपज ८७ मन है।

(५) दालें —चना, चड़दा, मूंग, अरहर आदि—ये मोहन के आवश्यक अंग हैं। मुख्य उत्पादक उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, पंजाब, बम्बई, बंगाल हैं। कृषि-क्षेत्र के लगभग $\frac{2}{3}$ भाग में दालें उगाई जाती हैं। दालों में चना का उत्पादन प्रमुख है।

प्रथम योजनाकाल में खाद्यान्न उत्पादन में ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सन् १९५०-५१ में कुल उत्पादन ५०० लाख टन था, जो १९५५-५६ में बढ़कर ६५८ लाख टन हो गया।

द्वितीय योजनाकाल में कुल उत्पादन का लक्ष्य ७५० लाख टन रखा था जो बाद में बढ़ाकर ८०५ लाख टन निर्धारित कर दिया। इस प्रकार वृद्धि अनुमानतः १५ प्रतिशत होगी।

तृतीय योजना में कृषि तथा सामुदायिक विकास के लिए दस अरब ६० की 'प्रारम्भिक राशि' निर्धारित की गई है। यह आश्वासन केन्द्रीय खाद्य मन्त्री ने दिया है कि तीसरी योजना के अन्त तक देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायगा।

(६) गन्ना —भारत के गन्ने का क्षेत्र सवार में सबसे अधिक है। यह नकद पसलों में सबसे प्रमुख है। १९५७-५८ में गन्ना ५० लाख एक्ड़ भूमि में बोया गया और कुल उत्पादन ६४१ लाख टन था। महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार हैं जिनमें से केवल उत्तर प्रदेश में कुल गन्ने का क्षेत्र का ६०% भाग है। प्रथम योजना में गन्ने के उत्पादन में विशेष वृद्धि नहीं हुई। द्वितीय योजना में १९६०-६१ तक उत्पादन ७१ लाख टन तक करने का लक्ष्य था, जिसको बाद में ७८ लाख टन कर दिया गया। गन्ने की प्रति एकड़ उपज तथा किस्म में सुधार के लिये भी सरकार प्रयत्नशील है।

(७) कपास —विश्व में कपास उत्पन्न करने वाली देशों में भारत का स्थान अमेरिका और रूस के बाद है परन्तु यहाँ अधिकतर छोटे रेशोवाली कपास पैदा होती है। इस लिये बड़े रेशो की कपास का आयात किया जाता है। विमात्रन से इस प्रकार की आवश्यकता और भी बढ़ गई थी। सरकार अच्छे किस्म की कपास उत्पन्न करने की ओर प्रयत्न कर रही है।

भारत में कपास के मुख्य क्षेत्र बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास और हैदराबाद। प्रथम योजना में उत्पादन का लक्ष्य ४० लाख गांठों का था जबकि १९५५-५६ में उत्पादन ४० लाख गांठों का हुआ। द्वितीय योजना का लक्ष्य पहले ५५ लाख गांठें रखा गया था जो बाद में ६५ लाख गांठों तक बढ़ा दिया गया।

(८) जूट —विमात्रन से पूर्व जूट उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त था,

परन्तु अब भारत को कच्चे जूट के लिये पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता है। पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं। प्रथम योजना में उत्पादन का लक्ष्य ५४ लाख गांठ था। दूसरी योजना में उत्पादन का लक्ष्य ५० लाख गांठ था, जिसे बाद में ५५ लाख गांठ तक बढ़ा दिया गया। सन् १९५८-५९ में उत्पादन ५१८ लाख गांठ का हुआ और जूट उत्पादन क्षेत्र १८३ लाख एकड़ था।

(६) तिलहन — (मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी, रेंदी) इनका उपयोग तेल निकालने, वनस्पति घी, साबुन, मोमबत्ती, पालिश आदि बनाने में किया जाता है। इनकी खेती पशुओं के चारे के काम आती है तथा यह एक उत्तम खाद्य भी है। ये देश के लिये महत्वपूर्ण निर्यात की वस्तुएँ भी हैं।

तिलहनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूंगफली है। यह मुख्यकर बम्बई, आन्ध्र, मद्रास, मैसूर और उत्तर-प्रदेश में उत्पन्न होती है। सन् १९५४-५६ में तिलहनों का कुल उत्पादन ५६ लाख टन था। दूसरी योजना में उत्पादन का लक्ष्य ७० लाख टन था जिसको बाद में बढ़ाकर ७६ लाख टन कर दिया गया।

(१०) चाय — भारत चीन के बाद विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके उत्पादन का अधिक भाग इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों को भेजा जाता है। चाय के बगीचे मुख्य रूप से असम, दार्जिलिंग, देहरादून व नीलगिरी में हैं। दूसरी योजना में उत्पादन का लक्ष्य ७०० लाख पौंड है।

(११) कहवा — यह मैसूर, मद्रास, ट्रावनकोर, कोचीन में उगाया जाता है। पहले भारत से कहवा अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता था परन्तु अब यह स्थान ब्राजिल ने ले लिया है।

(१२) रबर — यह मुख्यतः दक्षिणी भारत में उत्पन्न होता है — केरल, मद्रास तथा मैसूर।

(१३) तम्बाकू — इसकी खेती मद्रास, मध्यप्रदेश, पंजाब तथा बंगाल में होती है। विश्व में भारत का स्थान अमेरिका तथा चीन के बाद आता है। परन्तु हमारे यहाँ की तम्बाकू घटिया किस्म की होती है, अतः इसकी सुधारना आवश्यक है।

(१४) जपान — पोस्त की खेती सरकार के आधीन है। यह उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान तथा मध्यप्रदेश में उत्पन्न की जाती है।

प्रश्न

- (१) भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइये। भारत में कृषि की पिछड़ी हुई दशा के क्या कारण हैं ? उसके सुधार के सुझाव भी दीजिये।
- (२) भारत की मुख्य फसलें क्या हैं ? उनका भौगोलिक विवरण दीजिये।
- (३) “किसान के लिये खेती करना व्यापार की अपेक्षा जीवन का एक टम है।” इस कथन की आलोचना कीजिये।

कृषि की एक विशेष महत्वपूर्ण बात जोत का आकार है। भारत में जोतों का आकार अत्यन्त छोटा है। योजना आयोग के अनुसार हमारे देश में ३४% जोतें एक एकड़ से भी छोटी हैं, ६४% जोतें ५ एकड़ से भी छोटी और केवल १ प्रतिशत जोतें ५० एकड़ से बड़ी हैं। विभिन्न राज्यों में जोतों का आकार भिन्न भिन्न है। जैसे ५० बंगाल में ४.४ एकड़, उत्तर प्रदेश में २.५ एकड़, मद्रास में ४.५ एकड़, बम्बई में १३.३ और पंजाब में १० एकड़। सारे देश की औसत ७.५ एकड़ है। दूसरे देशों की अपेक्षा यह औसत बहुत कम है; जैसे इंग्लैंड २० एकड़, अमेरिका १४५ एकड़ और फ्रांस २० एकड़।

भारत में कृषि उत्पादन के कम होने का एक मुख्य कारण जोतों का छोटे और बिखरे हुए होना है। खेतों के उपविभाजन से उत्पन्न यह है कि मूल्हामी के मरने पर उसके उत्तराधिकारियों में भूमि का छोटे छोटे अंशों में बंटना। इस प्रकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी जोत छोटी-छोटी जाती है।

कृषि जोतों के अपव्यवहार से अभिप्राय है कि किसानों के सब खेत एक स्थान पर न होकर कई स्थानों पर पाये जाते हैं। इस प्रकार खेत छोटे ही नहीं, किन्तु वे अनेक ठुकों में बँटकर गांवों के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। बहुत से विरोधों जैसे डा. मन (Mann) कलवर्ट, रामलाल भस्ला, डा. राधाकमल मुहूर्ती, डा. बिलवर्ट स्लेटर आदि की खोज से पुष्टि होती है कि देश के विभिन्न राज्यों में जोतों का आकार बहुत छोटा है तथा खेत बिखरे हुए हैं।

कारण

(१) भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव:—जनसंख्या का ७० प्रतिशत भाग कृषि पर अवलम्बित है जबकि नई भूमि को कृषि योग्य बनाने में विशेष रुचि नहीं हुई है। इसके साथ ही एक ओर तो जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही, दूसरी ओर लाभप्रद व्यवसायों का उपयुक्त विकास नहीं हो पाया है। अतः अधिकांश में लोगों को कृषि पर ही अवलम्बित होना पड़ता है जिससे खेत का आकार छोटा होता जाता है।

(२) उत्तराधिकार के नियम:—वैतक सम्पत्ति के विभाजन के फलस्वरूप रिता

की मृत्यु पर उसके खेतों का बँटवारा उसके उत्तराधिकारियों में होता है इससे पीढ़ी दर पीढ़ी खेत छोटे और छिदरे होते जाते हैं।

(३) कुटीर घन्घों का पतन—इंग्लैंड के औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् हमारे देश के कुटीर घन्घों का विनाश होने लगा और इन उद्योगों में लगे लोगों को कृषि पर ही निर्भर होना पड़ा जिससे खेतों का बँटवारा होता गया।

(४) समुक्त परिवार प्रणाली का अन्त—पश्चिमी सभ्यता व शिक्षा के प्रसार के साथ ही लोगों में व्यक्तिवाद की भावना उदय हुई और इस प्रकार सम्पत्ति के विभाजन की भावना पैदा हुई।

(५) कृषि श्रमणस्तता.—बहुत से कृषकों को महारजों के प्रति अपना श्रृणु चुकाने के लिये अपनी भूमि का कुछ अंश बेचना पड़ता है, जिससे जोतों का उपविभाजन बढ़ा।

लाम

(१) उपविभाजन से सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी भूमि जोतने के लिये मिल जाती है, जो आर्थिक समानता के अनुरूप है। इस प्रकार देश में आर्थिक व सामाजिक स्थिरता स्थापित होती है।

(२) भूमि के अपव्ययन से किसान के पास कई प्रकार की भूमि होती है, जिससे कम उपजाऊ भूमि की क्षतिपूर्ति अधिक उपजाऊ भूमि से हो जाती है।

(३) उपविभाजन से छोटे खेतों में गहरी खेती हो सकती है, जिससे प्रति एकड़ उपज बढ़ सकती है।

हानियाँ

(१) समय, भूमि तथा श्रम का अपव्यय—खेतों के छोटे तथा दूर दूर तक बिखरे हुए होने के कारण एक खेत से दूसरे खेत में जाने से समय नष्ट होता है। इसके साथ ही किसान वर्ष में कानी समय तक बेकार रहते हैं। इसके अतिरिक्त मेड़ों और रास्तों को बनाने के कारण बहुत सी भूमि का अपव्यय हो जाता है। श्रम बचाने वाली मशीनों, ट्रैक्टर आदि का उपयोग भी इन छोटे खेतों पर नहीं हो सकता।

(२) स्थानीय सुधार असम्भव.—छोटे किसानों की विषम आर्थिक स्थिति के कारण खेतों में स्थायी सुधार, जैसे सिंचाई आदि का प्रबन्ध नहीं हो सकता।

(३) मुकदमेबाजी—अपव्ययन होने से किसानों में आपस में द्वेष फैलता है, जिसके फलस्वरूप मुकदमेबाजी बढ़ती है, जिसमें किसानों का समय व धन बर्बाद होता है।

डा० मन के शब्दों में 'यह साइस को नष्ट करता है, अधिक श्रम बेकार जाता है, सीमाएँ और मेड़ बनाने से भूमि की बहुत अधिक हानि होती है और बीतों पर विस्तृत खेती असम्भव हो जाती है।'

उपाय

लामों की अपेक्षा इसके दीप अधिक हैं। इस कारण कृषि व्यवसाय को समुन्नत करने के लिये यह आवश्यक है कि जोतें उचित आर्थिक आकार की हों।

आर्थिक जोत के बारे में विभिन्न लेखकों ने विभिन्न अर्थ लगाये हैं, जिनमें प्रमुख हैं कीटिल, डा० मन, स्टैनले जेम्स आदि। इन सबका सारांश यह निकलता है कि आर्थिक जोत वह खेत है जो किसान तथा उसके परिवार का उचित रूप से भरण-पोषण कर सके।

इस प्रकार के खेत कई प्रकार से बनाये जा सकते हैं।

(१) भूमि का समाजोत्तरण — भूमि पर से निजी-स्वामित्व के अधिकार को समाप्त कर सरकार देश की सभी भूमि का राष्ट्रीयकरण करके बड़े बड़े खेतों पर स्वयं आधुनिक ढंग से खेती करे, जैसे कि रूस में होता है। परन्तु यह विधि भारत के लिये उपयुक्त नहीं है। अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर निजी अधिकार रखते हुए केवल भूमि पर ही यह सिद्धान्त लागू करना अन्यायपूर्ण होगा और दूसरे सरकार के पास इस कार्य के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं हैं।

(२) जोतों की उच्चतम व निम्नतम सीमा निर्धारित करना.—विभिन्न स्थानों की जांच करके आर्थिक जोतों का आकार निश्चित किया जाय। बड़े भूस्वामियों के पास उच्चतम सीमा से अधिक भूमि अनाधिक जोतों के स्वामियों को दिलाई जाय। यह अधिक न्यायपूर्ण होगा और समृद्धि का समान वितरण होगा, जो देश में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिये आवश्यक है। योजना आयोग ने रायों द्वारा कृषि उच्चतम सीमा निर्धारित करने की विचारित की है। परन्तु इस उपाय से अधिक भूमि उपलब्ध नहीं होगी जिससे अधिकांश अनाधिक जोतों को आर्थिक बनाया जा सके। विभिन्न रायों द्वारा उच्चतम सीमा निश्चित करने की और विचार बनाये गये हैं।

इसके साथ ही यह आवश्यक है कि एक निम्नतम सीमा के परचातु जोतों का भविष्य में किसी प्रकार से उपविभाजन व उपलब्धन न हो। इस बारे में भी कुछ रायों में विधान बनाये गये हैं, जिनके अन्तर्गत भूमि का ऐसा विभाजन पट्टा या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता जो जोत को रैसिडेंट क्षेत्र या आहार से कम कर दे।

(३) उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन — इस नियम में परिवर्तन उत्तराधिकार केवल सबसे बड़े पुत्र को दिया जाय, परन्तु यह न्यायसंगत न होगा, क्योंकि इससे छोटे पुत्रों की जीविका प्रश्न बना रहेगा।

(४) नई भूमि को कृषि योग्य बनाना — इसके द्वारा भी समस्या का समुचित हल नहीं हो सकता है क्योंकि एक ओर तो भूमि का क्षेत्र निश्चित है और दूसरी ओर जनसंख्या भी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अब यह आवश्यक है कि जनसंख्या पर नियन्त्रण किया जाय और उद्योग-वनों के विकास द्वारा अतिरिक्त जनसंख्या को खपाया जाय, जिससे भूमि पर दबाव कम हो।

(५) चक्रबन्दी — इसके मुख्यतः तीन तरीके हैं —

(i) छोटे और बिल्वे हुए खेतों को स्वेच्छा से बड़े बड़े खेतों में संगठित किया जाय और सहकारी सिद्धान्त पर खेती की जाय।

(ii) यह अनुभव हुआ कि स्वैच्छिक चक्रबन्दी की गति बहुत मन्द होगी, अतः सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन देना आवश्यक समझा गया। परन्तु यहाँ भी सहकारी समिति की स्थापना सभी सदस्यों की स्वीकृति से ही हो सकती थी। पञ्जाब की इस प्रयोग में सफलता मिली। उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में भी इस ओर प्रगति हुई।

(iii) अनिवार्य चक्रबन्दी — स्वेच्छा से सहकारी समितियों के निर्माण में अधिक सफलता न मिलने के कारण विभिन्न राज्यों ने इसे अनिवार्य बनाने का कदम उठाया। इस प्रकार यदि गांव का बहुमत अथवा किसानों का एक निश्चित प्रतिशत चक्रबन्दी की स्वीकार करता है तो अल्पसङ्ख्यकों पर भी यह योजना अनिवार्य रूप से लागू की जा सकती है। इस तरह के कानून मध्य प्रदेश, पञ्जाब और उत्तर प्रदेश आदि में बनाये गये, परन्तु परिणाम सन्तोषजनक नहीं रहा।

इस ओर अधिक प्रगति न होने से यहाँ कहा गया कि चक्रबन्दी का कार्य स्वयं सरकार करे और वह उसे सभी किसानों पर लागू करे चाहे किसान अपनी स्वीकृति न दें। इस प्रकार के अनिवार्यता के कानून बम्बई पञ्जाब और उत्तर प्रदेश में बनाये गये। इन कानूनों ने समस्या को केवल छू भर दिया है, वास्तविक रूप में विशेष सफलता नहीं मिली है। यह आशा की जा सकती है कि जमींदारी प्रथा के समाप्त होने से और भूमि व्यवस्था के अधिक सरल बनाये जाने और भूमि-पुष्कार के विभिन्न उपायों के कार्यान्वित होने से चक्रबन्दी की समस्या अधिक सुगम हो जायगी।

(६) सहकारी कृषि — इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसान सहकारी कृषि समितियाँ संगठित करते हैं, वे अपनी जमीन को एक साथ मिलाकर संयुक्त रूप से खेती करते हैं और पूर्व निर्धारित आधार पर उत्पादन का आपस में बटवारा कर लेते हैं। इसके द्वार बड़े स्तर पर खेती की जा सकती है और साथ ही किसान का भूमि से सम्बन्ध-विच्छेद भी नहीं होता। यह चार प्रकार की होती है —

(i) सहकारी संयुक्त कृषि (Cooperative Joint Farming) — छोटे छोटे खेतों के स्वामी अपने खेतों को एक साथ मिला खेते हैं परन्तु अपनी अपनी भूमि का स्वामित्व बना रहता है। प्रत्येक सहकारी समिति द्वारा होता है और अम की मजदूरी तथा भूमि के स्वामित्व का लाभार्थ सदस्यों को मिलता है।

(ii) सहकारी कालतकार कृषि (Cooperative Tenant Farming) — सहकारी समिति स्वयं भूमि की स्वामी होती है परन्तु वह स्वयं खेती न करके भूमि के हिस्सों को किसानों को लगान के आधार पर देकर खेती करवाती है। सदस्यों को अन्धा बीज,

खाद, औजार प्रदान किये जाते हैं, परन्तु खेती समिति की बनाई योजना के अनुसार होती है।

(iii) सहकारी कृषि सुधार समिति:—विभिन्न भूस्वामी अपनी भूमि पर अधिकार रखते हुए केवल उन्नत खेती के लिये सहकारी समिति बनाते हैं। यह समिति उनको अच्छा बीज, खाद औजार देती है और उत्पादन के विक्रय की व्यवस्था करती है।

(iv) सहकारी सामूहिक कृषि (Cooperative Collective Farming) सहकारी समिति स्वयं ही भूमि की स्वामी होती है और स्वयं ही खेती का कार्य संचालन करती है तथा सदस्यों को उनके परिश्रम के लिये मजदूरी देती है। सदस्य भूमि के स्वयं स्वामी नहीं होते।

भारत के विभिन्न राज्यों; जैसे बम्बई, असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मैसूर, उत्तर प्रदेश में सहकारी कृषि प्रयोग के रूप में चल रही है। भारत में सहकारी कृषि एक विवादप्रसूत प्रश्न बन गया है। परन्तु इसके अनेक लाभ हैं, जैसे बीतों के आकार में वृद्धि होना, बड़े पैमाने के लाभ व श्रुत, पसल के खराब होने की जोखिम का अधिक लोगों में बटना, सहकारिता की भावना का उदय होना और किसान तथा सरकार के निकट सम्पर्क आदि। इन लाभों के विपरीत भारत में इसकी उपलब्धता अनिश्चित है क्योंकि किसानों में स्वयं सेवा, पारस्परिक विश्वास और नेतृत्व का जो इन समितियों के लिए आवश्यक है, प्रायः अभाव पाया जाता है। अतः यह अनुभव किया जा रहा है कि किसानों को अपनी भूमि एक में मिलाने और सहकारी प्रणाली से खेती की व्यवस्था करने में कुछ दबाव डालना आवश्यक है।

कांग्रेस कृषि सुधार समिति १९५६-५७ ने सहकारी कृषि की सिफारिश की है। अब हाल में प्रधानमंत्री ने कृषि को उन्नत करने का एकमात्र उपाय सहकारी खेती बताया है। प्रथम योजना में ५० लाख रु० विभिन्न राज्यों में सहकारी कृषि के प्रयोग के लिए निर्धारित किये थे, परन्तु इस दिशा में कुछ नहीं हो पाया। द्वितीय योजना में मुख्य लक्ष्य यह रखा गया कि ऐसे आवश्यक पद उठाये जायें जो देश में सहकारी खेती के विकास के लिए ठोस आधार प्रदान करें, जिससे अगले १० वर्षों में अधिकतर खेती सहकारी ढंग से होने लगे।

प्रश्न

- (१) भारत में बीतों के छोटे और छिटे होने की समस्या के हल करने के उपाय बताइये।
- (२) भारत में सहकारी कृषि के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिये। क्या आप भारत में सहकारी कृषि का समर्थन करते हैं?
- (३) आर्थिक बीत का क्या अर्थ है? भूमि की उच्चतम सीमा निश्चित करने के बारे में आपके क्या विचार हैं?



अध्याय ७

भूमि-अधिकार प्रणालियाँ

भूमि प्रकृति की देन है। अतः सभी देशों में सरकार स्वयं को भूमि का स्वामी मानती है, परन्तु वह खुद खेती न करके निजी व्यक्तियों को खेती करने का अधिकार भूमिकर (मालगुजारी) लेकर प्रदान करती है। इस प्रकार हमें यह देखना है कि किसान के भूमि में क्या अधिकार हैं और इनके साथ ही उनका राज्य अथवा अन्य मध्यजनों से क्या सम्बन्ध है। यदि स्वयं भूमि जोतने वाला ही भूमि का स्वामी है और उसके तथा सरकार के बीच कोई अन्य मध्यस्थ नहीं है तो देश में खेती की दशा उन्नत होगी। आर्थर यंग के शब्दों में “निजी सम्पत्ति का जादू रेत की भी सोना बना देता है।”

भारत में भूमि-सुधार अधिनियम लागू होने से पूर्व भू-अधिकार की तीन प्रणालियाँ रही हैं:—

(१) रैयतवारी, (२) महलवारी और (३) जमींदारी।

(१) रैयतवारी.—इस प्रथा के अन्तर्गत किसान और सरकार के बीच कोई जमींदार अथवा मध्यस्थ नहीं होता और उसका सरकार से सीधा सम्बन्ध होता है। अतः वह स्वयं ही सरकार को मालगुजारी देने का उत्तरदायी होता है। किसान को अपनी भूमि जोतने, बेचने या छोड़ने का पूरा अधिकार होता है। मालगुजारी परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर निश्चित की जाती है।

गुण

(१) किसान और सरकार के बीच सीधा सम्बन्ध होने के कारण किसानों का जमींदारी प्रथा के अनुसार शोषण नहीं होता।

(२) इस प्रथा के अन्तर्गत मालगुजारी सदा के लिए निश्चित नहीं हो जाती, समय समय निर्धारित होती है जिससे भूमि पर होने वाली उन्नति का लाभ सरकार को पहुँच जाता है।

(३) जिन मार्गों में यह प्रथा पाई जाती है, वहाँ चकवन्दी, सड़कारी खेती आदि को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

कृषि-सुधार में जमींदारी उन्मूलन एक महत्वपूर्ण कार्य था। जमींदारों की समाप्ति से देश में एक स्वस्थ वातावरण स्थापित हो गया। किसानों की भूमि पर अपना अधिकार मिल गया तथा सरकार के साथ सीधा सम्पर्क हो गया। ग्राम पर स्थायी सुधार सम्भव होने लगे। लगान निश्चित हो गया और अधिक लगान, बेगारी और नबरातों के दोष समाप्त हो गये। किसानों की आय में वृद्धि हुई और उनका जीवनस्तर ऊँचा हो गया। इसके साथ ही सरकार की आय भी बढ़ी। ग्रामीण समाज में समानता, सहकारिता और न्याय का वातावरण उपस्थित होने की आशा है।

परन्तु इसके साथ ही हमें यह याद रखना पड़ेगा कि केवल जमींदारी-उन्मूलन ही कृषि-उत्पादन का एकमात्र उपाय नहीं है। प्रधान मन्त्री के शब्दों में "इसके द्वारा विकास की राह में बाधा को हटाया गया है।" अतः आवश्यकता ऐसे सक्रिय पद उठाने की है, जिससे वास्तव में कृषि-उत्पादन बढ़े, जैसे-सिंचाई की व्यवस्था, अच्छे बीज, वैज्ञानिक खाद, आधुनिक यन्त्र तथा साख और ऋण की सुविधाएँ। इसके साथ ही लघु और कुटीर उद्योगों का विकास तथा उनका विद्यालयांतर उद्योगों से समन्वय आवश्यक है।

यह प्रसन्नता की बात है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सरकार उपयुक्त कार्यों की ओर प्रयत्नशील है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भूमि-सुधार के प्रस्ताव निम्नलिखित भागों में बाँटे गए हैं :—

(१) मध्यस्थ, (२) बड़े भूमिपति, (३) छोटे भूमिपति, (४) दम्बित फारतफार और (५) भूमिहीन कृषि-भूमि।

सर्वप्रथम यह कहा गया कि सभी जमींदार तथा अन्य मध्यस्थ के अधिकार समाप्त होने चाहिये। इसके बाद लगान वसूली का प्रबन्ध अच्छा होना चाहिये। उच्चतम सीमा को लागू करने से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृषि-भूमिकों को बाँटना तथा उनकी दशा सुधारना। लोगों की चकबन्दी द्वारा सहकारिता के सिद्धान्त का पुनर्गठन करना आदि महत्वपूर्ण कार्य करना आवश्यक है।

द्वितीय योजना में भी भूमि-सुधार के कार्यों पर अधिक महत्व दिया गया है। राज्य सरकारों को भूमि-प्रबन्ध सम्बन्धी विधान पास करना चाहिये। उच्चतम मामों को प्रोत्साहन देना चाहिये। भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करने पर बल दिया गया है। ग्रामों में विभिन्न भूमि-सम्बन्धी अधिकारों के नियमों का अमल ग्राम पञ्चायतों द्वारा उचित क्षेत्रों में होना चाहिये। अन्त में यदि सहकारी आधार पर पूरे ग्राम का प्रबन्ध हो सके और कृषि से सम्बन्धित अन्य उद्योग-धन्धों का विकास हो सके तो समस्या का हल हो सकता है।

प्रश्न

- (१) भारत में प्रचलित भूमि-अधिकार प्रणालियों का वर्णन कीजिए । उनके दोष प्रकट करते हुए सुधार विषयक प्रस्ताव दीजिये ।
 - (२) भारत में भूमि-समस्या का क्या स्वरूप है ? पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भूमि-नीति की व्याख्या कीजिये ।
 - (३) भारत में उच्चतम भूमि-सीमा निश्चित करने पर अपने विचार प्रकट कीजिये ।
 - (४) गत कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में भूमि के सम्बन्ध में जो कानून बने हैं उनकी क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं और उनका कृषि-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ?
-

कृषि सुधार और विकास के राजकीय कार्यक्रम

खाद्य-समस्या (Food Problem)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् खाद्य-समस्या हमारे आर्थिक पुनर्स्थापनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा गंभीर रही है। अभी भी इसका समाधान के लिये हल नहीं हो पाया है, परन्तु स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। वास्तव में यह एक आश्चर्य की बात है कि कृषिप्रधान देश होते हुए भी भारत को अपने निवासियों के पेट भरने के लिये दूसरे देशों के सम्मुख हाथ पसारना पड़ता है।

सन् ६० वर्षों में देश की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या ने वर्तमान खाद्य समस्या को जन्म दिया। सरकार, जनता व नेताओं सभी का ध्यान इस ओर लगा हुआ है। सन् १८८० के अकाल कमीशन ने बताया था कि देश में ५ मिलियन टन अनाज अतिरिक्त था। परन्तु १९१४ की मूल्य जांच समिति के इस कथन ने कि भारत में कृषि योग्य भूमि की अपेक्षा जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, सब लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया। सन् १९४२ में खाद्यान्नों की अत्यन्त कमी हुई और १९४३ के रंगान के दुर्मिर्ज ने तो समस्या का विकट रूप प्रकट किया।

खाद्यान्नों की कमी के कारणः—यह तो सर्वविदित ही है कि पिछले १० वर्षों में जनसंख्या में अत्यन्त तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भारत के जनगणना कमिशनर ने प्रकट किया कि सन् १९८१ तक जनसंख्या लगभग ५६ करोड़ हो जायगी। यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया और खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि नहीं की गई तो यह एक बहल समस्या हो जायगी। द्वितीय महायुद्ध के साथ मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिये सन् १९४२ में मूल्य नियंत्रण लगाया गया। बाद में सन् १९४३ से राशनिंग भी आरम्भ कर दिया गया। कुछ लोगों के अनुसार देश में पर्याप्त अनाज था, परन्तु वितरण और निर्वहण के कारण खाद्यान्नों की कमी हो गई। इसके अतिरिक्त सरकार की नीति के कारण संवहन और बाजार को प्रोत्साहन मिला।

इसके साथ ही कुछ राजनैतिक मटनाओं ने भी भारत की खाद्य समस्या को बहल बनाने में योग दिया। सन् १९३७ में बर्मा भारत से पृथक् कर दिया गया, जिससे चावल का अभाव हो गया। सन् १९४७ में विभाजन के पश्चात्सर्व गेहूँ तथा चावल उद्योग करने

वाले क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चले गये। कपास व चूट वाले क्षेत्रों के जाने से भी हमें अपने उद्योगों के लिये उनका उत्पादन बढ़ाना पड़ा।

देश में विभाजन के साथ साथ विस्थापिता की एक नयी समस्या के भारत आगमन से खाद्यान्नों का संकट और बढ़ गया।

प्रतिवर्ष हमारे देश में प्राकृतिक प्रकोप, जैसे वर्षा न होना, बाढ़ आना आदि के कारण फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे अनाज की कमी हो जाती है।

इन सब कारणों से हम सहज ही समझ सकते हैं कि यदि देश में खाद्यान्नों का अभाव है तो फिर क्या आश्चर्य।

समस्या को हल करने के प्रयत्न

(१) आयात —सरकार ने खाद्य के अभाव की पूर्ति करने के लिये विदेशों से आयात करना आरम्भ कर दिया, जिससे कुछ सोमा तक आतक समाप्त हो गया और दूसरे संकटकालीन स्थिति का भी सामना किया जा सका। गेहूँ का आयात कनाडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि से और चावल का बर्मा, चीन आदि से किया जाने लगा। सन् १९५८ में आयात लगभग ३२ लाख टन का था। सन् १९५९ के आयात का अनुमान १५ लाख टन है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए और देश के आर्थिक विकास के हित में हम अधिक दिन तक आयात पर निर्भर नहीं रह सकते। साथ ही विदेशों से अन्न मगाने से हमारे देश के औद्योगीकरण के लिये विविध मशीनें नहीं मगाई जा सकती।

(२) नियंत्रण —सबसे पहले सन् १९४२ में केन्द्र में खाद्य विभाग की स्थापना की गई, जिसका कर्तव्य वितरण पर नियंत्रण करके भावों में कमी करना था। इसके अतिरिक्त जुलाई १९४३ में खाद्यान्न नीति समिति नियुक्त की गई, जिसने देश में राशनिंग तथा नियंत्रण के सुझाव दिये। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अन्नभण्डार की स्थापना की गई। अन्न खरीदने का कार्य सरकारी विभाग को सौंपा गया।

(३) 'अधिक अन्न उगाओ आन्दोलन' —यह आन्दोलन सन् १९४३ में आरम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में अधिक भूमि कृषि के लिये उपयोग में लाकर तथा वर्तमान भूमि को सुचारु कर अन्न उत्पादन बढ़ाना था। इस आन्दोलन की बातें निम्नलिखित थीं—

(१) खाद्यान्नों के उत्पादन क्षेत्र में नई भूमि कृषि के अन्तर्गत लाकर वृद्धि करना। राज्य सरकारों ने इस और लोगों को उत्साहित करने के नियम श्रृंखला आदि आर्थिक सहायता प्रदान की।

(२) सिंचाई साधनों का विस्तार तथा सुधार करना।

(३) अन्धे बीज और वैज्ञानिक खाद का उपयोग करना।

(३) दीर्घकालीन — जो खेतों में स्थायी सुधार करने के लिए, जैसे कुशा, ताम्बाब खोदना, आधुनिक मशीनों खरीदना आदि तथा पैतृक ऋण चुकाने के लिए लिया जाता है।

ऋण लेने के साधन

(१) देशी बैंकर व साहूकार — यद्यपि महाजनों के कार्यों पर सरकार द्वारा निमित्त नियन्त्रण लगा दिये गए हैं परन्तु अभी भी गांव में ऋण प्राप्त करने का सबसे प्रमुख साधन महाजन है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार निम्न ऋणों का ७०% भाग महाजनों से प्राप्त करते हैं।

महाजनों की कार्य-प्रणाली बहुत ही सीधी-सही होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी कार्य के लिए कितनी भी मात्रा में महाजन से ऋण प्राप्त कर सकता है। इन सुविधाओं के कारण ही ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था में महाजन का महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु यह बहुत अपनी दिव्यता का अनुचित लाभ उठाता है। कच्ची-धान की दर लेना तथा कई प्रकार की धोखाधड़ी करना साधारण बात है। स्ट्रैटलैंड के अनुसार महाजन अनियंत्रित ऋण देता है—किसान की हेसियत से अधिक ऋण देना। परिणामस्वरूप भारतीय किसान ऋण में ही जम जाता है, ऋण में ही रहता है और ऋण में ही मरता है।

इन दोषों के होने पर भी महाजन को समाप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि किसान को ऋण देने के दूसरे साधनों का समुचित विकास नहीं हो जाता। इस प्रकार यह एक आवश्यक बुवाई है जिसमें उचित सुधार करना चाहिए। कृषि-वित्त उपसमिति (गांधी-गिल समिति) ने महाजनों की लाइसेंस लेने, ठीक हिसाब-किताब रखने, उचित ब्याज की दर निश्चित करने व किसानों की मारपीट से रक्षा के लिए सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के अनुसार निम्न शर्तों में कानून बनाये जा रहे हैं, जिससे आशा है कि महाजन देश के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

(२) सहाकारी साख्त समितियाँ — सन् १९०४ के कानून से सहाकारी साख्त समितियों की स्थापना हमारे देश में होने लगी। एक व्यवसाय जाति अथवा गाँव के कम से कम १० व्यक्ति मिलकर एक समिति बना सकते हैं, जो सदस्यों को उत्पादन के कार्यों के लिए ऋण दे सके। सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। १९१८ के एक्ट ने गैर साख्त समितियों की स्थापना की भी सुविधा दी।

परन्तु इन समितियों को अधिक सकलता नहीं मिली है और इनसे किसानों को ऋण सम्बन्धी आवश्यकता का ३% ही पूरा होता है। असफलता के कारण जनता की अशिष्टा, सरकारी नियन्त्रण, सदस्यों का ऋण न लौटाना आदि है।

सहाकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुउद्देश्यीय समितियों की स्थापना का मुझ रिजर्व बैंक ने दिया है। एक समिति ही किसान की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को

पूरा कर सके, जैसे सदस्यों की उपज की बिक्री करना, उत्तम बीज व औजार का वितरण, चकवन्दी करना, अच्छा जीवन बिताने के उपाय आदि ।

(३) भूमिबन्धक बैंक :—किसान को भूमि में स्थायी सुधार करने तथा भूत-कालीन ऋण चुकाने के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता है । भूमिबन्धक बैंक भूमि रहन रखकर किसान को २०, २५ वर्षों के लिए ऋण देते हैं । सन् १९२० में सर्वप्रथम पंजाब में ये स्थापित किये गए, परन्तु इनकी सफलता सबसे अधिक मद्रास में हुई है । रिजर्व बैंक ने यह सुझाव दिया है कि इन बैंकों को कम ब्याज पर भूमि तथा कृषि सुधार की योजनाओं में पूँजी लगानी चाहिये ।

(४) मिश्रित पूँजी वाले बैंक :—किसानों को व्यापारिक बैंकों से बहुत कम ऋण प्राप्त होता है । किसान ऋण प्राप्त करने के लिए धरोहर नहीं दे सकते और ये बैंक अपनी शाखाएँ गावों में खोलना नहीं चाहते । इन बैंकों से केवल बड़े गावों के सम्पन्न लोगों को ऋण मिलता है । इसके अतिरिक्त ये सहकारी, केन्द्रीय तथा राज्य बैंकों को ऋण देते हैं । इस प्रकार ये कृषि-वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं को कुछ सीमा तक परोक्ष रूप में पूरा करते हैं ।

(५) रिजर्व बैंक :—रिजर्व बैंक ने कृषि को आर्थिक सहायता देने के लिए एक कृषि-साल विभाग खोला है । यह निम्नलिखित कार्य करता है —

(१) सहकारी प्रतिभूतियों के पीछे अधिक से अधिक ६० दिन के लिए राज्य सहकारी बैंकों केन्द्रीय तथा भूमिबन्धक बैंकों को ऋण दे सकता है ।

(२) राज्य सहकारी बैंकों के कृषि-सम्बन्धी वागज १५ मास के लिए पुनर्वर्द्ध पर खरीद सकता है ।

(३) राज्य सहकारी बैंकों को १५ मास से लेकर ५ वर्ष की अवधि के लिए मध्य-कालीन ऋण दे सकता है ।

(४) सन् १९५६ से रिजर्व बैंक उन कृषकों को भी ऋण दे सकता है जो किसी सहकारी संस्था के सदस्य हों और जिन्हें कृषि उत्पादनों की तैयारी या बिक्री से सम्बन्धित किसी कार्य के लिए अर्थ की आवश्यकता हो ।

(५) एक राष्ट्रीय कृषि साल (दीर्घकालीन) कोष तथा एक राष्ट्रीय कृषि साल (स्थायीकरण) कोष स्थापित करने का अधिकार भी रिजर्व बैंक को दिया गया है, जिससे राज्य सरकारें बड़ी नदी सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों तथा भूमिबन्धक बैंकों की अथवा पूँजी में भी कुछ योग दे सकती हैं ।

(६) राज्य बैंक (स्टेट बैंक आफ इण्डिया) :— सन् १९५१ की गोखाला समिति के सुझावों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना सन् १९५५ में की गई । इसे ५ वर्षों

में ४०० शालाएँ स्थापित करना था। यह बैंक बैंकिंग सम्बन्धी व्यावसायिक कार्य करने के साथ ही सहकारी संस्थाओं की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए श्रृंखला देगा।

(७) सरकार —राज्य सरकारें किसानों को लघु तथा दीर्घकालीन श्रृंखला देती हैं बिन्दु तकावी श्रृंखला करते हैं। दीर्घकालीन श्रृंखला भूमि सुधार श्रृंखला कानून (१८८३) के अन्तर्गत दिया जाता है तथा लघुकालीन श्रृंखला किसान श्रृंखला कानून (१८८४) के अन्तर्गत। दीर्घकालीन श्रृंखला भूमि में सुधार करने, जैसे कुआँ खोदने, बंध बनाने आदि के लिए अधिक से अधिक ३५ वर्षों के लिए तथा लघुकालीन श्रृंखला १ या २ वर्षों के लिए बीज, खाद, हल, बैल आदि खरीदने के लिए दिया जाता है।

परन्तु यह देखा गया है कि तकावी श्रृंखलाओं को बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। इसके साथ ही श्रृंखला देने में देरी, वसूल करने समय सख्ती और सरकारी अवसरों की शिथिलता आदि मुख्य दोष हैं।

राज्य सरकारों द्वारा श्रृंखला सम्पत्ति कानून भी पास किये गये हैं, जिनके द्वारा श्रृंखला-दाता तथा श्रृंखला और सरकारी अफसर तथा गैर सरकारी व्यक्ति मिलकर श्रृंखला कम कर देते हैं और श्रृंखला को श्रृंखला किराये में चुकाने की सुविधा दी जाती है।

इतना सब होने पर भी ग्रामीण श्रृंखला की समस्या अभी तक नहीं चुनभरी है, क्योंकि जो कानून बनाये गये हैं उनसे पुराने श्रृंखला को कम करना तथा किसानों को महाजन के चंगुल से बचाना ही कुछ आशा तब सम्भव हो सफा है। ऐसे प्रयत्न नहीं किये गये, जिनसे किसानों को आर्थिक दृष्टि में स्थायी और पर सुधार हो सके। ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि पुराने श्रृंखला को समाप्त कर कृषि विकास की समुचित योजना बने, जिसमें सामूहिक कृषि, सिंचाई का प्रबन्ध, सहायरी समितियों का पुनर्गठन तथा कृषि सम्बन्धी कुटीर-घण्टे आदि बातें सम्मिलित हों। इर्ष का नियम है कि पंचवर्षीय योजनाओं तथा सामूहिक विकास योजनाओं द्वारा कृषि-विकास लाने का प्रयास किया जा रहा है।

सामूहिक विकास योजना (Community Projects)

भारत में ग्रामीणों की अधिकता होने के कारण यह समझा गया कि गाँवों के विकास द्वारा ही देश की आर्थिक उन्नति सम्भव है। इस उद्देश्य को लेकर ही २ अक्टूबर, १९५२ को देश में ५५ सामूहिक विकास योजनाओं को आरम्भ किया गया, जो १९५६ के आरम्भ में २४०५ हो गई। अक्टूबर, १९६३ तक सारे देश में विकास खण्डों का जाल जाल बिछा दिया।

गाँवों के लोगों के जीवन के हर पहलू को उन्नत करने के लिए इस योजना में ८ उद्देश्य रखे गये—(१) कृषि, (२) वातावरण, (३) शिक्षा, (४) स्वास्थ्य, (५) ट्रेनिंग, (६) सहायक राजस्व, (७) मनोरंजन और (८) सामाजिक इत्यादि।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस योजना के उद्देश्य अधिक ही नहीं, वरन् प्रत्येक उद्देश्य बड़ा व्यापक है जिनको पूरा करना मामीण जनता का पूरा पूरा सहयोग मिले बिना सरकार के लिये असम्भव है।

सन् १९५६ में इस योजना के अन्तर्गत हुए कार्य के कारण एक वृषक मन्त्रालय स्थापित किया गया। एक केन्द्रीय समिति तथा सामूहिक योजना प्रबंधक समिति भी निर्मित की गई जो इस योजना के नियोजन निर्देशन तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

प्रत्येक योजना क्षेत्र में लगभग ३०० गांव हैं, जिनमें २ लाख व्यक्ति तथा १॥ लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि है। प्रत्येक विकास खण्ड को ५ से १० ग्रामों के समूह में बांटा गया है। इस खण्ड में एक मण्डी इकाई है जो आर्थिक, सामाजिक तथा सामूहिक कार्यों का केन्द्र है।

इस योजना के कार्यक्रमों की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताएँ केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और अमेरिकन टेक्नीकल कोऑपरेशन मिशन द्वारा पूरी होती हैं। प्रथम योजना में इसके लिए ६६ ५ करोड़ ६० लख रुपये थे, लेकिन इस पर कुल ५२ करोड़ ६० लख रुपये। द्वितीय योजना में इस पर २०० करोड़ ६० लख का निश्चय था।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा

(National Extension Service)

यह २ अक्टूबर, १९५३ से आरम्भ की गई। इसका उद्देश्य गांव में किसानों को कृषि विज्ञान के विषय में जानकारी बसाना है, जिससे खेती के उन्नत तरीके लोगों को मालूम हो जायें। इसके द्वारा गांव की सब समस्याएँ सहकारी सिद्धान्त पर सुलभाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस योजना की व्यवस्था सामूहिक विकास योजना के अनुसार ही है। प्रथम योजना में इस पर १०१ करोड़ ६० लख रुपये किये गये। द्वितीय योजना में सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को फैलाना था।

योजना आयोग ने इस योजना के कार्यक्रमों की जांच करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसने इस योजना की श्रुतियों तथा सुझावों को बनाया है। लोगों में आत्मनिर्भरता तथा स्वयं कार्य करने की भावना उत्पन्न नहीं हो पाई है और प्रत्येक बात में वे सरकार का मुँह जोड़ते हैं। इसी प्रकार इस योजना के लाभ अधिकतर पहुँच के अन्दर के गांवों को तथा बड़े खेत वाले किसानों को मिला है। सामाजिक दृष्टिकोण में भी कोई अन्तर नहीं हो सका है और लोग सहकारी समितियों तथा पंचायतों में कम भाग लेते हैं। दूसरी ओर इस योजना के उद्देश्य और टेक्नीक अपर्याप्त तथा असमान हैं।

कुछ समय पूर्व ही नलवन्तराय मेहता समिति ने सामूहिक विकास योजना के विकास के लिए अपने सुझाव दिये हैं, जिसमें बताया गया है कि योजना का नियन्त्रण कार्य पंचायत समिति को सौंप दिया जाय। इसका कार्य खेती, लघु सिंचाई आदि की उन्नति, प्रारम्भिक

स्त्रों का नियन्त्रण तथा स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। केन्द्रीय सरकार वन द्वारा राज्य सरकारों की सहायता करे और अनुसन्धान के एकीकरण का कार्य करे। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएँ अपर्याप्त हैं, वहाँ मोटे अनाज के उत्तम बीज वितरित किये जायें।

जनवरी, १९५८ की राष्ट्रीय उन्नति कौन्सिल ने मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार का लिया है तथा विवास क्षेत्रों में प्रजातांत्रिक संस्था स्थापित करने के कार्य कुछ राज्यों में किये जा रहे हैं।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामूहिक विकास योजनाएँ तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ आश्चर्यजनक रूप में कार्य कर रही हैं। यदि कुछ आधारभूत तथा महत्वपूर्ण कठिनाइयों को दूर कर दिया जाय तो निश्चय ही इस योजना से भारत का ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से बदल जायगा और सुन्दर-समृद्ध हो सकेगी।

राज्य और कृषि

अमेरिका ने भारत की कृषि की उन्नति में कोई रुचि नहीं ली। सन् १८८० के अकाल कमीशन ने राज्यों में कृषि विभाग खोलने को कहा, जिससे अकाल फिर न पड़े और कृषि का विकास हो सके। किसानों को कुछ राहत देने के लिये १८५६ में लगान कानून, १८८३ में भूमि सुधारक सृष्ट कानून, १८८४ में कृषक सृष्ट कानून और १८८५ में भूमि अधिकार कानून बनाये। १८८६ में शाही कृषि समिति के डा० वापलकर ने कृषि की परिस्थितियों का अध्ययन कर बहुमूल्य सुझाव दिये। सन् १९०४ में सहकारी समिति कानून बनाया गया। कृषि विकास का सबसे प्रमुख सरकारी कदम पञ्जाब, उत्तर प्रदेश और मद्रास में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध करना था।

१९१६ के सुधारों के बाद कृषि प्रान्तीय विषय बना दिया गया, जिससे कृषि के विभिन्न परलुओं में सरकारी सहायता का कार्य बढ़ गया। १९२६ में कृषि की जाच के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने १९२८ में विभिन्न सुझावों से युक्त विस्तृत रिपोर्ट दी। सरकार ने एक सुझाव को मानते हुए १९२६ में शाही कृषि अनुसन्धान सभा की स्थापना की, जिससे कृषि अनुसन्धान का कार्य उन्नत हो सके।

विश्वमन्दी के समय कृषि उपज की बिक्री के संगठन के लिये बहुत से नियंत्रित बाजारों की स्थापना की। द्वितीय महायुद्ध के समय बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये नियंत्रण तथा राशनिंग आरम्भ किये गये। बंगाल में अकाल के कारण १९४३ में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन चलाया गया। विभाजन के बाद देश में खाद्य स्थिति की गंभीरता को देखकर कृषि उपज बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किये, जिनमें खेतीबारी उन्मूलन, चक्रबन्दी, सहकारी कृषि, बहुउद्देश्यीय नदी पाणी योजनाएँ, सामूहिक विकास योजनाएँ आदि प्रमल हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी। दूसरी योजना में उद्योग-धन्धों को प्रमुखता प्रदान की गई है, परन्तु फिर भी कृषि के महत्व को कम नहीं किया है। प्रथम योजनाकाल में कृषि और सिंचाई पर ६६२ करोड़ रु० व्यय किये गये अर्थात् कुल व्यय का ३१%। द्वितीय योजना में कृषि उत्पादन में १८% वृद्धि की आशा है। कृषि और सिंचाई पर कुल व्यय की २१% राशि निर्धारित की गई थी।

इस प्रकार सरकार कृषि के विकास के लिये सतत प्रयास कर रही है, परन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह कहा गया है कि भारत सरकार प्रति किसान पर कृषि उन्नति के लिये ११ आने प्रतिवर्ष व्यय कर रही है, जबकि कनाडा में २० रु० प्रति व्यक्ति तथा अमेरिका में ७७ रु० प्रति व्यक्ति खर्च किया जाता है।

प्रश्न

१. भारत की खाद्य समस्या के हल करने के सरकारी प्रयत्नों की विवेचना कीजिये और उनमें कहा तक सफलता मिली है।
२. भारत में कृषि के प्रति राज्य की नीति की समीक्षा कीजिये।
३. भारत में कृषि वित्त देने के वर्तमान साधनों का वर्णन करिये।
४. भूदान यज्ञ का आर्थिक महत्व बताते हुए यह बताइये कि यह कहा तक सफल हुआ है।
५. भारत में सामूहिक विकास योजनाओं का मूल्यांकन कीजिये। इनके दोषों को दूर करने के सुझाव दीजिये।

प्राचीन काल में भारत में कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व था। भारत सूती वस्त्र, नककाशी, नारें तथा जलपोत के निर्माण के लिए ससार प्रसिद्ध था, लेकिन भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से कुटीर धन्धों का हास होता गया।

जो उद्योग—धन्धे कारीगर स्वयं अपने घर पर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से करता है, वे कुटीर धन्धे कहलाते हैं। इनको घरेलू धन्धे भी कहते हैं, जैसे—कपड़ा बुनना, सूत काटना, रेशम बनाना, तेल निकालना, दस्तकारी के काम, धातु के बर्तन, सोने—चादी के तार आदि।

कुटीर धन्धों का वर्गीकरण

(१) वे घरेलू उद्योग जो किसानों के लिए सहायक होते हैं, जैसे हाथकर्म की बुनाई, टोकरी रस्ती, चढ़ाई बनाना, रेशम की कीड़े पालना आदि

(२) वे उद्योग जिनसे गाओं की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे लोहार छापी, शुकाई, सुनार, कुम्हार आदि।

महत्व

कुटीर उद्योगों का देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत एक कृषिप्रधान देश है। यह एक निर्धन देश है और अधिकांश जनता का जीवनस्तर नीचा है। हमारे कृषकों को पूरे वर्ष भर काम नहीं करता पड़ता है। कृषि के शाही कमीशन के अनुसार कृषक को वर्ष भर काम करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष में ४ महीने वह विन्युक्त छाती रहता है, ऐसे खाली समय में उसको तथा उसके परिवार को कोई काम देने के लिये कुटीर व्यवसायों की आवश्यकता है। भारतीय बैंकिंग खाद्य समिति का मत था कि कुटीर धन्धों द्वारा किसान अपनी आय बढ़ा सकता है।

राष्ट्रीय योजना समिति के अनुसार ग्रामीण भारत की अधिकांश जनता अपने भौतिक कल्याण के लिए अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाती, अतः उनके लिए कुटीर उद्योगों का इतना आवश्यक है। "यदि हम कृषि को

वैज्ञानिक व यांत्रिक करना चाहते हैं तो जो लोग बेरोजगार हो जायेंगे, उन्हें कुटीर धन्वों द्वारा जीविका निर्वाह का साधन प्राप्त हो सकता है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, अतः कुटीर धन्वों द्वारा अकाल की भीषणता कम हो सकती है। इस प्रकार कसलें लराव होने की दशा में "घनुप में दूसरी बोरी के समान" ये उद्योग सहायक सिद्ध होंगे।

कुटीर उद्योग हमारे देशवासियों की प्राकृतिक प्रतिभा और राष्ट्रीय परम्परा के अनुकूल हैं। कई पीढ़ियों के अनुभव से यहाँ के कारीगरों ने इन कार्यों में दक्षता प्राप्त की है। इन उद्योगों के लिये आवश्यक बच्चा माल हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इनमें बहुत कम पूँजी की आवश्यकता होती है जो कि कारीगर स्वयं लगा सकते हैं। इनमें साधारण औजारों की आवश्यकता पड़ती है जो देश में आसानी से बनाये जा सकते हैं।

हमारे देश का भ्रम अभी अशिक्षित एवं अनिपुण है, अतः इस भ्रम से छोटें कार-खानों का विकास सुगमतापूर्वक हो सकता है। मृमि पर जनसंख्या के अधिक बढ़ जाने से कृषि अलाभदायक उद्योग हो गया है अतः कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कुटीर धन्वों का विकास करना आवश्यक है। बड़े बड़े कारखानों में महंगी व पेचीदा मशीनों के प्रयोग से भ्रम उन्मूलन का लाभ प्राप्त होता है, अतः कम आबादी वाले देशों में जहाँ भ्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इनसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

महात्मा गांधी ने देश के आर्थिक पुनर्गठन में कुटीर धन्वों के महत्त्व पर अधिक बल दिया। इसके अतिरिक्त दूसरे नेताओं जैसे त्रिनेत्रा भाने, डा० राजेन्द्रप्रसाद आदि ने भी कुटीर उद्योगों को देश के आर्थिक विकास में आवश्यक बताया है।

कुटीर उद्योगों की अवनति

(१) राजदरबारों की समाप्ति.—प्राचीन काल में राजदरबारों की छत्रछाया में बहुत से धन्ये पला करते थे। अंग्रेजी की सत्ता बढ़ने के साथ साथ राजाओं-नवाबों की शक्ति क्षीण होती गई, जिसके फलस्वरूप जो सरल व आर्थिक सहायता उद्योगों को मिलती थी, उसका अन्त हो गया और इस प्रकार धीरे धीरे उद्योग-धन्वों का विनाश होता गया।

(२) पार्श्वस्थ सभ्यताः—अंग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजी व्यवसायों की नकल के कारण विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। इस प्रकार कलात्मक वस्तुओं तथा निपुण कारीगरों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं की मांग कम हो गई, जिससे कुटीर उद्योग लुप्त होते गये। जेस एन्सर्ट का कहना है कि भारत के भनी वर्गों ने पश्चिमी वैश्वीकरण करना आरम्भ किया और पश्चिमी देशों में बनी वस्तुएँ खरीदना आरम्भ कर दिया।

(३) ब्रिटिश सरकार की नीतिः—ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानून बनाये, जिससे इंग्लैंड में भारत के कपड़े का आयात पूर्णतः बन्द हो गया। इसके अतिरिक्त भारत में इंग्लैंड का मशीन निर्मित माल बेचने को सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन दिया गया। इस

भारत ब्रिटिश नीति भारत को बच्चा माल का उत्पादक बनाने तथा अपने अधीन रखने की थी।

(४) मशीन निर्मित माल के साथ प्रतियोगिता :— भारत के कुटीर धन्धों के पतन का मुख्य कारण मशीन द्वारा बने हुए माल के साथ प्रतियोगिता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति (१७६०) के कारण बड़े पैमाने पर सस्ता माल बड़ी बड़ी मशीनों से बनने लगा। भारत में रेलों के विकास तथा सरकारी नीति के कारण यह सस्ता माल देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुँच गया, जिसके सामने देशी उद्योग-धंधे खड़े नहीं रह सके और वे नष्ट होने लगे।

(५) भारत सरकार की मुक्त व्यापार नीति (Free Trade Policy) :— भारत सरकार ने इन गृहमय उद्योग-धन्धों को कोई सहाय नहीं दिया। भारत सरकार ने ब्रिटिश नीति का अनुकरण करते हुए प्रतिव्यवहारित व्यापार नीति अपनाई और उद्योगों के संरक्षण के बारे में सन् १९२३ तक कुछ भी नहीं सोचा।

कुटीर धन्धों की कठिनाइयाँ तथा उपचार

(१) कारीगरों की सस्ते दाम पर उचित मात्रा में बच्चा माल नहीं मिलता है। बच्चे माल की समस्या को सहाय समितियों द्वारा सुगमता से हल किया जा सकता है। ये समितियाँ थोक भाव पर मात्र खरीद कर अपने सदस्यों को उचित मूल्य पर दे सकती हैं।

(२) यद्यपि कारीगरों की थोड़ी ही पूँजी की आवश्यकता होती है परन्तु वह भी उन्हें सुगमता से नहीं मिल पाती है। उन्हें महाजनों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है या अधिक मूल्य पर बच्चा माल लेना पड़ता है। सहाय समितियाँ, मानवीय औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल तथा सरकारी सहायता द्वारा कारीगरों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है।

(३) कारीगर इतने निर्धन हैं कि वे छोटे छोटे औजार भी प्राप्त नहीं कर सकते। कुटीर धन्धों की उन्नति के लिए छोटे छोटे औजार, मशीनों तथा विद्युत की आवश्यकता है। इस ओर सहाय समितियाँ तथा सरकार उचित सहायता प्रदान कर सकती हैं।

(४) कुटीर धन्धों की वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था ठीक नहीं है और कारीगरों को उचित मूल्य नहीं मिलता। बिक्री का कार्य सहायी विक्रय समितियों द्वारा किया जा सकता है। प्रत्येक प्रदेश में विपणन मण्डल बनाकर उनकी शालायाँ प्रत्येक गाँव में खोलना आवश्यक है। महाजनों द्वारा शोषण को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने एम्पोरियम खोल दिये हैं।

(५) अन्य कठिनाइयों में कारीगरों की अशिक्षा व अज्ञानता, अनुसन्धान का अभाव, शिल्पिक सहायता का अभाव आदि मुख्य हैं, जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार का कुटीर उद्योग बोर्ड महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

कुटीर उद्योग और सरकार

कुटीर उद्योगों का देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये संस्थाएँ स्थापित की हैं— अखिल भारतीय खादी बोर्ड, कुटीर उद्योग बोर्ड, कोयल बोर्ड तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।

तात्कालिक सहायता देने के लिए औद्योगिक विस्तार सेवा आरम्भ की गई है, जिसका दिनांक १९५८ में पुनर्गठन किया गया है जिससे प्रत्येक राज्य में एक एक संस्था स्थापित की जा सके । विदेशों से विशेषज्ञ कुलावर इन उद्योगों को सहायता दी जाती है । इसी प्रकार विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भी कारीगर भेजे जाते हैं । परवरी १९५५ में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई, जो सरकार के कई विभागों से सम्पर्क रखता है और उनकी ओर से छोटी उद्योग इकाइयों को मल सफाई करने का आदेश देता है । इसके अतिरिक्त, निर्यात की प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय दूरतकारी विकास कारपोरेशन स्थापित किया गया है ।

सरकार ने देश में ७२ औद्योगिक स्टेट स्थापित करने का निश्चय किया है, जिनका उद्देश्य छोटे उद्योगों को नगरों से हटाकर दूसरे स्थानों पर संगठित करना है ।

प्रथम योजना के अन्तर्गत कुल ३३६ करोड़ ४० विभिन्न कुटीर धन्धों पर व्यय किया गया । द्वितीय योजना में इनके लिए २०० करोड़ ४० रुपये बंधे हैं । इस योजना में अम्बर चर्खों के उपयोग पर जोर दिया गया है । तृतीय योजना में ग्राम्य एवं लघु उद्योगों के लिए २॥ अरब ४० की 'प्रारम्भिक राशि' निर्धारित की गई है । विभिन्न ग्राम व लघु उद्योगों के लिए धनराशि इस प्रकार है—खादी ३२ करोड़, अम्बर खादी ३७ करोड़, बिजली कपड़े ४ करोड़, ग्रामीण २० करोड़, हाथ कपड़े ३२ करोड़ रेशम क्रीड-पालन ७ करोड़, दस्तकारी ८ करोड़ और मूल ३ करोड़ ।

जून १९५५ में कर्वे (Karve) समिति नियुक्त की गई, जिसके सुझावों को मानकर सरकार एक पृथक् मन्त्रालय स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ।

प्रश्न

१. १९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कुटीर उद्योग के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिये ।
२. भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर धन्धों का क्या महत्व है ? कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्रम सन्निधम (Labour Legislation)

भारत में बड़े बड़े उद्योगों के स्थापित होने के पश्चात् भी बहुत समय तक कोई फैक्ट्री-एक्ट नहीं बनाया गया जिससे परिणामस्वरूप मिल मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण बहुत होता था। श्रमिकों की इस अवनत दशा के कारण लोगों द्वारा सरकार की आलोचना होने लगी तथा बहुत से औद्योगिक स्पर्ध दुष्ट। इन सब बातों से प्रभावित होकर सरकार को समय समय पर श्रम सन्निधम बनाने पड़े। किसी भी देश का औद्योगिक उत्पादन श्रम-शक्ति पर निर्भर रहता है, अतः सरकार द्वारा मजदूरों के अधिकार की रक्षा के लिए नियम बनाना आवश्यक है। मिल मालिक अधिकतम लाभ के लिए मजदूरों से, कम मजदूरी देकर अधिक समय तक काम कराना चाहते हैं—उनके आसपास या सुरक्षा पर कुछ व्यय नहीं करना चाहते। मजदूरों की कार्य-वृत्तता का कुल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अतः मानवीय, सामाजिक व आर्थिक बातों के विचार से श्रम की सहायता करना आवश्यक है।

फैक्ट्री नियम

यह जानना आवश्यक है कि भारत सरकार ने जो प्रारम्भ में फैक्ट्री एक्ट पास किये, वे मजदूरों की दशा सुधारने के लिए नहीं, बल्कि लक्ष्मणपुर के मिल मालिकों की शिकायत भारतीय पूँजीपतियों की अपेक्षा अष्ट करने के लिए दिये गये थे। भारत में १८८१, १८९१, १९११, १९२०, १९३४ और १९४८ में फैक्ट्री नियम बनाये गये। इन नियमों का उद्देश्य यह था कि कारखानों में बच्चों को काम पर न लगाया जाय, काम करने के घण्टे सीमित हो, मजदूरों सहित कप्लाई में एक दिन की छुट्टी मिले और कारखानों में उनकी सुरक्षा तथा आराम का प्रबन्ध हो। धीरे धीरे इन नियमों द्वारा श्रमिकों की दशा में सुधार होने लगा। यहां हम सन् १९४८ के फैक्ट्री नियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करेंगे, जो निम्न प्रकार से हैं—

(१) क्षेत्र— यह नियम ऐसे कारखानों पर जो शक्ति से चलते हैं और जहां १० या इससे अधिक मजदूर काम पर लगे हैं तथा जिसमें शक्ति से काम नहीं होता, किन्तु २० से अधिक मजदूर लगे हैं, लागू होता है। राज्य सरकार द्वारा यह नियम किसी भी फैक्ट्री पर लागू किया जा सकता है।

(२) आयु — १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता । १५ से १८ वर्ष की आयु के किशोर को डॉक्टर के प्रमाणपत्र देने पर ही काम पर लगाया जा सकता है ।

(३) कार्य करने के घण्टे — बयस्क मजदूरों के लिए कार्य करने के ४८ घण्टे प्रति सप्ताह तथा ८ घण्टे प्रतिदिन है, जिसमें ५ घण्टे बाद आधा घण्टे का विश्राम आवश्यक है । बालक तथा किशोर के लिये कार्य के घण्टे प्रतिदिन ४॥ है ।

(४) स्त्री तथा बच्चों को सायंकाल ७ वन से प्रातःकाल ६ बजे तक काम पर नहीं लगा सकते । सप्ताह में एक १ दिन मजदूरों सहित टुट्टी की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त १२ महीने के निरन्तर कार्य के पश्चात् प्रत्येक बयस्क का प्रति २० दिन में १ दिन और प्रत्येक किशोर को प्रति १५ दिन में १ दिन सैवतनिक छुट्टी दी जायगी ।

(५) काम करने की दशा — मजदूरों में स्वास्थ्य सुरक्षा तथा हित का प्रबन्ध प्रत्येक कारखाने में होना आवश्यक है । सगई और प्रकाश के अतिरिक्त तापमान को नियन्त्रित रखने, पीने का पानी देने तथा स्नान व कपड़े धोने की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने के लिए समुचित स्थान देना आवश्यक है जिससे भीड़भाड़ न हो सके । मजदूरों की सुरक्षा के हेतु मशीनों के चारों ओर घेरा लगाना तथा आलों का विपैली गैसी से बचाव का प्रबन्ध भी अनिवार्य कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त शौचालय, हाथ धोने की सुविधा पेन्टीन विभागसह, बच्चों के लिटाने के स्थान आदि अमकल्याण के कार्य तथा अमहित अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रबन्ध है ।

नियम की विविध धाराओं के कारखानों द्वारा पालन किये जाने के लिए अम-निरीक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है ।

निम्नतम मजदूरी विधान, १९४८

(Minimum wages Act, 1948)

निम्नतम मजदूरी कानून का निर्माण उन उद्योगों के लिए किया गया है, जिनमें धम-संगठनों की कमजोरी के कारण मजदूरों की बहुत कम मजदूरी मिलती है । यह कानून चाय बागानों, तेल मिल, चावल मिल, आटा मिल, मोटर यातायात, चमड़ा-वर्पाई-उद्योग आदि में लागू होता है । इसे कृषि उद्योग पर भी लागू किया जायगा । जिन उद्योगों में एक हजार से कम व्यक्ति काम करते हैं, उनमें निम्नतम मजदूरी का निर्धारण नहीं होगा ।

राज्य सरकार स्वयं किसी उद्योग के लिए निम्नतम मजदूरी की दरों का प्रस्ताव रख सकती है, अथवा एक कमेटी नियुक्त कर सकती है, जो उचित जाच करके मजदूरी की निम्न-तम दरों के सम्बन्ध में सुझाव देगी । कमेटी की दरें गजट में प्रकाशित होगी और प्रकाशित होने के ३ मास बाद लागू हो जावेंगी । इस प्रकार की दरें ५ वर्ष तक लागू रहेगी, उसके बाद उनमें परिवर्तन होगा । परिवर्तन के लिए सरकार एक सलाहकार समिति नियुक्ति करेगी

और यह समिति दरों में परिवर्तन के लिए सलाह देगी कि किस सीमा तक परिवर्तन होना चाहिए।

विभिन्न उद्योगों के लिए जो कमेटीया और बोर्ड नियुक्त होंगे, उनमें मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधि समान संख्या में रहेंगे और कुछ स्वतन्त्र सदस्य भी होंगे जो सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक न होंगे। सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा होगी और एक स्वतन्त्र सदस्य अध्यक्ष का कार्य करेगा।

निम्नतम मजदूरी या तो समय के अनुसार निश्चित की जा सकती है अथवा काम के अनुसार। स्त्रियों, और बच्चों के लिए अथवा विभिन्न प्रकार के कामों के लिए अथवा विभिन्न स्थानों के लिये निम्नतम मजदूरी की दर भिन्न भिन्न हो सकती हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा कानून, १९४८

(Employees State Insurance Act, 1948)

जिन कारखानों में २० या अधिक मजदूर काम करते हैं अथवा जो रिजली ने चलते हैं, वे सब इस कानून के अन्तर्गत आ गये हैं। जिन मजदूरों का वेतन (४००) मासिक से अधिक है, उन पर यह कानून लागू नहीं होता। जो कारखाने पर वर्ष न चलकर केवल एक मौसम में चलते हैं, उन पर भी यह लागू नहीं होता। जो मजदूर इस कानून के अन्तर्गत बीमा किये जायेंगे, उनके वेतन से नियमित रूप से चंदा काटा जायगा। इस योजना से निम्नलिखित सुविधायें मिलेंगी —

(१) बीमारी के पहले दिन से मुफ्त में चिकित्सा होगी। यदि राज्य सरकार चाहे तो ये सुविधायें मजदूर के परिवार के लोगों को भी मिल सकती हैं।

(२) बीमारी के तीसरे दिन से दैनिक औसत वेतन का आधा वेतन नकद मिलेगा। यदि बीमारी लम्बी है अथवा बत्ती बत्ती होती है तो इस तरह का आधा वेतन साल में छोट सप्ताह तक मिल सकता है। लेकिन इस भत्ते को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि मजदूर ६ महीने तक चिकित्सा केंद्र में अपना चंदा देता रहा हो अथवा कोप आरम्भ होने से २/३ समय तक का, जो १२ सप्ताह से कम न हो।

(३) अगम्य होने पर समुचित सहायता की व्यवस्था है। यदि कारखाने में काम करते समय मजदूर चोट खा जाता है और अथ रूर में या पूर्ण रूप में काम करने लायक नहीं रह जाता तो उसे मुफ्त चिकित्सा और नकद भत्ता मिलेगा। यदि कोई मजदूर काम करते समय मर जाता है तो उसके आश्रिता को कानून के अनुसार पेंशन या निर्वाह व्यय मिलेगा।

(४) छुट्टी मजदूरों को गर्महान में १० सप्ताह के लिए १२ आने प्रतिदिन के दिवार से भत्ता मिलेगा। यह भत्ता नवम्बर होने के ६ सप्ताह पहले और ६ सप्ताह बाद तक मिलेगा। इस योजना का काम कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाया जाता है। अगस्त

१९५८ में केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने कहा—'हम चाहते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कम चारी राज्य बीमा योजना प्रत्येक ऐसे औद्योगिक नगर में लागू हो जाय, जहाँ कम से कम १५०० अधिक रहते हों। इस प्रकार हम सारे राज्य में २२ लाख श्रमिकों को उक्त योजना में ले सकेंगे।'

कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, १९५२

इस फंड के लिए सब मजदूरों के वेतन से ६ रु० प्रतिशत काटा जायगा। फंड में जितना धन कर्मचारी देंगे, उतना ही मालिक भी देगा। यह अधिनियम ५० से अधिक व्यक्तियों वाले कारखानों में और सैन्ट सिगर लोहा अथवा इस्पात से बने, बिजली सम्बन्धी, मशीनरी अथवा सामान्य इन्जिनियरिंग कारखानों और स्त्री वस्त्र की मिलों पर लागू होता है। दिसम्बर १९५६ में इस विधान में संशोधन करके सरकार को ये सुविधायें कारखानों के मजदूरों के अलावा अन्य श्रमिकों को भी देने का अधिकार मिल गया।

औद्योगिक संघर्ष सम्मन्धी विधान (Industrial Disputes Act)

प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद से औद्योगिक भग्न की संख्या में वृद्धि होती गई। भारत सरकार ने १९०८ में एक एक्ट पास किया जिससे अन्तर्गत प्रार्थना करने पर जाच अदालत तथा समझौता बोर्ड की नियुक्ति कर दी जाती थी, परन्तु इसका निर्णय दोनों पक्षों को मानना अनिवार्य नहीं था। अतः इस एक्ट से कुछ लाभ न हुआ। १९२८ में बम्बई सरकार ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार हड़ताल या तालाबन्दी से पूर्व भगड़ों की जाच होना अनिवार्य कर दिया गया।

द्वितीय महायुद्ध के बाद तो देश में औद्योगिक अशांति की एक लहर सी दौड़ गई। ऐसी स्थिति में सरकार ने १९४७ में औद्योगिक नव एक्ट पास किया, जिसमें संशोधन १९४८, १९५० और १९५६ में किया गया। इस एक्ट के अन्तर्गत श्रम समितियाँ (श्रमिक व मालिक के प्रतिनिधि) प्रत्येक ऐसे कारखाने में स्थापित की जायेंगी, जिसमें १०० या अधिक श्रमिक हैं। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना होगा। इसके अतिरिक्त संघर्षों को रोकने व निपटाने के लिए समझौता अधिकारी, समझौता नार्ड, जाच अदालत, औद्योगिक न्यायालय आदि की नियुक्ति की व्यवस्था है। सर्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योगों में बिना ६ सप्ताह का नार्डिस दिए हड़ताल अथवा तालाबन्दी करना गैरकानूनी कर दिया गया है।

सन् १९५० के कानून के अनुसार एक अपील न्यायालय (Appellate Tribunal) नियुक्त करने का प्रवन्ध किया गया, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। सन् १९५१ में एक श्रम सम्बन्ध एक्ट (Labour Relations Act) पास हुआ। इसके अनुसार सरकार कई प्रकार के अफसर व न्यायालय स्थापित कर सकती थी, परन्तु इसका तीव्र विरोध हुआ और इन कानूनों को विवेक से रद्द किया गया। अन्तिम सरकार की समाप्ति के साथ ही यह भी समाप्त हो गया।

औद्योगिक स्वयं संचालित एक्ट १९४६ के अनुसार अब ३ तरह के ट्रिब्यूनल नियुक्त किये जा सकते हैं:—

(१) भ्रम अदालत:—इसका कार्य छोटे छोटे मामलों को सुलझाना होगा।

(२) औद्योगिक ट्रिब्यूनल:—यह मजदूरी तथा मज्द, कार्य करने के घण्टे, छुट्टी, बीमर आदि महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने का कार्य करेगी।

(३) राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल:—इसको केन्द्रीय सरकार उन झगड़ों को सुलझाने के लिए स्थापित करेगी, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जो एक से अधिक राज्यों पर प्रभाव डालते हैं।

भारत में आजकल औद्योगिक झगड़ों को निपटाने के लिए निगुट सम्मेलन, भारतीय भ्रम काउंसिल तथा बहुत सी परामर्श देने वाली समितियाँ हैं, जिनके स्वरूप बहुत से झगड़े आपस में तय हो रहे हैं।

श्रमिक संघ अधिनियम (Trade Union Act)

यद्यपि भारत में औद्योगिक विकास का प्रारम्भ हुए काली समय हो चुका था, परन्तु ट्रेड यूनियनों का संगठन बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ। बी कुछ भी श्रमिक संघ प्रारम्भ में बने उनका कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं था, वे अधिकतर हड़ताल करने के लिए ही बनाये जाते थे। धीरे धीरे श्रमिक संघों की वृद्धि तथा औद्योगिक झगड़ों के बढ़ने से भ्रम संघों को मान्यता देने पर जोर दिया जाने लगा। अन्त में सन् १९२६ में इम्प्लियमेंट ट्रेड यूनियन कानून बना जिसने समय समय पर संशोधन हुए।

इस कानून के अन्तर्गत मजदूरों और मालिकों के संगठन की रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति सरकार को प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी यूनियन का एक सचिवान होना चाहिये और उसकी कार्यकारिणी के कम से कम आधे सदस्य कारखाने या उद्योग में काम करते हों। उसे अपनी आय-भय का वार्षिक हिसाब रखना पड़ता है और वह अपना धन राजनैतिक कार्यों के लिए व्यय नहीं कर सकती। इस कार्य के लिए एक अलग कोष स्थापित हो सकता है, जिसमें सदस्य इच्छानुसार चन्दा देंगे। यूनियन के वैधानिक कार्यों के लिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

सन् १९४८ के संशोधन द्वारा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों को मिला मालिकों द्वारा मान्यता देना अनिवार्य कर दिया गया है। मान्यता न देने पर भ्रम-अदालत से मान्यता का प्रमाण-पत्र लिया जा सकता है। सन् १९४१ के ट्रेड यूनियन बिल के अनुसार मालिक मिलकर अधिकृत एजेंटों द्वारा सीदा तय कर सकते थे, परन्तु मालिक तथा मजदूर दोनों के द्वारा ही तीव्र विरोध होने के कारण इस बिल को समाप्त होने दिया गया।

ग्रन्थ

- (१) भारतीय केंद्रीय एक्ट का सविस्तृत विवरण दीजिए।
- (२) भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के तरीकों का वर्णन कीजिए।
- (३) भारतमें औद्योगिक स्वयंकी रोक और निपटारे के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं?
- (४) भ्रम संघ कानून की निम्नलिखित बातों का वर्णन करिए।

किसी भी देश के आर्थिक विकास का उसके परिवहन की व्यवस्था से बड़ा निकट सम्बन्ध रहता है। यातायात ने हमारे आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों में विशेष प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। यातायात के साधन माल और मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के साथ साथ ही सभ्यता, संस्कृति तथा शिक्षा का प्रसार करते हैं। किसी देश के यातायात के साधनों की उन्नति से उस देश के आर्थिक विकास का पता लगाया जा सकता है। यातायात ने समय और दूरी को कठिनाईयों को पार कर सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, सभ्यता, धर्म और शिक्षा का नया प्रसार स्थापित कर दिया है। यह कहा गया है कि “यदि कृषि तथा उद्योग को किसी राष्ट्र का शरीर और अस्थिमाना माना जाय तो यातायात के साधन रक्त-जाल के समान होंगे।”

भारत में मुख्यकर यातायात के विकास के कारण आन्तरिक और विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, अकाल की भीषणता कम हुई तथा देश एकत्र में बँध गया। सन् १८५० तक देश में सड़कों का नितान्त अभाव था। ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाने तथा प्रशासन को संगठित करने के उद्देश्य से ही हमारे देश में यातायात के साधनों का विकास आरम्भ में किया था। परन्तु अब औद्योगिक उन्नति के लिये विविध साधनों का विकास किया जा रहा है।

यातायात के मुख्य साधन ३ हैं.—

- (१) स्थल यातायात (रेलें तथा सड़कें)
- (२) जल मार्ग (आन्तरिक व सामुद्रिक)
- (३) वायु मार्ग (आन्तरिक और बाहरी)

रेल्वे यातायात का महत्त्व

सामाजिकः— (१) रेलों से समय, दूरी, चोरी-डकैती आदि की समस्याएँ दूर हो गई हैं।

(२) रेलों ने नगरों तथा गावों में सम्बन्ध स्थापित कर लोगों में पारस्परिक विचार-विनिमय व सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहन दिया।

(३) रेलों द्वारा सुआलूत, अथ विरवाष, घृणा आदि का क्षोभ होता जा रहा है।

(४) रेलों के द्वारा विज्ञापन, समाचार पत्र, स्वच्छता, स्वास्थ्य सम्बन्ध वगैरे आदि का प्रसार सुगमतापूर्वक हुआ है ।

राजनैतिक — (१) रेलों द्वारा भारत में शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना सम्भव हुई, राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत हुई तथा देश का सुशासन, सैनिक रक्षक आदि कार्य हुए ।

(२) रेलों के निर्माण के कारण राज्य को आर्थिक कार्यों में भाग लेना पड़ा ।

(३) रेलों द्वारा राज्य की आय में वृद्धि हुई, क्योंकि अविकारा रेलों राज्य की सम्पत्ति हैं ।

आर्थिक — आर्थिक क्षेत्र में रेलों ने कृषि, उद्योग, व्यापार तथा श्रमिकों को प्रभावित किया है ।

कृषि — (१) रेलों द्वारा हमारे क्षेत्रों की उपज विदेशों को जाने लगी, जैसे जूट, चाय, तिलहन आदि । इसके साथ ही हमारी मण्डियों का विस्तार बढ़ गया ।

(२) रेलों के विकास से ही किसानों को उन्नत बीज, खाद व मशीनें उपलब्ध होने लगी ।

(३) रेलों द्वारा स्थानीय उत्पादन में वृद्धि हुई—मुख्यकर शाक-सब्जी, दूध, मक्खन, फल आदि में ।

(४) रेलों द्वारा अन्न का भण्डार कम हो गया, परन्तु यह माना जाता है कि रेलों से वास्तव में कृषि की उन्नति नहीं हुई । पशुओं के विशिष्टीकरण और स्थानीयकरण के कारण यदि किसी पशु में वृद्धि हुई तो दूसरी में कमी । रेलों द्वारा हमारे पुराने जुड़ीर पशुओं का विनाश हुआ और मृष्टि पर अधिक जनसंख्या का भार बढ़ा ।

रेलों द्वारा स्त्रीपर व दिवंगों के लिये लकड़ी की मांग बढ़ी और इस प्रकार वनों का विकास हुआ ।

उद्योगः— (१) रेलों द्वारा उद्योगों की श्रम, कोयला तथा कच्चा माल शीघ्रता से पहुँचने लगा, जिससे देश में बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे ।

(२) रेलों से ही उद्योगों द्वारा वैश्व माल दूर दूर के स्थानों को भेजा जाने लगा, जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने लगी ।

(३) रेलों ने मूल्य पर भी प्रभाव डाला । वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे लाकर दूसरे स्थान पर बेची जाने लगी ।

(४) रेलों द्वारा बेकार मनुष्यों को काम मिलता तथा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर काम करने लगे ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रेलों का हमारे देश की आर्थिक व सामाजिक दशा में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है ।

भारत में रेलों का विकास

भारत में रेलों का विकास सन् १८४४ से आरम्भ हुआ, जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ईस्ट इण्डियन रेलवे कं. तथा ग्रेट इण्डियन पेनिनसुलर रेलवे कम्पनी को दो रेलवे लाइन के निर्माण की स्वीकृति दी। ग्राह्वेट कम्पनियों को पुराना प्रणाली के अन्तर्गत रेलों के निर्माण का अधिकार दिया गया, जिसके द्वारा सरकार ने ५ प्रतिशत न्याय की गारन्टी दी तथा विशेष मामलों में देखभाल करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ रखा। सन् १८६६ के बाद १० वर्षों तक सरकार ने स्वयं रेलें निर्माण करने का प्रयत्न किया, परन्तु सफलता नहीं मिली। अतः सरकार ने ब्रिटिश कम्पनियों को नई गारन्टी पर रेलें बनाने का ठेका दे दिया। नई प्रणाली के अन्तर्गत १॥ प्रतिशत न्याय की गारन्टी दी गई और रेलों सरकार की सम्पत्ति घोषित कर दी गई।

सन् १९०८ में मैके समिति ने रेलों पर सरकार द्वारा अधिक व्यय करने पर जोर दिया। प्रथम महायुद्ध के समय रेलों पर अधिक कार्य रहा। सन् १९२०-२१ में रेलों की समस्याओं पर विचार करने के लिये आकवर्थ समिति (Aokworth Committee) की नियुक्ति की गई जिसने यह सिफारिश की कि सरकार रेलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले तथा रेलवे बजट सामान्य बजट से पृथक् कर दिया जाए। सरकार ने सुझावों को मानने हुए रेलों का प्रबन्ध अपने अधीन करना आरम्भ कर दिया और सन् १९२४ से रेलवे बजट अलग से पेश किया जाने लगा। रेलवे की समस्या

रेलों ने सन् १९०० से सर्वप्रथम लाभ कमाना शुरू कर दिया था परन्तु सन् १९२६ के विश्व मन्दो के कारण रेलों को भारी हानि उठानी पड़ी। इस समय पोप समिति तथा जेम्सपुर्क समिति नियुक्त की गई, जिन्होंने की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के सुझाव दिये।

द्वितीय महायुद्ध के समय रेलों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, परन्तु युद्ध के बढ़ने के साथ साथ यातायात का अधिक से अधिक भार रेलों पर पड़ने लगा और जनता के लिए टिकटों का अभाव होने लगा। सन् १९४२ में युद्ध यातायात समिति तथा केन्द्रीय यातायात संघ की स्थापना की गई। इनका कार्य यातायात के दूसरे साधनों का विकास करना था, जिससे रेलों पर भार कम हो जाए।

सन् १९४७ में देश के विभाजन के पलटवुरूप रेलों को काफी हानि उठानी पड़ी। सन् १९४६ तक रेलों की दशा में पर्याप्त सुधार हुआ और यात्रियों की सुविधा के प्रयत्न किये गये। सन् १९५० तक सरकार के अधीन लगभग सभी रेलें आ गईं। इस समय रेलों की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा व्यय में कमी करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण रेलवे व्यवस्था को कुछ बड़े वर्गों में बाटा गया। ये वर्ग निम्न प्रकार से हैं—

(१) उत्तरी रेलवे — उसका १४ अंश, १९५२ को निर्माण किया गया।

इसमें ई० आई० आर० का पश्चिमी भाग, ई० पी० रेल्वे, बी० बी० एण्ड सी० आई० आर० की आगरा, कानपुर लाईन तथा अवध-तिरहुत रेल्वे सम्मिलित की गई।

(२) पश्चिमी रेल्वे:— यह ५ नवम्बर, १९५१ को बनी। इसमें बी० बी० एण्ड सी० आई० आर०, सीराष्ट्र, चोबपुर, बीकानेर, चम्पूर, राजस्थान और कच्छ रान की रेलें हैं।

(३) मध्य रेल्वे:— इनको भी ५ नवम्बर, सन १९५१ को निर्मित किया गया। इसमें बी० बी० एण्ड सी० आई० आर० की ब्राह्मगढ़ भाग, बी० आई० पी० आर० सिधिया, धौलपुर और निजाम राज्या की रेलें मिलाई गईं।

(४) दक्षिणी रेल्वे:— यह १४ अप्रैल, १९५१ को बनी। इसमें एम० एर एम० एम० रेलवे, मैसूर रेलवे तथा दक्षिण भारत की रेलें सम्मिलित हैं।

(५) उत्तरी-पूर्वी रेल्वे:— यह १४ अप्रैल, १९५२ को बनाई गई। इसमें लखनऊ, कानपुर से पूर्व की ई० आई० रेल्वे, छपरा से पूर्व अवध-तिरहुत रेल्वे शामिल हैं।

(६) पूर्वी रेल्वे:— इसका निर्माण १ अप्रैल, १९५५ को हुआ। इसमें तीन डिवीजन को छोड़कर समस्त ईस्ट इण्डियन रेल्वे हैं।

(७) दक्षिणी-पूर्वी:— यह भी १ अगस्त, १९५५ को बनाई गई। इसमें बंगाल नागपुर रेलवे शामिल हैं।

(८) उत्तरी पूर्वी सीमा रेल्वे:— इसका बन्ध १५ जनवरी, १९५८ को हुआ। इसमें अरुण रेल्वे सम्मिलित हैं।

रेलों के पुनर्वर्गीकरण (Regrouping of Railways) के लाभ

रेलों के इस पुनर्वर्गीकरण से भारतीय रेलों की कार्यक्षमता बढ़ी है तथा व्यय में कमी हुई है। अमेरिका आदि पश्चिमी देशों में रेलों को बड़े बड़े भागों में बांटा गया है, जिससे रेलों में अभूतपूर्व उन्नति हुई है।

रेलों का प्रशासन सर्वप्रथम पी० हज्जू० डी० के अन्तर्गत होता था परन्तु सन् १९०५ में रेलों के प्रबन्ध के लिए एक रेल्वे बोर्ड बनाया गया। सन् १९२६ में आकरमं समिति की शिफारिश के अनुसार रेलवे क्रिया परामर्श समिति की नियुक्ति की। सन् १९४६ में एक रेलवे क्रिया परिषद् (Railway Rates Tribunal) की स्थापना की गई, जो अनुचित रेल किराया की दरों के सम्बन्ध में शिकायतें सुन सके।

प्रथम योजना के अन्तर्गत रेलों के लिए ४०० करोड़ रु० रसे गये थे, परन्तु वास्तव में ४२३.७३ करोड़ रु० खर्च हुआ। इस समय रेल्वे इन्डियन तथा हिन्दी बनाने के भी प्रयत्न चल रहे। चित्तूरन तथा टाटा के कारखानों द्वारा इन्डियन बनाने का काम मुचाद रूप से आरम्भ हुआ तथा मद्रास के निकट चेन्नूर कोच फैक्ट्री द्वारा हिन्दी निर्मित किये जाने लगे।

द्वितीय योजना में ११०५ करोड़ रु० के व्यय का अनुमान किया गया। देश में इस समय ३५,००० मील लम्बी रेलें हैं। परन्तु फिर भी रेलों की अत्यधिक कमी है। रेलों में अधिक भीड़ तथा माल के ठुकिंग करने में अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ती है। विदेशी विनिमय के अभाव तथा दूसरे और आवश्यक कार्यों के कारण नई रेलवे लाइन बनने में कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हैं। अभी यही कहा जा सकता है कि ये कठिनाइयाँ भविष्य में भी बनी रहेंगी।

सड़क यातायात

भारत में यातायात के साधनों में सड़कों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। भारत मुख्यकर ग्रामों का देश है, अतः शहरों तथा गाँवों को मण्डियों के साथ मिलाने के लिए सड़क ही एक सरता तथा सुगम यातायात का साधन है। किन्तु यह दुःख का विषय है कि इतना होते हुए भी भारत में सड़कों का पर्याप्त विकास नहीं हो सका। १६वीं सदी के मध्य तक सड़कों की बहुत कमी थी। सन् १८५५ में केन्द्र तथा प्रान्तों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में बहुत सड़कें बनीं। सड़क विकास के लिए सरकार ने सन् १९०७ में एक सड़क विकास कमेटी की नियुक्ति की, जिसे J. J. Aker Committee कहते हैं। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि पेट्रोल पर दो आना प्रति गैलन से कर लगाया जाय और इसकी आय को एक सड़क विकास कोष में जमा किया जाय। सरकार ने इस सिफारिश को मानते हुए सन् १९३४ में सड़क विकास कोष की स्थापना कर दिया।

सन् १९४३ में भारत सरकार ने सड़क विकास पर विचार-विमर्श करने के लिए नागपुर में एक सम्मेलन बुलाया, जिसने सड़क विकास के लिए १० वर्षीय योजना बनाई, जिसे नागपुर योजना (Nagpur Plan) कहते हैं। इस योजना ने सड़कों को तीन वर्गों में बांटा है :—

(१) राष्ट्रीय मार्ग :—ये ग्राड ट्रंक सड़कों के अनुसार रहेंगे तथा राज्यों की राजधानी और बन्दरगाहों को मिलायेंगे। इनके निर्माण और देखभाल का उत्तरदायित्व भारत सरकार के अधीन होगा।

(२) राज्य मार्ग —ये मार्ग राज्य में व्यापार के मुख्य केन्द्रों को जोड़ेंगे और इनका आर्थिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होगा।

(३) जिला और ग्राम्य सड़कें :—जिले के महत्वपूर्ण स्थानों को रेलों तथा अन्य राष्ट्रीय मार्गों से जोड़ेंगी। इनकी जिम्मेदारी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं (म्यूनिसिपल बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड) के पास रहेगी। ग्राम्य सड़कें अधिकतर गन्धी होती हैं, जो गाँवों को मण्डियों से जोड़ती हैं। इनका उत्तरदायित्व ग्राम्य पंचायत पर होता है।

इस योजना का लक्ष्य यह था कि विभिन्न कृषि क्षेत्र में कोई भी गाँव मुख्य सड़क से ५ मील से अधिक दूरी पर नहीं रहे।

विस्त सम्बन्धी कठिनाइयों तथा बाद में देशके विभाजन के कारण नागपुर योजना का महत्व समाप्त हो गया ।

प्रथम योजनाकाल में सड़कों के विकास के लिए कुल व्यय १५५ करोड़ रु० का हुआ । इस योजना के अन्त तक हमारे देश में सड़कों की कुल लम्बाई ३,२०,००० मील थी । द्वितीय योजना में सड़क कार्यक्रम के लिए कुल २५१ करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई थी । आशा है कि इस योजना के अन्त तक १८०० मील लम्बी नई सड़कें बन बायेगी । इस समय आर्थिक व सञ्चालन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सड़कों पर विशेष बज्र दिया जा रहा है ।

मोटर यातायात

मोटरों सड़क यातायात के सर्वोत्तम साधन हैं । इनके द्वारा मनुष्य और माल को शीघ्रता से पहुँचाया जा सकता है । परन्तु हमारे देश के आकार और जनसंख्या को देखते हुए मोटरों की संख्या बहुत कम है । भारत में प्रति १३५० व्यक्तियों के पीछे एक मोटर है, जबकि अमेरिका में ३ व्यक्तियों के पीछे १ तथा इंग्लैंड में १५ के लिए १ है ।

मोटरों की संख्या की इस कमी के कारण मोटर यातायात बहुत समय तक अर्धवर्धित रहा और रेलों के साथ अत्यधिक प्रतियोगिता करने लगी, जिससे रेलों को बहुत हानि उठानी पड़ी ।

रेल-सड़क प्रतियोगिता

सन् १९३२ में रेल-सड़क प्रतियोगिता की जाय के लिए मिचल कर्नैस समिति नियुक्त हुई । इसने मोटर यातायात प्रतिक्रम के लिए उपयुक्त सुझाव दिये । सन् १९३७ में बैबवुड समिति ने मोटर परिवहन की अनुचित प्रतियोगिता से रेलों की रक्षा के लिए सुझाव दिये ।

अतः १९३६ में मोटरगाडी अभिनियम पास हुआ । इसके अनुसार मोटरों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गए, जैसे—लाइसेंस लेना, मोटर में सवारियों की निश्चित संख्या होना, नियत समय तथा काम करने के घण्टे पालन करना, बीमा कराना आदि प्रमुख हैं ।

रेल-सड़क समन्वय

(Rail Road Coordination)

मोटर यातायात का नियन्त्रण करना ही देश के आर्थिक विकास में पर्याप्त नहीं है । इसके साथ ही यह आवश्यक है कि मोटर परिवहन का इस प्रकार विकास हो कि यह रेलों के साथ प्रतियोगिता करने के स्थान पर उनके लिए पूरक सिद्ध हों । सड़कों को रेलों के समानान्तर चलाने की अपेक्षा उनका इस प्रकार निर्माण किया जाय कि वे आन्तरिक मार्गों में चला रेलों नहीं हैं, सामान तथा यात्रियों के आवागमन का प्रक्रम करें ।

दूसरी ओर रेल और सड़क के क्षेत्रों को सीमित किया जाना आवश्यक है । रेलों

का क्षेत्र अधिक बोझिल और दूरी के आवागमन के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि मोटर का क्षेत्र मध्यम बोझों और कम दूरी तथा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए।

समानान्तर चलने वाली सड़कों के लिए यह सुझाव दिया गया है कि सड़क परिवहन का स्वाभित्व विदलीय हो (1) निजी स्वामी (11) राज्य सरकार, (111) रेलें। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए कुछ रायों ने इस ओर ध्यान दिया है। अगस्त, १९५६ में सरकार ने एक रेल-सड़क संयोजन समिति नियुक्त की, जो रेल-सड़क यातायात में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुझाव देगी।

देश के औद्योगिक विकास में यातायात के विभिन्न साधनों का उन्नत होना आवश्यक है। रेल-सड़क समन्वय ही नहीं, परंतु समस्त यातायात के साधनों में सामंजस्य होना आवश्यक है। सड़क परिवहन निगम १९५० के अधिनियम के द्वारा यह आशा की जा सकती है कि रेल तथा सड़क यातायात में परस्पर अधिक समन्वय सम्भव हो सकेगा।

मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण

रेल-सड़क प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए कुछ वर्षों से सरकार ने मोटर परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने की नीति अपनाई है। अधिकांश राज्यों ने सड़क यातायात का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में यह कहा गया है कि इससे कार्यक्षमता बढ़ेगी, यात्रियों को सुविधाएँ मिलेंगी, कर्मचारियों की दशा में सुधार होगा, व्यय में कमी होगी और सरकार की अतिरिक्त आय होगी।

परन्तु वास्तव में जिन राज्यों में राष्ट्रीयकरण हो चुका है जैसे बम्बई, यू. पी., दिल्ली आदि में वहाँ ये सब आशाएँ पूरी हुई नहीं हुई हैं। अतः योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि सड़क परिवहन राष्ट्रीयकरण की धीमी गति हो और १९५० के अधिनियम के अन्तर्गत निगमों की स्थापना की जाय।

जल-यातायात

यातायात के साधना में जल यातायात बहुत प्राचीन तथा सरल है। यह भारी बोझों के इसके मुख्य वाले सामान को दोने में अत्यधिक उपयुक्त है, जैसे कोयला, लकड़ी तथा कच्चा माल। इसके सार ही मुरादा के लिए एक सुदृढ़ जहाजी घेरे की अत्यन्त आवश्यकता है।

आन्तरिक जल-मार्ग

हमारे देश का विस्तार क्षेत्रफल होते हुए भी आन्तरिक जल मार्गों का विशेष विकास नहीं किया गया है।

भारत में इस समय २०,००० मील लम्बे जल-मार्ग हैं, जिनमें ८००० मील नदियों के तथा शेष १२,००० मील नहरों के। इन नदियों में ३००० मील तक नाव चल सकती है और नहरों के उन्नत होने पर उनमें स्टीमर तथा नावें चल सकती हैं।

सरकार अब बल-मार्गों के विकास की ओर अधिक प्रयत्नशील है। सन् १९४५ में केंद्रीय बल-मार्ग विचारों तथा नौकावाहन आयोग स्थापित किया गया, जिसका नाम बाद में केंद्रीय बल-विद्युत आयोग रखा गया। बहुउद्देश्यीय नदी-घाटी योजनाओं में नौकावाहन को समुचित स्थान दिया गया है। सन् १९५२ में गंगा ब्रह्मपुत्र बल-परिवहन मण्डल की स्थापना की गई। केंद्रीय सरकार इस बोर्ड के लिये २ लाख रु० प्रति वर्ष की राशि देती है।

द्वितीय योजना में ३४० लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से ११५ लाख रु० अधिकतम नहर, ४३ लाख रु० पश्चिमी तट की नहरों के लिये तथा शेष गंगा-ब्रह्मपुत्र बोर्ड की योजनाओं के लिये है। इस विकास के कार्यक्रमों में बल-मार्गों को गहरा करना, रेडियो, टेलीफोन सिग्नल की व्यवस्था करना आदि मुख्य हैं। इन सब पर दृष्टिपात करने से यह आशा की जा सकती है कि हमारे आन्तरिक बल-मार्गों का फिर से अभिन्न उन्नयन हो जायगा।

समुद्रीय यातायात

भारत में ३३३५ मील का विशाल समुद्रतट है और यह पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओर के व्यापार मार्ग में स्थित है। प्राचीनकाल में हमारा देश समुद्रीय यातायात में बहुत उत्तम था, परन्तु रटीम शिप के आविष्कार से भारतीय जहाजों की महत्वपूर्ण स्थिति समाप्त हो गई। अंग्रेजी कंपनियों ने भारत के तटीय तथा समुद्रीय व्यापार में एकाधिकार प्रप्त कर लिया था। इन कंपनियों ने भारतीय जहाजी कंपनियों से प्रतियोगिता करने के लिए भाड़े कम करने की नीति अपनाई।

सन् १९०३ में इण्डियन मरकेन्टाइल तथा मैटिन समिति ने तटीय व्यापार को भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित रखने का सुझाव दिया, परन्तु सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया। सन् १९०८ में श्री हाजी ने तटीय व्यापार को भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखने के आशय का एक बिल पेश किया, परन्तु उसे भी सरकार ने नहीं माना। सन् १९३७ में सर गबनरबी ने समुद्रीय यातायात में सुधार के हेतु एक बिल का प्रस्ताव किया, परन्तु सरकार के कानों तक वह तक न रंगी।

द्वितीय महायुद्ध के समय जहाजों की कमी अनुभव हुई और भारतीय जहाजों के विकास के लिये एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता हुई। इस कारण सन् १९४५ में पुनः निर्माण नीति उपसमिति नियुक्त की गई जिसने १९४७ में अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति ने सिफारिश की कि भारत को अपने तटीय व्यापार का १०० प्रतिशत, बर्मा व पड़ोसी राज्यों से व्यापार का ७५ प्रतिशत तथा अन्य दूर के देशों से व्यापार का ५० प्रतिशत अपनेपना चाहिये। सरकार के इस सुझाव को मानने के बाद भारतीय जहाजी व्यापार की काफी उन्नति हुई।

१९५० से तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित कर दिया गया और अब लगभग सारा तटीय व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा ही होता है। भारतीय जहाजों ने दूर देशों के

व्यापार में भी भाग लेना आरम्भ कर दिया है। जहाज निर्माण का प्रमुख केन्द्र विशाखापट-
नम् है जो भारत सरकार के अधीन है। सन् १९४७ में सरकार ने प्रति निगम दस करोड़
की पूँजी से तीन जहाजी निगम स्थापित करने की घोषणा की, जिसमें से १९५२ में ईस्टर्न
शिपिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। इसका क्षेत्र आस्ट्रेलिया और सुदूरपूर्व निश्चित
किया गया है। सन् १९५६ में एक पश्चिमी जहाजी निगम को भी स्थापना हुई, जिसका क्षेत्र
लाल सागर, पारस की खाड़ी, पोर्लैंड तथा रूग है।

प्रथम योजना में जहाजों के लिए २६३ करोड़ ६० की व्यवस्था की गई थी जिसमें
से योजना के अन्त तक १८ करोड़ ४० व्यय हुआ। शेष ८ करोड़ ४० द्वितीय योजना में
काम में लिया गया। योजनाकाल में जहाजी बेटे में २,१५,००० टन वृद्धि करना था जिससे
योजना के अन्त तक कुल भार ६ लाख टन हो जाये। इस योजना में जहाजों के लिए ३७
करोड़ ४० की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के शेष ८ करोड़ ४० भी काम
में लाये जायेंगे। जहाजी मामलों की देखभाल करने के लिए एक जहाजी संचालक नियुक्त
किया गया है। १९५६ में जलमार्ग-विकास के सम्बन्ध में परामर्श देने हेतु राष्ट्रीय जलपोत
मण्डल की भी स्थापना की गई है।

वायु यातायात

यह यातायात का सबसे तीव्र गति का माधन है। इसकी उन्नति विशेष रूप से द्वितीय
महायुद्ध के पश्चात् हुई। भारत में सर्वप्रथम १९११ में उड़ान आरम्भ हुई और प्रथम
राज्य में कुछ प्रगति हुई। १९२७ में नागरिक उड्डयन विभाग खोला गया और १९२८
में विभिन्न नगरों में पलाह ग कनच स्थापित हुए। १९२६ में दिल्ली लन्दन का वायु मार्ग द्वारा
सम्बन्ध स्थापित किया गया। सन् १९३२ में टाटा एयर लाइन और १९३३ में इण्डियन
नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई। द्वितीय महायुद्ध के समय हवाई यातायात की अधिक
उन्नति हुई। सन् १९४६ में हवाई यातायात लाइसेंसिंग बोर्ड स्थापित किया गया। इस
बोर्ड ने अनियमित रूप में वायुयान कम्पनियों को लाइसेंस दिये, जिससे उनमें अनुचित प्रति
योगिता होने लगी और बहुत सी कम्पनियों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी।

सन् १९५१ में एक वायु यातायात बाल समिति नियुक्त की गई, जिसने वायुयान
समितियों की संख्या में कमी करने उनका पुन संगठन करने और अथ सहायता देने के सुझाव
दिये। परन्तु फिर भी वायु यातायात में अन्वयस्था बनी रही। अतः सरकार ने सन् १९५३
में एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया, जिसके अनुसार दो कॉर्पोरेशन स्थापित किये गए—
(१) इण्डियन एयर लाइन्स कॉर्पोरेशन देश की आन्तरिक हवाई सेवाओं की व्यवस्था के
लिए और (२) एयर इण्डिया इन्टरनेशनल विदेशी हवाई सेवाओं के लिए। इन
दोनों के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए एक वायु यातायात समा भी स्थापित
की गई।

हवाई सेवाओं का नवीनीकरण और सस्ती हवाई सेवाएं प्रदान करने के लिए वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण किया गया।

प्रथम योजना के अन्तर्गत वायु यातायात के लिए ६५ करोड़ ६० लखे गए थे। दूसरी योजना में १६ करोड़ ६० इण्डियन एयर लाइन्स कॉर्पोरेशन के लिए तथा १४५ करोड़ ६० एयर इण्डिया इन्टरनेशनल के लिए निर्धारित किये गए थे।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वायु सेवाओं में बहुत उन्नति हुई है। डाक और यात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं और सेवाओं का विभिन्न दिशाओं में विकास हो रहा है।

प्रश्न

१. भारत में यातायात के विभिन्न साधनों की महत्ता बताइये।
२. भारत में रेलों के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिये।
३. रेलों के लाभ और हानि का वर्णन करिये।
४. भारत में सड़क यातायात का महत्त्व तथा वर्तमान स्थिति बताइये।
५. सड़क-रेल परिवहन सम्बन्ध के लिए अपने सुझाव दीजिए।
६. भारत में आन्तरिक जल यातायात के विकास के प्रयत्नों का वर्णन करिये।
७. भारत में समुद्री यातायात को उन्नत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?
८. भारतीय वायु यातायात के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिये। उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?



भारतीय प्रशुल्क नीति (Indian Tariff Policy)

किसी भी देश का विदेशी व्यापार वहा की व्यापार नीति पर निर्भर रहता है। १९वीं सदी के मध्य से इंग्लैंड ने उन्मुक्त व्यापार नीति (Free Trade Policy or Laissez Faire Policy) अपनाई थी। इस प्रकार उस समय विदेशी व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप वाछनीय नहीं समझा गया और अबाध व्यापार का युग कहा गया। इंग्लैंड के अनुसार ही भारत में यही नीति अपनाई गई अर्थात् निर्यात-आयात व्यापार पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई।

प्रथम महायुद्ध के समय सरकार का ध्यान देश के उद्योग-धंधों के विकास की ओर गया। १९१६ के औद्योगिक कमिशन ने देश में उद्योगों के विकास की सिफारिश की। यह तब ही सम्भव हो सकता था, जब सरकार सरक्षण की नीति ग्रहण करे। सन् १९२२ में एक सटकर आयोग की स्थापना हुई, जिसने सरक्षण नीति अपनाने की सिफारिश की। इस नीति के अनुसार उद्योगों को विवेचनात्मक सरक्षण दिया जायेगा। इस सिफारिश को स्वीकार करके सरकार ने १९२३ में एक सटकर बोर्ड (Tariff Board) नियुक्त किया, जिसका कार्य सरक्षण के लिए प्राचीन उद्योग की जांच कर उचित सिफारिश करना था। उद्योग को सरक्षण निम्नलिखित तीन शर्तों के पूरा करने पर ही दिया जा सकता था —

(१) जिस उद्योग के पास प्राकृतिक सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, जैसे कच्चा माल, शक्ति भूमि तथा बाजार।

(२) जिस उद्योग की उन्नति बिना सरक्षण के नहीं हो सके।

(३) जो उद्योग बाद में सरक्षण के बिना अपने पाव पर खड़ा हो सके अर्थात् विश्व बाजार में प्रतियोगिता का सामना कर सके।

इन तीन मुख्य शर्तों के अतिरिक्त आयोग ने कुछ अन्य बातों पर भी प्रकाश डाला, जैसे सरक्षणता देते समय प्राथमिकता उन उद्योगों को दी जाय जो बड़ी मात्रा में उत्पादन के व्यवस्था में होते हों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हों, जो देश की समस्त आवश्यकता की पूर्ति कम समय में कर सकें और जिन उद्योगों को विदेशी उद्योगों की हानिकारक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता हो।

तटकर आयोग की इस तीनदली योजना (Triple Formulae) की परीक्षा आलोचना की गई और कहा गया कि इस प्रकार नये उद्योगों का विकास देश में नहीं हो सकेगा। विवेचनात्मक संरक्षण नीति (Discriminating Protection Policy) की तीन छठें कड़ी बताई गई, जिसका पालन करना उद्योगों के लिए सम्भव नहीं हो सकेगा। फिर भी सरकार ने इन विचारों को स्वीकार कर लिया और तटकर बोर्ड की जाच के बाद लोहे तथा इस्पात, सूती वस्त्र, कागज, रियासलाई, चीनी, भारी रासायनिकों के उद्योगों को संरक्षण दिया गया और कोयला, सीमेंट, काँच और तेल के उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया।

द्वितीय महायुद्ध के समय नये नये उद्योगों की स्थापना हुई और सरकार ने आवश्यकता से अधिक कि सुद्ध के पश्चात् इन उद्योगों को संरक्षण दिया जा सकेगा। ३ नवम्बर, १९४१ को सरकार ने दो वर्ष के लिए एक तटकर बोर्ड नियुक्त किया, जिसका उद्देश्य संरक्षण देने के लिए सरकार को सुझाव देना था। संरक्षण प्राप्त करने के लिए तीन नयी छठें बताई गईं :—

- (१) जो उद्योग हट व्यापारिक आधार पर स्थित हों।
- (२) जिस उद्योग की उचित समय में विकास की सम्भावना हो।
- (३) जो उद्योग राष्ट्रहित के लिए आवश्यक हो।

इस बोर्ड ने ४२ उद्योगों को संरक्षण देने की सिफारिश की—३८ उद्योग युद्धकालीन और ४ पूर्वस्थित (सूती वस्त्र, इस्पात, कागज और चीनी)।

सन् १९४७ में तटकर बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। इसको दो विशेष कार्य दिये गये— (१) विदेशी वस्तुओं से देशी वस्तुओं के उत्पादन व्यय की अतिरिक्त के कारण की जाच करना तथा (२) न्यूनतम व्यय से देशी उत्पादन बढ़ाने के सुझाव देना। १९४८ में इस बोर्ड के निम्न कार्य थे :—

- (१) वस्तुओं के शोक और वैरीय मूल्य निर्धारित करना।
- (२) हल्के विदेशी माल के विरुद्ध भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना।
- (३) संरक्षित उद्योगों की समय समय पर जाच करना। इस जाच के कारण ३४ युद्धकालीन उद्योगों को संरक्षण दिया गया और ६ पुराने उद्योगों से संरक्षण हटाया गया (सूती वस्त्र, इस्पात, कागज, मेन्सियम क्लोरोहाइड्र, चांदी के तार खोचने का और चीनी उद्योग)। बाद में १ वर्ष के लिए चीनी उद्योग को संरक्षण दिया गया, जिसे अप्रैल, १९४७ में हटा दिया गया।

अप्रैल १९४६ में नया तटकर आयोग नियुक्त किया गया, जिसने जुलाई १९४७ में अपनी रिपोर्ट दी। इसकी मुख्य सिफारिशें ये थीं :—

- (१) स्थायी प्रशुल्क बोर्ड की नियुक्ति की जाय। इस सिफारिश को मानकर सरकार ने जनवरी, १९४७ में एक स्थायी प्रशुल्क बोर्ड नियुक्त कर दिया।

इस बोर्ड के प्रधान कार्य :—

- (i) सरक्षण देने के लिए उद्योगों को जाच करना ।
- (ii) सरक्षण की दरों में परिवर्तन करने की सिफारिश करना ।
- (iii) सस्ती विदेशी वस्तुओं के आयात रोकने के उपाय बताना ।
- (iv) सरक्षित उद्योग के अनुचित कार्यों को रोकना; जैसे मूल्य बढ़ाने के प्रयत्न आदि ।

(v) सरक्षण का मूल्यस्तर, जीवनस्तर और राष्ट्रीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है—यह बताना ।

(vi) उद्योगों पर व्यापारिक समझौतों के प्रभाव की जाच करना ।

(vii) सरक्षण देते समय निम्न बातों का ध्यान रखना :—

(१) देशी-विदेशी वस्तुओं का उत्पादन व्यय, विदेशी वस्तुओं का आयात मूल्य और उचित रिफ़ी मूल्य । इसके अतिरिक्त सरक्षण का कुल उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

(२) राष्ट्रहित में रक्षा व प्रमुख उद्योगों को सरक्षण देना ।

(३) अन्य उद्योगों के लिए — प्राकृतिक साधनों के होने, उत्पादन व्यय के कम होने तथा आरामनिर्भरता की सम्भावना होने पर सरक्षण देना ।

(४) कृषि उद्योगों को भी सरक्षण आवश्यक है ।

(५) आयात-दरों का प्रतिफल एक निश्चित भाग एक पृथक् विभाज कोष जमा किया जाय, जिसमें से उद्योगों को निम्न अर्थसाधना में सहायता दी जाय :—

(i) जो उद्योग मांग की पूर्ति कुछ अथ तक ही कर सकता हो ।

(ii) जिस उद्योग का प्रमुख उत्पादन कच्चा माल हो ।

(iii) जिस उद्योग की विभिन्न श्रेणियाँ पृथक् नहीं हो सकती ।

इस प्रकार स्थायी प्रशुल्क बोर्ड का स्थापित होने तथा उसके कार्यों को बढ़ाने के फलस्वरूप हमारे देश में उचित तटकर नीति स्थापित हो गई है, जो देश के औद्योगीकरण के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है ।

प्रश्न

(१) विवेचनात्मक सरक्षण नीति की समीक्षा कीजिये और उचित तटकर नीति के लिए अपने सुझाव दीजिये ।

भारत में मुद्रा विकास

भारत में आर्थिक सम्पन्नता के लक्षण अति प्राचीन युग में भी थे। पहले वस्तु-विनिमय (Barter) प्रचलित था, परन्तु इसमें कठिनाइयाँ होने से धीरे धीरे लोगों ने धातु की अपनाया और मुद्रा का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय में मुद्रा का प्रमुख हमारे देश में स्थापित हुआ, उस समय देश में विभिन्न मुद्रायें प्रचलित थीं। मुद्रा में समानता लाने के लिए सन् १८३५ में एक मुद्रा कानून बनाया गया। इसके अन्तर्गत १८० ग्रैन का चांदी का रुपया प्रामाणिक एवं असीमित रूप से बिचिमाया घोषित कर दिया गया। सोने की मोहर सरकारी खजाने में १५१:६० प्रति मोहर के अनुसार स्वीकार की जाती थी।

सन् १८७३ तक भारत की मुख्य मुद्रा चांदी का विक्रय हो गई और उसका निर्माण निर्बाध गति से होने लगा। परन्तु कुछ समय बाद चांदी के मूल्य में गिरावट आ गई, क्योंकि संसार के कुछ देशों में चांदी की नई खानें खुल गईं तथा यूरोप के कुछ देशों ने चांदी की मुद्रा का परिहाण कर दिया। भारत में रुपये की दलाली स्वतन्त्र रूप से होती थी, अतः चांदी का मूल्य रुपये के मूल्य में गिरता गया। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने सन् १८८२ में हर्शेल समिति (Herschell Committee) नियुक्त की। इस समिति ने रुपये की स्वतन्त्र दलाली बन्द कर स्वर्णमान ग्रहण करने की सिफारिश की। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर रुपये की स्वतन्त्र दलाली बन्द कर दी। परन्तु कुछ समय बाद देश में उद्योग-व्यापार के विकास के साथ ही रुपये की कमी महसूस होने लगी। देश में रुपये की कमी होने से ६० का स्टर्लिंग मूल्य बढ़ने लगा और १८८८ तक वह प्रति ६० १ शि० ४ पैसे हो गया।

इस पर सरकार ने फोर्लर समिति (Fowler Committee) नियुक्त की, जिसने कहा कि ६० की विनिमय दर १ शि० ४ पैसे निर्धारित कर दो चाप और देश में सोने के सिक्के प्रचलित हो। अंग्रेजी सावरेन प्राण मुद्रा घोषित कर दी जाय।

सरकार ने ये सिफारिशें मान लीं, परन्तु निम्न की टक्काल की एक शाली सावरेन डालने के लिए वहां के विरोध के कारण स्थापित न हो सकी। सरकारी खजाने में सावरेन लोगों को दिये जाने लगे। इस ही समय निरन्तर अकाल पड़े, जिसके कारण लोग चांदी के सिक्के चाहने लगे और सोने के सावरेन खजाने में वापिस बना

होने लगे। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने रुपया डालना फिर आरम्भ कर दिया और इट दलाई से जो लाभ होने लगा, उसको एक स्वर्णमान सुरक्षित कोष (Gold Standard Reserve) में रखा जाने लगा। भारत में इसका विरोध होने पर भी कोई सुनाई नहीं हुई।

इस समय विदेशी व्यापार भारत के पक्ष में था, अतः इंग्लैंड से सोना भारत को आने लगा, परन्तु स्वर्णमान सुरक्षित कोष में जो लन्दन में स्थापित किया गया था, रुपयों की दलाई का लाभ खमा करने के लिए भारत से सोना इंग्लैंड को भेजा जाता था। इस प्रकार सोने के आने-जाने के कारण अन्तर्व्यय होता था। इस लचके को बचाने के लिए भारत सचिव द्वारा इंग्लैंड में कांसिल ड्राफ्ट (एक प्रकार की हुण्डी) १ शि० ४ १/८ पैसे प्रति रु० की दर से बेचे जाने लगे। इस पर ब्रिटेन के व्यापारी भारत को सोना भेजने के स्थान पर कांसिल ड्राफ्ट खरीद कर भेजने लगे, जिनके बदले में भारतीय व्यापारी भारतीय सरकार से रुपया प्राप्त कर लेते थे।

सन् १९०७ से व्यापार भारत के विपक्ष में हो गया, जिससे भारत में स्टर्लिंग की अधिक माग बढ गई। ने भारत में रिवर्स कांसिल ड्राफ्ट बचना आरम्भ किया, जिनकी इंग्लैंड के व्यापारी सरकार से मुना कर स्टर्लिंग प्राप्त कर सकते थे। इसकी दर १ शि० ३ १/४ पैसे प्रति रुपया थी। इस प्रकार भारत में स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard) की स्थापना हुई सन् १९०० से १९१७ तक भारत में स्वर्ण विनिमय मान रहा जिसके पल्लवस्वरूप सरकार रुपयों के बदले लन्दन में स्टर्लिंग के रूप में देती थी और सुरक्षित कोष लन्दन रखा जाता था।

इस पद्धति से सोने की बचत होती थी। क्योंकि देशमें सोने का खिस्का नहीं चलता था तथा सुरक्षित कोष का सोना दोनों देशों की भुआ के सुरक्षित कोष का काम देता था। परन्तु कोई सरकारी बैंक न होने के कारण इसका प्रबन्ध दोषपूर्ण था।

इस मान की असफलता का मुख्य कारण चादी के मूल्य में वृद्धि होना था। व्यापार भारत के पक्ष में होने के कारण रुपया की माग बढ गई और इसलिए रु० का टाणना आवश्यक हो गया। परन्तु युद्ध के कारण चादी का आयात करना कठिन था। अतः विनिमय दर १ शि० ४ पैसे से बढकर अगस्त १९१७ में १ शि० ५ पैसे हो गई और दिसम्बर १९१७ में २ शि० ४ पैसे।

इस स्थिति को देखते हुए सरकार को विवश होकर स्वर्ण विनिमय मान को त्यागना पड़ा। सन् १९१६ में डेलिगमन स्मिथ समिति नियुक्त की गई, जिसने रुपये की विनिमय दर २ शि० (स्वर्ण) निश्चित करने की सिफारिश की। इस ऊँची दर से मूल्यों में वृद्धि रुक जायगी और इंग्लैंड को जो राशि (Home Charges) प्रशासन के व्यय के लिए भेजी जाती थी, उसमें बचत होगी।

सरकार ने यह सिफारिश मान ली, परन्तु इसमें सरकार को सफलता नहीं मिली।

क्योंकि जनवरी १९२० से विदेशी व्यापार भारत के निर्यात में हो गया, और इस कारण रुपये की माग में भारी कमी आ गई। विनिमय दर में सट्टा शुरू हो गया, क्योंकि ऊँची दर का लाभ उठाने के लिए भारतीय व्यापारी लन्दन में अपना देय चुकाने लगे। रुपये स्टर्लिंग की माग बढ़ गई और सरकार को २ शि० (सोने) की दर को स्थिर रखना प्रसम्भव हो गया। सितम्बर १९२० तक सरकार को ३५ करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी और उसके बाद सरकार द्वारा विनिमय दर निश्चित नहीं की गई।

१९२१-२२ के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ। व्यापार भारत के पक्ष में हो गया और बजट में सङ्गण हुआ। अक्टूबर १९२४ में विनिमय दर १ शि० ६ पैस हो गई। अगस्त १९२५ में हिस्सन्सग कमोशन नियुक्त हुआ, जिसने जुलाई, १९२६ में तीन मुख्य सिफारिशें कीं—

- (१) देश में स्वर्ण धातुमान (Gold Bullion Standard) स्थापित किया जाय।
- (२) एक रिजर्व बैंक की स्थापना की जाय।
- (३) रुपये की विनिमय दर १ शि० ६ पैस रखी जाय।

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और १९२७ के कानून के अनुसार सोने के तोले का मूल्य २१ द० ३ आ० १० पाई रखा गया और विनिमय दर १ शि० ६ पैस निर्धारित की गई। सरकार २१ द० ३ आ० १० पा० प्रति तोले की दर से ४० तोले सोने की छक् खरीद सकती थी और मुगलान करने के लिए (४०० आँठ से कम नहीं) पीस बेच सकती थी।

विनिमय दर के निश्चित करने में बड़ा वादविवाद हुआ। बहुमत १ शि० ६ पैस के पक्ष में था परन्तु सर पुरपोसमदास ठाकुरदास ने १ शि० ४ पैस की दर रखने की माग की।

१ शि० ६ पैस के पक्ष में यह कहा गया कि यह दो वर्गों से बालू है और मूल्य तथा मजदूरी की दरें इस अनुपात से स्थिर हो गई हैं। दूसरे दर बदलने से भारत के विदेशी व्यापार में भी अस्थिरता आ सकती है। ठेके और सौदे अधिकतर १ शि० ६ पैस की दर के समय ही हुए हैं, अतः उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। १ शि० ४ पैस की दर रखने से इंग्लैंड को जो 'होम चार्ज' दिये जाते थे, उनमें श्रद्धा होगी। इससे बजट में भी सङ्गण न रह सकेगा।

इसके विपरीत अल्पमत का यह कहना था कि विनिमय दर १ शि० ४ पैस अधिक समय (सन् १८८८ से १९१७) तक रही है। इस कारण मूल्य और मजदूरी ऊँचे अनुपात से स्थिर नहीं हुई हैं। १ शि० ६ पैस की दर से भारत में आयात अधिक होगा और निर्यात कम और इस प्रकार व्यापार निर्यात में हो जायेगा, जिससे व्यापार में मन्दी आयेगी, मजदूरी की दरें घटायी जायेंगी तथा हड़ताल आदि सबक होगा। ऊँची दर रखने से मजदूरों को

लाभ होगा और श्रृंखला किसानों की दुदशा । १ शि० ४ पैसे की दर रखने से हिाव-किताव रखने में सुविधा होगी, क्योंकि इस दर से एक पौंड पूरे १५ रुपये के बराबर हो जायेगा ।

परन्तु सरकार ने रुपये की दर १ शि० ६ पैसे ही निर्धारित की । यह स्थिति २१ सितम्बर, १९३१ तक रही, जबकि इंग्लैंड ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया । भारत को भी इंग्लैंड का अनुसरण करना पड़ा । अब रुपये का सबध सोने के स्थान पर स्टर्लिंग के साथ हो गया और भारत स्टर्लिंग विनिमय मान पर आ गया १ शि० ६ पैसे की दर से सरकार असमीत मात्रा में स्टर्लिंग खरीद और बेच सकती थी । इसका परिणाम यह हुआ कि सोने का मूल्य बढ़ गया और भारत से सोने का निर्यात इंग्लैंड होने लगा । स्टर्लिंग विनिमय मान की भारत में आलोचना की गई, क्योंकि यह कहा गया कि स्टर्लिंग का सोने के भाव में जो उतार-चढ़ाव होगा, वही रुपये के भाव में भी होगा । परन्तु स्थिति को देखते हुए स्टर्लिंग विनिमय मान ही उचित था क्योंकि बहुत से देशों ने स्वर्णमान को त्याग दिया था और भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर इंग्लैंड से ही होता था । सन् १९३५ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया स्थापित किया गया ।

१९३६ में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने से चादो का मूल्य बढ़ गया और लोग चांदी के सिक्कों को उपद्रव करने लगे । सरकार ने कम चांदी की मात्रा के नये चादो के सिक्के निकाले और पुराने सिक्कों को वापस ले लिया । इस ही समय रेशम की बहुत कमी हुई, तब १९४१ में ताये के छेद वाले पैसे निकाले गए और पीतल की इकत्री, दुधनी । युद्धकाल में पत्र-मुद्रा का बहुत अधिक प्रचार हुआ । सितम्बर, १९१६ में १८० ६ करोड़ रुपये के नोट्स निर्गमित किए गए थे, जो जून १९४६ में बढ़कर १३७२६ करोड़ रुपये के हो गए । १ रुपये तथा २ रुपये के नोटों को भी प्रसारित किया गया । युद्धकाल में इंग्लैंड में भारत के खाते अधिक स्टर्लिंग सिक्योरिटीज जमा होने लगे, क्योंकि युद्ध का आवश्यक माल अधिकतर इंग्लैंड भारत से खरीदा था और उसका तत्काल मूल्य न चुकाकर भारत के खाते में स्टर्लिंग प्रतिभूतिया जमा कर देता था, इनको (Sterling Balances) पौंड-पावने कहते हैं । इस खाते में १९४७ तक १७०६ करोड़ ६० जमा हो चुके थे, जो बाद में मई, १९५७ में घटकर ४६६ करोड़ रुपये रह गए ।

युद्ध के पश्चात अमेरिका में २ सत्य ए स्थापित की गई—(१) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (I M F) जिसका कार्य विभिन्न देशों की मुद्रा की विनिमय दर की स्वीकृति देना था, और (२) अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक (World Bank), जिसका कार्य देशों के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देना था । इन संस्थाओं के स्थापित होने से रुपये एक स्वतंत्र मुद्रा घोषित कर दिया गया और विनिमय दर १ शि० ६ पैसे प्रति रुपया तथा ३० २३ सेंट (Cents) प्रति रुपया कर दी गई ।

देश के निमाजन के फलस्वरूप मुद्रा नोटी भी प्रभावित हुई । ३० सितम्बर, १९४८ तक दोनों देशों में एक मुद्रा रही और रिजर्व बैंक द्वारा पाकिस्तान के निचे भी नोट छापे

भारत में बैंकिंग व्यवस्था

किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी सुव्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली पर अधिक निर्भर रहता है। भारत की कृषि, उद्योग तथा व्यापार की अवनत दशा का एक मुख्य कारण अपर्याप्त बैंकिंग व्यवस्था है।

भारत में बैंकिंग व्यवसाय अति प्राचीन काल से लोग करते थे। यद्यपि उस समय आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के अनुसार कार्य नहीं होता था। हुण्डियों का चलन भी भारत में बहुत प्राचीन है। इस व्यवसाय में लगे लोग सेठ, साहूकार, सर्गई, मुल्तानिया आदि कहलाते थे। ये रुपया जमा करते थे, व्याज पर रुपया उधार देते थे और सरकार की ओर से लगान भी वसूल करते थे।

भारत में अभी भी देशी बैंकिंग प्रणाली (Indigenous Banking System) अधिक महत्वपूर्ण है। देशी बैंकर अधिकतर व्यक्तिगत जमानत पर छोटे व्यापारियों को ऋण देते हैं, हुण्डियों का लेनदेन करते हैं, रुपया जमा करते हैं और अपना व्यापार भी करते हैं। देशी बैंकर अनेक छोटे छोटे व्यापारियों की वित्त व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, जो व्यापारिक बैंकों की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते।

देशी बैंकर की इतनी महत्वपूर्ण स्थिति होते हुए भी वे अभी तक असंगठित हैं और पुरानी विधियों से कार्य करते हैं, अधिक व्याज की दर लेते हैं और हिसाब-किताब ठीक ढंग से नहीं रखते। इस प्रकार ये आधुनिक मुद्रा बाजार तथा रिजर्व बैंक से सम्बन्धित नहीं हैं।

यह दु एल का विषय है कि इन बैंकरों की महत्ता पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इनकी उन्नत किया जा सके तो देश की आर्थिक प्रगति अधिक तीव्र गति से सम्भव हो सकती है। इनका सुसंगठित करने के लिये इन्हे दूसरे अनुसूचित बैंकों के समान रिजर्व बैंक से सम्बन्धित करना चाहिये तथा उन्हें वेसी ही सुविधाएं मिलनी चाहिये। इन बैंकों को अपने लेखे उचित ढंग से प्रमाणित कराकर प्रकाशित कराने के लिये प्रेरित करना चाहिये और उन्हें अपने बैंकिंग व्यापार को अपने व्यापारिक धन्धे से पृथक् रखना चाहिये।

१९३८ में रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को अपने साथ शृंखलाबद्ध करने की योजना बनाई, परन्तु यह स्वीकार नहीं की गई। १९५१ में केन्द्रीय सर्गई सभा की स्थापना द्वारा देशी बैंकरो को रिजर्व बैंक के साथ सम्बन्धित करने का समर्थन किया गया। इस सभा की

सिमारियों पर ही यह कहा जा सकेगा कि देशी बैंकर किस सीमा तक बैंकिंग प्रणाली के साथ सम्बन्धित हो सकेगे।

आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का सूत्रपात हमारे देश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा बैंकिंग कार्य अपनाये जाने से हुआ जिसके कार्यालय कलकत्ता-बम्बई में खोले गये। अत्यधिक सट्टे की प्रवृत्ति के कारण तन् १८२६-३२ के व्यापारिक लूट के कारण इन एजेन्सी एहों का अन्त हो गया। सबसे प्रथम आधुनिक बैंक सन् १६८८ में मद्रास में खोला गया। दूसरा बैंक बम्बई सरकार ने सन् १७२४ में खोला। इसके बाद मद्रास में तथा अन्य स्थानों में बैंक खुले। सन् १७७० में Bank of India खुला, परन्तु १८०६-३२ के व्यापारिक सबटकाल में यह फल हो गया।

१९वीं सदी के आरम्भ में १८०६ में प्रेसीडेन्स बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। सन् १८४० में ऐसा ही एक बैंक बम्बई में तथा १८४३ में मद्रास में खोला गया। सट्टेबाजी के कारण बम्बई का बैंक १८६८ में फल हो गया। इसके बाद सरकार ने बंगाल और मद्रास वाले क्षेत्रों के अंश देव दिये और इस प्रकार वे समाप्त हो गये। सन् १८७१ में इन बैंकों के समान सरकारी बैंक इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया बना। इस पर सरकार का नियंत्रण था यह ६ महीने से अधिक श्रृण नहीं दे सकता था, विदेशी विनिमय का कार्य नहीं कर सकता था, यह अचल सम्पत्ति व अपने अंश की जमानत पर श्रृण नहीं दे सकता था। इस बैंक के संचालक सरकार की ओर से नियुक्त किये जाते थे।

परन्तु इस बैंक के कुछ दोष थे और इसी कारण इसकी आलोचना की जाती थी। यह बैंक सरकारी होने के नाते विशेष प्रतिष्ठा रखता था और अनुचित लाभ कमा रहा था। यह विदेशी पणों को अधिक सुविधा देता था। इसका प्रमुख विदेशियों के हाथ में था, अतः प्रमुख पद विदेशियों को ही दिये जाते थे। इन दोषों के कारण १ जुलाई, १८५५ को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसका नाम 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया' रख दिया।

मिश्रित पूंजी वाले बैंक

सन् १८६० में इण्डियन कम्पनीज एक्ट के पास हो जाने पर सीमित दायित्व का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया। इससे लोग अविश्वसित क्षेत्रों को खरीदने के लिये उत्साहित हो सके। इस ही समय अमेरिकन एशुयुड के कारण बैंकों को प्रोत्साहन मिला। अतः १८६५ में कलकत्ता-बम्बई बैंक, १८७४ में अलायन्स बैंक, ऑफ सिमला, १८८१ में अथर्व कर्मस्थान बैंक, सन् १८८५ में पञ्जाब नेशनल बैंक और १८९१ में पीपल्स बैंक खुले। आरम्भ में सभी बैंकों का संचालन अंग्रेज करते थे। १८९३ में पीपल्स बैंक और सन् १८९३ में सिमला के बैंक बन्द हो गये।

सन् १८९५ के स्वदेशी आन्दोलन से भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ। १८९५ से १८९३ तक अनेक बैंक स्थापित हुए। इसके बाद तो देश में बैंकों की बाढ़ सी आ गई।

सन् १९१३ में भारतीय बैंकों के लिये एक संवत्काल उपस्थित हुआ। १९१४ से १९१८ तक लगभग ६५ बैंक फेल हुए। सन् १९१६ व १९२५ के बीच में ५१ करोड़ की पूंजी वाले ८४ बैंक फेल हुए।

बैंकों के फेल होने के कारण

देश की जनता का बैंकों पर कोई विश्वास नहीं था। जब भी बैंक जमा राशि लौटाने में विलम्ब करते, समस्त ग्राहक घबड़ा जाते थे और तब एक साथ अपना रुपया निकालने के लिये बैंक पर जुट जाते थे और इस प्रकार बैंक का दिवाला निश्चल जाता था। बैंकों के प्रारम्भिक काल में इन स्थिति को उत्पन्न करने वाले मुख्य कारण (१) कुशल एवं अनुपयुक्त संचालकों का अभाव (२) बैंकों में वार्षिक प्रतिस्थापन और (३) जनता की निरक्षरता थे।

भारत में बैंकों के फेल होने का दूसरा कारण देश में किसी भी प्रकार के बैंकिंग विधान का अभाव था। बहुत से बैंक सट्टेबाजी एवं अनियमित कार्यों में रुपया लगाकर फेल हो जाते थे।

बैंकों के फेल होने का तीसरा कारण ऐसे केन्द्रीय बैंक का न होना था, जो देश में मुद्रा तथा साल का सार्वजनिक रख सकता बैंकों के लिये पथप्रदर्शक, विचारक व मित्र होता और सरकार को समय समय पर बैंकिंग व्यवसाय पर उचित नियन्त्रण लगाने की सलाह देता।

व्यापारिक बैंकों के कार्य

(१) ये बैंक रुपया जमा करते हैं। जमा राशि तथा सुरविन कोष से थोड़े समय के लिये व्यापारियों को ऋण देकर देश के वाणिज्य एवं उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योग देते हैं। व्यापारिक बैंकों के द्वारा देश के धन में लचक तरलता तथा गतिशीलता आती है।

(२) ये बिल टुयटी मुनाकर भी व्यापारियों को अवकालीन सहायता देते हैं, वे उनसे राता छुलवाकर बैंक काटने की भी अनुमति देते हैं।

(३) ये सोना, चादी, राज्य प्रतिभूतियाँ एवं अन्य साल पत्रों की जमानत पर ऋण देते हैं। माल व खेती की उपज पर भी ये ऋण देते हैं।

(४) ये कभी कभी निश्चयनीय व पर्याप्त धन वाले की व्यक्तिगत जमानत पर भी ऋण देते हैं।

(५) व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को दूसरे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने में सहायक होते हैं।

(६) एक एजेंट के रूप में व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ऋणपत्र व वस्तुनिष्ठों के अथवा खरीदते हैं, ग्राहकों की ओर से सहायक प्रतिनूतियों पर ब्याज लेते हैं, बीमा की निश्चय आदि का सुगठान करते हैं। ये आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षास्थल में रखते हैं।

विनिमय बैंक (Exchange Banks)

विदेशों को मुग्तान करने के लिए अथवा उससे धन लेने के लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ती है और वह वर्तमान काल में विनिमय बैंक है ।

सन् १८४२ में ओरियन्टल विनिमय बैंक की स्थापना की गई । सन् १८५३ में चाटर्ड बैंक आफ इण्डिया, चीन और आस्ट्रेलिया तथा मर्र्क्वाइल बैंक इंग्लैण्ड में स्थापित हुए । सन् १८८३ में कलकत्ता ब्रिगि कारपोरेशन खुला, बिस्का नाम बाद में बदलकर 'नेशनल बैंक आफ इण्डिया' कर दिया गया । इसका प्रधान कार्यालय पहले कलकत्ते में था, परन्तु बाद में लन्दन ले जाया गया । सन् १८८६ में भारत में कई विनिमय बैंक स्थापित हुए । सन् १८८४ में ओरिएण्टल बैंक फल हो गया । भारत में बितने भी विनिमय बैंक हैं, वे सब केवल शाखाएँ हैं, जिनके प्रधान कार्यालय लन्दन, सुदूरपूर्व, अमेरिका आदि में हैं । भारत के प्रमुख विनिमय बैंक ये हैं—नेशनल बैंक आफ इण्डिया (लन्दन), लायड्स बैंक (लन्दन), भारत, चीन और आस्ट्रेलिया का चाटर्ड बैंक (लन्दन), मर्र्क्वाइल बैंक आफ इण्डिया (लन्दन), नेशनल सिटी बैंक आफ न्यूयार्क, बैंक आफ चाइना, पेगिस बैंक आदि ।

विनिमय बैंक के कार्य

- (१) विदेशों को मुग्तान करने में सहायता देना ।
- (२) भारत में विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता देना ।
- (३) विदेशी विनिमय पत्रों का क्रय-विक्रय करना तथा उनको सुनाना ।
- (४) भारत के आन्तरिक व्यापार की आर्थिक सहायता देना और बन्दरगाह से सामान देश के भीतरी मण्डियों में पहुँचाना ।
- (५) जनता का रुपया जमा करना, रुपया उधार देना आदि अन्य बैंकों के कार्य करना ।
- (६) स्वर्ण एवं रजत धातु का क्रय-विक्रय करना और उनका आयात-निर्यात करना ।
- (७) विदेशी व्यापारियों को भारत के अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति बताना और यहाँ के बाजारों की स्थिति से उन्हें अवगत करना ।
- (८) भ्रमणार्थ आने वाले विदेशियों की मुद्रा को देशी मुद्रा में परिवर्तित कर ये बैंक दो देशों के राजनैतिक, साम्प्रदायिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों को दृढ़ करने में सहायता देते हैं ।
- (९) कष्ट बैंक अपने यहाँ जनता की जमा भी रखते हैं और बहानी प्रलेखों की बमानत पर श्रृण भी देते हैं ।

विनिमय बैंकों की आलोचना

प्रायः भारतीय विनिमय बैंकों को इस क्षेत्र में कार्य करने की सुविधा नहीं दी जाती थी। भारतीय इसमें सतृप्त न थे। इसके निम्न कारण हैं—

(१) ये बैंक आन्तरिक व्यापार में भी भाग लेते हैं और इससे भारतीय बैंक नहीं बन सकते।

(२) इनकी पूंजी भारतीय मुद्रा में नहीं होती, इनका कार्यसंचालन भी विदेशी सरकार के अधिनियमों द्वारा ही होता है, अतएव ये भारत के लिए अहितकार हैं।

(३) ये बैंक भारतीयों पर विश्वास नहीं करते। उच्चरदायी स्थानों पर विदेशी ही नियुक्त करते हैं।

(४) ये बैंक अपने अथ भारतीयों को नहीं बेचते। परिणामस्वरूप भारतवासी ऐसे बैंकों के कार्य-संचालन में भाग नहीं ले पाते और देश प्रबन्ध निश्चय ही देश के लिए घातक सिद्ध होगा।

(५) जब माल मगाया जाता है तो यह विदेशी बहाबी व बीमा कंपनियों को विशेष प्राथमिकता (Preference) देते हैं। परिणामस्वरूप भारतीय कंपनियाँ बचित रह जाती हैं और देश का धन भी बाहर चला जाता है।

(६) ये बैंक भारतीयों से अधिक कमीशन वसूल करते हैं।

(७) ये बैंक यहाँ से पूंजी एकत्रित कर अपने देश में लगाते हैं और यहाँ विकास का कार्य नहीं हो पाता।

(८) ये विदेशी व्यापार की अधिक उन्नति चाहते हैं।

(९) ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट नहीं बनाते और अपने आय-व्यय के आंकड़े नहीं प्रकाशित करते।

सन् १९४६ में भारतीय बैंकिंग कंपनी विधान के पास हो जाने पर विदेशी विनिमय बैंकों पर निम्नलिखित नियन्त्रण लगाये गये—

(१) इन्हें लाइसेंस लेना आवश्यक है।

(२) विदेशी बैंक रिजर्व बैंक के पास १५ लाख रुपया जमा रखें और यदि इनका व्यवसाय बम्बई और कलकत्ता में भी हो तो २० लाख रुपया रखना आवश्यक है।

(३) रिजर्व बैंक के पास इनकी जमा राकम पर बैंक के बन्द होने पर भारत के बैंक के लेनदारों का प्रथम अधिकार होगा।

(४) प्रत्येक बैंक को सावधि तथा मांग की जमाओं के विद्वद् उनके ७५% मूल्य की सम्पत्ति सदैव भारत में रखनी पड़ेगी।

(५) इन्हें वर्ष के अन्त में अपने भारत में किए गए व्यापार का हानि-लाभ का साठा तथा वार्षिक चिट्ठा रिजर्व बैंक को भेजना पड़ेगा।

सेद का विषय है कि विनिमय बैंकिंग कार्य में भारतीयों का हाथ नहीं के बराबर है और इस कारण बहुत सा धन कमीशन, दलाली तथा बीमे के रूप में विदेशों को चला जाता है। कुछ भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपनी शाखाएँ खोली हैं। १९५६ में १०६ भारतीय बैंकों की शाखाएँ विदेशों में थी। भारतीय बैंकों को इस कार्य में पूर्वी तथा कुछ कर्मचारियों की कमी और राजनैतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

इसका निर्माण इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर १ जुलाई, १९५५ को हुआ। इसका प्रबन्ध संचालन एक केन्द्रीय बोर्ड द्वारा होता है, जिसमें २० सदस्य होते हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति सरकार रिजर्व बैंक की सलाह से करेगी। २ प्रबन्ध बाहरेक्टरों की नियुक्ति केन्द्रीय बोर्ड सरकार की सहमति से करती है। ६ संचालक रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य अस्थापितों द्वारा तथा ८ संचालक रिजर्व बैंक की सलाह के अनुसार सरकार स्थानीय तथा आर्थिक दिनों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से नियुक्त करती है। एक संचालक केन्द्रीय सरकार और एक रिजर्व बैंक नियुक्त करेगा।

कार्य

- (१) यह उद्योग व व्यापार को लाभ मुक्त करता है।
- (२) रिजर्व बैंक के रूप में भी यह कार्य करता है।
- (३) अपनी स्थापना के ५ वर्षों में यह ४०० शाखाएँ खोलेगा।
- (४) यह अधिक मात्रा में धन के स्थानान्तरण की सुविधा मुक्त करता है, विशेष रूप से देहाती बचत के स्थानान्तरण के हेतु अधिक प्रयत्नशील रहेगा।

(५) अपनी शाखाओं का विस्तार करके तथा गोदामों एवं अन्य पक्कन की किसी सन्वन्धी आवश्यक सुविधाएँ मुक्त करके—इससे आशा की जाती है कि बाद में यह माध्य साध की मात्रा में काफी वृद्धि कर सकेगा।

(६) केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर स्टेट बैंक अन्य बैंकों के व्यवसाय, उनकी सम्पत्ति तथा देनदारियों पर भी स्वामित्व कर सकता है।

(७) स्टेट बैंक की अधिकृत पूंजी २० करोड़ रुपये है, जिसमें से निर्गमित पूंजी ५६२५ करोड़ रुपये है।

(८) विदेशी विनिमय के विभाग में महत्वपूर्ण भाग लेता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

६ मार्च, १९३४ को सरकार ने एक अधिनियम 'रिजर्व बैंक एक्ट' घोषित किया। १ अप्रैल, १९३५ से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कार्य प्रारम्भ किया। १९३५ से १९४८

तक यह बैंक अ शघारियों का रहा । १ जनवरी १९४६ को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और अब यह राष्ट्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है ।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् मी बैंक की पूंजी ५ करोड़ ही है । अब यह पूंजी सरकार द्वारा ही लगाई गई है, क्योंकि अ शघारियों को उचित मुआवजा दे दिया गया । इस बैंक की नीति सरकार के आदेशानुसार ही निर्धारित होती है ।

प्रबन्धसंचालन

इस बैंक का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल द्वारा होता है जिसका निम्नलिखित स्वरूप है —

(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक गवर्नर और दो डिप्टी गवर्नर जिनका कार्य-काल ५ वर्ष तक का होता है ।

(२) चार स्थानीय बोर्डों में हैं । प्रत्येक में सरकार द्वारा मनोनीत ५ सदस्य होते हैं, जिनमें से सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक बोर्ड में से एक संचालक अर्थात् ४ संचालक ।

(३) भारत सरकार द्वारा नियुक्त ६ संचालक और एक सरकारी अग्रेसर । इस केंद्रीय बोर्ड में १४ संचालक होते हैं ।

रिजर्व बैंक के मुख्य विभाग

(१) निर्गम विभाग (Issue Department) — इसका मुख्य कार्य अर्थवत्त निर्गमित करना है । इसकी दो शाखाएँ हैं—एक शाखा का कार्य नोट निकालना तथा उनका विनिमय करना है तथा दूसरी का काम रजिस्ट्रेशन करना नोटों की जाँच करना, उनको रद्द करना हिाव रखना और अन्तरिम आडिट करना है ।

(२) बैंकिंग विभाग — यह देश के अन्य बैंकों से सम्बन्ध रखता है और उनका मदद कोष रखता है । इसके ५ उपविभाग हैं—जमा खाता, अर्थों का हस्तांतरण, साख्यपत्र, सरकारी खाता तथा सरकारी ऋण ।

(३) कृषि साख्य विभाग — इस विभाग का कार्यक्षेत्र कृषि समस्याओं का समाधान करना है । यह कृषि साख्य नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भाग लेता है ।

(४) विदेशी विनिमय नियंत्रण विभाग — इस विभाग का मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय दर को स्थायी रखना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करना है ।

(५) शोधन एवम अंक विभाग — यह विभाग मुद्रा, साख्य, बैंकिंग बैंकदर आदि विषयों पर अनुसंधान करता है तथा अपनी शोध के परिणाम प्रकाशित करता है । यह देश के मुद्रा बाजार तथा बैंकिंग व्यवस्था से सम्बन्धित आंकड़े भी एकत्रित करता है तथा उन्हें प्रकाशित करता है ।

(६) बैंकिंग विनास विभाग — इसका मुख्य उद्देश्य छोटे नगरों में बैंकिंग सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करना है ।

(७) बैंकिंग क्रियाओं का विभाग :—देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण रखता है।

रिजर्व बैंक के कार्य (Functions)

केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी कार्य :—(१) पत्र मुद्रा निकालना । यह कार्य निगम विभाग करता है। इस विभाग की सम्पत्ति स्वर्णपाट, स्वर्णमुद्रा, सुरक्षित कोय, विदेशी साख. पत्र तथा व्यापारिक बिलों में रखी जाती है। पहले सम्पूर्ण निर्गमित नोटों का ४०% स्वर्ण-पाट, स्वर्ण सिक्के तथा स्टर्लिंग प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य था। बाद में स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के स्थान पर विदेशी प्रतिभूतियों को रखा जाने लगा। नवम्बर १९५७ के एक आदेश द्वारा न्यूनतम रिजर्व २०० करोड़ रु० होना चाहिए, जिसमें ११५ करोड़ रु० का सोना सम्मिलित है। यह कार्य विदेशी विनिमय संकट को दूर करने के लिए किया गया है।

(२) अनुसूचित बैंकों के नकद कोय का कुछ अंश जमा रखना—अनुसूचित बैंक अपनी चालू जमा का ५०% तथा सार्वजनिक जमा का २% इस बैंक के पास जमा रखते हैं।

(३) सरकार का सम्पूर्ण बैंकिंग सम्बन्धी कार्य करना।

(४) विदेशी विनिमय का कार्य—दो विदेशी मुद्राओं का विनिमय करता है।

(५) केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी अन्य कार्य—यह केन्द्रीय बैंक के रूप में अन्य सेवाएं भी करता है, जिसमें समारोपण घर (Clearing House) की व्यवस्था मुख्य है। यह बैंक नोटों को बाढ़ी के सिक्कों में बदलने की नोटों में बदलता है और रेजगारी निकालता है। देश के बैंकिंग सम्बन्धी अंक एकत्रित करता है और देश की अर्थ नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भाग लेता है।

व्यापारिक कार्य

(१) यह बिना व्याज के भारत सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं से रुपया जमा कर सकता है।

(२) वह अपने अनुसूचित बैंकों से स्टर्लिंग भ्रम करने तथा उन्हें विक्रय करने का कार्य करता है अर्थात् विदेशी मुद्रा में देश की मुद्रा परिवर्तित करता है।

(३) यह मांगत तथा राजन सरकारों को तीन माह से अधिक अवधि का श्रृण नहीं दे सकता।

(४) यह व्यापारिक बिलों का प्रयोजन कर सकता है अथवा उन्हें पुनः मुना सकता है। इन बिलों में निम्न बातें होना आवश्यक हैं :—

(a) ये जिन व्यापारिक सौदों के हों।

(b) ६० दिन की अवधि से अधिक के न हों।

(c) इन पर कम से कम २ हस्ताक्षर हों।

(d) इनका मुग्तान भारत में होने वाला हो ।

(५) यह अपनी पुंजी से अधिक मात्रा में ऋण नहीं ले सकता ।

(६) यह बिटेन के ऐसे साल पत्रों का क्रय-विक्रय कर सकता है, जो क्रय करने से १० वर्ष के अन्दर पक जावें ।

(७) यह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रत्येक साल-पत्र का क्रय-विक्रय कर सकता है ।

(८) यह अनुमूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, स्थानीय शासन संस्थाओं आदि को सोना, स्टर्लिंग और रुपया प्रतिभूतियों या स्वीकृत अधिपत्रों की खमानत पर ६० दिन के लिए ऋण दे सकता है ।

(९) यह अनुमूचित बैंकों से कम से कम १ लाख ६० के विनिमय बिकों तथा स्वीकृत मुद्राओं का क्रय-विक्रय कर सकता है ।

(१०) मुद्रा प्रतिभूति एक अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ रख सकता है तथा उनका मूल्य भ्यात्र सहित बचल कर सकता है ।

(११) किसी भी विदेशी बैंक से सम्बन्ध स्थापित कर सकता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है ।

(१२) स्वयं व रजत का क्रय-विक्रय तथा उनका स्थानान्तरण कर सकता है । चल अथवा अचल संपत्ति जो भी बैंक के अधिकार में आवे, उनका विक्रय कर सकता है ।

(१३) १९५१ में रिजर्व बैंक ने बिल मार्केट योजना बनाई, जिसका उद्देश्य मुद्रा बाजार में लोच लाना था । इसके अनुसार अनुमूचित बैंकों को विशेष सुविधाएँ दी गई हैं ।

रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य

देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते यह अन्य व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता नहीं कर सकता । यह कोई व्यापार नहीं कर सकता तथा अचल संपत्ति को अपने निजी काम के अतिरिक्त नहीं खरीद सकता । यह अपने या अन्य बैंक तथा कम्पनी के अंश नहीं खरीद सकता और न इन अंशों की खमानत पर ऋण दे सकता है ।

इस बैंक को कार्य करते हुए २५ वर्ष हो चुके हैं । यह निजी संस्था से अब सरकारी बैंक के रूप में कार्य कर रहा है । इसने बहुत सी विषम परिस्थितियों में सकलतापूर्वक कार्य किया है—मन्दी, मुद्रा, मुद्रा स्फीति (Inflation), विभाजन, ६० का अवमूल्यन और पंचवर्षीय योजनाएँ । इतना सब करने पर भी रिजर्व बैंक अभी तक देशी बैंकों को अपने साथ शृंखलाबद्ध करने में असफल रहा है ।

भारत में बैंकिंग व्यवस्था की अभी तक इतनी उन्नति नहीं हुई है, जितनी कि देश के क्षेत्रफल और जनसंख्या को देखते हुए होनी चाहिए । यही कारण है कि हमारे देश में उद्योग-धंधों का आधुनिक रूप में अधिक विकास नहीं हो सका । हमारी बैंकिंग व्यवस्था में निम्न दोष हैं—

(१) अधिकतर बैंक हमारे देश के नगरों तथा बड़े बड़े कस्बों तक ही सीमित हैं। भारत गांवों का देश है, परन्तु गांवों में बैंक का नाम भी नहीं है। इस प्रकार देशांतर वचन की प्रोत्साहन नहीं मिल पाता तथा पूर्वी निर्माण में कमी होती है।

(२) देश में मुद्रा बाजार के विभिन्न भागों में आपसी सम्बन्ध नहीं है। विदेशी विनिमय बैंक व्यापारिक बैंकों से अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा देशी बैंक और महाजन का सम्बन्ध देश के अन्य बैंकों से नहीं है।

(३) विभिन्न प्रकार के बैंकों की न्याय की दर भिन्न भिन्न है, जिससे मुद्रा बाजार सुसंगठित रूप में विकसित नहीं हो पाता।

(४) एक बड़ा दोष यह है कि उद्योग-धन्धों की मांग की पूर्ति के लिये बैंकों के पास पर्याप्त द्रव्य और साधन नहीं है। इसका मुख्य कारण लोगों की रुपये को दबाकर रखने की प्रवृत्ति है तथा अशिष्टता है।

(५) हमारे देश में संगठित बिल बाजार का अभाव है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश में लोग सरकारी पत्रों को अधिक अष्ट समझते हैं तथा नकद साधन का अधिक प्रयोग है। निकासी तथा विलयणों (Clearing Finance Houses) का निराला अभाव है।

इन दोषों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक तथा बैंकिंग कम्पनीज एक्ट १९४६ ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। रिजर्व बैंक की बिल मार्केट योजना से आशा है कि शीघ्र ही हमारे देश में एक अच्छे बिल बाजार का निर्माण हो जायेगा।

रिजर्व बैंक देश के देशी बैंक तथा महाजनों से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी प्रयत्नशील है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी गीदामों के बनाने की योजना है, जिनमें सामान रखकर अधिकार पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं, जिनसे रिजर्व बैंक को बिलों का पुनर्बंटन करने में कोई आपत्ति न होगी। इसके अतिरिक्त एक अखिल भारतीय बैंक स्थापित होना चाहिए, जिसका कार्य बैंकों के हितों की रक्षा करना तथा आपसी प्रतिस्पर्धा रोकना हो।

प्रश्न

(१) भारत की बैंकिंग व्यवस्था के मुख्य दोष बताइये और उन्नति के सुझाव दीजिए।

(२) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के मुख्य कार्यों का वर्णन करिये और यह बताइये कि उसने कहा तक सफलतापूर्वक कार्य किया।

(३) विदेशी विनिमय बैंकों की कार्य कारिता भारतीय हितों के लिए किस प्रकार हानिकर हुई है?

द्वितीय भाग

अध्याय १—६

इंग्लैंड का आर्थिक विकास

अध्याय

१. प्रारम्भिक
२. कृषि उद्योग और कृषि क्रान्ति
३. औद्योगिक क्रान्ति
४. प्रमुख उद्योग
५. यातायात के साधन
६. भ्रम संघ
७. सामाजिक सुरक्षा और बीमा
८. स्वतन्त्र व्यापार नीति
९. बैंकिंग और राजस्व

मध्य युग में इंग्लैंड कृषिप्रधान देश हो पा। परन्तु वास्तव में जो प्राकृतिक साधन वहाँ पाये जाते हैं वे वहाँ के उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। इनमें हम इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति को ले सकते हैं व इसके साथ साथ वहाँ की भूमि व समुद्रतट व लनिज पदार्थों को भी देख सकते हैं। इंग्लैंड के दायें पारप के विभिन्न उन्नत राष्ट्र व दूसरी ओर अमेरिका, इनके बीच में इंग्लैंड है। इंग्लैंड की भूमि अधिकतर कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ की भूमि का क्षेत्रफल कम है व पहाड़ी भूमि है। अतः वह केवल औद्योगिक देश के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। इसीलिए इंग्लैंड उद्योगप्रधान देश है। कृषि गौरवरूप से की जाती है। वहाँ की जनसंख्या का केवल ११ प्रतिशत कृषि या इससे सम्बन्धित कार्य में लगा हुआ है, जबकि हमारे वहाँ यह ७६ प्रतिशत है। इंग्लैंड को इस प्रकार खाद्यान्नों की आवश्यकता है और वहाँ राशन प्रणाली है और दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है।

कृषि योग्य भूमि की कमी, क्षेत्रफल के हिसाब से इंग्लैंड राशियान से भी कम क्षेत्रफल का है। उत्तर व पश्चिम में भूमि की बनावट पहाड़ियों के रूप में है। केवल दक्षिण पूर्वी भाग ही मैदान के रूप में है और इसी मैदान में गेहूँ, जौ, चुकन्दर, आलू, पत्त व सब्जी आदि का उत्पादन होता है। भूमि का मूल्य वहाँ अधिक है, अतः कृषि उत्पादन व्यय अधिक है। कृषि भूमि पर काम करने वाले मजदूरों की लागत भी बहुत ज्यादा है। निष्कर्ष यह है कि इंग्लैंड का कृषि उत्पादन व्यवसाय विदेशों से आयात किए हुए अनाज से अधिक होता है। गहन कृषि प्रणाली अपनाने के कारण देश की आवश्यकता की कुछ पूर्ति हो जाती है।

देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो दूसरी ओर प्राकृतिक साधन देश को औद्योगीकरण को प्रधानता दिए हुए हैं। वहाँ शक्ति की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। कोयला बड़ी मात्रा में अच्छी किस्म का मिलता है और कोयले की खानों के पास ही लोहे की भी खानें हैं। ये दोनों उद्योग की आधारशिला हैं। देश की जलवायु समशीतोष्ण है व मशीनों के निर्माण से सूती व ऊनी वस्त्र का विकास सम्भव हुआ। इसी कारण लंकाशायर व मानचेस्टर के पास विभिन्न सूती वस्त्र मिलें बनी थीं।

उस समय भूमि ४ भागों में विभाजित थी :—

(१) डेमसने (Demesne), जो ग्रामपति की भूमि होती थी ।

(२) स्वतन्त्र या प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भूमि ।

(३) दासों की-विलेन्स और कार्टर्स की भूमि ।

(४) चारागाह, जो सब व्यक्तियों के पशुओं के लिए होते थे ।

खेतों की कृषि की ३ खेत प्रणाली थी । इसके अनुसार १ खेत के ३ भाग हर उसमें से प्रतिवर्ष २ हिस्सों पर खेती की जाती थी व एक हिस्से को पालतू छोड़ दिया जाता था, जिससे वह फिर से अपनी उर्वर शक्ति प्राप्त कर ले ।

१५वीं तथा १६वीं शताब्दी में कृषि प्रणाली में परिवर्तन हुए । वाणिज्य-व्यापार में वृद्धि हुई तथा मुद्रा का भी प्रचलन हुआ । इससे दासों और मजदूरों की स्थिति में काफी सुधार हुआ । इस प्रकार १६वीं सदी तक मेनोरियन प्रणाली का अन्त हो गया । इसके निम्न कारण थे :—

(१) डेमसने भूमि की समाप्ति, मजदूरों के अभाव के कारण ।

(२) भूमि का घेरा डालना या सामावरण (Enclosure) :—बड़े बड़े उद्योग पतिवों ने अपनी अपनी भूमि को या डेमसने भूमि को खरीदकर, उनके चारों ओर परकोष डालना आरम्भ कर दिया । इन लोगों ने दासों की भूमि को भी खरीद लिया । इन बड़े बड़े खेतों में वे अधिकतर व्यापारिक कृषि करने लगे ।

(३) मेड़ें पालने के व्यवसाय का विकास :—ऊन की अधिक मांग तथा इस व्यवसाय में कम व्यय और कम श्रमिकों की आवश्यकता ।

(४) दासवृत्ति की समाप्ति :—सन् १३४८ में प्लेग फैलने के कारण भारी संख्या में मजदूरों की मृत्यु व इसके कारण मजदूरों की कमी व शेष मजदूर उचित मजदूरी मांगने लग गए थे ।

(५) न्यायालयों की समाप्ति :—सरकारी न्यायालयों के खुल जाने से मेनोरियन प्रणाली के न्यायालय समाप्त हो गए । इस प्रकार लार्ड्स की प्रभुता भी समाप्त हो गई ।

कृषि-क्रान्ति (Agricultural Revolution)

१८ गलैरड में १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिन्हें हम कृषि-क्रान्ति के नाम से पुकारते हैं । कृषि में यह क्रान्ति सन् १७५० से आरम्भ हुई और उन्नीसवीं सदी के मध्य तक चरती रही । इस क्रान्ति के फलस्वरूप ग्रेट्रिन में खेती की प्रथा प्रायः समाप्त हो गई और उसका स्थान समावृत्त खेतों की प्रणाली ने ले लिया । त्रिवेणीय प्रथा तथा खेतों की खाली छोड़ दिये जाने की प्रथा के स्थान पर अब फसलों के हेरफेर की प्रणाली अथवा Rotation of Crops System अपनाई जाने लगी । कृषि का वैज्ञानिकीकरण हुआ और बीज बोने, फसल काटने एवं पशुओं की देखभाल

मुधारने आदि के लिए नये नये तरीके काम में लाये जाने लगे । सन् १७२० में जब कि कृषि क्रान्ति प्रारम्भ हुई, उस समय कृषि की दशा इस प्रकार थी कि लगभग आधे गावों में अब भी खुले खेतों की प्रथा प्रचलित थी । कृषि के तरीके प्राचीन एवं साधारण थे । प्रति एकड़ उपज कम थी । कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी । कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य, जैसे सूत व ऊन की कटाई-बुनाई आदि भी घर पर हो कर लेते थे । इससे उन्हें कुछ अतिरिक्त आय हो जाती थी ।

कृषि क्रान्ति के कारण

१८ वीं सदी में जिन कारणों ने कृषि क्रान्ति को जन्म दिया, वे निम्नलिखित थे—

(१) जनसंख्या की वृद्धि, (२) खाद्य पदार्थों का अभाव और मूल्य वृद्धि (३) ग्रामीण जूती वस्त्र व्यवसाय का पतन, (४) भूमिपतियों के पास अधिक पूँजी का संग्रह और (५) कृषि सुधारकों का कृषि सुधार के लिए जनता में प्रचार ।

देश की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी साथ साथ ही खाद्य पदार्थों का अभाव हो रहा था । इससे खाद्यान्न के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये थे । खाद्य पूर्ति के लिए अधिक अन्न उत्पन्न करने की आवश्यकता थी तथा अन्न के बड़े बड़े मूल्य कृषि सुधार और विकास के लिए पर्याप्त आकर्षण प्रदान कर रहे थे । बड़े बड़े ग्रामपतियों के पास विकास के लिए आवश्यक पूँजी जमा हो गई थी । अन्न वातावरण कृषि परिवर्तनों के अनुकूल था । इधर दूसरी ओर बड़े कृषि सुधारक रोबर्ट बेकवेल, आर्थर यंग, बैथरोडुल आदि अपने क्षेत्रों तथा भाषणों द्वारा जनता में प्रचार कर रहे थे । राजनैतिक वातावरण भी कृषि के विकास के लिए सहायकपूर्ण था । पार्लियामेंट में भी कृषक स्वार्थों का प्राधान्य था और अन्न कानून (Corn Laws) के पास होने से एक सत्ताधीश तब ट्रिनिटी कर्कों के स्वार्थों की रक्षा हुई ।

अन्न कानून (Corn Laws)

कृषि को प्रोत्साहन देने तथा भूमिपतियों के स्वार्थों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से ब्रिटेन ने अनाज के आयात-निर्यात पर अन्न कानून बनाकर नियन्त्रण किया । सर्वप्रथम सन् १६८६ में कर्न बाउन्टी एक्ट (Corn Bounty Act) बना, जिसका उद्देश्य अनाज के निर्यात को प्रोत्साहन देना था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की जनसंख्या कम थी और अन्न उत्पादन अधिक । बाद में परिस्थितियाँ बदल गईं और अनाज की कमी प्रतीत होने लगी । अतः इस नीति में परिवर्तन किया गया और सन् १७६३ तक ब्रिटेन से अनाज का निर्यात बन्द कर दिया गया । इस समय अनाज का बहुत अभाव हो गया और बाहर से अनाज का आयात करना पड़ा ।

सन् १८१२ में बुद्ध की समाप्ति होने पर ब्रिटेन के कृषक स्वार्थों ने अनाज के आयात पर नियन्त्रण लगाने की माँग की क्योंकि उन्हें यह आशंका थी कि बाहरी अनाज

की प्रतियोगिता के कारण देश में अन्न का मूल्य स्तर गिर जायगा और इस प्रकार कृषकों को हानि होगी। इस समय पार्लियामेन्ट में कृषक स्वार्थों का प्रमाण था। अतः सन् १८१५ में Corn Law पास किया गया, जिसके अनुसार गेहूँ के आयात पर नियंत्रण लगा दिया गया। राई, जौ और बजड़ा के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये। अन्नान्न के भाव गिरने और मन्दी के कारण सन् १८२७, १८२८ और १८४२ में इसमें संशोधन करने पड़े, जिनके अनुसार मूल्य की उच्चतम सीमा और आयात करों की दर में परिवर्तन किये गये।

इनका प्रधान उद्देश्य यह था कि कृषि और कृषकों की उन्नति होगी, परन्तु यह नहीं हुआ। कृषि की दशा गिरती गई। इसके सिवा यह केवल एक निरोध वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति के लिये बनाये गया था। अतः ये जनता का समयन न प्राप्त कर सके। जनता को इनसे हानि उठानी पड़ी।

इसलिये इन कानूनों को समाप्त करने के लिये आन्दोलन आरम्भ हो गया। सन् १८३८ में लकाशायर के कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर एक अन्न कानून विरोधी समिति (Anti Corn Law League) की स्थापना रिचार्ड कोब्डन और जोन ब्राइट के नेतृत्व में हुई। सन् १८४५ में आलू की फसलों के नष्ट हो जाने से सर रोबर्ट पील ने यह अनुमति दिया कि अन्नान्न के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना देश के हित में न होगा और फलस्वरूप १८६६ से अन्नान्न का आयात स्वतन्त्र रूप से ब्रिटेन में होने लगा।

कृषि क्रान्ति की निरोधताएँ

(१) समावरण आन्दोलन की पुनरावृत्ति।

(२) बड़े खेतों की प्रभुत्वता।

(३) कृषि का पूँजीवादी संगठन।

(४) कृषि के तरीकों में सुधार।

(५) छोटे कृषकों का लोप।

(१) समावरण आन्दोलन (Enclosure Movement) — जिन गाँवों में खुले खेत रह गये थे, वे धरे जाने लगे। यहाँ तक कि सामान्य चारागाहों को भी घेर कर कृषि उत्पादन किया जाने लगा। सन् १८०१, १८२६ और १८४५ में समावरण अधिनियम पास किये गये जिनके कारण इस आन्दोलन को बड़ा प्रोत्साहन मिला। फलस्वरूप १८५० तक प्रायः सभी खेतों की बाड़ेबन्दी पूर्ण हो चुकी थी। खुले खेतों पर कृषि करना हानिकारक तथा मध्यशुगीन तरीका समझा जाने लगा।

समावरण आन्दोलन वास्तव में मेनोरिपन प्रणाली का पतन होने से आरम्भ हुआ। कृषि दलों के स्तव्य हो जाने और अन्न के ह्रास पर ऊँच की माँग बढ़ जाने के कारण भूमिपतियों ने अपने खेतों को घेर कर कृषि के बन्नाय में हस्तक्षेप करने का व्यवसाय

करना आरम्भ कर दिया। यह कार्य छोटे छोटे खेतों को मिलाकर या चारागाह या बंजर भूमि को घेर कर पूरा किया गया। इससे छोटे छोटे कृषकों को बहुत हानि हुई। लोग गांव छोड़ छोड़ कर नगरों में जाकर बसने लगे। अंत जनता द्वारा इसका विरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में सबसे पहला कानून सन् १२३५ में बना। १५वीं और १६वीं सदी में कई बार इसमें संशोधन किये गये। समावरण आन्दोलन जोर पकड़ता गया। समावरण आन्दोलन की पुनरावृत्ति १८वीं सदी के मध्य में कपि क्रान्ति के साथ हुआ। एडमस्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों ने कृषि में अपव्यय रोकने तथा खुले खेतों के दोषों से बचने के लिये समावरण का समर्थन किया। सन् १८०१ के कानून के अनुसार स्वे-व्यापक समावरण करने के लिये सुविधा मिल गई। सन् १८३६ में दो-विहाई बहुमत मिलने पर समावरण किया जा सकता था। सन् १८४५ में जनरल एनक्लोजर एक्ट बनाया गया, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय समावरण मंडल की स्थापना की गई।

समावरण के कारण धीरे धीरे बड़े खेतों की स्थापना हो गई। अच्छी कीमत मिलने के कारण छोटे कृषकों ने अपने खेत बेच दिये। सम्मिलित चारागाह होने से जनता को लकड़ी और चारे की कठिनाई होने लगी।

(२) बड़े खेतों की प्रमुखता — समावरण आन्दोलन के कारण छोटे कृषकों का खेती करना असम्भव हो गया। मूल्य स्तर बढ़ रहा था। बाड़ेबंदी के लिये धन की आवश्यकता थी। चारागाहों को घेर लिया गया था तथा उनमें भी खेती होने लगी थी। चारे और लकड़ी का सर्वत्र अभाव होने लगा। इस काल में भूमि की मांग बढ़ गई और भूस्वामी होना बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी। उन दिनों पार्लियामेंट तथा स्थानीय संस्थाओं की सदस्यता के लिये लड़े होने वाले व्यक्ति के लिये भूस्वामी होना आवश्यक था। व्यापारी तथा उद्योग पतिषों की इतनी प्रतिष्ठा नहीं थी। अतः वे भी ऊंची कीमतों पर खेत खरीदने के लिये तत्पर रहते थे। इन सब कारणों से छोटे छोटे कृषक अपने खेत बेचकर शहरों में औद्योगिक मजदूर बन गये।

(३) कृषि का पृथिवीवादी संगठन — कृषि का बड़े आकार के समायुक्त खेतों के रूप में संगठित थी। इनके स्वामी धनी ग्रामपति थे। वे अपने धन का प्रयोग कृषि के विकास में करते लगे। मजदूरों के अभाव में नई मशीनों तथा यंत्रों का प्रचलन बढ़ गया। कृषि व्यापारिक रूप से की जाने लगी। ऊँचे मूल्यों के कारण कृषि अत्यन्त लाभदायक उद्योग हो गया और ग्रामपति मालामाल होते गये।

(४) कृषि के तरीकों में सुधार — जनसंख्या के बढ़ने से खाद्यान्न की मांग में वृद्धि हुई, जिसकी पूर्ति करने के लिये कृषि के तरीकों में सुधार किया जाने लगा। अथ एवं समय की बचत के उद्देश्य से नये नये प्रकार के यंत्रों का आविष्कार हुआ और उन्हें कृषि में प्रयोग किया जाने लगा। १८३८ में शाही कृषि परिषद् की स्थापना की गई और १८४२ में कृषि रसायन मण्डल स्थापित हुआ। पसलों के हेरफेर की प्रथा अपनाई गई और कृषि-

क्षेत्र में अनुसंधान व खोज के कार्य आरम्भ किये गये। पशुनस्ल मुघारने की ओर भी प्रयत्न किये गये। पशुओं की खुले चराने की प्रथा न रही और उन्हें प्रायः घेरी में ही चरना जाने लगा। भेड़ों और गायों की नस्लों में उन्नति हुई।

(५) छोटे कृषकों का लोप—समावरण आन्दोलन तथा व्यापारियों की प्रवृत्ति के कारण छोटे कृषकों का लोप हो गया। वे औद्योगिक नगरों की ओर प्रस्थान कर गये और वहाँ कारखानों में श्रमिक बन गये।

कृषि क्रान्ति के परिणाम

कृषि में हुई इस क्रान्ति का परिणाम यदि एक ओर कृषि उत्पादन के लिये उत्तम हुआ तो दूसरी ओर लाखों छोटे छोटे कृषकों के लिये घातक सिद्ध हुआ। नये तरीकों के कारण प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन वृद्धि के कारण त्रिटिश कृषि कई वर्षों के लिये आत्मनिर्भर हो गई, किन्तु साथ ही कृषि व्यवस्था पर केवल धनी और ममिपतियों का एकाधिकार हो गया। भूमि में छोटे छोटे कृषकों को हट जाना पड़ा, क्योंकि वे घनाभाव के कारण नये तरीकों को अपनाने तथा प्रतियोगिता में ठहरने में असमर्थ थे। ये लोग गहरों में निराश्रित हो गये।

वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के कारण व्यापारिक फसलों को उगाया जाने लगा। फलस्वरूप किसानों के तीन समुदाय हो गये—लेविहर् किसान, कृषक और श्रमिक। साधारण जनता को ईंधन तथा चारे का अभाव हो गया। नगरों में बड़े बड़े कारखाने खुलने लगे कारण लोगों को सहायक कार्यों—यथा कुनने व काटने द्वारा अतिरिक्त आय के भी वंचित होना पड़ा।

ब्रिटिश कृषि (१८५० से प्रथम महायुद्ध के आरम्भ तक)

ब्रिटेन की कृषि के इन ६४ वर्षों (सन् १८५० से १९१४) के इतिहास को हम दो भागों में विभक्त कर अध्ययन कर सकते हैं। प्रथम काल सन् १८५० से १८७५ तक जो ब्रिटिश कृषि का स्वर्ण-युग कहलाता है और द्वितीय सन् १८७५ से १९१४ तक जिसे मन्दी का युग कहते हैं।

(१) स्वर्ण युग (१८५०-१८७५) सन् १८७० तक इंग्लैंड की हुरि में आयातीत मुघार दो जुगा था। कृषि क्रान्ति के फलस्वरूप समावरण आन्दोलन तथा बड़े बड़े खेतों की स्थापना हो चुकी थी। छोटे छोटे कृषकों का शरा लोप हो चुका था और वे बड़े नगरों में आ बसे थे। इस समय वसारी समाप्त हो गई और हुरि के अतिरिक्त अन्य कार्यों द्वारा लोगों की आय में वृद्धि हो रही थी तथा उनका जीवनस्तर बढ़ता जा रहा था। फसलों की हेरफेर की प्रणाली तथा रासायनिक खाद के कारण प्रति एकड़ उपज बढ़ गई।

इस समय देश में रेलों की स्थापना हो चुकी थी, जिससे मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से भेजा जा सकने लगा। व्यापार और उद्योग की भी उन्नति अवस्था हो गई। अन्न की मांग बढ़ रही थी, जिसने अनाज के मूल्य में काफी वृद्धि हो चुकी थी। उद्योगों

में लगे हुए भूमिकों का वेतन स्तर बढ़ता जा रहा था तथा जनता की सामान्य क्रयशक्ति भी घट गई थी। व्यापार तथा उद्योग की सम्पन्नता का कृषि पर भी बड़ा अनुत्पन्न प्रभाव पड़ा। कृषकों को अच्छा लाभ हुआ और उनकी आय बढ़ी। कृषि सुधार तथा अनुसंधान के लिये कई संस्थाएँ स्थापित हुईं। समय व भूमि वृद्धि के लिये नाना प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया गया, जिससे कृषि व्यवसाय बड़ा सरल हो गया। इसी काल में कृषि प्रदर्शनियों तथा उपज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यद्यपि अब कानून सन् १८४६ में ही समाप्त कर दिये गये थे तथापि बाहर से अन्न का आयात किया जा सकता था, परन्तु फिर भी कृषि इतनी उन्नत अवस्था में थी कि वह इस बड़ी हुई मांग की भली प्रकार पूर्ति कर सकती थी। बाहर से आयात किया अनाज महंगा पड़ता था।

मन्दी का युग (१८७५ से १९१४)

ब्रिटेन की कृषि का यह स्वर्णयुग सन् १८७५ में समाप्त हो गया। उसके बाद कृषि व्यवसाय का स्थिति सकटकालीन हो गई। यह युग कृषि के लिये घोर मन्दी का था। इस मन्दी के कई कारण थे, जिनमें सबसे प्रमुख कारण १८७५ के परधातु बार बार फसलों का खराब होना था। १८८० में ड्यूक ऑफ रिचमण्ड की अध्यक्षता में जो राजकीय आयोग नियुक्त हुआ था, उसके अनुसार मन्दी के निम्न कारण थे —

(१) लगातार खराब फसलों के कारण अन्न की कमी हो गई। इस कमी को बाहर के देशों से लाया जा आयात करके पूरी किया गया। विदेशी प्रतियोगिता के कारण भी कृषि की हानि उठानी पड़ी।

(२) १८७५ से १८८४ तक अधिक वर्षा एवं अधिक शीत से फसलों को बहुत क्षति हुई। उसके बाद १९०० तक वर्षा की कमी के कारण उपज पर्याप्त न हो सकी।

(३) पशुओं में कई प्रकार की बीमारियाँ फैल गईं। परिणामस्वरूप पशुओं, भेड़ों एवं सुअरों की भारी संख्या में मृत्यु हो गई।

(४) सन् १८८५ में कनेडियन पैसिफिक रेलवे बन जाने से अमेरिका के उपजाऊ मैदानों का गेहूँ ब्रिटेन के बाजारों में आने लगा। इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, अरजेन्टीना, रूस व भारत के गेहूँ के कारण भी अन्तर्राष्ट्रीय मन्दी उत्पन्न हो गई।

(५) प्रसीतन विधि के आविष्कार हो जाने से आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अरजेन्टीना तथा अमेरिका से भेड़ों तथा सुअरों का मांस आयात होने लगा। इससे अतिरिक्त मछली, मक्खन, पनीर, फल और सब्जी भी भारी परिमाण में इंग्लैंड में आयात की जाने लगी। इससे ब्रिटिश कृषि में और भी मन्दी आ गई।

मन्दी के परिणाम

मन्दी का सबसे घातक परिणाम यह हुआ कि अनाज के मूल्यों में भारी कमी आ गई। कृषकों की आय बहुत कम हो गई। कृषि मजदूरों का वेतन भी घट गया। छोटे कृषकों,

की तो दशा बहुत ही बिगड़ गई। वे निराश्रय होकर और गांवों को छोड़कर नगरों में बसने लगे।

इस समय इंग्लैंड का उद्योग और व्यापार उन्नत अवस्था में था। पार्लियामेंट में भी ऐसे ही व्यक्तियों का बहुमत हो गया था। अतः निर्बाध व्यापार (Free Trade Policy) का अपनाया जाना स्वाभाविक हो गया। इस नीति के कारण ब्रिटेन में माल और खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा। ब्रिटेन की कृषि को प्राप्त संरक्षण समाप्त हो गया।

सुधार के प्रयत्न

सन् १८६४ के बाद कृषि की गिरती हुई दशा चिन्ता का प्ररत बन गया। उसके पुनर्निर्माण व सुधार के उपाय सोचे जाने लगे। लोग इन समस्याओं में रुचि लेने लगे। मन्दी के कारणों की जांच के लिये सन् १८८२ में एक शाही कमीशन की नियुक्ति हुई जिसने मन्दी के कारणों पर प्रकाश डाला। सन् १८६१ में एक और शाही कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने मन्दी के परिणामों एवं उपायों पर विचार किया तथा सुधार के लिये कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इसके अनुसार विदेशी प्रतिযোগिता को देखते हुए इंग्लैंड में खाद्यान्नों की खेती करना लाभदायक नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कृषि व्यवसाय द्वारा नई दिशाएं अपनाये जाना आवश्यक था, जैसे बागबानी, तरकारी उत्पादन करना, डेयरी व्यवसाय, भेड़ पालना तथा मुर्गी-मुर्गी पालना आदि।

बीसवीं सदी में प्रारम्भिक वर्षों में ब्रिटिश कृषि में सुधार के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। लोगों ने खाद्यान्न बोना कम कर दिया तथा कृषि के सहायक उद्योग अपनाये जाने लगे। ब्रिटेन को अब तक मेहूर में आत्मनिर्भर था, अब ६० प्रतिशत मेहूर का आयात करने लगा। इस प्रकार खाद्यान्नों की पूर्ति के लिये ब्रिटेन परावलम्बी हो गया। देश में जनसंख्या का केवल १० प्रतिशत भाग ही कृषि व्यवसाय में रह गया। वे भी खाद्य पदार्थों के स्थान पर मांस, ऊन, फल-फूल, तरकारियां, दूध, मक्खन, पनीर और अण्डों का उत्पादन करने लगे।

इन यन्त्रों के उत्पादन में अधिक व्यक्ति तथा मजदूरों की आवश्यकता थी। गांवों में बहुत थोड़े व्यक्ति रह गये थे, जो भी अकुशल थे। बड़े बड़े गेहूँ के कारण भूमिकोशा गांवों में कोई स्थान न था। अतः मजदूरों का अभाव था। कुशल मजदूरों को गांवों में रोकने और बसाने के उद्देश्य से छोटे छोटे खेतों की स्थापना में रुचि ली जाने लगी। सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाये। सन् १८८७ में यह कानून बना कि स्थानीय अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे बड़े भूमिपतियों से भूमि खरीद कर अथवा पट्टे पर लेकर छोटे छोटे कृषकों को दें। यह लगभग वैसा ही आन्दोलन था, जैसे हम भारत में आत्र भूदान आन्दोलन के रूप में देखते हैं। सन् १९०७ में Small Holdings and Allotment Act पास किया गया जिसके अनुसार काउन्टी काउन्सिलों के लिये यह आवश्यक है कि वे भूमिहीन व्यक्तियों के लिये भूमि का प्रबंध करें; यह कानून बहुत सफल रहा।

सन् १८८६ में कृषि बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका कार्य कृषि सम्बन्धी शिक्षा का नेरीक्षण व निर्देशन करना था। सहकारिता के सिद्धान्त को अपनाया गया तथा भूमि और कृषि कार्य के लिये उदारतापूर्वक ऋण दिये जाने लगे। पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिये भी कई उपाय किये गये। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप १९१४ तक इंग्लैंड की कृषि में पर्याप्त सुधार हो चुका था। यद्यपि उत्पादन की दृष्टि से इंग्लैंड आत्मनिर्भर नहीं था, फिर भी सगटन एवं कुशलता की दृष्टि से ब्रिटेन का कृषि व्यवसाय फिर अपनी बढ जमा चुका था।

प्रथम महायुद्ध तथा कृषि नीति

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में कृषि की दशा अच्छी न थी। शताब्दी के अन्त में कृषि का निम्न बिन्दु आ चुका था। किसानों ने यह अनुभव किया था कि उन्हें नवीन परिस्थितियों के अनुकूल बदल जाना चाहिये। खाद्य पदार्थ के आयात की रोकने की वि आशा नहीं कर सकते थे। अनाज का आयात बराबर हो रहा था तथा रेल-मार्गों के विकास तथा बहाजरानी की उन्नति होने से सुदूरवर्ती खाद्यान्न उत्पादक देशों से बड़ी प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। खाद्यान्नों के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर मास, पनीर, फल आदि का आयात हो रहा था।

यद्यपि बीसवीं सदी के आरम्भ में सरकारी मोताबिक से कुछ सुधार हुआ, परन्तु फिर भी कृषि आत्मनिर्भर न हो पाई। ब्रिटिश कृषि वर्ष में केवल १२० दिनों के लिए खाद्यान्न उत्पन्न कर पाती थी, शेष दिनों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। जने हुए मास के आयात के बाद भी पशुपालन इंग्लैंड में लाभप्रद बना रहा। क्योंकि यहाँ का मास विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ था। इनके साथ दूध, अण्डे, मक्खन, पनीर, फल तथा तरकारियों की माग बराबर बढ रही थी। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के आरम्भ होने तक इंग्लैंड की कृषि कम हो गई तथा उसका स्थान कृषि के सहायक उद्योगों ने ले लिया।

सन् १९१४ में विश्वयुद्ध के कारण कृषि से पुनर्जीवन के लक्षण दृष्टिगोचर हुए। विदेशों से आयात करना दुर्लभ हो गया तथा खाद्य पदार्थ की माग तथा मूल्य बढने लगे। अतः अनाज उत्पन्न करने की आवश्यकता अनुभव की गई तथा कृषि के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होने लगा। ऐसे स्थानों पर भी कृषि की जाने लगी, जहाँ अब तक घास ही उत्पन्न की जाती थी।

सन् १९१६ में खाद्य मन्त्रालय स्थापित किया गया तथा एक खाद्य नियंत्रक की नियुक्ति की गई। प्रत्येक जिले में खाद्य समितियों की स्थापना हुई। खाद्य पदार्थ के उपभोग उत्पादन, वातायात एवं संचय के संबंध में नियन्त्रण लगाया गया। राशनिंग द्वारा माग और वितरण व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ, किन्तु उत्पादन विशेष नहीं बढ सका। सन् १९१७ में अन्न उत्पादन कानून बनाया गया, जिसके द्वारा गेहूँ और जई के

न्यूनतम लगान और वेतन निश्चित किए गए। केन्द्रीय कृषि बोर्ड और वेतन समिति नियुक्त की गई।

सन् १९१६ में ब्रिटिश कृषि की जाच के लिए शाही कमीशन नियुक्त हुआ और सन् १९२० में कृषि अधिनियम पास हुआ, जिसका उद्देश्य युद्ध के उपरान्त ब्रिटिश कृषि का स्थायी सुधार करना था।

प्रथम महायुद्ध के भी समाप्ति के बाद युद्ध के पूर्व की सामान्य दशाओं के कारण ब्रिटिश कृषि फिर कठिनाई में पड़ गई। विदेशों से अतिरिक्त खाद्यान्नों का आयात प्रारम्भ हो गया। ब्रिटिश कृषि विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असमर्थ हो गई। इसका कारण सरकारी अबाध व्यापार नीति (Free Trade Policy) था। ब्रिटिश अमीकी की कच्ची वेश्म दरें भी थीं। जिससे उत्पादन न्यून बढ़ गया, परिणामस्वरूप ब्रिटिश कृषि संकुचित होने लगी। कृषि की अपेक्षा पशुपालन अधिक लाभदायक हो गया। दूसरी ओर राज्य की ओर से कृषकों को उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की व्यवस्था थी, परन्तु मूल्य न्यूनतम दरों से भी नीचे गिर रहे थे। अतः राज्य द्वारा सहायता देने के कारण सरकार को लाखों पाँड़ की हानि प्रति वर्ष हो रही थी।

अतः में विश्व मन्दी से विवश होकर सन् १९२१ से अन्न के न्यूनतम मूल्यों की गारंटी दिए जाने की नीति का परिचालन करना पड़ा। सरकारी कृषि नीति के बारे में भारी मतभेद उत्पन्न हो गया। राष्ट्रीय कृषक सभ ने कृषकों के लिए साल सुविधाओं तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की मांग की। मजदूर दल ने कृषक अधिकों के लिए उच्च मजदूरी तथा अन्य सुविधाओं की मांग की। भूमि के राष्ट्रीयकरण की आशयकता पर भी जोर दिया गया, अतः कृषि की दशा में सुधार करना आवश्यक हो गया।

कृषि की दशा सुधारने के लिए सन् १९२१ में कृषि साल विधान पास किया गया, जिसके द्वारा उन कृषकों को जिन्होंने युद्धकाल में भूमि खरीदी थी, दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था की गई। इससे अनेक कृषकों को लाभ हुआ।

सन् १९२४ में कृषि वेतन समितियों की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य कृषि धर्मियों का वेतन निश्चित करना था। सन् १९२८ में एक दूसरा कृषि साल नियम पारित हुआ, जिसके अनुसार एक कृषि साल निगम की स्थापना की गई। इसके द्वारा उचित मूल्य पर लम्बी अवधि के लिए ऋण दिया जाता था।

इन सुधारों के अतिरिक्त कृषि उपज के लिए विपणन की भी समुचित व्यवस्था की गई। सन् १९३१ में (Agricultural Marketing Act) पास हुआ, जिसके अनुसार विपणन बोर्ड विभिन्न पदार्थों के अथर्विक्रय उत्पादन एवं मूल्य निश्चित करने के लिए स्थापित किए जा सकते थे।

सन् १९३१ ब्रिटिश कृषि के इतिहास में महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। इस वर्ष सरकार ने निर्बाध व्यापार की नीति को त्याग दिया और संरक्षण की नीति अपनाई। इस

नीति के अनुसार १९३७ से जई, आलू, कृषि मशीनों, साद आदि के आयात पर आयात कर लगा दिए। कृषि पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषकों को सरकार द्वारा धन के रूप में सहायता दी जाने लगी। परिणामस्वरूप १९३७—३९ तक ब्रिटिश कृषि की दशा में पर्याप्त सुधार हो गया और कृषि पदार्थों के मूल्य कुछ बढ़ गए।

द्वितीय महायुद्ध के समय ब्रिटेन में निरन्तर समस्या गंभीर हो गई। देश का उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति के लिए अपर्याप्त था तथा बाहर से अनाज का आयात करना कठिन हो गया। अतः कृषि के सम्बन्ध में प्रगतिशील नीति अपनाई गई। सन् १९३९ में कृषि मन्त्रालय को कृषि के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार दिये गये। एक कृषि प्रबन्धक समिति नियुक्त हुई। यह समिति भूमि के अपव्यय को रोकने एवं भूमि के लाभप्रद उपयोग के सम्बन्ध में अपने अधिकारों का प्रयोग करती थी। कृषि के पैनाज या उत्पादन वृद्धि के लिए कई अन्य उपाय किये गये। परिणामस्वरूप कृषि का क्षेत्रफल तथा उत्पादन भी बढ़ गया। मांग को नियंत्रित करने के लिये राशनिंग एवं मूल्य नियन्त्रण की प्रणाली काम में लाई गई। सन् १९४७ में ब्रिटिश कृषि ऐक्ट पस किया गया, जिसका प्रधान उद्देश्य कृषि मूल्यों में स्थिरता लाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना तथा कृषि-कुरलता में वृद्धि करना और लोगों को भूमि दिये जाने की व्यवस्था करना था।

१९५८ में ब्रिटिश कृषि की उन्नति के लिये गेहूँ की अपेक्षा चारे की फसलों पर अधिक ध्यान देने, अधिक मांग की उपज बढ़ाने तथा दूध, मांस व अण्डों के उत्पादन को बढ़ाने के सुझाव रखे गये। सरकार ने कृषि को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जिससे उद्योग का तीव्र गति से विकास हो सके।

प्रश्न

1. Give the salient features of Agricultural Revolution
2. Give a short analysis of leading features of British Agricultural Policy during world war I
3. Trace the history of English Agriculture from 1914 to 1939
4. Indicate the important reforms made in English Agriculture after 1939

औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व आर्थिक स्थिति

सन् १७६० से इंग्लैंड के आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन होने लगे, जिनमें वहाँ के आर्थिक जीवन में उथलपुथल मचा दी। इन परिवर्तनों का अध्ययन करने से पूर्व वहाँ की औद्योगिक क्रान्ति से पहले की आर्थिक अवस्था का विचार करना आवश्यक है।

सन् १७६० से पूर्व इंग्लैंड की अर्थ व्यवस्था कृषिप्रधान तथा व्यापारिक थी, परन्तु औद्योगिक न थी। लगभग ७० प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में ही रहती थी। नगरों का अधिक विकास न हो पाया था।

कृषि बहुत ही साधारण अवस्था में थी और कृषि का कार्य परम्पराओं एवं प्रथाओं के अनुसार चल रहा था। खेत छोटे आकार के थे और कृषि सामूहिक रूप से की जाती थी। तीन खेत का प्रचलन था, जिसके अनुसार खेत के तीन टुकड़ों में से एक का प्रतिवर्ष खाली छोड़ दिया जाता था, जिससे वह अपनी उर्वरा शक्ति फिर से प्राप्त कर ले।

चरागाह का उपयोग सब कर सकते थे, परन्तु अधिकार सामूहिक न थे। पशुओं बहुत थोड़ी थीं तथा अटल-बदल की प्रथा का ज्ञान न था। मेड़ों के पालने का व्यवसाय उचित दग से नहीं किया जाता था। कृषि के यन्त्र पुराने तथा पिछड़े हुए थे।

उद्योग-धंधों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग अन्न का था, जिसके प्रमुख केन्द्र नार्विच, मेडम्प्टन, साउथम्प्टन। दूसरा मुख्य उद्योग लोहे का था, जो लगभग साइथेल्स में ही केन्द्रित था। लोहा पहले लकड़ी के कोयले द्वारा पिनाया जाता था, परन्तु अब कोयले से उत्पन्न कोक से। कोयले का उद्योग अधिक महत्वपूर्ण न था। इसके केन्द्र लकाशायर, मैन्चेस्टर व बोम्बन थे। सूत काटने तथा बुनने वाले गाँवों में रहते थे। उद्योग का सन्तानन वस्त्र व्यापारी के हाथ में था जो शहर में रहता था। गुलाई, रगाई, छपाई शहरों में होती थी। इसके अतिरिक्त सिल्क उद्योग तथा होजरी उद्योग भी विद्यमान थे। अधिकतर औद्योगिक उत्पादन घरेलू था और पूँजीपति अधिक सम्पन्न न थे।

व्यापार अधिक क्लिष्ट न था। अधिकतर मेलों में व्यापार होता था। वहाँ के निर्माण के कारण व्यापार उन्नति करने लगा था। यातायात के साधन विकसित नहीं थे।

सड़कों की दशा बहुत हीन थी। सन् १७६० के आसपास नहरों द्वारा कुछ यातायात होता था। औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व इंग्लैंड की दशा का वर्णन सत्येप में हम बी० डी० एच० कोल के शब्दों में कर सकते हैं,—“इंग्लैंड एक व्यापारिक दृष्टि से उन्नत तथा औद्योगिक प्रगति में उत्साह देने वाला राष्ट्र था, न कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत एवं व्यापारिक खोज करने वाला राष्ट्र।”

औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution)

सन् १७५० से १८५० के काल में इंग्लैंड के आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, उन्हें औद्योगिक क्रान्ति के नाम से पुकारा जाता है। सन् १७६० इंग्लैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि इसके पश्चात् ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति का सुरुवात हुआ।

प्रायः क्रान्ति शब्द का अर्थ रूढ़ी विद्रोह अथवा आकस्मिक उथल-पुथल लगाया जाता है, जैसे १७८९ की फ्रांस की क्रान्ति अथवा सन् १९१७ की रूसी क्रान्ति। यदि हम उक्त काल में हुए इंग्लैंड के आर्थिक परिवर्तनों का अर्थ इसी दृष्टिकोण से लगाते हैं तो उन्हें क्रान्ति कहना अनुचित होगा क्योंकि वहाँ इस काल में न तो कोई रूढ़ी विद्रोह ही हुआ और न कोई आकस्मिक उथल-पुथल ही। ये परिवर्तन औद्योगिक क्षेत्र में सन् १७६० से होने आरम्भ हुए और शनैः शनैः सन् १८५० तक होते रहे। ऐसे शान्त एवं सुव्यवस्थित परिवर्तनों को यदि हम क्रान्ति के स्थान पर अधिक प्रिफरेंस करें तो अधिक उपयुक्त होगा।

किन्तु फिर भी इन औद्योगिक परिवर्तनों को क्रान्ति ही कहा जाता है। बड़े बड़े लेखकों ने इनके लिये औद्योगिक क्रान्ति शब्द का ही प्रयोग किया है। इसका कारण यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों के परिणाम इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्होंने इंग्लैंड के आर्थिक क्षेत्र के प्रत्येक अंग में एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न कर दी। यद्यपि उस समय के लोगों को कदाचित् इस बात का आभास नहीं हुआ कि असाधारण परिवर्तन हो रहे हैं, किन्तु फिर भी ये परिवर्तन इतने क्रान्तिकारी थे कि इन्होंने न केवल उद्योगों में ही बल्कि कृषि, व्यापार एवं यातायात में भी आश्चर्यजनक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। जिस प्रकार क्रान्ति के पश्चात् प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था का जन्म होता है, उसी प्रकार औद्योगिक क्रान्ति के बाद इंग्लैंड में जिस नई आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ, वह प्राचीन से नितान्त भिन्न थी। यही नहीं इंग्लैंड की इस क्रान्ति का विश्व के अन्य देशों की आर्थिक व्यवस्था पर भी गहरा और निश्चित प्रभाव पड़ा। अतः इसे क्रान्ति कहना ही उचित होगा। नॉबेल (Knowles) के अनुसार इसे क्रान्ति इसलिए नहीं कहा जाता कि जो परिवर्तन हुए वे बड़ी शीघ्रता से हुए, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि जो परिवर्तन हुए, वे महत्वपूर्ण या क्रान्तिकारी थे।

औद्योगिक क्रान्ति ब्रिटेन में सर्वप्रथम हुई:—

जैसे औद्योगिक क्रान्ति ग्रेट ब्रिटेन में हुई, वैसे ही अन्य देशों में भी हुई। परन्तु ब्रिटेन अन्य देशों का अग्रणी रहा। इसके कई कारण थे—

(१) उत्तम भौगोलिक स्थिति:— इंग्लैंड योरोप के इतने निकट है कि सरलतापूर्वक व्यापारिक सम्बन्ध रख सकता है, परन्तु इंग्लिश चैनल के द्वारा महाद्वीप से वृष्य भी है। अतः स्थानीय आक्रमणों से सुरक्षित रहा है। दूसरी ओर अटलांटिक महासागर के उस पार अमेरिका का घनी महाद्वीप है। इस प्रकार इंग्लैंड दोनों महाद्वीपों के मध्य स्थित है। स्पेस नहर के निर्माण के बाद से तो यह विश्व के सब देशों से सम्पर्क स्थापित करने में सक्षम हो सका और औद्योगिक क्रान्ति के लिये उपयुक्त हुआ।

(२) अनुकूल जलवायु:— यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। न यहाँ कठु सर्दी होती है और न विषम गर्मी। जलवायु की यह समता यहाँ के निवासियों को कठिन शारीरिक और बौद्धिक परिश्रम के लिये प्रेरित करती रही, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन सबसे प्रथम इंग्लैंड में हो सम्भव हो सके। जलवायु के अनुकूल होने से ही यहाँ महान व उत्तम प्रकार का वस्त्र उद्योग चलने लगा।

(३) कटा-फटा समुद्रतट:— यहाँ के समुद्रतट की लम्बाई ७००० मील है और यह इतना कटा-फटा है कि सुरक्षित खाडियाँ बन गई हैं, जिनमें अनेक विरवविख्यात प्राकृतिक बन्दरगाह हैं। देश का कोई भाग समुद्र से ६० मील से दूर नहीं है। इसी कारण यहाँ का बहानी बेड़ा भी उत्पत्ति कर गया। बहाव निर्माण उद्योग और मत्स्य व्यवसाय भी यहाँ अधिक विकसित हो सके।

(४) पूँजी की प्रचुरता:— इंग्लैंड के व्यापारियों ने १७वीं और १८वीं शताब्दी में व्यापार में कानूनी धन एकत्रित कर लिया था। इस पूँजी की प्रचुरता के कारण ही वहाँ बैंकिंग व्यवसाय का विकास पहले हुआ, जिसने वहाँ नये उद्योगों के विकास में सहायता दी। सादृशी प्रवृत्ति के ब्रिटिश व्यापारियों ने नये आर्थिक कार्यों में रुनबा लगाने का बोलिया उठाया, जिसके कारण वहाँ आर्थिक क्रान्ति हुई।

(५) श्रमिकों की सुलभता:— मेनोरियल प्रणाली की सन्तानि के फलस्वरूप गाँवों के निरुधित लोग शहरों में आकर बस गये थे और नगरों में ऐसे लोगों की वृद्धि होती जा रही थी। अतः उद्योगों में श्रमिकों को कार्य मिलता गया और उद्योगों की श्रमिकों की कमी नहीं प्रतीत हुई।

(६) व्यापार क्षेत्र का विस्तार:— सन् १७६० के बाद इंग्लैंड का शासन कई महाद्वीपीय देशों में कायम हो चुका था और उसके उपनिवेशों के बाजार उसके हाथ में आने का रो दे उन देशों से कच्चा माल प्राप्त करने और इंग्लैंड में निर्मित माल वहाँ बेचने की सम्माननाई बढ़ गई थी। योरोप के अन्य देशों में ऐसी परिस्थिति नहीं थी।

इंग्लैंड ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाया, जिसके कारण सर्वप्रथम वहाँ उद्योगों का विकास हुआ।

(७) राजनैतिक सुदृढता — राजनैतिक स्वतन्त्रता और आन्तरिक शान्ति इस देश के जीवन की एक विशेषता रही है। यह देश योरोप का एक भाग होते हुए भी योग्य से पृथक् रहा है। यही कारण था कि जब महाद्वीप के अन्य देश एक-दूसरों एवं बाहरी आक्रमणों से अस्त रहे, तब इंग्लैंड इनसे निष्कुल रहित रहा और इसी व्यापार व उद्योग का विकास करने का अवसर मिल गया।

(८) कोयले और लौह की खानें — कोयले और लौह का इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भाग रहा है। इन खनिज पदार्थों के साथ साथ कारखानों की स्थापना सरल हो गई जो औद्योगिक क्रान्ति के विशिष्ट अंग बन गये।

(९) आविष्कार :—स्वचालित या शक्तिचालित मशीनों के आविष्कार सर्वप्रथम वहाँ हुए—मुख्यतः कर्मी और सूती वस्त्र उद्योगों में। इन आविष्कारों ने बाद में रासायनिक व लौह उद्योगों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन किये। इस प्रकार उत्पादन के लिये मशीनों का प्रचलन होता गया।

(१०) ब्रिटिश सरकार ने भी वहाँ के उद्योग धंधों के विकास में कानो आर्थिक सहायता दी। आविष्कारों के पेटेन्ट बनाने की सुविधाएँ दी गईं और रायब मौसादटी आफ आर्ट्स न आविष्कारों को उत्साहित किया। क्राम की वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया गया और १७६६ में क्राम निर्मित कुमाल रखने पर एक ब्रिटिश रजि. पर २० पाउंड का जुर्माना किया गया।

औद्योगिक क्रान्ति की विशेषताएँ

नॉब्लिस (Knowles) के अनुसार इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति में निम्नलिखित ६ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का समावेश था और ये परिवर्तन परस्पर एक-दूसरे से प्रभावित थे।

(१) सूती वस्त्र उद्योग में मशीनों की परम्पत तथा निर्माण के लिए दक्ष लोगों की आवश्यकता थी। अतः इन्जिनियरिंग उद्योग का विकास हुआ। अन्य भारी मशीनों, रेल्वे इन्जनों आदि के निर्माण के लिये इस उद्योग का विकास आवश्यक था। किन्तु इस उद्योग के लिए लौह और इस्पात उद्योग का विकास होना भी बकरी था।

(२) इन्जिनियरिंग उद्योगों में मशीन तथा औजार बनाने के लिए इस्पात तैयार करना आवश्यक था क्योंकि अन्धो स्टील के अभाव में मशीनें नहीं बन सकती थी। अतः अन्धे निस्म का इस्पात निर्माण करने की नई प्रक्रियाओं का आविष्कार किया गया।

(३) स्टीम से चलने वाली इन मशीनों का प्रयोग सूती वस्त्र उद्योग में किया गया। सन् १७६४ में स्पनिंग जेनी (Spinning Jenny) का आविष्कार हुआ।

सन् १७६८ में आर्नराइट ने वाटर फ्रेम तथा क्रॉम्पटन (Crompton) ने मूल (Mule) का आविष्कार किया। इन मशीनों से कातने में सरलता हो गई। सन् १८१५ तक कार्टव्राइट (Cartwright) तथा जॉन्सन (Johnson) के प्रयत्नों से शक्तिचालित करघे का आविष्कार हुआ, जिससे बुनाई भी सरल हो गई। बाद में इन मशीनों का उपयोग कनी वस्त्र उद्योगों में भी हो गया।

(४) रासायनिक उद्योगों का भी विकास हुआ। कपड़ों की धुलाई, रंगाई व इसाई आदि के लिये विविध प्रकार के रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता अनुभव हुई। अब बड़े बड़े रासायनिक कारखानों का निर्माण किया गया।

(५) उपर्युक्त सारे उद्योगों के लिए कोयले की भारी परिमाण में आवश्यकता थी, क्योंकि यही शक्ति का प्रमुख साधन था। अब कोयला उद्योग का विकास अनिवार्य था। इसमें भी वाष्प इंजिन ने बड़ी सहायता दी क्योंकि गहरी कोयलों की खानों से कोयला उठाने और पानी बाहर निकालने में इन इंजिनों ने ही सहायता दी। अब भारी मात्रा में कोयले का उत्पादन सम्भव हो गया।

(६) इतने उद्योगों के विस्तार तथा वृद्ध परिमाण में उत्पादन के साथ साथ यातायात के शीघ्र साधनों का विकास आवश्यक था, क्योंकि कच्चा माल, निर्मित माल तथा कोयला एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना जरूरी था। इसमें रेल्वे इंजिन ने सहायता दी और इंग्लैंड के बड़े बड़े नगर रेलों से मिला दिये गये, जिससे माल आदि के यातायात का प्रश्न सरल हो गया।

इन परिवर्तनों ने इंग्लैंड के सारे आर्थिक जीवन का टाचा ही बदल दिया। आर्थिक जीवन में परिवर्तन के साथ साथ लोगों के सामाजिक और राजनैतिक जीवन में भी परिवर्तन हुए। देश में एक नये युग का आरम्भ हुआ।

औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव

सामाजिक प्रभाव :—

(१) औद्योगिक क्रान्ति के कारण ब्रिटेन की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रथम जनगणना १८०१ में हुई थी। अनुमान से १७५० में ब्रिटेन की जनसंख्या ६० लाख थी यह बढ़कर १८०१ में ८७ लाख हो गई। १८५१ तक यह दुगुनी हो गई। औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व अधिकांश व्यक्ति गावों में रहते थे। ब्रिटेन की आबादी अधिकांश दक्षिण-पूर्व के जिलों में थी। उत्तरी इंग्लैंड बहुत कम बसा हुआ तथा वीरान था। औद्योगिक परिवर्तनों के फलस्वरूप नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा दक्षिण वेल्स एवं मिडलैंड के कोयला तथा लौहा क्षेत्रों में आबादी घनी हो गई। वर्तमान समय में इंग्लैंड ३/४ से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है।

(२) अधिक वर्गों सम्बन्धी कई समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। चूंकि उस समय निर्वाय व्यापार नाविक के सिद्धान्त दखल पर थे तथा राज्य नियंत्रण एवं नियमन समाप्त

हो रहे थे। इनके कारण अधिक वर्ग पर कुप्रभाव पड़ा। उन्हें सरक्षण मिलना बंद हो गया। वे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते थे। प्रारम्भ में अधिक सत्ता की स्थापना करने के प्रयत्न भी कानून द्वारा दबा दिये गये।

(३) फ़ैक्टरी सिस्टम के सुनपात के समय अधिक तथा यन्त्रों का सम्बन्ध बदल गया। पहिले बड़ा अधिकारी की शक्ति से काय होता था। अब अधिक केवल मशीनों के सहायक सत्ता नियन्त्रण मात्र हो गये। उत्पादन करने वाले मशीनों का स्थान प्रमुख व अधिकारों का स्थान गौण हो गया।

(४) इस समय इंग्लैंड में पूँजी पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो रही थी, अतएव इंग्लैंड में एक नये वर्ग—पूँजीपतियों का उदय हुआ। पूँजीपतियाँ तथा अधिकारों के सम्बन्ध बिगड़े, जिनसे कई नई औद्योगिक सर्प की समस्याएँ उत्पन्न हुई।

(५) सस्ती मशीनों के उत्पादन के कारण अधिकारी की आवश्यकताएँ बढ़ गई तथा उनका जीवन स्तर भी बढ़ा। अधिक वर्ग को अपार कष्ट हुआ। यद्यपि उन्हें रोजगार मिल सकता था, पर निर्वाध नीति के कारण सरकारी हस्तक्षेप के अभाव, पूँजीपतियों की अधिक वर्ग के प्रति अपमानित जा रही नीति, कम मजदूरी अधिक काम के घण्टा इन्हें के निरत रहने सहन योग्य मकानों के अभाव के कारण उनकी स्थिति अमेरिका के नीचो दासों से भी अधिक शोचनीय हो गई थी।

(६) फ़ैक्टरी सिस्टम के कारण देश की पूँजी तथा सम्पत्ति में अपार वृद्धि हुई। दूसरी ओर औद्योगिकरण के कारण भूमि की सगठित होने का अवसर मिला और यद्यपि कुछ समय तक उनकी स्थिति दयनीय रही परन्तु तुरन्त यह अनुभव किया गया कि अधिकारों की क्रायत्वमत्ता बढ़ाना उतना ही आवश्यक है, जितना कि कारखानों का उत्पादन। उद्योगों के विकास से इंग्लैंड में रोजगार सम्बन्धी समस्याओं का अन्त हुआ।

आर्थिक राजनैतिक प्रभाव

- (१) नये उद्योगों का विकास हुआ।
- (२) व्यापार में क्रान्ति हुई। व्यापार का क्षेत्र बढ़ गया। इंग्लैंड में बाहर से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ आने लगे और निर्मित माल बाहर जाने लगा।
- (३) इंग्लैंड के उत्तरी जिला को महत्व प्राप्त हो गया क्योंकि कोयला और लोहे की खानें उनके समीप थी और उद्योग वहीं स्थापित हुए।
- (४) उत्पादन का आकार बढ़ गया, अन्त विभाजन और विशिष्टीकरण का जन्म हुआ।
- (५) कई प्रकार के सहायक उद्योग खुल गये—मध्यस्थ लोगो को काय मिलने लगा।
- (६) बैंकिंग तथा बीमा व्यवस्था और यातायात में भी भारी परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड की सरकारी नीति में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ तथा कम से कम सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाने लगी।

हो गई कि उसका कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों की कमी होने लगी। अतः अब कपड़ा बुनने के लिए उत्तम करधों का आविष्कार करने के लिए प्रयत्न किया जाने लगा। यह आविष्कार सन् १७८५ में एडमण्ड आकराइट ने किया। यह भाप की शक्ति से संचालित किया जाता था और इस प्रकार कपड़ा शीघ्र बुना जाने लगा। बाद में इसमें कई सुधार किये गये।

इन चारों आविष्कारकों ने सूती वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिये। बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई ए० लकाशायर विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केन्द्र बन गया। बाद में इन मशीनों का उपयोग कनीय रेशमी वस्त्र उद्योगों में भी किया जाने लगा।

प्रश्न

1. *Is it correct to call what took place in England between 1750 and 1850 an Industrial Revolution? Explain the term. Why did it occur first in England?*
2. *Give a brief sketch of Industrial Revolution. How did it affect the people of England?*
3. *Discuss the importance of Arkwright, Cartwright, Crompton & Kay in British Industrial History.*
4. *Describe the economic, social & political effects of Industrial Revolution in England.*

१६वीं सदी तक इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति सफलता की न्यून सीमा तक पहुँच चुकी थी और यह विस्मय का नैता बन चुका था। इंग्लैंड के उद्योगों में हम वहाँ के तीन प्रमुख उद्योगों का अध्ययन करेंगे — (१) वस्त्र उद्योग, (२) लौह उद्योग और (३) लौह व इस्पात उद्योग।

(१) सूती वस्त्र उद्योग

१८वीं सदी तक इंग्लैंड सूती वस्त्रों का उत्पादन नहीं था। ऊन वस्त्रों का उत्पादन यहाँ प्रचुरता से होता था किन्तु सूती वस्त्र यहाँ भारत से आयात किया जाता था। १६वीं सदी के अन्त में कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं, जिनके कारण वह स्वरूप एक बड़ा भारी सूती वस्त्र उत्पादन बन गया। इसके निम्नलिखित कारण थे —

(१) १८वीं सदी में इंग्लैंड में ऊन का अभाव।

(२) सन् १७०० के बाद भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबन्ध।

(३) इंग्लैंड के व्यापारियों द्वारा सूती कपड़े की मांग।

(४) सन् १७६० के बाद कटाई और बुनाई में नये नये आविष्कारों का होना जैसे

Spinning Jenny, Water Frame, Mule आदि जिनका विस्तृत वर्णन पूर्व अध्याय में किया गया है।

(५) रासायनिक उद्योग के विकास के कारण मुलाई, रंगाई एवं छ्दाई के कार्य में सुगमता हुई।

(६) उपनिवेशों की स्थापना के कारण विस्तृत बाजारों का प्राप्त हो जाना, जिनके फलस्वरूप भारी धातु में इंग्लैंड के कपड़े की खपत अन्य देशों में सम्भव हो गई।

(७) यातायात के उत्तम व शीघ्र साधनों का विकास यद्यपि इंग्लैंड न तो कपास का उत्पादन ही रहा है और न वहाँ सूती वस्त्रों का इतना अधिक प्रयोग हो किया जाता है, परन्तु उसके अप्रत्यक्ष, सहस्र, कुशलता और आविष्कार के कारण ही इस उद्योग का विकास सम्भव हो सका। इस उद्योग की उत्पत्ति यहाँ इतनी अधिक हुई कि प्रथम विश्वयुद्ध के समय इंग्लैंड विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन बन गया था।

इंग्लैंड में इस उद्योग के लकाशायर के पास स्थापित होने के निम्न लिखित कारण थे—

(१) अनुकूल जलवायु—लकाशायर में साल भर वर्षा होती रहती है, अतः वहाँ की जलवायु नम है तथा उस जलवायु में घासा नहीं सूखता है और बाँधी सूत की कटाई सम्भव है।

(२) पहाड़ों के नालों तथा कस्बों से स्वच्छ जल की प्राप्ति हो जाती है, जो कपड़े व सूत की धुलाई के लिये आवश्यक है।

(३) लकाशायर के समीप ही कोयले की खानों के होने के कारण कपड़े की मशीनों को आवश्यक शक्ति उपलब्ध हो गई।

(४) कपास के आयात और वस्त्रों के निर्यात के लिये निवरपूल (Liverpool) का शार्डर्स बन्दरगाह।

यद्यपि प्रथम महायुद्ध के समय कुछ कठिनाइयाँ आईं, परन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद जिन निर्यात देशों में माँग बढ़ जाने के कारण वस्त्र उद्योग उन्नति करने लगा। सन् १६०० तक यह उद्योग एक सफल उद्योग था। उसके बाद विश्व-मन्दी के कारण उद्योग की दशा गिरने लगी और तब से आज तक गिरती ही जा रही है। इसके निम्न कारण हैं—

(१) पूर्वी देशों में औद्योगिक प्रगति—भारत, चीन जापान तथा मध्यपूर्व के देशों में औद्योगीकरण की गति तीव्र हो गई, इन देशों ने सूती वस्त्र उद्योग स्थापित कर लिये और इस प्रकार ब्रिटिश वस्त्र की माँग कम हो गई।

(२) विदेशी प्रतिযোগिता—सन् १६०० के बाद जापान में सूती वस्त्र का विकास अधिक होने लगा और वह ब्रिटेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगा। जापानी कपड़ा सस्ता होने के कारण दक्षिणी-पूर्वी एशिया के अनेक देशों के बाजारों में बिकने लगा।

(३) राष्ट्रीय भावना व आयात वस्त्र—बहुत से देशों में राष्ट्रीय भावना के कारण विदेशी माल का बहिष्कार किया जाने लगा। विशेषकर भारत में इस भावना के कारण ब्रिटिश वस्त्रों की माँग बहुत गिर गई। इसके अतिरिक्त अन्य देशों ने आयात पर भारी कर लगा दिये, ताकि उनके उद्योग को संरक्षण प्राप्त हो सके।

(४) उत्पादन लागत में वृद्धि—ब्रिटेन में उद्योग का सगठन दोषपूर्ण हो गया। बच्चा माल बेगाने में यातायात व्यय अधिक होता था। ब्रिटिश मजदूरों का वेतन-स्तर कम था। अतः उत्पादन की लागत बहुत अधिक हो जाती थी।

इन सब कारणों से सन् १९३०-३१ तक उद्योग की दशा बहुत गिर गई। उद्योग के पुनर्गठन के लिये आधुनिकतम मशीनें स्थापित की गईं। वैज्ञानिक प्रगति और विवेकीकरण के सिद्धान्तों को लागू किया गया। छोटी छोटी मिलों को मिलाकर बड़ी बड़ी मिलों की स्थापना की गई। सरकार तथा बैंक आफ इंग्लैंड ने सस्ती व्याज की दर पर मिलों को

शुरू देना आरम्भ कर दिया। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों से अन्य देशों की वस्तुओं की आयात कर में रियायतें प्राप्त कर लीं। विधिगोष्ठि शप्त करने के उद्देश्य से कृषि, नौरीक और उच्चकोष्ठ के वस्त्रों का ही उत्पादन होने लगा।

इन सब प्रयत्नों के कारण कुछ सुधार हो आया, किन्तु फिर भी ब्रिटेन की सूती वस्त्र उद्योग अपनी पूर्ण स्थिति को नहीं प्राप्त कर सका। द्वितीय महायुद्ध के बाद ही लकाशापर की सूती मिलों को फिर सङ्गठनीय स्थिति से सुवरना पड़ा। भारत में १९ उद्योग का इतना अधिक विकास हो गया है कि उसने एशिया के ही नहीं, बल्कि अफ्रीका और पश्चिमी योरोप के सब देशों में निर्यात आरम्भ कर दिया है।

परन्तु फिर भी इंग्लैंड का उद्योग बढ़ा के विदेशी व्यापार का विशेष भाग प्राप्त भी बना हुआ है। इसका कारण यह है कि समय के अनुसार उसका स्तर बदलता जा रहा है और सूती तथा सिन्थेसिक कपड़े बनाने के प्रतिष्ठित रेयन (Rayon) का भी उत्पादन करने लगा है।

(२) कोयला उद्योग (Coal Industry)

किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिये शक्ति के साधनों का होना अत्यन्त आवश्यक है। आरम्भ में ही ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में कोयले का बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग रहा है। बड़े बड़े मोठे के कारखानों तथा वातावरण के साधनों का विकास बस कोयले के बल पर ही सम्भव हो सका है। अतः यह कथन कि इंग्लैंड का आर्थिक इतिहास वास्तव में कोयले की खानों के विकास की ही कहानी है—सत्य है। ब्रिटेन की औद्योगिक शक्ति की आधारशिला कोयला ही है।

सन् १७७० से पूर्व कोयले का प्रयोग केवल ईंधन के लिये किया जाता था। वार्षिक उत्पादन ४० लाख टन में भी कम था। सन् १७६० के बाद से माप के इन्जिन का आविष्कार हो जाने से कोयले की माग बढ़ी। खानों के अन्दर से पानी निकालने के लिये माप के इन्जिन का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त अन्य कठिनार्यों को भी हल किया गया, जैसे प्रकाश व वायु तथा उचित तापमान की व्यवस्था, अन्दर से गहरी खानों का कोयला बाहर निकालने के लिये कुशल साधनों की व्यवस्था और कृत्रिम साधनों द्वारा रसायनप्रद वातावरण उत्पन्न करना आदि।

१८वीं सदी के अन्त में कोयले में कोक बनाने की विधि ज्ञात कर ली गई। इससे कोक के प्रयोग द्वारा उत्पाद बनाना सरल हो गया। नहरों तथा रेलों के निर्माण ने कोयले के वातावरण के प्रश्न को हल कर दिया। प्रथम महायुद्ध में अमिनों की कमी के कारण तथा निर्यात की कठिनाई के कारण उद्योग के समस्त कुछ कठिनाई आई। कोयले के उत्पादन व मूल्य के सम्बन्ध में सरकार ने हस्तक्षेप किया। परन्तु सन् १९२५ में निर्यात समाप्त कर दिया गया। मन्दी के कारण मूल्य गिरने लगे तथा अन्य देशों में भी कोयले

की खानों का विकास होने लगा। अतः इंग्लैंड के कोयले की मांग अपेक्षाकृत कम हो गई और उत्पादन कम हो गया।

सन् १६२२ में कोयला कमीशन नियुक्त हुआ। जिसने अनेक सुझाव दिये जैसे नई मशीनों का प्रयोग, कोयले का अच्छी विभाजन, विवेकीकरण तथा उत्पादन व्यय कम करने के लिये बड़ी बड़ी इकाइयों का निर्माण आदि। सन् १६३० में उत्पादन और विक्रय के सम्बन्ध में Coal Mines Act पास किया गया। सन् १६३७ में एक और एक्ट पास हुआ, जिसका उद्देश्य अनिवार्य एकीकरण करना तथा उत्पादन एवं विक्रय के सम्बन्ध में सुधार करना था।

द्वितीय महायुद्ध में फिर उद्योग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धमिकों की कमी हो जाने तथा निर्यात के बन्द हो जाने से उत्पादन भी कम हो गया। जुलाई १९४६ में कोयले उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये एक एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार कोयले की खानें सरकार के स्वामित्व एवं प्रबंध में आ गईं। १ जनवरी १९४७ को राष्ट्रीय कोयला बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके अधिकार में १५०० कोयले की खानें एवं अन्य सम्बन्धित उद्योग आ गये। बोर्ड का यह कर्तव्य था कि वह उद्योग का प्रबन्ध कुशलता से करे और राष्ट्रीय हित में कोयले का उत्पादन करके उचित मूल्य पर उसे जनता को प्रदान करे। १९५० में इस बोर्ड ने कोयले के उद्योग के विकास के लिये एक नई योजना बनाई, जिसका उद्देश्य कोयले का उत्पादन बढ़ाना तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना था।

परन्तु फिर भी उस उद्योग की वर्तमान दशा यह है कि यह देश की केवल आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है और बहुत ही थोड़ी मात्रा में कोयला निर्यात कर सकता है। इस प्रकार ग्रिन्ध का कोयला उद्योग जो आरम्भ में काले घीरे के समान था, घीरे घीरे अवनत दशा की ओर अग्रसर हो रहा है।

(३) लौहा-इस्पात उद्योग

आधुनिक युग में इस्पात का उत्पादन किसी भी देश के औद्योगिक विकास का मापदण्ड है। लौहा-इस्पात उद्योग इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्रमुख उद्योग रहा है। १९वीं सदी के अन्त तक इंग्लैंड इस उद्योग में विश्व का प्रमुख राष्ट्र बन गया।

१८वीं सदी के मध्य तक इंग्लैंड में लौहा लकड़ी के कोयले की सहायता से बनाया जाता था। कच्चा लौहा स्पेन और स्वीडन से आयात किया जाता था। बाद में पत्थर के कोयले का प्रयोग करके लौहा बनाया जाने लगा। याक्यायर, वेल्स और बर्मिंघम इसके केन्द्र बन गए। कोयले को कोक के रूप में परिवर्तन करने में सकलता मिल जाने से लोहे के बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जाने लगे।

सन् १८२१ के बाद रेलों के विकास के कारण भी इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला

और जिनेन से इस्पात का निर्यात भी होने लगा। सन् १८७५ तक इंग्लैण्ड विश्व का सबसे प्रमुख देश था। १८७५ के बाद अन्य देशों में भी इस्पात उद्योग का विकास होने लगा। धीरे धीरे अमेरिका और जर्मनी में इस्पात उत्पादन की मात्रा बढ़ने लगी और वटमान शताब्दी के आरम्भ में ये दोनों ही देश इंग्लैण्ड से आगे बढ़ गये। सन् १८९३ में अमेरिका इंग्लैण्ड से चार गुना अधिक इस्पात तैयार करता था।

सन् १८२० के बाद विश्वव्यापी मन्दी के कारण उद्योग की कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मूल्यों में कमी, अन्य देशों में इस्पात का उत्पादन, विदेशी प्रति-योगिता, निर्यात में कमी तथा ऊँचे उत्पादन व्यय। इन कठिनाइयों के कारण इस्पात उद्योग मन्दी के काल में अधिक प्रिकात नहीं कर सका।

सन् १८३१-३२ के बाद इस उद्योग का पुनर्गठित किया गया। बाहर से आने वाला इस्पात तथा अन्य सर्वाधिकत वस्तुओं पर स्वतन्त्र दर लगा दिये गए। उत्पादन व्यय में कमी करने के लिए छोटी छोटी इकाइयों का एकीकरण व विप्रेक्षीकरण किया जाने लगा। इस्पात के मूल्य स्थिर कर दिये गये सन् १८३० में ब्रिटिश इस्पात निर्यात वष स्थापित किया गया। उद्योग में बच्चे व आश्रित रहस्य दिये जाने की व्यवस्था की गई।

द्वितीय महायुद्ध में इंग्लैण्ड इस्पात निर्माण की दिशा में अधिक प्रगति नहीं कर सका। सन् १९४७ में नोबेल के संघट के कारण उद्योग की बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मांग की पूर्ति के लिए जिनेन को लगभग ४० लाख टन इस्पात अन्य देशों से आयात करनी पड़ी। ब्रिटिश लौह और इस्पात बोर्ड की स्थापना युद्ध के बाद की गई। नई उच्च कोटि की स्टील बनाई जाने लगी।

आज विश्व में इस्पात उत्पादन की दृष्टि से जिनेन का तृतीय स्थान है। वार्षिक उत्पादन १८० लाख टन है। प्रथम स्थान अमेरिका का है, बड़ा ६५० लाख टन स्टील बनता है, द्वितीय रूस का है बड़ा का उत्पादन ३७० लाख टन है। पश्चिमी जर्मनी ने भी इस उद्योग में काफी प्रगति कर ली है और उसकी स्थिति लगभग जिनेन के बराबर ही है।

जिनेन के इस उद्योग को प्रमुख रूप से दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है—प्रथम तो बच्चे मांग की अत्यन्त कमी है। जिनेन के बड़े हुए इस्पात उद्योग के लिए पिग आइरन का उत्पादन बहुत कम है। दूसरे कारखानों में काम करने के लिए अधिकों की कमी की समस्या है।

देश की आर्थिक प्रगति के लिए जिनेन को इस उद्योग को उन्नत बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसमें अधिक पूँजी लगी हुई है तथा यह आधारभूत उद्योग है।

प्रश्न

- 1 What led to the development of the Cotton Textile Industry in England, specially at Lancashire when England was neither producer nor consumer of cotton ?

Explain & discuss the causes of its downfall in post-war period

- 2 "The economic history of England can well be interpreted as the story of her Coal Mining" Discuss
- 3 Discuss the growth of British Iron & steel industry and write a few lines about its present position
- 4 Great Britain lost her leadership in one staple industry after another as modern industrialism spread over other countries"

Do you agree with this statement ? Discuss

औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप उद्योग और व्यापार का विकास हुआ। इनके विस्तार के साथ साथ ही यातायात के साधनों में भी प्रगति हुई। १७वीं सदी तक इंग्लैंड के यातायात के साधनों की बड़ी दुर्दशा थी। बिभिन्न के अनुसार "रोमन सड़कें, जो मध्य युग में अच्छी दशा में थीं समाप्तप्राय और जीर्णोद्धार में थीं। कई सड़कों का निर्माण तो दूर रहा, पुरानी सड़कों की मरम्मत भी ठीक ढंग से नहीं की गई।" यातायात के नाम पर केवल घोड़े और खच्चरों का ही प्रयोग होता था। उद्योग-धन्धे अविश्वसित थे, जनसंख्या कम थी तथा पूँजी का अभाव था। आग एडम शार्प के अनुसार "उस समय सड़कें केवल गन्दी ही नहीं थीं, अश्वि वहाँ खोर व हाथुओं का भी बाहुल्य था, जिसके कारण यात्रा दुर्लभ थी।"

यातायात के साधनों में हम निम्नलिखित का अध्ययन करेंगे।

१ सड़क, २ नहर, ३ रेल, ४ सामुद्रिक जहाज और ५ वायुयान।

१. सड़क

बहुत समय तक इंग्लैंड में सड़कों के निर्माण व देखभाल की ओर कीर्तित ध्यान न दिया गया। १८वीं शताब्दी में सड़कों की स्थिति सुधारने के प्रयत्न किये गये। परन्तु इच्छेप नहीं करने की नीति के कारण सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित था। सड़कों के निर्माण के लिये निजी उद्योग का ही सहारा लिया गया। सड़कों पर नियंत्रण का अधिकार उन घनी व्यक्तियों को दे दिया गया, जो सड़क बनाने में पूँजी लगाते थे। ऐसी निजी सड़कों की व्यवस्था व नियंत्रण के लिये सड़कों पर पाटक थे, जिसमें प्रत्येक यात्री, पशु व सवारी में कर वसूल किया जा सके। उसी घन में से कुछ सड़कों की मरम्मत व सुधार पर व्यय का दिया जाता था। इन घनी व्यक्तियों ने समूह के रूप में ट्रस्ट बना लिये थे, जिनको टर्न पाइक ट्रस्ट (Turn Pike Trust) कहते थे। C B Ray के अनुसार "इस ट्रस्ट का कार्य एक निर्धारित दूरी तक सड़क का निर्माण करना था और यह साल होने वाले व्यक्तियों से कर वसूल करता था।"

ऐसे ट्रस्टों को मान्यता देने के लिए और सड़क निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सन् १६६३ में टर्न पाइक एक्ट पास किया गया। योही ही काल में ऐसे अधिनियम अधिक संख्या में पास हो गए, जिनके परिणामस्वरूप सड़क निर्माण करने वाली ऐसी संस्थाओं की संख्या भी बढ़ गई और सड़क निर्माण का कार्य तीव्र गति से होने लगा। विभिन्न अधिनियमों में एकरूपता लाने के लिए सन् १७७३ में एक सामान्य टर्न पाइक एक्ट पास किया गया। सन् १८३१ में दूसरा एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार सड़कों

का उपयोग करने वालों पर अधिक कर लगाया जा सकता था। इससे ट्रस्टों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

इतना होने पर भी सड़कों का विशेष विकास नहीं हो पाया, क्योंकि सड़क निर्माण में वैज्ञानिक तरीकों को काम में नहीं लाया जाता था। १९वीं शताब्दी में इस कार्य में बड़े बड़े इंजिनियर रुचि लेने लगे। परिणामस्वरूप चेनी (Cheney) के शब्दों में "टेलफोर्ड, मैकएडम और अन्य इंजिनियर तथा निजी टर्न पाइक कंपनियों व स्थानीय सत्ताओं के प्रयत्नों से इंग्लैण्ड में अच्छी सड़कों का निर्माण हो सका।"

मैकएडम ने कक्रोट का प्रयोग कर पक्की सड़कों के निर्माण का द्वार खोल दिया, जिससे यात्रा में एक नई माति आरम्भ हुई। अब सब श्रुतुओं में यात्रा करना सरल हो गया। इस समय औद्योगिक विकास और व्यापार की वृद्धि के कारण सड़क निर्माण की आवश्यकता हुई, जिसके विकास के लिए अधिक योग्य और कुशल इंजिनियरों की आवश्यकता थी, साथ ही अधिक पूंजी भी चाहिए थी। अतः ट्रस्ट धीरे धीरे लुप्त होने लगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति गिरने लगी थी। सन् १८८८ में सरकार ने सड़कों का प्रबन्ध राष्ट्रीय परिषद् तथा देहाती व शहरी हाईवे बोर्ड को सौंप दिया। इस प्रकार सड़क निर्माण का कार्य सरकारी नियन्त्रण में चला गया।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में मोटरों के आविष्कार से सड़कों की महत्ता बढ़ गई। सन् १९०७ में मोटर व पेट्रोल पर कर लगाया गया, जिसका कुछ अंश सड़क निर्माण व मरम्मत में व्यय किया जाने लगा। बढ़ती हुई औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए सड़कों को अधिक मजबूत, कम घूल उठाने वाली तथा कम आवाज करने वाली बनाया गया।

प्रथम महायुद्ध में सड़कों की दशा बिगड़ने लगी। सन् १९१८ में एक विशेष कोष की स्थापना की गई, जिसका उपयोग केवल सड़क विकास के लिए ही किया जा सकता था। सड़कों को ५ वर्गों में विभाजित किया गया।

(१) ट्रक रोड, जिसका समस्त आर्थिक उत्तरदायित्व सड़क कोष पर था।

(२) 'अ' वर्ग रोड, जिसका ७५% व्यय सड़क कोष पर था।

(३) 'ब' वर्ग रोड, जिसका ६०% व्यय सड़क कोष पर था।

(४) 'स' वर्ग रोड जिसका ५०% व्यय सड़क कोष पर था।

(५) अवर्गित रोड।

शेष व्यय स्थानीय सत्ताओं द्वारा होता था।

इस ही समय सड़क-रेल यातायात में तीव्र प्रतिस्पर्धा होने लगी, अतः १९३० में सरकार ने मोटर यातायात पर कुछ नियन्त्रण लगाये। द्वितीय महायुद्ध के समय सड़कों के अधिक प्रयोग के कारण उनकी अवस्था बिगड़ती गई। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए

अथ निजी कम्पनियों का ही है। परन्तु सरकार ने रेलों के विकास पर नियन्त्रण करने के अनेक प्रयत्न किये। व्यापार मण्डल की आज्ञा बिना नई रेलवे कम्पनियाँ नहीं बन सकती थीं तथा १० प्रतिशत से अधिक लाभ होने पर क्रिया नहीं बढ़ाया जा सकता था।

(३) सन् १८४५ से १८७३ तक—इस काल में रेलों में काफी सुधार हुआ। छोटी छोटी लाइनों को ट्रक लाइनों से मिलाया गया। जन-साधारण का मत भी रेलों के अनुकूल होने लगा। रेल कम्पनी पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार ने सन् १८४४ में नियन्त्रण मण्डल की स्थापना की। १८६५ में शाही कमीशन की नियुक्ति हुई। परन्तु कोई विशेष सफलता नहीं मिली और रेलवे कम्पनियों का एकाधिकार हो गया।

(२) सन् १८७४ से १८८३ :—इस काल में रेलों का व्यवस्थित नियमन तथा राज्य द्वारा नियन्त्रण हुआ। सन् १८८३ में एक अधिनियम के द्वारा रेलवे तथा नहर आयोग के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। सन् १८८३ में रेल किराये की निश्चित दर लागू की गई। इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि तय की हुई मजदूरी नियमित रूप से दी जाय। रेल के समस्त दो समस्याएँ थीं—एक तो दरों की तथा दूसरी लागत व्यय में हुई की। रेल दरों को बढ़ाने के हेतु रेलों का एकीकरण आरम्भ हुआ।

(४) सन् १८८४ से १९१४ :—इस काल में कम्पनियों में पारस्परिक प्रतियोगिता समाप्त हो रही थी। इसी समय रेलवे कर्मचारी रेलों के राष्ट्रीयकरण के लिए आन्दोलन करने लगे। अभिकों के भगड़ों के फलस्वरूप रेलवे मजदूरों ने सबों की स्थापना आरम्भ कर दी। व्यापार मण्डल ने हस्तक्षेप कर कई सुलह मण्डलों (Conciliation Boards) की स्थापना कराई, जिसमें रेलों तथा मजदूरों के प्रतिनिधि आपस में मिलकर भगड़े निपटाने लगे। सन् १९११ में राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ के रूप में मजदूर एकत्रित हो गये। कुछ प्रस्ताव नई नहरों के निर्माण के भी आये जो रेलवे कम्पनियों द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये।

(५) सन् १९१४ से १९३० :—प्रथम महायुद्ध में सामरिक दृष्टि से रेलों की सवारी नियन्त्रण में ले लिया गया। यह नियन्त्रण सन् १९२१ तक रहा। परन्तु इस राष्ट्रीयकरण से रेलों की स्थिति में कई सुधार हो गए। सन् १९२१ में रेलवे एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार रेलों का एकीकरण अनिवार्य कर दिया गया तथा रेल दरें निश्चित करने के लिए 'रेलवे रोट ट्रिग्यून-न' की स्थापना की गई। रेल-सड़क प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने के कारण सन् १९३० में सड़क यातायात एक्ट पास किया गया और सन् १९३२ में एक रेलवे सड़क सम्मेलन बुलाया गया। रेलों की सहायता के हेतु सड़क यातायात पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये।

(६) १९३६ से अब तक :—द्वितीय महायुद्ध में पुनः रेलें राज्य के नियन्त्रण में आ गईं। १ जनवरी, १९४८ को ब्रिटेन के समस्त यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

सन् १९५३ में यातायात एक्ट के अन्तर्गत एक यातायात आयोग की नियुक्ति की गई, जिसने रेलों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। सन् १९५४ से रेलें विद्युत् से भी चलने लगीं। सन् १९५५ में यातायात आयोग द्वारा एक १५ वर्षीय योजना बनाई गई। यानियों की छुविषा के लिए सम्मिलित प्रयत्न किये जा रहे हैं।

४. सामुद्रिक यातायात

किसी भी देश के आर्थिक व राजनैतिक महत्त्व के लिए सामुद्रिक शक्ति बहुत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड की स्थिति अति उपयुक्त है। इसका विद्याल समुद्रतट बटा-बटा है तथा कोई भी स्थान समुद्र से अधिक दूर नहीं है। इसी कारण इस देश ने सामुद्रिक यातायात में आश्चर्यजनक उन्नति की और इसे जहाजों का राष्ट्र कहते हैं।

सामुद्रिक यातायात के विकास का इतिहास निम्न कालों में बांटा जा सकता है।—

(१) १७६६ से १८५४ तक.—१८वीं शताब्दी से पूर्व जहाजरानी के विकास के कई प्रयत्न किये गये। सन् १३८१ में नौवहन अधिनियम पास किया गया, जिसके द्वारा विदेशी जहाजों का नहिष्कार कर दिया गया। सन् १४८५ के एक एक्ट के अनुसार इंग्लैण्ड को माल अथवा जहाजों में ही लाया जाय। इसके बाद जहाजों के कप्तान का अथवा होना भी अनिवार्य कर दिया गया। सन् १५५६ में यद्यपि यह कानून समाप्त कर दिया गया, परन्तु १६६० इसे फिर लागू कर दिया गया। विदेशी जहाजों को इंग्लैण्ड के उपनिवेशों के साथ व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इन अधिनियमों के द्वारा इंग्लैण्ड विश्व में सामुद्रिक शक्ति का नेता बन गया। इंग्लैण्ड की इस नीति के कारण अन्य राष्ट्र लुब्ध हो गये और अन्त में सन् १८४६ में इन नियमों को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश जहाजी यातायात को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई।

(२) सन् १८५४ से १८८० तक.—इस काल में वैज्ञानिक आविष्कारों से ब्रिटिश जहाजरानी में अनेक परिवर्तन हुए। भाप के इंजन तथा लोहे के जहाज का विकास हुआ। जहाज निर्माण की तकनीक में महान परिवर्तन हुए। इसी समय स्वेज नहर के निर्माण ने इस विकास को प्रोत्साहन दिया। जहाजों की गति बढ़ाई गई। माल के उतारने-चढ़ाने में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, लागत व्यय में कमी हुई तथा किराये भाड़े की दर भी कम हुई। लोहे के स्थान पर इस्पात का प्रयोग होने लगा। इन सबका यह फल हुआ कि प्रथम महायुद्ध के समय तक ब्रिटेन की सामुद्रिक शक्ति विश्व के समस्त राष्ट्रों से अधिक हो गई।

(३) सन् १८८० से १९१४ तक :—इस काल में विदेशों की प्रतिस्पर्धा एवं एकीकरण प्रमुख तत्व रहे। अमेरिका, जर्मनी आदि देशों ने ब्रिटेन से जहाजी शक्ति में टक्कर लेना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार परस्पर जहाजी सन्धियों का महत्त्व बढ़ गया तथा कई सम्झौते हुए।

(४) युद्धकाल १९१४-१९१८ :—प्रथम युद्ध के आरम्भ होते ही सरकार ने वायु यातायात को अपने नियन्त्रण में ले लिया। युद्ध में जहाजों की क्षति के कारण जहाज निर्माण को प्रोत्साहन मिला। अमेरिकन तथा जापानी जहाजी शक्ति के विकसित होने से धीरे धीरे इंग्लैण्ड का महत्व इस क्षेत्र में कम होने लगा।

(५) १९१८-३६ तक—कोयले के व्यापार में कमी आने के फलस्वरूप जहाज निर्माण तथा जहाज यातायात का विकास रुक गया। व्यापार की कमी के कारण ब्रिटिश जहाजी यातायात को काफी आघात लगा। १९२६-३० की विस्वमन्दी के कारण वायु यातायात का विद्युतन आरम्भ हो गया।

(६) १९३६ से अब तक—द्वितीय युद्ध के समय अंग्रेजी जहाजों की भारी क्षति हुई। इसकी पूर्ति अब तक नहीं हो सकी है। सन् १९५५ में सर्वेक्षण बोर्ड ने एक पञ्चवर्षीय योजना तैयार की, जिसके अनुसार ५५ मि० पाउंड खर्च वायु यातायात पर व्यय किये जायेंगे।

५. वायु यातायात

ब्रिटेन में वायु यातायात का वास्तविक आरम्भ १५ अगस्त १९१६ को हुआ, जबकि एक कम्पनी द्वारा एक सर्विस लन्दन और पेरिस के बीच स्थापित की। सन् १९१६ में ब्रिटिश ठाकाओं ने अटलांटिक समुद्र पार किया। १९२३ में वायु यातायात की प्रगति के लिए छोटी कम्पनियों को सत्ता बनाने का सुझाव दिया गया। अप्रैल १९२४ में Imperial Airways Ltd. के रूप में कम्पनियों का पुनर्गठन हुआ और सरकार ने इसको आधिक सहायता प्रदान की।

इस कम्पनी ने ही अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात सर्विस और Royal Air Force का कार्य आरम्भ किया। सन् १९२६ में इंग्लैण्ड और भारत के बीच वायु यातायात आरम्भ हो गया। दिसम्बर १९३४ में पहली Mail Service लन्दन और ब्राज़ीलिया के बीच स्थापित हुई और १९३५ में वायो सर्विस।

सन् १९३७ में इस कम्पनी ने अटलांटिक पार किया। सन् १९३६ के एक अधिनियम के द्वारा British Overseas Airways Corporation (B. O. A. C.) की स्थापना हुई, जिसने सन् १९४० Imperial Airways Ltd. तथा British Airways Ltd. का कार्य समाल लिया।

द्वितीय महायुद्ध के समय B. O. A. C. ने आवश्यक सेवाएं आरम्भ की। युद्ध के परचाव् सेनाओं का इतना भित्तिार हो गया कि वायुपानों की कमी बनी रहने लगी। इस कमी की पूर्ति मिलिट्री एयरक्राफ्ट तथा बाहर से वायुपान खरीद कर की गई।

वायु यातायात की प्रगति का भार एक मन्त्री पर है, जिसकी सहायता के बिना ३ मुख्य सहायक हैं—(१) वायु यातायात परामर्शदात्री परिषद् (२) वायु रजिस्ट्रेशन बोर्ड तथा (३) वायु सुरक्षा बोर्ड।

वायु यातायात संस्थाएँ अपने कार्यों को व्यापारिक संस्थाओं के समान करती हैं और मन्त्री इन संस्थाओं पर अधिक नियन्त्रण रखता है। प्रत्येक संस्था अपने भूमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखती है। सन् १८५२ में एक नई नीति के कारण वायु यातायात को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस नीति का उद्देश्य वायुयानों की गति में वृद्धि करना, लागत में कमी करना तथा यात्रिया तथा व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधाएँ देना है।

प्रश्न

1. Trace history of Rly development in England.
 2. Describe the development of shipping in England during 1822-1845. What were the effects of the abolition of Navigation Acts (1849-1854)?
 3. Give an idea of revolution in British Transport system and show how it helped the Industrial Revolution?
-

औद्योगिक क्रांति से पूर्व जब कि उद्योगों का संगठन कुटीर प्रणाली पर था। मानिक और श्रमिकों के स्वार्थों में अधिक अन्तर नहीं था। वे एक दूसरे के पूरक थे और मिलजुल कर रहते थे। अतः श्रमिकों के पृथक् संगठन बनाने का प्रश्न ही उस समय नहीं उत्पन्न होता था।

औद्योगिक क्रांति के परिचात् परिस्थितियाँ बदल गई। बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे, जिनमें मशीनों के कारण बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती थी। बड़े बड़े पूँजीपति कारखानों के मानिक होने लगे और श्रमिकों का शोषण करने लगे। अधिक धरणी तक काम लेना और कम वेतन देना साधारण सी बात हो गई। निर्धन, दुखित और निराश्रित श्रमिक वर्ग ने अपनी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए सबों द्वारा ही अपने को संगठित करने का प्रयास किया। अतः यदि हम यह कहें कि श्रमिक सबों की आवश्यकता एक प्रगति औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम थी, तो यह कथन सत्य होगा।

आरम्भ में जब श्रमिक अपने स्वार्थों की सुरक्षा के लिए आपस में मिलने लगे तो इसे अवैधानिक समझा गया। सन् १७८६ और १८०० के Combination Laws के अनुसार श्रमिक सब गैरकानूनी घोषित कर दिए गए। इन नियमों के अनुसार यदि श्रमिक अपने कार्य के धरते कम करने अथवा वेतन बढ़ाने के लिए आपस में मिलकर संगठन बनाते थे तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता था। उस समय लोगों की भय था कि कहीं माव की राज्यकाल की पुनरावृत्ति इंग्लैंड में भी न हो जाए। अतः श्रमिकों के सबों की वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। हाँ, Friendly Societies अवश्य थीं। इन निष् स्वार्थों में सदस्य चन्दा देते थे और उसके समय पड़ने पर बीमारी और बेकारी के अवसर पर आर्थिक सहायता लेते थे। इसके अतिरिक्त कुछ सब श्रमिकों के देते भी थे, जो गुप्त रूप से अपना कार्य करते थे।

सन् १८२४ में एक अधिनियम पास किया गया, जिसके अनुसार इंग्लैंड के इतिहास में प्रथम बार श्रमिक सबों की वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। अब इस बात की उन्हें पूरा भी विश्वास था कि वेतन तथा काम के धरतों के विषय में बातचीत करने के लिए वे अपना संगठन बना सकते थे। इस संगठन के कारण कई हड़तालें हुईं। अतः सन् १८२५ में एक कानून में संशोधन किया गया। इसका तात्पर्य यह था कि यदि श्रमिक वेतन व काम के धरतों के संरक्ष में संगठन बनाकर हड़ताल करें तो उनका सामान्य कानून के अन्तर्गत जाना कि जा सकेगा। इस प्रकार श्रमिकों की शक्ति बढ़ गई। परन्तु फिर

मो १८२४ और १८४३ के मध्य कई सों को स्थापना हुई। सन् १८२४ में Grand National Consolidated Trade Union की स्थापना हुई परन्तु कुछ काल बाद यह असफल रही।

सन् १८४३ के बाद अमिक सभों के इतिहास में एक नए ही युग का आरम्भ हुआ। अर इङ्गलैंडों पर लोवों का विश्वास न रहा और इनके स्थान पर आपसी बातचीत तथा पंच फैसले के द्वारा झगड़ों का निपटारा किया जाने लगा। अतः सभा के संगठन, तरीकों और उद्देश्या आदि में कई परिवर्तन आ गए।

सन् १८६७ में एक शाही आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके सुझावों पर सन् १८७१ में ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया गया, जिसमें निम्न बातों का समावेश किया गया —

(१) सभों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता था।

(२) सभों के अधिकार में भूमि, भवन और चन-अवन सम्पत्ति रह सकती थी और वे मुद्दमें दूसरे पक्षों पर चला सकते थे तथा अन्य पक्ष उन पर कानूनी कार्यवाही कर सकता था।

(३) उनकी सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान की गई।

यद्यपि १८७१ के कानून क द्वारा अधिकों को पर्याप्त स्वतन्त्रता मिली, परन्तु उसी वर्ष पौख्तारी कानून में सुधार कर धरना देने पर भारी दण्ड देने की व्यवस्था की गई। इस दोष को सन् १८७५ में दूर कर दिया गया, जबकि शांतिपूर्ण धरना देने पर कोई दण्ड की व्यवस्था न रही। इस प्रकार सन् १८८० तक इंगलैंड का अमिक सब आंदोलन काफी प्रगति कर चुका था।

सभों की वैधानिक मजबूती प्रदान कर दी गई थी। वे वेतन बढ़ाने एवं काम के घण्टे घटाने के लिए अपना संगठन बना सकते थे और शांतिपूर्ण दंग से इङ्गलैंड भी कर सकते थे तथा धरना दे सकते थे। इस बीच वे कृषि-अमिकों तथा अन्य व्यवसायों के अमिकों के सब भी बन चुके थे। सन् १८८३ में स्वतंत्र Labour Party की स्थापना हो गई थी और इस पार्टी का समर्थन करके अमिक सब राजनैतिक द्धेश में भी अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करने लगा।

सन् १८०१ में T. V. Rly Co के मजदूरों ने इङ्गलैंड कर दी। न्यायालय ने इस इङ्गलैंड को अवैधानिक घोषित कर दिया और ग्लेवे अमिक सब को २३००० पौंड क्षति-पूर्ति के रूप में देने पड़े। १८०६ में औद्योगिक संघर्ष एक्ट के अन्तर्गत इङ्गलैंड व शांतिपूर्ण धरना देने के विरुद्ध मुकदमा लेने का निषेध न्यायालयों के लिए हो गया, जिससे अम सभों की शक्ति काफी बढ़ गई।

सन् १८०८ में न्यायालय ने W. Osborne के इस पक्ष को मान लिया कि सदस्यों से राजनैतिक कार्यों के लिए चन्दा लेना अमिक सभों के क्षेत्र के बाहर है और इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। इन नियमों ने सभा को सत्ता क्षेत्रों में काम दिया। Trade Union Congress और लेबर पार्टी का मजबूत सम्बन्ध बन गया।

सन् १९१३ में उपर्युक्त दोष को दूर करने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा अमिक सय राजनैतिक कार्यों के लिए बहुमत से चन्दा बसा कर सकते थे, परन्तु शर्त यह थी कि ये राजनैतिक पण्ड अन्य पण्डों से पृथक् रहना चाहिए।

प्रथम महायुद्ध के बाद अम सय आंदोलन अधिक प्रगति करने लगा। १९११ में National Union of Rly. men १९३१ में Trade Union Congress की जनरल कौंसिल बनाई गई। राजनैतिक प्रभाव से सन् १९२४, १९३१ और १९४५ में Labour Govt बनी।

इस एक शताब्दी के लम्बे सर्प के कारण ही अब अम संघटन इस चोख बन गये हैं कि वे अपने हक्यों की सुरक्षा कर सकें। वे राष्ट्रिय हित को सम्मान लते हैं और शांतिपूर्ण तरीकों में ही विश्वास करते हैं। दकता भी हुई, परन्तु बहुत कम और प्रायः समझौते द्वारा ही झगड़ों को सय किया गया है।

इंग्लैंड में अमिक सय ने जो सफलताएं प्राप्त की हैं वे हैं वेतन दर में वृद्धिकार्य के घण्टी एवं दशाओं में परिवर्तन, अपने सम्मान व सगठन में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में श्रम से कई लाभ प्राप्त कर लेना। ये सफलताएं कम नहीं हैं। अब इंग्लैंड का अमिक, धीनस्तर और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी अन्य राष्ट्र के अमिक से उत्तम स्थिति में है। विशेष बात यह है कि वहा के अमिकों ने यह सफलता किसी विपक्ष के द्वारा नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण सर्प के कारण ही प्राप्त की है।

प्रश्न-

1 Trace the growth of trade union movement. How has it influenced the condition of labour

सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रतिक्षण किसी न किसी आकस्मिक दुर्घटना या संकट का मय बना रहता है, जैसे मृत्यु, बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था आदि। एक अच्छे समाज में इन संकटों से लोगों की सुरक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है, नाहि व्यक्ति इन दुर्घटनाओं के भय से मुक्त होकर समाज में अपने कर्तव्य को पूरा कर सके।

प्राचीन काल में समाज का संगठन भिन्न प्रकार था। परिवार बड़े आकार के और सम्मिलित होते थे। जातीय और वंश-परम्पराओं के आधार पर बीमारी, बेकारी और वृद्धावस्था के समय व्यक्ति की सहायता और सुरक्षा स्वतः ही हो जाती थी।

औद्योगिक क्रान्ति के बाद नगरों में श्रमिकों की संख्या बढ़ गई। सम्मिलित परिवारों के स्थान पर छोटे आकार के परिवार बढ़ गये और लोगो में व्यक्तिवाद की भावना का उदय हुई। अब संकट के समय श्रमिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सारे समाज या राष्ट्र पर आ गया।

इन दुर्घटनाओं और संकटों से सुरक्षा करने के लिए समाज में जिन योजनाओं की व्यवस्था की गई, वे सब सामाजिक सुरक्षा या बीमा की योजनाएँ कहलाती हैं। आजकल एक प्रजातन्त्र और कल्याणकारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा या बीमा की व्यवस्था अनिवार्य समझी जाती है। श्रमिक वर्ग प्रत्येक राष्ट्र में समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कहा जाता है कि प्रत्येक नागरिक के लिए जन्म से मृत्यु तक की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर होना चाहिये, अर्थात् बीमारी, बेकारी, जन्मा, वृद्धावस्था और दुर्घटनाओं की सुरक्षा की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिये। परन्तु क्रियात्मक रूप में अभी राष्ट्र इस आदर्श से दूर हैं।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं को आरम्भ करने का श्रेय जर्मनी को है, वहाँ गत शताब्दी में बिस्मार्क के प्रयत्नों से श्रमिकों के बीमा की व्यवस्था की गई। इंग्लैंड में सामाजिक सुरक्षा का आरम्भ बीसवीं सदी में हुआ। सर्वप्रथम वृद्धावस्था के लिए पेन्शन की व्यवस्था 'वृद्धावस्था पेन्शन अधिनियम १९०८' के अन्तर्गत की गई। सन् १९११ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा अधिनियम के द्वारा बीमारी व बेकारी के बीमा की व्यवस्था की गई। इसके बाद तो वंश इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई।

सन् १९४२ में सर विलियम बेवेरिज (Sir William Beveridge) ने सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बहुत ही व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे Beveridge Plan (बेवेरिज योजना) कहा जाता है। इस योजना के आधार पर ही सन् १९४६ में

वानर बनाकर इंग्लैंड के प्रत्येक नागरिक के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें जीवन में घटित होने वाले प्रायः सब संकटों से सुरक्षा का प्रवन्ध है। आज इंग्लैंड सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व में सबसे अग्रगण्य है। बड़ा कुल राष्ट्रीय आय का १०% सामाजिक सुरक्षा पर व्यय किया जाता है। ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा का अध्ययन हम निम्न योजनाओं के अन्तर्गत कर सकते हैं :-

(१) अधिक क्षतिपूर्ति व्यवस्था — दुर्घटना के समय अधिक को क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था सर्वप्रथम सन् १८८० में की गई, जिसका ध्यान १८६७ में अधिक क्षतिपूर्ति अधिनियम ने ले लिया। क्षतिपूर्ति के लिए अधिकों को न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती थी। यह केवल उन्हीं उद्योगों में लागू किया गया जिन्हें त्वतरनाक समझा गया। इसे व्यापक बनाने के लिए १९०६ में एक और क्षतिपूर्ति एक्ट बनाया गया। यह सब उद्योगों में लागू किया गया। वे सारे अधिक बिनाबी वार्षिक आय २५० पौंड से कम थी, इसमें सम्मिलित कर लिये गये। अधिकों को स्थायी या आंशिक क्षति के लिए आजीवन भत्ता या औसत साप्ताहिक आय की आधी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देने की व्यवस्था की गई। परन्तु शर्त यह थी कि क्षति जानबूझकर या अधिक की लापरवाही के कारण न हुई हो।

(२) वृद्धावस्था पेन्शन योजना:— सन् १९०७ में वृद्धावस्था पेन्शन अधिनियम पास किया गया, जो जनवरी १९०८ से लागू किया गया। इसके अन्तर्गत ५० वर्ष की अवस्था के पश्चात् प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक को पेन्शन दिये जाने की व्यवस्था की गई। पेन्शन पाने के लिए यह व्यक्ति ब्रिटेन का नागरिक हो तथा जिसकी वार्षिक आय के ११॥ पौंड से अधिक न हो। अधिकों और मिल मालिकों को इसमें चन्दा देना अनिवार्य नहीं था। इस प्रकार पेन्शन देने का उत्तरदायित्व राज्य पर ही कर दिया गया।

(३) स्वास्थ्य बीमा — सन् १९११ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा अधिनियम पास हुआ। इसके अन्तर्गत १६ वर्ष से ६५ वर्ष की आयु वाले प्रत्येक ब्रिटिश अधिक के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमे का आयोजन किया गया। इसके लिए मिल मालिक, अधिक और राज्य को चन्दा देना अनिवार्य कर दिया। इस निधि में से व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा और उपचार की सुविधा दी गई। स्त्री अधिकों की प्रसूति के समय भत्ता मिलने का प्रवन्ध किया गया।

(४) बेकारी का बीमा:— यह वास्तव में ब्रिटिश सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। यह बीमा भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत सन् १९११ में लागू किया गया। आरम्भ में यह केवल उन्हीं उद्योगों में लागू किया गया, जिनमें बेकारी अधिक थी। धीरे धीरे इसे अन्य उद्योगों में भी आरम्भ कर दिया गया। आर्थिक व्यवस्था का प्रबन्ध अधिकों, मालिकों और राज्य द्वारा प्रदत्त शुल्क द्वारा किया गया। बेकारी के काल में प्रत्येक अधिक को ७ शि० प्रति सप्ताह सहायता दी जाती थी और एक वर्ष में अधिक से अधिक १५ सप्ताह तक सहायता दी जा सकती थी।

प्रथम महासुद्ध में यह योजना श्रुत रूपल हुई और बेकारी घटने के कारण प्रगति हुई। सन् १९२१ में एक और अधिनियम पास किया, जिसे बेकारी बीमा अधिनियम कहते हैं। इसके द्वारा बेकारी के बीमा क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया। सन् १९३१ में सारी योजना पर विचार करने के लिए शाही आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके सुझावों पर सन् १९३४ में इस योजना में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। सन् १९३६ में कृषि-अधिकों के लिए भी पृथक् बेकारी के बीमों की योजना प्रचलित की गई।

(Beveridge Plan) बेवरीज योजना.—इस योजना का स्वरूप सर विलियम बेवरीज द्वारा १९४० में प्रस्तुत किया गया। यह योजना सार के सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक क्रान्तिकारी कदम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन में प्रचलित सामाजिक बीमों की विभिन्न योजनाओं को एक सूत्र में बांधकर ब्रिटेन के सब नागरिकों को जीवन के प्रायः सब सम्भावित खतरों से सुरक्षा प्रदान करना था।

इस योजना के अन्तर्गत सारे समाज को दू वर्गों में विभाजित किया गया है—सेवक, मालिक, एहिणिया, अन्य व्यक्ति जो कि अर्ध बेकारी की अवस्था में हैं, सोलह वर्ष के कम से कम आयु के लड़के-लड़किया और सेवानुवृत्त वृद्ध व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो इन वर्गों में आ जाते हैं—सामाजिक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। मालिक या अन्य धनिक वर्ग चाहे इस योजना से लाभान्वित हो या न हो परन्तु चन्दा देना प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है। रिश्वतों के लिए विनाश के समय तथा बच्चों के पालन-पोषण के लिए सहायता एक भत्ता दिये जाने का प्रबंध किया गया है। छुटिपूर्ति बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था पेन्शन के लिए भी इसी प्रकार सहायता व भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

इस योजना की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लगभग ८० करोड़ पाँड की आवश्यकता का अनुमान किया गया था, जिसे अधिकों, मालिकों और राज्य द्वारा प्रदत्त चन्दे से पूरा किया जायगा। चन्दे को दरें और लाभ की मात्रा मूल्यस्तर के अनुसार घटती-बढती रहेगी।

इस योजना के आधार पर फरवरी १९४६ में ब्रिटेन में एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पास किया गया, जिसके अन्तर्गत बेवरीज योजना की प्रायः सब महत्वपूर्ण बातों का समावेश कर लिया गया। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आदर्श परिस्थितिया लागू हो गई हैं। ब्रिटेन के नागरिकों को इस योजना से जीवन के सब कष्टों की चिन्ता से मुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न

1. What do you mean by Social Insurance?
it been provided in England ?

१६वीं सदी में इंग्लैंड द्वारा स्वतंत्र व्यापार की नीति (Laissez Faire Policy) का अपनाने जाना उस देश के आर्थिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह एक ऐसी घटना थी, जिसने इंग्लैंड की आर्थिक प्रगति को एक नया मोड़ दे दिया, जिसके द्वारा वहाँ के उद्योग एवं व्यापार आदि के लिये विकास के सब मार्ग खुल गये। कच्चे माल तथा खाद्य पदार्थों का आयात बढ़ा, बड़े बड़े कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई और पारी मात्रा में वहाँ सब प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। सात्व, चक, बेमा और यानायात के क्षेत्रों में भी प्रिटेन ने उत्थिति की।

इस समृद्धि का लाभ प्रिटेन के प्रत्येक वर्ग को हुआ। मिल मालिक और व्यापारी मालामाल हो गये। श्रमिकों के वेतन बढ़े और उनके जीवनस्तर में वृद्धि हुई। अतः यह कथन सत्य है कि स्वतंत्र व्यापार की नीति के कारण ही १६वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रिटेन की आर्थिक समृद्धि में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। यद्यपि इस समृद्धि के अन्य कारण भी थे, जैसे इंग्लैंड की अनुकूल स्थिति, नाविक शक्ति तथा आर्थिक आदि। फिर भी यह निर्विवाद है कि इस सम्पन्नता का सबसे प्रमुख कारण यह निर्धन नीति ही था।

१७वीं और १८वीं सदी में प्रिटेन में व्यापारवादी नीति (Mercantilism) थी। इस नीति के अन्तर्गत राष्ट्र को शक्तिशाली और सम्पन्न बनाने के उद्देश्य से देश के आर्थिक जीवन के प्रत्येक अंग की सम्यक् द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इस नीति के अनुसार अनेक कानूनों द्वारा निदेशी अनाम के आयात पर प्रतिबन्ध अथवा मारी पर लगा दिया गया। नाविक शक्ति का विकास नाविक कानूनों द्वारा किया गया। पर व्यापारवादी नीति कृत्रिम कानूनों, प्रतिबंधों और नियन्त्रणों के द्वारा प्रिटेन को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में सफल हुई। अनेक कानूनों के कारण इति की दशा में सुधार हुआ। नाविक कानून के कारण प्रिटेन का बहाली बड़ा बहुत शक्तिशाली हो गया। १८वीं सदी के अन्त तक और १६वीं सदी के आरम्भ में इंग्लैंड में व्यापारवाद का ही जीवनशाला रहा।

१९वीं सदी के आरम्भ में परिस्थितियों में फिर परिवर्तन हुआ और व्यापारवादी नीति की सफलता पर सन्देह प्रकट किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति के कारण इन वर्षों में इंग्लैंड के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। लोग स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन करने लगे। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक Wealth of Nations में सन् १७७६ में इस नीति का स्पष्टीकरण किया। बाद में इस नीति का समर्थन

रिकाबों, जेम्स मिल आदि ने भी किया। इस नीति का प्रधान उद्देश्य यह था कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये और उद्योग तथा व्यापार व्यक्तिगत क्षेत्रों के लिये छोड़ दिये जायें। राज्य का प्रधान कार्य केवल देश की रक्षा करना और देश में शान्ति बनाये रखना था।

आरम्भ में तो यह नीति केवल एक सिद्धान्त मान ही थी। क्रियात्मक रूप में इस पर अमल बहुत बाद में किया गया। सन् १८२४ में (Combination Laws) को समाप्त कर दिया गया और अधिकों को अपने सप बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई।

सन् १८२० में नाविक कानूनों की समाप्ति कर दी गई। सन् १८२४ तक जल यातायात के सम्बन्ध में सामुद्रिक और तटीय प्रतिबन्ध हटाये जा चुके थे।

सन् १८६६ में अन्न कानूनों की समाप्ति हो चुकी थी और पुले रूप में अनाज का आयात होने लगा। व्यापार नीति में भी सुधार किया जाने लगा। कच्चे माल के आयात पर करों को घटा कर कम कर दिया गया। मशीनों के निर्यात प्रतिबन्धों को हटा लिया गया। इस प्रकार कई वर्षों के संघर्ष के पश्चात् इंग्लैंड में अब स्वतंत्र व्यापार की नीति का पूर्ण-रूपेण अवलम्बन होने लगा।

वास्तव में स्वतंत्र व्यापार की नीति का आन्दोलन पर बेग से सन् १८२० से आरम्भ हुआ। १८४० से १८७५ तक का काल त्रिटेश कृषि का काल स्वर्णयुग कहलाता है। लेकिन यही काल ब्रिटिश उद्योग व व्यापार का भी स्वर्णयुग कहलाता है। अन्तर केवल इतना ही है कि उसके बाद कृषि की दृष्टि तो गिरती ही चली गई, किन्तु उद्योग और व्यापार प्रथम महायुद्ध तक बढ़ता गया। यह स्वतंत्र व्यापार की नीति का ही परिणाम था। इस नीति को अपनाते के बाद बिना विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक राष्ट्र बन गया। अन्न और कच्चे माल का आयात होने लगा तथा निर्मित माल का निर्यात। विदेशी व्यापार में वृद्धि के कारण बैंकिंग, बीमा और यातायात में भी विकास हुआ। इस सर्वांगीण उत्पत्ति में स्वतंत्र व्यापार की नीति का ही दाय था।

स्वतंत्र व्यापार की नीति का परित्याग

सन् १८७० के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं, जिनके कारण स्वतंत्र व्यापार की नीति के विरुद्ध लोगों में प्रतिक्रिया होने लगी। इस नीति के समर्थकों का यह विचार है कि संसार के सब देश इस नीति का अनुसरण करें, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी और सब देशों को इससे लाभ होगा—निर्मूल सिद्ध हुआ। अन्य देशों ने स्वतंत्र व्यापार के स्थान पर संरक्षण की नीति अपना ली। दूसरी बात यह थी कि अन्य देशों ने भी औद्योगिक उत्पत्ति कर ली थी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बिना प्रतिस्पर्धिता करने लगे थे। अतः यह आवश्यक समझा जाने लगा कि प्रतियोगिता से बचने के लिए बिना भी संरक्षण की नीति अपना ले। स्वतंत्र व्यापार की नीति में लोगों का विश्वास न रह

गया था और उसकी सफलता में सन्देह होने लगा था । सन् १८७५ के बाद ब्रिटिश कृषि की दशा गिरने लगी और बाहरी प्रतियोगिता के कारण अन्न के भाव बहुत अधिक गिर गए ।

मन्दी की परिस्थितियों व विदेशी व्यापार के असन्तुलन के कारण स्वतन्त्र व्यापार की नीति असफल होने लगी । बाहरी सस्ते अनाज एवं अन्य सस्ते माल के स्वतंत्र आयात के कारण ब्रिटिश कृषि व उद्योगों की दशा गिरने लगी । विदेशी बाजारों में भी जर्मनी और अमेरिका के माल द्वारा प्रतियोगिता होने लगी ।

इस कठिनाई से बचने के लिए यह कहा जाने लगा कि आयात कर नीति के सबब में ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों में गठबन्धन हो जाना चाहिए । अन्य राष्ट्रों के माल पर आयात कर लगाना जाना चाहिए और उपनिवेशों के माल पर आयात कर में रियायतें दी जाय । इसी प्रकार ब्रिटिश माल पर भी उपनिवेशों द्वारा अन्य देशों के माल की अपेक्षा कम दर पर आयात कर लगाना चाहिए । इस बात का प्रयत्न किया गया कि स्वतन्त्र व्यापार की नीति के स्थान पर पारस्परिक व्यापार संधियां करने और औपनिवेशिक प्राथमिकता (Imperial Preference) की नीति अपनाई जाये ।

प्रथम महायुद्ध आरम्भ होते ही कई वस्तुओं पर आयात कर लगा दिया गया । सन् १९१५ में कई विलास की वस्तुओं, जैसे मोटर साइकिल, सिनेमा किन्ट्स, पड़िया, मामोपोन आदि पर आयात कर लगाये गए । बहालों की कमी और विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण यह कदम उठाया गया । युद्ध के बाद भी ये कर जारी रहे । सन् १९१६ में उप-निवेशों से आने वाले माल पर इन करों में कुछ कमी कर दी गई । सन् १९२० में रंग उद्योग को सरक्षण दिया गया और १९२२ में उद्योग मुरबा अधिनियम के द्वारा विदेशी सस्ते माल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और कई अन्य वस्तुओं पर कर लगा दिए गए ।

इस काल में मन्दी और बढ़ती जा रही थी । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी हो रही थी । युद्ध के कारण कई देशों की आर्थिक व्यवस्था क्षिणभित हो गई थी और लोगों की जन शक्ति गिर गई थी । अन्य देशों में औद्योगीकरण बढ़ रहा था और उन्होंने भी अपने बहाली के विकास कर लिया था तथा अब वे जन यातायात में ब्रिटेन के साथ प्रतियोगिता करने लगे थे ।

भूखरी और ब्रिटिश उद्योगों की दशा गिरती जा रही थी और उनमें अन्य देशों से प्रतियोगिता करने की क्षमता नहीं रह गई थी । निर्यात का मूल्य एवं परिमाण कम हो गया था और विदेशी व्यापार का सन्तुलन बिगड़ रहा था । इन सब कारणों से कई ब्रिटिश कंपनियों को भारी हानि सहन करनी पड़ रही थी । अतः अब जनमत स्वतन्त्र व्यापार की नीति के नितान्त विरुद्ध था और सरक्षण की नीति का समर्थन किया जा रहा था ।

सन् १९३० में उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण सरक्षण की नीति अपना ली गई और आयात कर अधिनियम पास किया गया । इसके अन्तर्गत कुछ वस्तुओं को छोड़कर रोप

सब वस्तुओं पर आयात कर लगा दिया गया। अनाज के आयात पर भी कर लगाया गया। कुछ वस्तुओं पर तो ५० से १००% तक आयात कर लगाया गया। आयात-निर्यात कर घटाने-बढ़ाने और उठकर नीति में संशोधन करने के लिए एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की गई। सन् १९३३ में हुए सम्मेलन के अनुसार शाही सरकार की नीति को अपना लिया गया।

इस प्रकार इंग्लैंड ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति, जो वहाँ पिछली एक शताब्दी से प्रचलित थी, उसका परित्याग कर दिया और अब वह भी संरक्षणवादी देशों की धरोहर में आ गया। नीति में यह परिवर्तन तत्कालीन आर्थिक आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के कारण किया गया। इस संरक्षण की नीति को अरना लेने से इंग्लैंड को निम्नलिखित लाभ हुए—

(१) राष्ट्र की आय में वृद्धि हुई और इन करों का भार सारी जनता पर समान रूप से पड़ा।

(२) उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हो गया और वे बाहरी सस्ते माल की प्रति-योगिता से बच गये।

(३) इसमें आयात पर रोक लग गई एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण विदेशी व्यापार का अस्तित्व ठीक हो गया।

(४) उपनिवेशों के साथ शाही प्राथमिकता (Imperial Preference) के कारण व्यापारिक सम्बन्ध अटूट हो गए।

(५) असह्युक्त व्यापार के कारण स्टर्लिंग मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, यह रक गया और समुलन स्थापित हो जाने से स्टर्लिंग ने अपने पूर्व मूल्य की प्राप्ति कर लिया।

(६) सस्ते अनाज पर कुछ कर लग जाने से ब्रिटिश इण्डिया की भी लाभ हुआ।

उपरोक्त लाभों को देखते हुए इस नीति का अपनाया जाना उचित ही था। अपने इंग्लैंड की गिरती हुई आर्थिक दशा में सुधार कर दिया। यद्यपि इंग्लैंड अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने उस लोभे हुए स्थान को तो न प्राप्त कर सका, जो कि उसे प्रथम युद्ध से पूर्व प्राप्त था, फिर भी संरक्षण के द्वारा उसने अपनी गिरती हुई आर्थिक अवस्था को रोक ही नहीं लिया, बल्कि कुछ सुधार भी कर लिया।

प्रश्न

1. In what ways did the British Govt. deviate from the usual Free Trade Policy after the war of 1914-18? Explain the circumstances which necessitated this change.
2. The adoption of Free Trade Policy in England was a turning point in the history of her economic development. Comment.
3. The characteristic change in British Commercial Policy after 1815 is a reaction from world Economics to Imperial Economics."—Knowlce. —Discuss.

बैंकिंग व्यवस्था

ईसाई धर्म द्वारा व्याज लेना वर्जित था, साथ ही उस समय व्याज लेना कानूनी अपराध समझा जाता था। इस स्थिति में बैंकिंग व्यवसाय के आरम्भ होने की कोई सम्भावना न थी। धीरे धीरे लोग सोचने लगे कि पूंजी की व्यापारी अपने व्यवसाय में लगा कर लाभ अर्जित करते हैं तो धन देने वालों का भी कुछ भाग उस लाभ में होना चाहिये।

सन् ११४५ में कानून द्वारा व्याज लेना वैध कर दिया गया। सन् १६०४ में व्याज की अधिकतम दर ८% कर दी गई।

इंग्लैंड में बैंकिंग का आरम्भ १७वीं शताब्दी में हुआ। उस समय लोग अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए सुनारों के पास रख देते थे। इस वजह से आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर लोग धन निकालते थे। इस प्रकार सुनारों ने लोगों को धाक-पिट करने के लिए वज्रा धन पर व्याज देना भी आरम्भ कर दिया और वज्रा धन का एक भाग व्याज पर उधार भी देने लगे।

सन् १६९४ में बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) की स्थापना हुई। इस बैंक को व्यवसाय करने के लिये सरकार से अधिकार पत्र (Charter) मिल गया था। सन् १८२६ तक यही बैंक एक सम्मिलित पूंजी वाला बैंक था।

सन् १७५० से पहले बैंकिंग मुख्यतः लन्दन तक ही सीमित था। देशों में जो भी बैंक थे, वे निजी थे। गाँवों में व्यापारी व्यापार के साथ बैंकिंग कार्य भी करते थे।

औद्योगिक क्रांति के कारण बैंकिंग व्यवसाय का भी बहुत विस्तार हुआ। जगह जगह निजी बैंक खुल गये थे। परन्तु बैंकिंग व्यवसाय सीमित साधनों वाले सामान्य घोषणा के लोगों के हाथ में था। १७६३ और १८२५ के बीच के आर्थिक संकटों के कारण कितनी ही बैंक फेल हो गईं।

सन् १८१५ में इन छोटे छोटे निजी बैंकों के विपक्ष में यह कहा गया किने सट्टा करते हैं, प्रत्यक्ष अकुशल हैं और ये अपर्याप्त जमानत पर ऋण देते हैं।

बैंकों के अधिक संख्या में फेल होने के कारण सरकार का ध्यान इस ओर गया। सन् १८२६ के कानून के द्वारा लन्दन से ६५ मील दूर के स्थानों पर सम्मिलित पूंजी वाले बैंक स्थापित किये जा सकते हैं, जिन्हें नोट निगमन का अधिकार होगा। सन् १८३३ के कानून के अनुसार सम्मिलित पूंजी वाले बैंकों को लन्दन में अपने कार्यालय स्थापित करने

का अधिकार मिल गया। इन कानूनों ने इंग्लैंड में महत्वपूर्ण बैंकों के स्थापित होने में सहयोग दिया।

परन्तु इस समय तक अपरिमित दायित्व का (Unlted Liability) सिद्धान्त चलता था, इसलिए कम्पनियों और साझेदारी में कोई अन्तर न था। सन् १८५५ में कम्पनियों सीमित दायित्व के सिद्धान्त के अनुसार रजिस्टर्ड हो सकती थी। सन् १८५८ में यह सिद्धान्त बैंकिंग कम्पनियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक अंश-धारी अपनी शेयर की रकम तक के लिए ही उत्तरदायी माना जाता था। इस सिद्धान्त के लागू होने से बड़ी बड़ी बैंकिंग कम्पनियों की स्थापना होने लगी। इन्होंने स्थान स्थान पर शाखाएं भी खोलना आरम्भ कर दिया।

बड़े बैंकों के विकास की यह प्रवृत्ति २०वीं शताब्दी में भी चलती रही। ये बैंक प्रचुर साधन होने के कारण बड़े सड़कों का सामना करने में समर्थ हो सके और लोगों के विश्वास को प्राप्त कर सके। आजकल इंग्लैंड का बैंकिंग व्यवसाय बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा पांच बड़े बैंकों द्वारा होता है, जिनकी शाखाएं देश के विभिन्न भागों में हैं। इनकी शाखाएं विदेशों में भी हैं। ये ५ बड़े बैंक हैं—(१) बार्क्लेज (Barclays), (२) (Lyd's) लायड्स, (३) मिडलैंड (Midland), (४) वेस्ट मिनिस्टर (West Minister) तथा (५) नेशनल प्रोविन्सियल (National Provincial)।

सन् १८४४ के बैंक कानून द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड के दो विभाग हो गए—बैंकिंग तथा नोट निर्गम विभाग (Issue Department) लन्दन के किसी अन्य बैंक को नोट निर्गम का अधिकार नहीं रहा। सन् १९०१ से बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ही नोट निर्गमन किया जा सकता था। सन् १८४४ के बाद से ही बैंकों का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा।

इंग्लैंड का बैंक सन् १६६४ में स्थापित हो चुका था। धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता गया और वह देश का केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के रूप में कार्य करने लगा। नोट निर्गमन का उसे एकाधिकार प्राप्त हो गया। सरकार के सारे बैंकिंग सम्बन्धी कार्य उसको सौंप दिये गए। वह सरकारी ऋण का प्रबन्ध करने लगा और आर्थिक मामलों में सरकार को परामर्श देने लगा। यह बैंकों का बैंक (Bankers Bank) बन गया और इस प्रकार दूसरे बैंक इससे धन उधार लेने तथा उससे ऋण लेने लगे, जिससे अधिक स्थिरता आ गई। सन् १६४६ में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

राजस्व (Finance)

इंग्लैंड के राजस्व की स्थिति परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। व्यापार-वादी युग में आयात-निर्यात के कर राज्य की आय के मुख्य साधन थे। परन्तु निर्बाध व्यापार नीति (Laissez Faire or Free Trade Policy) के कारण ये आय के स्रोत कम होते गए। परन्तु सन् १६९२ में सरकार की नीति अपनाई जाने के फलस्वरूप आयात-निर्यात करों की वृद्धि से महत्ता बढ़ गई। आयकर (Income Tax) आरम्भ

में करघायी छोर पर लगाये गये थे, परन्तु बाद में आय के रग्यायी आचन बन गए। श्रृणों का परिराम बृद्ध अधिक बढ गया।

१९८८-८९ से पूर्व ह गलैड में राजा की प्रधानता थी और उसकी छी आय होती थी, छी से सरकार का व्यय चलता था। बाद में पार्लियामेंट पर उत्तरदायित्व आ गया और राजा की आय और दरबार के खर्च प्रशासन के सामान्य व्यय से पृथक कर दिये गये। राजा को प्रतिद्वर्ष टी जाने वाली राशि पहले मे निश्चित कर दी जाती थी।

सन् १८९६ से सार्वजनिक आय-व्यय के निरीक्षण का कार्य कन्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल के द्वारा किया जाने लगा।

आयात-निर्यात कर

सन् १९१० से पूर्व सरकारी आय के मुख्य साधन आयात-निर्यात कर तथा उत्पादन कर थे। बाद में कुछ वस्तुओं पर से सीमा शुल्क हटा दिया गया और अनेक पर कम कर दिया क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि इससे व्यापार में वृद्धि होगी और लोगों की सम्पन्नता बढेगी।

सन् १९८३ से मुक्त व्यापार नीति अपनाने के कारण बहुत मे अश्रयत् करों (Indirect Taxes) में कमी की गई, जैसे चाय पर आयात कर १६% से बढाकर १८॥% कर दिया।

नेपोलियन युद्धों की समाप्ति पर सन् १८१६ में आयकर (Income Tax) हटा दिया गया। इस कारण पुनः आयात कर लगाए गए, जिससे साधारण जनता पर कर का भार बढ गया।

सन् १८२३ मे मुक्त व्यापार की और तिर प्रवृत्ति बढी। निर्यात की कुछ वस्तुओं पर छी आर्थिक सहायता दी जाती थी, छने कम कर दिया गया। इसके साथ ही अनेक वस्तुओं पर छी भारी कर लगाये जाते थे, उनमें कमी कर दी गई।

सन् १८४२ में कच्चे माल की अनेकों वस्तुओं पर से आयात कर हटा दिया गया तथा कई निर्मित वस्तुओं पर से निर्यात कर समाप्त कर दिया गया।

सन् १८४५ में श्रीमदा युद्ध के कारण चाय, चीनी, काफी और मसिरा पर आयात कर बढा दिये गये। सन् १८६० में मुक्त व्यापार नीति अपनी चरम सीमा पर थी, केवल ४८ वस्तुओं पर छी कर रह गए थे, वे भी सरलरात्मक नहीं थे।

सन् १९३२ में सरलरा की नीति को अपनाया गया और वस्तुओं के मूल्य पर आयात कर लगा दिये गए।

आयकर

यह सर्वप्रथम १९६८ में लगाया गया। यह युद्ध कर के रूप में लगाया गया था और १८१६ में हटा दिया गया था। सन् १४८० में कर व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए बृद्ध छी वस्तुओं पर से सीमा शुल्क हटा दिया गया था, छी अग्यायी छोर से आयकर छिर लगा

दिया गया। कीमिया युद्ध, भारत का विद्रोह तथा चीन व रूस के युद्धों के कारण आयकर जारी रहा। परन्तु बदलती हुई परिस्थितियों के कारण आयकर की दरें घटती बढ़ती रहीं।

सन् १६०७ में आयकर को आय का स्थायी साधन मान लिया गया और १६०६ में सुपर टैक्स भी लगाया गया। १६१४-१८ के महायुद्ध के समय आयकर और सुपर टैक्स की दरों में वृद्धि की गई। अब ये सरकार की आय के स्थायी व महत्वपूर्ण साधन हैं।

भूमिकर

सर्वप्रथम १६६२ में लगाया गया। यह प्रथम प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) था, जो इंग्लैण्ड में सर्वप्रथम लगाया ~~गया~~ ^{गया}।

मृत्युकर

यह सर्वप्रथम १८६४ में लगा, जब ब्लैकसदन प्रधान मन्त्री थे। यह कर अब सम्पत्ति कर के नाम से प्रसिद्ध है। यह कर मृतक व्यक्तियों द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति पर लगता है। सन् १६०७ में इसकी दरें बढ़ा दी गईं। सरकार की आय का यह वर्तमान समय में अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा राज्य की आय बढ़ने के साथ ही समाज में विपन्न सम्पत्ति-वितरण का दोष भी कम हो जाता है।

लोक ऋण

सम्राटकालीन स्थिति में विशेषकर युद्धकाल में सरकार का व्यय उसकी सामान्य आय से नहीं पूरा हो पाता। देश की रक्षा करने के लिए तथा युद्ध के लिए ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसे ऋण सामान्यतः अनिश्चित काल के लिए लिये जाते हैं और उनको Funded Debts कहते हैं। जो निश्चित काल के लिए लिये जाते हैं उन्हें Unfunded Debts कहते हैं।

इंग्लैण्ड में अनिश्चित कालीन ऋण का प्रारम्भ सन् १६६३ में हुआ। कालान्तर में ऋण की राशि में निरन्तर वृद्धि होती गई, जिसका प्रमुख कारण युद्धों का होना था।

प्रश्न

1. Trace the origin of the development of Banking in England, and in this connection indicate the position of Bank of England.
2. Give a short account of the chief sources of Income of British Govt & trace their origin.

रूस का आर्थिक विकास

अध्याय

१. रूस के आर्थिक विकास की महत्ता
२. राज्यक्रान्ति के पूर्व की स्थिति
३. रूस की राज्यक्रान्ति (१९१७)
४. नवीन आर्थिक नीति
५. कृषि विकास
६. औद्योगिक स्थिति
७. 'रूसी योजनाएं' और उनसे शिक्षा

अमेरिका के बाद रूस ही ऐसा देश है, जिसमें प्राकृतिक सम्पदा प्रचुर मात्रा में है। विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र तथा प्रत्येक प्रकार की जलवायु और सतत परिश्रमी लोगों के कारण रूस आज विश्व में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। रूस की आर्थिक विशेषता की निम्न लिखित मुख्य बातें हैं -

(१) विशाल देश - रूस एक महान् देश है। उसका क्षेत्रफल २२५ वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल से ६ गुना है। उसकी २० करोड़ से अधिक जनसंख्या है। तथा इस दृष्टि से उसका विश्व में तीसरा स्थान है। वह उत्तर से दक्षिण तक २७०० मील तथा पूर्व से पश्चिम तक ७,००० मील तक फैला हुआ है। उसके शक्ति के साधन बहुत अधिक हैं। खनिज सम्पदा के अद्भुत भंडार हैं, जैसे पेट्रोल, लौह, सोना, प्लैटिनम आदि। यूरेनियम, काकेशस, मध्य साइबेरिया के मुख्य पहाड़ी क्षेत्रों से निकली नदियाँ यातायात के और विचार के लिये प्रसिद्ध हैं।

कृषि के लिये उपयोगी जलवायु व विस्तृत समतल भूमि के कारण प्रायः सभी प्रमुख फसलें यहाँ उत्पन्न की जाती हैं, जैसे—गेहूँ, जौ, शीत फल, चुकन्दर, कपास, तिलहन आदि खेती बड़े बड़े राजकीय फार्मों में यन्त्रों तथा वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। इसके अतिरिक्त पशुपालन व मत्स्य उद्योग के प्रसिद्ध क्षेत्र भी यहाँ हैं। इस प्रकार प्राकृतिक सम्पदा तथा परिश्रमी जनता के सहयोग से ही रूस विश्व में सबसे आगे बढ़ने में प्रयत्नशील है।

(२) राजनैतिक व्यवस्था—मिश्रित जातियों से भरा यह देश धीरे-धीरे सगठन शक्ति और स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर हुआ। पहले यहाँ सामन्तवादी राज्य 'जार' का चलता था, परन्तु जार के आत्मकत्यादी तथा अत्याचारपूर्ण राज्य का अन्त १९१७ की क्रांति के बाद समाप्त हो गया, जब लेनिन ने शासन संभाला। लेनिन की मृत्यु (१९२४) के पश्चात् स्तालिन के नेतृत्व में रूस ने आश्चर्यजनक उन्नति की। स्तालिन की मृत्यु के बाद ख्रुश्चेव ने राष्ट्र की रफ़ती हुई प्रगति को नया जीवन दिया।

आज रूस में मजदूरों की सरकार समाजवादी ढंग पर स्थापित है। द्वितीय महायुद्ध के बाद वह आर्थिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली होगया कि अन्य बड़े राष्ट्र भी भयभीत रहते हैं।

(३) योजनाबद्ध कार्यक्रम—विश्व में रूस ही ऐसा राज्य है जहाँ इतने कम समय में योजनाओं द्वारा इतनी अधिक उन्नति हुई है। एक समय में अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में होते हुए बिना किसी विदेशी सहायता के भारी मात्रा में औद्योगीकरण करना दूसरे देशों के लिए एक आदर्श बन गया है। स्वतन्त्रता—प्राप्ति के बाद प्रत्येक राष्ट्र आज प्रगति करना चाहता है और इसके लिये रूस का उदाहरण अनुकरणीय है।

(४) वैज्ञानिक प्रगति—विज्ञान के क्षेत्र में रूस ने अद्भुतपूर्व उन्नति कर ली है यह इसके द्वारा छोटे गैर स्फुटनिक से स्पष्ट है। इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रयत्नों से प्राकृतिक शक्तियों का उचित उपयोग होकर एक नई अणुशक्ति प्रधान औद्योगिक क्रांति का आरम्भ होने को है। अतः संसार के भविष्य निर्माण में इसका बहुत बड़ा हाथ होना निश्चित है।

राज्यक्रान्ति के पूर्व की स्थिति

१६१७ की क्रान्ति के पूर्व रूस एक सामान्य देश था। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी तथा भूमि की अकुशलता के कारण उत्पादन कम था। लोगों का जीवन-स्तर निम्न था। देश का औद्योगिकरण नहीं हुआ था तथा जनसंख्या का अधिक भाग कृषि पर आश्रित था।

उपरोक्ता सामग्री के लिये रूस को अधिकतर आयात पर ही निर्भर रहना पड़ा था। मशीनों के अभाव में औद्योगिक प्रगति नहीं हो पाई थी यातायात के साधन अवि-
कसित अवस्था में थे।

इस समय की आर्थिक स्थिति का अध्ययन निम्न प्रकार में किया जा सकता है:—

(१) कृषि—बार के समय लगभग ८०% जनसंख्या का जीवननिर्वाह कृषि द्वारा होता था। जनसंख्या की वृद्धि तथा निर्यात की नीति के कारण वास्तविक दशा ठीक नहीं थी। किसानों का शोषण बना रहा और अधिकतर कृषि पुष्पने तरीकों से ही चलती रही।

सन् १८६१ के बाद ग्राम समुदाय (Village Commune) बहुत शक्तिशाली बन गये। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ सेत छोटे होते गये और किसानों की दशा शोचनीय होती गई। धनी किसानों का अभाव अधिक बढ़ गया, जिससे ग्राम समुदायों को कार्य करना सम्भव न रहा और १८६० तक इनका पतन हो गया।

सन् १८६१ के दास मुक्ति कानून के बाद यद्यपि किसानों की सेत अवश्य मिलने लगे, परन्तु भूमि की कमी तथा मुआवजे के कारण उनकी दशा शोचनीय हो गई। सन् १८७२ के कमीशन ने किसानों की दुर्दशा का प्रमुख कारण आसमान और पक्षपात राज्य कर बताया। वार्षिक भुगतान न दे सकने के कारण किसानों की सेतों के हथान पर बड़े पैमाने पर पूँजीवादी रेती आरम्भ हो गई।

पूँजीवादी सेतों के आरम्भ होने में उत्पादन अवश्य बढ़ा, परन्तु किसानों की अधिक दुर्दशा हो गई तथा चरागाह, बंगल आदि भूमि पर सेतों की जाने लगी। सन् १८०० तक पूँजीवादी सेतों का स्पष्ट रूप सामने आ गया। इस समय घनी, तेज तथा कुशल छोटे से वर्ग ने अपनी पूँजी से निर्धन, विवश किसानों की भूमि खरीद कर उनसे मजदूरी पर काम कराना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार दो वर्ग हो गये—एक तो निर्धन किसानों का जो अपनी भूमि बेचकर मजदूर बन गया और दूसरा सन्तुष्टिशाली पूँजी पतियों का जिन्होंने

बड़े पैमाने पर मशीनों से वैज्ञानिक ढंग से खेती करना आरम्भ कर दिया। इस घनी वर्ग का प्रभाव बढ़ता गया। सन् १८८३ में कृषक भूमि बैंक (Peasant Land Banks) की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य किसानों को भूमि खरीदने में आर्थिक सहायता करना था।

सन् १८८५ में सामंत भूमि बैंक स्थापित हुए, जो भूमि को बंधक रखकर भूस्वामियों को श्रृणु देते थे।

सन् १८७५-८५ की ॥ दी ने अनाज का दाम गिरा दिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि निर्धनता, समृद्धिशाली किसानों द्वारा शोषण तथा राज्य की अनिश्चित नीति ने आने वाले विद्रोह की नींव डाली। अमिर्कों की बढ़ती हुई संख्या और संगठन, विभिन्न स्थानों पर किसान विद्रोह अधिक इकटाल, बुद्धिवादी वर्ग में क्रांति की भावना, सरकार की अयोग्यता आदि सग्यों ने राज्यक्रांति का वातावरण उत्पन्न किया।

सन् १९०१-१३ के समय में खेती की अधिक उन्नति हुई। अन्न तथा व्यापारिक पसलों बढ़ी, परन्तु फिर भी प्रति एकड़ उत्पादन की दृष्टि से इस का स्थान सबसे नीचा था। विस्तृत क्षेत्र होने के कारण देशी पूँजी अपर्याप्त रही और इस प्रकार विदेशी पूँजी का अधिक प्रयोग हुआ।

कृषि सुधार की महत्वपूर्ण योजना पीटर के राज में बनाई गई। सन् १९०६ के कानून द्वारा व्यक्तिगत किसानों की भूमि उनके स्वामित्व में दे दी गई। व्यक्तिगत खेतों को बेचने तथा उत्तराधिकारियों को देने का पूर्ण अधिकार दिया गया। बिल्वे हुए खेतों के स्थान पर बंधे हुए खेत देने के प्रयत्न किए गए।

इन सुधारों की राजनैतिक पृष्ठभूमि थी। पीटर कृषि सुधार की आड़ में बढ़ती हुई क्रांतिकारी प्रवृत्तियों रोकना चाहता था और इसके लिए स्वतंत्र व्यक्तिगत किसानों का एक शक्तिशाली वर्ग स्थापित कर रहा था। परन्तु उसकी यह आकांक्षा विकल थी रही। इन सुधारों से घनी व्यापारियों की शक्ति अधिक प्रबल बन गई। कृषक बैंक भूमि को बेचने का कार्य करता था, जिससे भूमिहीन छोटे किसानों को लाभ नहीं हुआ। अधिकतर यह भूमि समृद्धिशाली किसानों में बड़ा असंतोष फैल गया। इस प्रकार इन सुधारों ने क्रांति की लहर रोकने के स्थान पर तत्कालीन संगठन के विघटन को ही प्रोत्साहित किया।

१९१४ में विश्वयुद्ध आरम्भ हो जाने से सुधारों को स्थगित कर दिया गया। युद्ध-काल में कृषि पर अधिक भार रहा। अमिर्कों की बड़ी कमी रही, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति मैना में भर्ती हो गये, मशीन खाद बीज और यशुओं का बड़ा अभाव रहा। परिणाम-स्वरूप अनाज के उत्पादन में बहुत कमी हुई। देश के अन्दर अन्न का अभाव सफट आया। सरकार कृषि उत्पादन को निश्चित दर से खरीदने लगी, जिससे अन्न तोष फैला। सरकार की इस अविश्वेकपूर्ण नीति ने बहुत परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं और देश की अर्थव्यवस्था में क्रांति के भाग पर अग्रसर हुआ।

के समय में ही स्थापित हुई । सड़कों की भी दशा अच्छी नहीं थी । २०००० मील लम्बी सड़कों में केवल ३००० मील लम्बी सड़कें ही पक्की थीं । रुग्ण जैसे विस्तृत देश के लिये ये साधन अपर्याप्त थे ।

सामाजिक स्थिति

उस समय शिक्षा, स्वास्थ्य व निम्नलिखित आदि सामाजिक सेवाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकता था । इन सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी लोगों में क्रान्ति की भावना का उदय हुआ ।



रूस की राज्यक्रान्ति के आर्थिक परिणाम देखने के पूर्व रूस की उस आर्थिक स्थिति पर दृष्टिपात करना उचित होगा, जिसने क्रान्ति का वातावरण तैयार किया।

रूस के पास प्रथम महायुद्ध के समय साधनों का नितान्त अभाव था और युद्ध के कारण इनकी आवश्यकता और भी प्रतीत हो रही थी—यहां तक कि १९१६ की शरदऋतु तक रूस की आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से अश्वस्थित हो गई। जर्मनी जैसे शत्रु के विरुद्ध रूस में युद्ध सामग्रियों का उत्पादन बहुत ही कम था। मित्र राष्ट्रों से इन सामग्रियों के आयात के प्रयत्न विधे गये, परन्तु दूरी इतनी अधिक थी तथा यातायात के साधन इतने अपर्याप्त थे कि रूस को केवल हजारों मील लम्बी ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर ही निर्भर रहना पड़ा। औद्योगिक क्षेत्र में लौह, इस्पात और कोयले का उत्पादन १९१६ में १९१४ के परिणाम में बहुत कम था।

युद्ध सामग्री की कमी के कारण सेना में अधिक से अधिक व्यक्तियों की मर्ती होने लगी। इस मर्ती के कारण औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के नये मजदूरों की संख्या घटने लगी। निर्मित वस्तुओं के साथ साथ खाद्यान्न और ईंधन की भी कमी होने लगी। इस प्रकार संकट बढ़ता ही जा रहा था, सरकार का कार्य बक गया और १२ मार्च १९१७ को भार को गद्दी छोड़नी पड़ी।

इस घटना के पश्चात् सारे देश में एक बड़ी संकटपूर्ण स्थिति आ गई। रेलवे प्रणाली पूर्ण रूप से क्षिन्न-भिन्न होने लगी। देश में ईंधन का अकाल हो गया। मर्दियों के ठहरी रहने के कारण कच्चे लौह का उत्पादन बहुत कम हो गया सूती और आटे की मिलों को भी काम बन्द करना पड़ा। महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों के मित्र मालिक ताने बन्दी द्वारा अमिकी की भागी का उत्तर दे रहे थे। १९१६-१७ में औद्योगिक उत्पादन युद्ध के पूर्व तुलना में केवल ७१% था। नवम्बर १९१७ तक जबकि बोल्शेविक क्रान्ति हुई, स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि इसमें बदतर कोई न हो सकती थी।

कृषि अस्थान्ति शीघ्रता से पैल रही थी और औद्योगिक विकास ठप्प सा हो गया था। अमिकी के नेता शक्ति प्राप्त कर रहे थे। अन्तरिम सरकार की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। अक्टूबर १९१७ में खानों में हड़ताल की एक लहर भी दौड़ रही थी, जिसके परिणामस्वरूप खानों का नियंत्रण खान में काम करने वालों के पास आ गया। सन् १९१७ के अगले कुछ महीनों में क्रान्ति का आरम्भिक काल आरम्भ हुआ। इन आरम्भ के कुछ महीनों के रूसी राज्य में तुल्य समाजवाद को अपनाते जा प्रश्न नहीं था। प्रश्न था

आर्थिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार करना और नये राज्य की राजनैतिक शक्ति को सुदृढ़ करना। सदैव इङ्गलैंड का भय था और उद्योगों की गतिशील रहने के प्रयत्न करने आवश्यक थे।

१४ नवम्बर १९१७ को आर्थिक नियंत्रण आदेश घोषित किया गया, जिससे प्रत्येक उद्योग की आर्थिक समितियों को प्रत्यक्ष और नियंत्रण में भाग लेने का अधिकार मिल गया, परन्तु इस आदेश में अधिकारों को कारखानों पर अधिकार करने का निषेध था।

क्रान्ति के दूसरे दिन ही अर्थात् ८ नवम्बर १९१७ को नई सरकार ने भूमि अधि-
कारी की घोषणा कर दी, जिसके द्वारा भूस्वामियों के समस्त अधिकार बिना मुआविजा दिये ही समाप्त कर दिये गये और उनकी समस्त भूमि, सम्पत्ति, शाही भूमि, चर्च भूमि, पशु, औजार, खलिहान और मजदूर आदि स्थानीय समितियों को हस्त-तन्त्र कर दिए गये। कृषकों ने कई स्थानों पर स्वयं भूमि का उत्पन्न करना शुरू कर दिया। इसलिये फरवरी १९१८ में सब प्रकार की भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और प्रत्येक किसान को उसके परि-
वार के सदस्यों की संख्या के अनुसार खेतों करने के लिये भूमि दे दी गई। किसानों को उत्पादन बढ़ाने को निर्देशित किया गया। इस प्रकार शतान्दिश से चला आ रहा भूस्वामी का अधिग्रहण समाप्त हो गया।

इसी समय बैलों, गोदामों व बीमा का राष्ट्रीयकरण करना निश्चित किया गया। उस समय केवल महत्वपूर्ण उद्योगों को ही सरकार के अधीन किया गया। पूरे उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना वाञ्छनीय नहीं समझा गया। कुछ पदों का राष्ट्रीयकरण निम्न कारणों से किया गया—

- (१) राष्ट्र के लिये पद की महत्ता।
- (२) मिल मालिकों द्वारा आर्थिक नियंत्रण आदेश की अवज्ञा।
- (३) मिल मालिकों द्वारा तालेबन्दी की नीति अपनाना।
- (४) मिल मालिकों द्वारा विन्धन में भाग लेना।
- (५) मिल मालिकों द्वारा अधिकारों की काम से हटाना।
- (६) कच्चे माल और ईंधन के पर्याप्त होने पर भी मिल मालिकों द्वारा उत्पादन रोकना।
- (७) किसी भी कारण से मिल का कार्य रुक जाना।

इसी समय ऐसे प्रस्ताव भी थे, जिनमें सरकार और प्राइवेट कम्पनी या रिदेशी मिल कर मिश्रित कम्पनियाँ खोल सके। परन्तु इन प्रस्तावों की तीव्र आलोचना की गई।

बहुत से छोटे उद्योगों का प्रशासन कुछ कन्दा को सौंप दिया गया, जिनके पास उद्योगों के नियंत्रित करने के विस्तृत अधिकार थे। दिसम्बर १९१७ में सुप्रीम इकोनॉमिक काउंसिल (Supreme Economic Council) निर्मित की गई। इस काउंसिल के विभिन्न विभागों के द्वारा बड़े उद्योगों का नियंत्रण किया जाने लगा। इस काउंसिल के सदस्य-सरकारी प्रतिनिधि,

अधिक अधिक सध के प्रतिनिधि और तांत्रिक विशेषज्ञ थे। इसका प्रमुख कार्य अधिक समितियों के कार्यों का समन्वय करना और राष्ट्रीयकरण के लिये उचित प्रणाली निर्धारित करना था। इस प्रकार यद्यपि केन्द्रों और कौंसिल का सविधान पृथक् था, परन्तु कार्य लगभग समान थे। केन्द्रों को व्यक्तिगत व्यापार का आदेश देने के विस्तृत अधिकार थे, जैसे कच्चा माल बांटना, मूल्य निश्चित करना, एकीकरण करना और कौंसिल की स्वीकृति से फर्मों का राष्ट्रीयकरण करना।

पूर्वोक्त से समाजवाद के इस बीच के समय यह समझा गया कि अन्त में दोनों मिल जायेंगे। दो कारणों से राष्ट्रीयकरण की प्रगति तीव्र हो गई।

(१) प्रथम तो यह कि अपने नये उत्साह के कारण अधिक समितियाँ अपने अधिकारों से भी आगे बढ़ गईं। इन्होंने अवैधानिक रूप में कई फर्मों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। केन्द्रों के अधिकारी इस कार्य को रोकने में समर्थ न हो सके। कौंसिल के आदेशों की भी अवस्था की गई और इस प्रकार केन्द्र स्थानीय अधिकारियों को नियंत्रित करने में असफल रहा।

(२) दूसरे, १८१८ के ग्रीष्मकाल में रूस में एह्युद आरम्भ हुआ, जिसके कारण कई मिल मालिक अपनी मिलों का अधिकार चर्मनों के हाथ बेचने लगे। ऐसी स्थिति में सरकार के पास इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के सिवा कोई उपाय न रहा।

२८ जून १९१८ को सामान्य राष्ट्रीयकरण (General Nationalisation) का आदेश घोषित किया गया जिसके अन्तर्गत सब बड़े उद्योग सरकारी अधिकार में आ गये। राष्ट्रीयकरण का कार्य इतनी शीघ्रता से हुआ कि १९१९ के आरम्भ तक लगभग ३०००-४००० फर्मों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। इस प्रकार युद्ध के कारणों से सरकार को विवश होकर साम्यवाद अपनाना पड़ा। उसका नाम समाजवादी गणतन्त्र सोवियत संघ (Union of Soviet Socialist Republics U. S. S. R.) पड़ गया।

प्रत्येक वस्तु के अभाव के कारण आर्थिक स्थिति अत्यवस्थित हो गई। सब और अवाल पैल रहा था। उद्योग को कपास, कोयला, लोहा और यातायात की कमी के कारण हानि उठानी पड़ रही थी। एह्युद के कारण सोवियत सरकार को रेल्वे लाइनों, इंजिन, हिन्नों, कारखानों और पुलों की हानि हुई। अधिकों की क्षमता और उत्पादनशक्ति दुर्भिक्ष के कारण घट रही थी। लोग शहरों से देशों को प्रस्थान करने लगे।

बजट की अस्तुति स्थिति के कारण सरकार को मुद्रा नीति का आग्रह लेना पड़ा। परन्तु सरकार केवल नोट छापकर ही आवश्यक साधन नहीं प्राप्त कर सकती थी। अतः केन्द्रीय संग्रहण और वितरण पूर्ण विभाग के अन्तर्गत व्यवस्थित किया गया। परन्तु यह उपाय भी दीर्घपूर्ण था। परिणाम यह हुआ कि लोग समझ करने लगे।

जून १९१८ को इस पद्धति को दृढ़ करने के लिए Committees of Village Poor स्थापित की गईं। इन समितियों का मुख्य ध्येय वाले किसानों द्वारा विरोध किया

गया। अतः १९१८ के अन्त में इन समितियों को समाप्त कर दिया गया। इस बीच औद्योगिकरण का कार्य चालू रहा और अब इसके अन्तर्गत बहुत छोटे छोटे कारखाने भी आ गये। नवम्बर १९१८ में व्यक्तिगत आन्तरिक व्यापार का निषेध कर दिया गया। सन् १९१९ में सहकारी संस्थाओं की स्वतन्त्रता भी समाप्त कर दी गई।

औद्योगिक संस्थाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया —

(१) बड़े पैमाने के उत्पादित के उद्योग, जो सुप्रीम इकोनोमिक काउंसिल के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत थे।

(२) मध्यम औद्योगिक संस्थाएँ, जो प्रांतीय आर्थिक परिषदों के अन्तर्गत रखी गईं, यद्यपि S E C का उन पर नियंत्रण था।

(३) स्थानीय लघु औद्योगिक संस्थाएँ प्रांतीय आर्थिक परिषद् के अन्तर्गत।

परन्तु इस अत्यधिक केन्द्रीय प्रबन्ध को क्रियाशील करना बहुत कठिन था। इसके कारण देश में बड़ी आर्थिक गड़बड़ मची। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए शॉक सिस्टम (Shock System) आरम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण उद्योगों को कच्चा माल, ईंधन आदि देने में प्राथमिकता की प्रथा अपनाई गई।

इस प्रथा के कारण दूसरे उद्योगों की हानि उठानी पड़ी। प्रत्येक उद्योग अपने की प्राथमिकता की सूची में सम्मिलित वस्तुओं को प्रयत्नशील था। इसके साथ साथ कुशल प्रशासन और राजनैतिक सहानुभूति के अभाव में स्थिति और भी खराब हो गई। देशांत में किसानों का और नगरों में श्रमिकों का असंतोष बढ़ता ही गया।

क्रान्ति का प्रभाव १९२१ के आरम्भ तक चलता रहा। इस समय लेनिन ने आश्चर्यजनक क्षमता का परिचय दिया। अक्टूबर १९२७ के बाद देश की वित्तीय समस्या बराबर गिरती गई। जर्मनी से संधि होने के बाद जब व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो उद्योगपतियों का विश्वास नहीं सरकार में कम गया। नई सरकार ने देशी-विदेशी श्रृंखला सब रद्द कर दिए और देश को शेष ससार से पृथक् कर लौहद्वार (Iron-Curtain) में बन्द कर दिया।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रूसी क्रान्ति की आवश्यकता एवं अस्थिरता आर्थिक क्षेत्र में इतनी अधिक रही कि क्रान्ति के कई वर्षों तक रूस में कम उत्पादन, बेकारी एवं मूल्य वृद्धि की समस्याएँ स्थित रहीं। लेनिन ने इस स्थिति को समझते हुए नई आर्थिक नीति (New Economic Policy—N E P) की घोषणा कर दी। इस नीति को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की तृतीय विश्व कांग्रेस ने १९२१ में रूस के लिए उपयुक्त मान लिया।

प्रश्न

1. Give a short account of the economic conditions Prevailing in Russia before the Revolution
2. Discuss the main features of the Russian Revolution of 1917 and what were its after effects ?

यशुद के बाद देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गई। औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि-उपज बहुत कम हो गई। मजदूरों की संख्या में तथा वास्तविक मजदूरी की दरा में कमी हो गई। यातायात युद्ध के कार्य में व्यस्त रहने के कारण द्विज-मिन्न हो गया था। १९२१ के अकाल ने स्थिति को और भी बदतर कर दिया। अतः आर्थिक उत्थान के अतिरिक्त रक्षा का कोई अन्य उपाय न था। ६ अगस्त १९२१ के एक आदेश के द्वारा नई आर्थिक नीति को लागू कर दिया गया।

नई आर्थिक नीति की विशेषताएँ (Main features)

(१) औद्योगिक संस्थाओं को कच्चे माल और निर्मित माल के सम्बन्ध में स्वतंत्रता दे दी गई। परन्तु फिर भी कुछ ऐसे उद्योग थे, जैसे कि ईंधन, धातु आदि जिनकी राज्य की पूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे उद्योगों की संख्या बहुत कम कर दी गई। इन उद्योगों का प्रबन्ध S. E. C. के १६ विभाग करने लगे।

(२) उद्योगों को ट्रस्ट (Trust) और सिंडिकेट (Syndicate) में विभाजित कर दिया गया। १० अप्रैल १९२१ के आदेश के अनुसार ट्रस्ट की वैधानिकता प्रदान की गई। ट्रस्ट का प्रबन्ध S. E. C. के द्वारा नियुक्त बोर्ड के द्वारा होता था, जो पैक्टरी मैनेजर को नियुक्त करता था। मैनेजर आन्तरिक प्रबन्ध को देखते थे तथा क्रय-विक्रय सिंडिकेट द्वारा होता था।

(३) पैक्टरीयों और खानों को चलाने के लिए रूसी और विदेशी पूँजीपतियों को सुविधाएँ दी गईं। State Bank फिर से खोला गया और धन जमा कराने तथा ऋण देने की व्यवस्था की गई।

(४) सरकारी और व्यक्तिगत स्टोर्स की आर्थिक और व्यापारिक स्वतन्त्रता दी गई।

(५) किसानों को अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने की आशा भिन्न गई। वे अतिरिक्त उपज को अपने पास टैक्स देकर जमा रख सकते थे।

(६) श्रमिकों को मजदूरी नकद मिलने तथा Overtime का मज्जा देने का आदेश दिया गया।

(७) प्रत्येक राजकीय औद्योगिक संस्था को वार्षिक चिट्ठा तथा लाभ-हानि का साठा बनाकर प्रकाशित करना आवश्यक कर दिया गया।

(८) यह समितियों का निर्माण हुआ और निराया व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और आय को देखते हुए निर्धारित किये जाने का आदेश हुआ।

N E P के परिणाम

(१) नई नीति के कारण देश में विदेशी पूँजी का आयात हुआ, विशेषी व्यापार बढ़ा और सन् १९२२-२३ में निर्यात दुगुना हो गया । *विदेशी पूँजी का आयात*

(२) रूसी मुद्रा (रुबल) का अवमूल्यन समाप्त हुआ और वह एक मुहठ स्तर पर आधारित हो गई

(३) कृषि का विकास हुआ और कृषकों की मांग निर्मित वस्तु के लिये बढ़ने लगी ।

(४) उद्योगों को कच्चा माल मिलने लगा और बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा । विशेषतः उद्योग का पुनर्गठन करने के लिये जुग गया और बहुत से उद्योगों की प्रारम्भिक क्रियाओं में सुधार किया गया । परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ गया । खरीद स्तरों खोले गये और नगरों की शोभा बढ़ गई । *उत्पादन में वृद्धि*

(५) कृषकों की दुदशा और बढ़ गई । सन् १९२३ में कृषि पदार्थों के मूल्य ६०% गिर गये । दूसरी ओर औद्योगिक संस्थाओं (Trusts) ने लाभ दिलाने के हेतु निर्मित वस्तुओं के मूल्य ८०% बढ़ा दिये । इस कारण कृषकों ने अनाज बेचना और निर्मित माल खरीदना बन्द कर दिया । गोदाम माल से भर गये और औद्योगिक अवरोध आरम्भ हो गई ।

(६) ऐसी स्थिति में माल लागत से भी कम मूल्य पर बचा जाने लगा और कृषि-पदार्थों के मूल्य बढ़ गए । परन्तु फिर भी स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सका ।

(७) व्यक्तिगत व्यापारी और छोटे निर्माताओं की शक्ति बढ़ गई और इन्होंने अधिक धन समझ कर लिया । इनकी बढ़ती हुई सम्पन्नता रोकने के लिए भारी कर और प्रतिबंध लगाये गए ।

नई नीति के आलोचकों ने कहा कि यह नीति देश को साम्यवाद से पूँजीवाद की ओर ले जाने वाली है । परन्तु वास्तव में इस नीति में दोनों वादों की विशेषताएँ थीं । सब बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना साम्यवाद का द्योतक था । कृषि व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए छोड़ दी गई थी । कृषि और उद्योग का सबंध मार्केट से था और यह पूँजीवाद का पक्षीर था । लेनिन ने इस नीति को सामाजिक अर्थव्यवस्था की स्थापित करने की प्रारम्भिक सीढ़ी बताया ।

इस नीति द्वारा रूस का आर्थिक विकास बढ़ा बंधकर हुआ । सर्वत्र कच्चे लाहे तथा ईंधन की कमी हो गई । कच्चे लाहे के यूराल में पाये जाने से कुछ कठिनाई कम हुई । सन् १९२१ के दुर्भिक्ष के कारण स्थिति और बिगड़ गई थी । विदेशी आर्थिक सहायता के अभाव में देश की स्थिति के साधनों पर पुनर्निर्माण करना पड़ा ।

संक्रमणम ईंधन की कमी को दूर करना आवश्यक था । वेतन देने की नई प्रणाली अपना ली गई, जिससे वेतन दर उत्पादन से सम्बन्धित कर दी गई । खान के भूमिका को भोजन वितरित किया जाने लगा । यातायात के साधनों में सुधार किया जाने लगा और खाद्य स्थिति को सुधारने के प्रयत्न हुए । परन्तु फिर भी कच्चे माल का सर्वत्र अभाव था ।

ट्रस्ट अपना निर्मित माल कच्चे माल के बढ़ते में बेचने लगे। कच्चे माल के मूल्य बढ़ गए और निर्मित माल के मूल्य कम हो गए। इस समस्या के लिए उत्पादन कम करने और अतिरिक्त उत्पादन के निर्यात तथा ट्रस्ट की प्वाँबी बढ़ाने के सुझाव दिये गए। कुछ समय बाद प्वाँबी के अच्छी होने से स्थिति में सुधार हुआ।

कृषि उत्पादन के बढ़ने तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से सन् १९२३ में स्थिति उद्योगों के पक्ष में हो गई। इस समय कच्चे माल की माग बढ़ जाने से कमी हो गई। किसानों की कम शक्ति के हास के कारण निर्मित माल का विक्रय कम होता था। मुख्य समस्या लागत व्यय में कमी करने तथा कृषि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने की थी। परन्तु समस्या का हल नहीं हो सका। समस्या के हल न होने का मुख्य कारण राज्य उद्योग का एकाधिकार था। सरकार ने इस एकाधिकार को कम करने के लिए निम्न प्रयत्न किये—

(१) रैंक द्वारा ट्रस्ट की सीमित सृण देना।

(२) आन्तरिक व्यापार समिति द्वारा अधिकतम मूल्य निर्धारित करना।

(३) कुछ वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिए विदेशी सस्ती वस्तुओं का आयात करना।

इन प्रयत्नों से उद्योगों को लागत व्यय में कमी करनी पड़ी। १९२३ में ट्रस्ट के पुनर्गठन के लिए एक कमीशन नियुक्त हुआ। कृषि पदार्थों के मूल्य बढ़ाने के लिए निर्यात बढ़ाने और कम सस्याओं को आर्थिक सुविधाएँ देने के प्रयत्न किये गए।

सन् १९२५-२६ से कम में पुनर्निर्माण का कार्य आरम्भ हुआ और औद्योगीकरण को महत्व दिया गया। दिसम्बर १९२५ में १५वीं पारी काँग्रेस में रतालिन की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें भारी उद्योगों को प्रारम्भिक महत्ता देने पर जोर दिया गया, जिससे रूस मशीन आयात करने वाले देश की अपेक्षा मशीन निर्माण करने वाला देश बन जाय।

यह निर्विवाद है कि नई नीति के परिणामस्वरूप प्रगति अवश्य हुई और यह एक आदर्श नीति थी। परन्तु इसके कारण उद्योगपतियों में राष्ट्रीयकरण और हस्तक्षेप का मन बराबर बना रहा। ऐसी स्थिति में निजी उद्योग को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता था।

प्रश्न

1. Give a short account of the background of N. E. P.
2. What were the main features of N. E. P.? Briefly describe its consequences

प्राचीन काल में रूस की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर थी। गेहूँ, जौ, राई और अड़न को मुख्य रूप से पैदावार की जाती थी। कम जनघनत्व और विस्तृत क्षेत्र होने के कारण निरस्त कृषि (Extensive Cultivation) की प्रथा थी। कृषि संगठन और विकास विदेशी आक्रमणों, युद्ध और मतभेदों के कारण समय समय पर बदलता रहा। उस समय सामाजिक वर्ग शायद और व्यक्तिगत सम्पत्ति का उद्देश्य नहीं हुआ था।

रूसी कृषि की सबसे बड़ी विशेषता सामुदायिक भूमिस्वामित्व १५वीं सदी से दृढ़-गाबर होती है, इस ही समय दास प्रथा प्रारम्भ हुई। १६वीं सदी में मुद्रा प्रयोग के कारण भूमिक रोज छोड़ कर लाभपूर्वक धन में जाने लगे। छोटे और मध्यम किसान वर्ग का प्रभाव प्रथम अवस्था में बढ़ा। १७वीं शताब्दी में देश में भारी उपज-पुथल तथा विप्लवों के कारण कृषि की दशा बिगड़ती गई और किसानों की स्वतन्त्रता प्रायः समाप्त हो गई। १८वीं शताब्दी में नई दिशा दी और प्रगति के प्रयत्न किए गए। औद्योगिक विकास ने कृषि को प्रभावित किया और सत्र किसानों ने लाभ की दृष्टि से अनाज व्यापारियों के हाथ बेचना शुरू किया, जो निर्यात कर दिया जाता था।

१९वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन की वृद्धि एक समस्या बन गया। अनाज के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा सर्वत्र अकाल का स्थिति बनी रहने लगे। कृषि की यह अनिष्टता दास प्रथा, पुराने खेती के ढंग, खेतों पर प्रणाली, पशुपालन की अवस्था और खाद के अभाव के कारण हुई।

रूस की कृषि के संबंध में एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ नीति कभी न हो सकी। यूरोप के कृषि के उन्नत तरीकों से किसान १९वीं सदी तक अभिभूत रहे। राजनैतिक संगठन बढ़ा बहुत देर में हुआ, अतः कृषि संबंधी नीति की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। परन्तु रूस में सेना के प्रयोग होने के कारण किसान अपनी भूमि छोड़ छोड़कर भाग गए, जिससे अव्यवस्था पैदा हो गई। उस समय कर वसूली कृषि नीति का मूलधार था।

रूसी कृषि का उत्पादन संगठन और अवस्था ओबश्टीना था। खेतों पर परिवार सहित कार्य किया जाता था। १९वीं सदी में मार पर कर वसूलों का उत्तरदायित्व भी डाल दिया। गाव, जिसे मीर कहते थे, आत्मनिर्भर तथा स्वशासित थे। सामुदायिक कृषि पद्धति रूसी कृषि की विशेषता रही है। १८६१ के दास मुक्ति अधिनियम के कारण मीर रूसी कृषकों को एकमात्र संगठन बन गया, परन्तु आपुनिक मुद्रा प्रणाली तथा विनियम ने इसकी स्थिति कमजोर कर दो २०वीं सदी के आरम्भ में यह नष्टपाव हो गया।

१८६१ से रूसी क्रांति १९१७ तक की कृषि की स्थिति का अध्ययन हम दूसरे अध्याय में कर आए हैं। यहाँ हम संक्षिप्त रूप में रूसी क्रांति के पश्चात् के कृषि विकास पर दृष्टिपात करेंगे।

क्रांति के पश्चात् पूर्ण भूस्वामित्व के स्थान पर किसानों की भूमि और सम्पत्ति सामाजिक सम्पत्ति घोषित कर दी गई। अब सोवियत राज्य किसानों का स्वामी हो गया। किसानों को बड़े सहकारी तथा सामुदायिक संगठनों में बाँटा गया और समाजवाद के सिद्धांतों से प्रभावित कराया जाने लगा। दूसरी और किसानों के अधिकतम सहयोग के औद्योगीकरण को सहाय्य दिया गया।

सहकारिता कृषि के तीन रूप अपनाये गए '१ तोज (Toz) अथवा संयुक्त खेतों जिसके अन्तर्गत किसान मिलकर कृषि करते थे परन्तु प्रत्येक का भूमि परस्परभिन्न बना रहता था और उपज बाँट ली जाती थी। (२) आर्टेल (Artel) सामूहिक रूप से खेतों पर काम किया जाता है और उत्पादन को आय सदस्यों में बाँट ली जाती है। इस प्रकार सदस्यों की निजी भूमि और सामुदायिक क्षेत्र दोनों से आय प्राप्त हो जाती थी। (३) कम्यून (Commune) इसमें सदस्य सामुदायिक रूप से काम ही नहीं करते, परन्तु वे सामुदायिक रूप से रहते भी हैं। उत्पादन के साधन और सम्पत्ति कम्यून की होती है। सामुदायिक रूप से उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया होती है।

आजकल तोज और कम्यून तो समाप्तप्राय हो गए हैं और आर्टेल रह गए हैं, जिन्हें कोलखोज पुनरा जाता है। इसकी उत्पत्ति १९३५ में निर्धारित की गई। इसके ऋतुसार सारी भूमि सोवियत राज्य की है और सामुदायिक आय को भ्रम के अनुसार बाँटने का प्रबन्ध किया गया। उत्पादन के साधन कोलखोज (Kolkhoz) के अधीन रहते हैं, परन्तु निवासस्थान पशु-पक्षी और औद्योगिक इमारतों में हैं। धर्म का काम सभी सदस्यों को करना पड़ता है। कोलखोज शासन की ओर से कार्य का प्रमाण तथा वेतन निश्चित किया जाता है। विशेष योग्य व परिश्रमी सदस्य को भत्ता मिलता है। प्रतिदिन का वेतन इस बात पर निर्भर करता है कि उस दिन किस वर्ग का काम किया गया। इस प्रकार कार्य के विभिन्न वर्गों के अनुसार पारिवर्त्मिक की मात्रा नापी जाती है।

कोलखोज का प्रबन्ध प्रजातन्त्रात्मक तरीके से होता है। राज्य कोलखोज का केवल पथ प्रदर्शन करता है। सन् १९४६ में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के अधीन कोलखोज समिति का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य संगठन प्रबन्ध और कार्यक्रम में सन्तुलन उत्पन्न करना है। १९५० की एक नई योजना द्वारा कोलखोज की संख्या में कमी करने का निश्चय किया गया जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके।

राजकीय कृषि पार्सो सोवखोज (Sovkhoz) के संगठन तथा विस्तार में राज्य ने पूरी सहायता दी। इनके द्वारा आधुनिक कृषि प्रणाली और सामुदायिक संगठन के लाभ प्रदर्शित

किए गए। इन कार्यों की प्रगति बहुत तीव्र रही इनका अधिक यत्नीकरण भी किया गया है। इसका काम करने का तरीका राजकीय कारखानों के समान है। इसका प्रबन्ध राज्य से नियुक्त अधिकारी करते हैं।

कृषि विकास के लिए आधुनिक शक्ति सहायता केन्द्रीय रूप से दी जाती है। मशीन-ट्रेक्टर स्टेशन सामुदायिक पार्कों को विभिन्न प्रकार का सहायता उपलब्ध करता है।

स्तालिन की मृत्यु के बाद रूस में महान् परिवर्तन हुए, जिनका कृषि पर विरोध प्रभाव पड़ा। यह आशा की जाती है कि १९६५ तक कृषि संगठन और प्रबन्ध में बहुत से परिवर्तन हो आवेंगे।

प्रश्न

1. Give the salient features of Russian Agriculture before the Revolution.

2. What changes were introduced in Agricultural policy after the Russian Revolution.

रूस के औद्योगिक विकास का संगठन किसी एक निर्दिष्ट पथ पर नहीं चला। कारखानों की स्थापना तथा कस्तु उत्पादन पर राजनैतिक स्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ा। १७वीं सदी तक राजनैतिक अस्थिरता के कारण रूसी शहरों में औद्योगिक वर्ग का भी जन्म न हुआ था, जबकि युरोप में कारीगर पथ बन चुके थे। आत्मनिर्भर ग्राम संगठन या और निर्मित वस्तुओं की माग बहुत कम थी। सर्वप्रथम लोहा और नमक उद्योग आरम्भ किया गया और बाद में खान, पोटाश और धातु निर्माण भी आरम्भ किये गए। राजकीय सरदार तथा प्रोत्साहन प्राप्त होने पर भी दास प्रथा के कारण रूस का औद्योगिक विकास उचित रूप में न हो सका।

पीटर के समय में औद्योगिक प्रगति में परिवर्तन हुआ। बड़ी मात्रा में वस्तु निर्माण हुआ। १६वीं सदी के मध्य में पूँजीवादो काग्यना पद्धति आरम्भ हुई। सेना और सुरक्षा की स्थिति सुधारने के लिए भिन्न और कारखाने बनने शुरू हुए। इस समय उत्साहन कार्य लगभग राज्य के द्वारा ही किया जाता था।

आधुनिक उत्पादन की नींव १६वीं सदी के प्रथम २० वर्षों में पड़ी। इस काल में नई औद्योगिक प्रणाली रूस के भिन्न भिन्न ठेकागो में अपनाई गईं। यह उत्पादन की प्रथा, पिछड़ा समाज और माग की कमी जैसी कठिनाइयों के होते हुए भी कुछ उपयोग लो उत्पत्ति कर गये। १८२४ में बाह्य व्यापारिक बंधों की स्थापना शुरू हुई। इस प्रकार औद्योगिक विकास को सहारा मिला। १८५५ तक मशीनों का उपयोग बहुत अधिक होने लगा, बिजली हाथ से काम करने वाले कारीगरों की महत्ता कम होने लगी। राजकीय प्रोत्साहन तथा संचालन की सहायता से व्यापारवादी सिद्धांत पर औद्योगिक उत्पत्ति करना इस समय की मुख्य नीति रही।

१८६१ से १९१७ तक की औद्योगिक स्थिति का अध्ययन हम पहले ही दूसरे अध्याय में कर आये हैं।

क्रान्ति के बाद प्रथम महायुद्ध के कारण रूसी औद्योगिक स्थिति अतहाय होकर द्विभ्रम हो गई। युद्धकाल में औद्योगिक प्रगति के सतत प्रयत्न सरकार की ओर से किये गये। क्रान्ति के तुरन्त बाद ही उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। कारखाना प्रणाली के लिये अधिक समितियाँ बनाई गईं। २८ जून १९१८ को सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। २६ दिसम्बर १९१८ को लघु उद्योगों की भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार अर्थ व्यवस्था का प्रबन्धन *Sapreme Economic Council* के अधीन कर दिया गया।

अम की कमी तथा ग्रहयुद्धों के कारण तथा ग्लेशी मशीन, रसायन तथा विशेषज्ञों के अभाव में उद्योगों की शक्ति क्षीण हो गई। १९२१ में निर्धारित नई आर्थिक नीति N.E.P. के द्वारा ट्रस्ट सिंडिकेट बनाकर तथा उनका प्रबंध S.E.C. के अधीन कर औद्योगिक उन्नति के प्रयत्न किये गये। इन प्रयत्नों से १९२२ से उत्पादन बढ़ने लगा।

रूस में औद्योगिक व्यवस्था के २ माग हैं—राजकीय एवं सहाकारी सहाकारी क्षेत्र एक अस्थायी व्यवस्था है और सरकार इस ओर प्रयत्नशील है कि सारी अथ व्यवस्था राजकीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाय।

सन् १९२६ में प्रबन्धकों कारखाने के प्रबंध में अधिक अधिकार और स्वतन्त्रता मिली। १९३४ में उत्पादन का क्षेत्रीय संचालन होने लगा। एक क्षेत्र के एक पदार्थ के उत्पादन में लगे सारे कारखानों का प्रबंध केन्द्रीय औद्योगिक प्रबंध समिति को दे दिया गया। प्रत्येक मैनेजर को अपने उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने का आदेश था। उत्पादन प्रणाली, मशीन, मजदूरों की भर्ती और अन्य आन्तरिक प्रबंध के मामले भी यह समिति निश्चित करती थी।

प्रत्येक कारखाना एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई है और बचत बढ़ाना तथा लागत को कम करना कुशल प्रबंध सम्झा जाता है—सत्ते पर कम व्यय पर अधिक उत्पादन सफलता की कसौटी माना जाता है। इस प्रकार प्रत्येक कारखाने को प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन के लिये प्रयत्नशील होने की प्रेरणा मिलती है। अधिक उत्पादन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के लिये एक पृथक समूह है। इसके साथ ही कारखाना सुधार केन्द्र भी है जहाँ पूँजीवादी प्रवृत्तियों से मजदूरों को दूर रखने के प्रयत्न किये जाते हैं।

मैनेजर और इंजिनियर को अधिक प्रोत्साहन तथा प्रतिष्ठा देने के लिये साम्यवादी दल में मिला लिया गया। प्रबन्धकों के अतिरिक्त कारखाने में समाजवाद दल समिति और श्रमिक संघ समिति का भी निर्माण हुआ। कारखाने का हर एक विभाग उपविभागों में बाँटा जाता है, जिसका अध्यक्ष अथवा फोरमैन उत्पादनश्रम का अन्तिम नायक होता है।

इस प्रकार यह शत होता है कि रूस के औद्योगिक संगठन की ऐसी प्रणाली है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम उत्पादन करके लक्ष्यों से भी आगे बढ़ने को उत्साहित हो। मजदूरों की योजना-लक्ष्य की पूर्ति, सामूहिक समझौते, श्रम कल्याणकारी कार्य, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन अधिक संघ के मुख्य कार्य हैं।

अम संघ और प्रबंध में समझौता ३ प्रकार से होता है—(१) देश में प्रचलित योजना का सिद्धान्त, (२) श्रमिक अधिनियम और (३) आदर्श सामूहिक समझौता, जिसकी रूपरेखा उच्च अधिकारी निर्धारित करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के समझौते को ही माना जाता है, क्योंकि न मानना अनुशासनहीनता का प्रमाण माना जाता है।

अम संघ के प्रतिनिधि विभिन्न समितियों तथा आयोगों में भाग लेते हैं। संघों का

कार्य अथ कल्याणकारी क्रियाओं तक ही सीमित रह गया है और महत्त्वपूर्ण विषय उन्नत राजकीय स्तर पर निश्चित किये जाते हैं।

सैद्धान्तिक रूप से सरकार एक मजदूर सरकार है, यह सरकार ही सब मजदूरों के लिये वेतन, कार्य के घंटे तथा कल्याणकारी सभ्यों की रूसरवा बनाती है। तो मजदूरों में असंतोष होना सम्भव नहीं प्रतीत होता। १९४२ में अथ सर प्रियम द्वारा यह मान लिया गया कि प्रत्येक अधिक राज्य के आदेशों का कार्य स्वीकार करने के लिये बाध्य है। इस प्रकार रूप में औद्योगिक संघों और इकाया तथा सन्धियों को कोई स्थान नहीं है। परन्तु फिर भी इन झगड़ा से तय करने के लिये एक विशेष संस्था है, जिसको R.K.K. कहते हैं। इसके निर्णय दोनों पक्षों को मान्य न होने पर अन्त में अदालत के फैसले पर निर्भर रहना पड़ता है। यह संस्था विधान द्वारा संचालित विषयों का निर्णय के लिये नहीं ले सकती। इसके क्षेत्र के अन्तर्गत काम का विभाजन, अतिरिक्त कार्य, जुट्टा आदि छोटे छोटे मामलों ही आते हैं। परन्तु इस संस्था का महत्त्व अब कम होता जा रहा है।

प्रश्न

1. Give a short account of Industrial Organisation in Russia before & after the Revolution.
2. Examine the functions of Trade Unions & discuss the position of the workers in the present Russian economic system.
3. Do disputes between workers and management occur in Russia? How are they settled?



रूसी योजनाएं और उनसे शिक्षा

रूसी एक पिछड़ा हुआ कृषिप्रधान देश था जिमने औद्योगिक विकास करने तथा शक्तिशाली बनने के लिये एक नया मार्ग अपनाया, जिसे 'राष्ट्रीय योजना' कहते हैं। इसके द्वारा राष्ट्र के सभी अंगों का संयोजित विनाश करने का लक्ष्य था। इस प्रणाली को अपना कर इस देश ने जो आश्चर्यजनक प्रगति की उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रूसी दश की योजना एक दिन अविकसित देशों के लिये आदर्श बन जायगी। यहाँ हम रूसी योजनाओं पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे और देखेंगे कि उनसे क्या शिक्षा मिलती है।

गोयलरो योजना (Goelro Plan)

रूस में लेनिन ने योजना की नींव डाली। लेनिन के अनुसार देश के विकास के लिये विद्युत्तीकरण आवश्यक था, इसलिये ही राजकीय विद्युत्तीकरण आयोग की स्थापना मार्च १९२० में की गई, इसे गोयलरो भी कहते हैं। इसका उद्देश्य १० से १५ वर्षों के बीच सारे देश में विद्युत् शक्ति पहुँचाना था। क्रान्ति के पूर्व रूस के उद्योगों में बिजली का प्रयोग बहुत कम होता था। सन् १९३० तक कठिनाइयों के होते हुए भी इस योजना ने लगभग अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली। १९३५ में इस योजना को पूर्ण सफलता मिली। औद्योगिक उत्पादन तथा विद्युत् उत्पादन इस समय १९१३ की अपेक्षा क्रमशः ५.७ गुना और १४.५ गुना बढ़ गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना [१९२८ से १९३२]

१९२८ में औद्योगीकरण की प्रगति बढ़ाने के लिये रूस में एक योजना की रूपरेखा तैयार की गई। इस योजना का प्रारम्भिक कार्य राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का, जो मुद और क्रान्ति के कारण जर्जरित हो गई थी, औद्योगीकरण द्वारा पुनर्निर्माण करना था। इस योजना में लगभग प्रत्येक सामाजिक और आर्थिक अंगों के सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया था। इस योजना में निम्न कार्यों को सम्मिलित किया गया—

(१) बिजली उत्पादन और वितरण, (२) भारी और हल्के उद्योग, (३) कृषि, (४) यातायात, (५) डाक, तार व टेलिफोन, (६) उपभोक्ता की सहायरी संस्थाएँ, (७) धन, (८) शिक्षा (९) वैज्ञानिक अनुसंधान, (१०) स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, (११) एर व्यवस्था और (१२) वित्त व्यवस्था।

इस प्रकार यह योजना केवल औद्योगिक उत्पादन के लिये ही नहीं, परन्तु रूसी जीवन की शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिये भी थी। इसने अविद्या के विरुद्ध युद्ध, अनिर्वाय सुल शिक्षा और स्कूलों के निर्माण के प्रस्ताव रखे। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य संबंध

अधिकों के लिये आरामगृह, शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन के दूर आदि सामाजिक कल्याणकारी कार्यों के करने के प्रस्ताव थे।

जो लक्ष्य इस योजना में निर्धारित किये गये, वे देश के विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों, ट्रस्ट, वैक्टरियों आदि के लिये थे।

इस योजना की बड़ी बड़ी बातें साम्यवादी पार्टी और सरकार ने निर्धारित कीं। योजना बनाने में सरकार की समाजवादी समाज की स्थापना करने की नीति को अपनाया गया, जिससे उत्पादन के साधनों का अधिकतम विकास हो और अधिकों की दृष्टि में क्रमबद्ध सुधार हो सके। अन्तिम योजना घोषित करने के पूर्व योजना की रूपरेखा के बारे में सरकार के विभिन्न विभागों, ट्रस्टों, अर्थिक व वैज्ञानिक संस्थाओं के विचार उपलब्ध कर लिये थे। योजना की यह विशेषता रही है कि लक्ष्य के निर्धारित होने के बाद भी, उन्हें लागू करते समय फिर से संशोधन किया जाता था।

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि करना इस योजना की विशेषता है। अधिकों की उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्साहित करने की वेतन बढ़ा दिये गए और कुशल अधिकों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई। पांच वर्षों के लिए २० मिलियन रुबल व्यय करने का अनुमान रिया गया। यह राशि उस धन के अतिरिक्त थी, जो यातायात, वाणिज्य और राष्ट्रीय आवश्यकताओं में विनिवेश की जा चुकी थी। भारी उद्योगों का ३३१% और हल्के उद्योगों का १४४% उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव रिया गया। विज्ञान के सबसे आधुनिक यन्त्रों को अपनाया गया।

उत्पादन वृद्धि के साथ साथ लागत व्यय को घटाने की विशेष महत्ता दी गई, परन्तु इससे वस्तुओं की किस्म (Quality) गिर गई। विद्युत् उत्पादन पर बहुत ध्यान दिया गया, इसका उत्पादन पांच गुना बढ़ाने का निश्चय किया गया। ४० बड़े बिजली के कारखाने स्थापित किये गए।

बिजली के बाद मशीन तथा लोहे के उत्पादन को विशेष महत्ता दी गई। धातु, रासायनिक और मशीन उद्योगों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। हजारों मील लम्बी नई रेलवे लाइन निर्मित हुई और रेलवे कारखानों से सुधार हुआ। छारे देश में नई वैक्टरिया और बिजली के कारखानों का जाल सा बिछ गया, जिनमें से कुछ विश्व में सबसे बड़े हैं। जहाज और ट्रेक्टर निर्माण में अधिक प्रगति हुई।

परन्तु इन सब परिणामों के लिए रूस को बहुत अधिक व्यय तथा त्याग करना पड़ा। सरकार को मशीनों, इन्जीनियरों और वाणिज्यों का आयात करने के लिए एक बड़ी राशि व्यय करनी पड़ी।

इस तीव्र औद्योगिक विकास ने १९३० तक बेकारी की समस्या समाप्त कर दी और अधिकों की कमी होने लगी। दूसरी ओर कुशल कारीगरों का सर्वत्र अभाव था।

कृषि क्षेत्र में सक्रिय प्रगति की गई। छोटे छोटे खेतों को बड़ी बड़ी इकाइयों में

संगठित किया गया जिससे कृषि उत्पादन पर राज्य को पूर्ण नियन्त्रण मिल सके। सामुदायिक कृषि की पद्धति अपनाई गई और सामूहिक फार्म (Kolkhoz) स्थापित किये गए। आय का वितरण प्रत्येक के धर्म के अनुसार होने लगा। यद्यपि धनो किसानों (Kulaks) ने विरोध किया, परन्तु उनको ज़टोस्ता से दबा दिया गया। सरकार ने सरकारी फार्म सम्बन्धी (Sovkhoz) भी खोले, जिसका प्रमुख कार्य कृषि सम्बन्धी प्रयोग एवं गवेषणा करना है। इस प्रकार योजना का उद्देश्य कृषि के सामूहिकीकरण द्वारा समाजवाद की प्रगति करना था।

१९२६ की अच्छी फसलों के कारण सामूहिक खेतों का अधिक विस्तार सम्भव हुआ और कृषि उत्पादन में सुधार हुआ। १ फरवरी, १९३० को सरकार के आदेश द्वारा सामूहिक कृषि का अभूतपूर्व विकास हुआ परन्तु फिर भी कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में सामुदायिक कृषि प्रणाली केवल कागजी योजना ही रही। २ मार्च, १९३० को स्तालिन ने घोषणा की कि सामुदायिक कृषि अनुपयुक्त क्षेत्रों में न लादी जाय। उसने कहा कि पूर्वी स्थिति सामूहिक खेतों को सुदृढ़ बनाया जाय और खेतों का सामूहिकीकरण किसानों की इच्छा से किया जाय।

कुछ वर्षों पश्चात् सामूहिक खेतों के अधिकारी की कार्यकुशलता का हाव होने लगा। चारे की कमी और भीमारियों के कारण देश में पशुओं की दशा दिगड़ गई और उनकी संख्या बहुत कम हो गई। पशुओं की कमी, १९३१-३२ की खराब फसलों, सरकार द्वारा निश्चित मूल्य पर भारी मात्रा में अनाज, मांस, दूध और दूसरी खाद्य वस्तुओं के खरीदने के कारण १९३३ में देश में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, जिससे लाखों रूसियों की मृत्यु हुई। इन सबका यह परिणाम निकला कि सरकार को राशनिंग पद्धति अपनानी पड़ी। बाद में औद्योगिक वस्तुएँ राशनिंग की दुकानों द्वारा वितरित की जाने लगी।

पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य ४ वर्षों में ही पूरे कर लिए। मशीनों का उत्पादन दुगुना, विद्युत् उत्पादन २१ गुना, औद्योगिक उत्पादन ११८% और उपभोक्ता की वस्तुओं का उत्पादन ८७% बढ़ गया इसके अतिरिक्त कोयले तथा लोहे के उत्पादन में भी वृद्धि हुई।

प्रथम योजना की समीक्षा

योजना की रुबरखा का अध्ययन करने के बाद यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि इस योजना की कमियाँ क्या थी। सर्वप्रथम कारखानों के स्थानीयकरण के बारे में यह कहा जा सकता है कि इनकी स्थापना उपभोक्ता और कच्चे माल की प्राप्ति को ध्यान में न रखकर राजनैतिक दृष्टि से की गई।

दूसरी ओर ऊँचे उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के कारण कारखानों की मशीनों की अधिक घिसाई (Depreciation) हुई।

विद्युत् उत्पादन पर अधिक बल देने के कारण देश में इतनी विशाल मात्रा में बिजली का उत्पादन हुआ, जितनी उपयोग में लेना सम्भव न हो सका।

भारी उद्योगों पर अत्यधिक घोर देने का परिणाम यह निकला कि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई, जिससे उपभोक्ता की वस्तुएं मिलना कठिन हो गया।

यातायात के साधनों का महत्व पूरी तरह नहीं समझा गया। अविकसित यातायात को प्रथम योजना की सबसे बड़ी कमजोरी बताया गया।

जबकि उद्योगों की तीव्रगति से प्रगति हो रही थी, अधिकों के रहने का उचित प्रबंध नहीं किया गया। मकानों का भारी अभाव रहा।

सुख में हो प्रथम योजना के लक्ष्यों की सफलता ने योजनाबद्ध कार्य कर्मों को प्रोत्साहन दिया। भविष्य के विकास के लिए योजित अर्थ व्यवस्था की सफलता की कुंजी माना जाने लगा। इस योजनाकाल में रूस एक पिछड़े हुए कृषक देश से कृषक औद्योगिक देश बन गया। प्रथम योजना अनुभव प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण का साधन थी। योजना के अन्तर्गत विद्यालय धनराशि के व्यय करने के सुपरिणाम लगने समय के बाद मिलने वाले थे, अतः रूस की जनता ने जारी कठिनाइयों को भेलना स्वीकार किया और योजना की सफलता के लिये प्राणपण से जुट गये। उनके त्याग और परिश्रम का ही पल है कि रूस एक बड़े शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना [१९३३-१९३७]

प्रथम योजना की सफलता से उत्साहित होकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना को १ जनवरी १९३३ से आरम्भ किया गया। प्रथम योजना ने बहुत सी कमियों के होते हुए भी देश की औद्योगीकरण के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। इसके साथ ही सामूहिक कृषि आन्दोलन की भी प्रगति हुई।

द्वितीय योजना की पृष्ठभूमि स्तरजित रही—स्टालिन ने राष्ट्रीय युद्ध के लिए अपने विरोधियों को नष्ट कर दिया।

बढ़ती हुई परिस्थितियों के कारण द्वितीय योजना में जीवनस्तर के मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया गया। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उपभोक्ता की वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक महत्व दिया गया। फरवरी १९३३ में योजना आयोग के अध्यक्ष ने कहा—“द्वितीय योजना काल में उपभोक्ता की वस्तुओं का उत्पादन दुगुना या तिगुना बढ़ाया जाएगा जिससे कि महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं के उपयोग का स्तर सोवियत रूस को १९३७ में विश्व का सबसे अधिक प्रगतिशील राष्ट्र बना दे।”

यह निश्चय किया गया कि औद्योगिक उत्पादन का $\frac{1}{3}$ भाग नये उद्योगों द्वारा उपलब्ध किया जाय। इसके लिए वारिक और थम उत्पादन में मुद्दे, लागत व्यय में कमी और वस्तुओं की निम्न मुद्दे पर घोर दिया गया। सन् १९३७ तक उत्पादन ६३% तक बढ़ाया जाय और लागत व्यय २६% तक घटाया जाय। वस्तुओं की निम्न मुद्दे के लिये प्रशासन और प्रबंध में मुद्दे किये गये। पुराने तानिकों से सहयोग प्राप्त किया जाय।

यद्यपि योजना के आरम्भ होने के पूर्व यह कहा गया था कि उपभोक्ता की वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक महत्व दिया जायगा, परन्तु वास्तव में योजनाकाल के अन्त में औद्योगिक वस्तुओं का ही उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा और मुख्यकर विद्युत् शक्ति, मोटर, ट्रैक्टर, वायुयान आदि का। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण युद्ध सामग्री के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया गया। मशीन उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ। कच्चे लोहे का उत्पादन १६३७ में १६३० से दुगुना हो गया तथा हस्पात का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ। तेल के उत्पादन में कमी हुई।

कृषि क्षेत्र में इस योजनाकाल में महत्वपूर्ण कार्य किये गये। किसानों को सामुदायिक कृषि की ओर प्रेरित करने के लिये १६३५ में कृषि आरटेल के आदर्श नियम बनाये गये, जिनसे किसानों को औद्योगिक मजदूरों के समान कठोर अनुशासन में रखा जा सके। इन अवसरों का उद्देश्य अधिकतम उत्पादन करना था।

सामुदायिक कृषि के अतिरिक्त व्यक्तिगत छोटे छोटे क्षेत्रों को विकसित करने तथा किसानों को गाय, सूअर, मुर्गियाँ और उद्यानों के लिये उत्साहित किया गया। यह आश्वासन दिया गया कि किसानों को उनके काम और कार्यकुशलता के अनुरूप नियमित रूप में मजदूरी दी जायगी।

योजना में निर्यात पर अधिक महत्व नहीं दिया, जिससे अधिक लाख पदार्थ देश में रह सके। इस कारण अक्टूबर १६३५ से सब प्रकार का राशनिंग हटा दिया गया। विभिन्न प्रकार के स्तर के कार्य और उत्तरदायित्व के लिये विभिन्न मजदूरी की दरों पर धोर दिया गया।

परन्तु इतना सब होने के बाद भी रूस की प्रति व्यक्ति औसत आय दूसरे पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत कम थी। अतः यह आशा व्यक्त की गई कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता की वस्तुओं पर अधिक महत्व दिया जायगा, जिससे भारी उद्योगों की बढ़ी हुई शक्ति का पूर्ण उपयोग हो सके।

तृतीय योजना (१६३८-१६४२)

इस योजना का उद्देश्य वर्गहित समाज के निर्माण को पूरा करना था तथा समाजवाद से साम्यवाद का क्रमिक परिवर्तन करना था। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण तृतीय योजना राष्ट्रीय सुरक्षा उद्योग को सुदृढ़ करने की ओर संचालित की गई थी। इसके साथ ही श्रमिक वर्गों के भौतिक और सांस्कृतिक विकास के भी विस्तृत कार्यक्रम बनाये गये थे।

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के विस्तार, श्रम उत्पादन में वृद्धि लागत व्यय में कमी, और वस्तुओं के किस्म में सुधार करने के उद्देश्य थे। कृषि उत्पादन ५०% से अधिक बढ़ाना और उद्योगों को कच्चे माल और उपभोक्ताओं के क्षेत्रों के समीप लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिससे की समस्या न रहे और पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके।

१९३६ में सुरक्षा उद्योगों का उत्पादन सबसे अधिक हुआ। अगले २ वर्षों में सरकार का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा उद्योग का अधिकतम उत्पादन अल्पतम समय में करने का था।

१९४१ में रूस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया, जिससे यह योजना अचूरी हो गई। यह योजना लगभग ३॥ वर्ष तक ही चल पाई। इतने कम समय में ही औद्योगिक उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। सामुदायिक सेवा ने कृषि पर पूर्ण प्रभाव बना लिया।

मुद्रकाल में रूस के आर्थिक साधनों की अत्यन्त क्षति हुई। प्रमुख औद्योगिक और कृषि क्षेत्र जर्मनी के अधिकार में आ गये। यूक्रेन पर कहा कि देश के सम्पूर्ण कोयला, कच्चा लोहा और इस्पात के उत्पादन का आधा भाग उपलब्ध होता था, जर्मनी का अधिकार हो गया। सब मिलाकर रूस को कोयले के उत्पादन का ३ भाग, कच्चे लोहे का ६०% और अनाज क्षेत्रों के ५०% भाग को हानि उठानी पड़ी।

जैसे जैसे शत्रु-सेनाएं आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे ही रूस अपने उद्योगों का स्थानान्तरण बोवंगा के पार सुराल पहाड़ों के पीछे और साइबेरिया में करता गया। इस पूर्व की ओर स्थानान्तरण का एक परिणाम यह निकला कि यातायात की कठिनाई उत्पन्न हो गई तथा पुषण क्षेत्रों में उद्योगों का केन्द्रीयकरण हो गया। दूसरी ओर उपमोक्षा की वस्तुओं के उत्पादन के अभाव में देशवासियों की अत्यन्त कष्ट हुआ।

इन सब हानियों की पूर्ति करना एक बड़ा कठिन कार्य था। १९४३ में आर्थिक पुनर्विकास के लिये एक विस्तृत योजना बनाई गई। परिणामस्वरूप अगले वर्षों में कुछ सुधार सम्भव हुआ, परन्तु फिर भी द्वितीय महायुद्ध के बाद पहले की उत्पादन शक्ति के एक भाग का ही पुनर्निर्माण किया जा सका।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना [१९४६-१९५०]

पुनर्निर्माण का वास्तव में कार्य १९४५ के पश्चात् आरम्भ हुआ और १९४६ में प्रथम मुद्रोत्तर योजना बनाई गई। एक बार फिर भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। लोहा व इस्पात का ३५%, कोयले का ४१%, बिजली का ७०%, ट्रैक्टर और मोटरों का ३॥ गुना बढ़ा, मशीन-औजार का चार गुना उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना ने पुराने पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी केन्द्रों के पुनः औद्योगीकरण की महत्त्व दिया। सन् १९५० तक उद्योगों का उत्पादन ४८% और औषिक उत्पादन ३६% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया।

कृषि-क्षेत्र में हुई क्षति की पूर्ति करने हेतु ८७% वृद्धि की योजना बनाई गई। इस योजना ने अपने लक्ष्यों की पूर्ति सदा की भांति अपने समय से पूर्व ही कर ली। औद्योगिक उत्पादन ८४% बढ़ गया। ट्रैक्टर और मोटर का उत्पादन १९३० से दुगुना हो गया। खाद्य पदार्थों के उत्पादन लक्ष्य तक नहीं बढ़ पाया। उपमोक्षा की वस्तुओं जैसे सूती वस्त्र, जूते और दूसरे इन्के उद्योगों का उत्पादन १०% बढ़ा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि युद्ध ने रूस की आर्थिक व्यवस्था को नष्टवाय कर दिया था, परन्तु युद्ध के बाद वहाँ अमूल्य प्रगति हुई। रूस के अनुसार वहाँ औद्योगिक उत्पादन दुगुना बढ़ गया, यद्यपि पश्चिमी निरीक्षकों के अनुसार ३०% ही बढ़ा। फिर भी इतना मानना ही पड़ेगा कि युद्ध के बाद उसकी सीमाएँ बड़ी और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। यह कहा जाता है कि जिनकी उन्नति बढ़ा हुई, यह उस ही परिणाम में हुई, जितनी कि पश्चिमी यूरोप के देशों में अमेरिकन आर्थिक सहायता द्वारा सम्भव हुई।

पंचम पंचवर्षीय योजना [१९५०-१९५५]

इस योजना में भी भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई और इसके साथ ही सुरक्षा को सुदृढ़ करना इस योजना का ध्येय था। औद्योगिक उत्पादन में ७२% वृद्धि करना था, जबकि १९५५ में वार्षिक वृद्धि ८.५% की हुई। उपभोक्ता की वस्तुओं का उत्पादन ७६% हुआ, जबकि लक्ष्य ६५% था। विकास की गति पूँजीवादी देशों के विकास से लगभग ५०% अधिक थी।

अत्यधिक विकास इन्जिनियरिंग उद्योगों में हुआ। तेल, कच्चा लोहा और कोयला का उत्पादन भी बढ़ा। खजर भूमि को ट्रैक्टरों की सहायता से कृषि योग्य बनाया गया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। पशुपालन में भी सुधार किये गये।

छठी पंचवर्षीय योजना (१९५६-६०)

जनवरी, १९५६ में यह योजना प्रकाशित की गई थी, परन्तु इसमें समय समय पर संशोधन किये गये और अन्त में १९५८ में इसे स्थगित कर दिया गया।

इस योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय आय को ६०% और औद्योगिक उत्पादन ६५% बढ़ाना था। कोयले का उत्पादन ५०% तेल तथा विद्युत् उत्पादन दुबना बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। योजना में परिणाम की अपेक्षा किस्म पर अधिक महत्व दिया गया। आधुनिकतम आविष्कारों के उपयोग और उत्पादन के मन्त्रीकरण पर बल दिया गया। एटम शक्ति के स्टेशनों का उत्पादन ५ वर्षों में २ से २.५ मि. किलोवाट तक होने का अनुमान किया गया।

सारे योजनाकाल में ऐसा प्रतीत होता है कि उपभोक्ता की अवस्था की गई। उत्पादक वस्तुओं की ६५% वृद्धि का आयोजन किया गया। अभी भी भारी उद्योगों को महत्व दिया गया है। मशीन निर्माण में ८०% वृद्धि करने का निश्चय है, जब कि वास्तविक मजदूरी में ३०% वृद्धि ही योजना है। पिछले कुछ वर्षों में हल्के उद्योग ने साधारण से अधिक उन्नति की है। १९५५ में सामान्य उपभोक्ता की वस्तुओं, जैसे सूती वस्त्र, जूते आदि का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के बराबर ही था। कुछ ऐसी वस्तुओं, जैसे घड़ियों, रेडियो या घीने की मशीनों का उत्पादन कुछ कम हुआ।

ऐसा प्रतीत होता था कि निकट भविष्य में एक औसत रूढ़ी अधिक सुखपूर्वक रहने की आशा नहीं कर सकता। हा, वह इतना सतोष पा सकता था कि प्रति ५ वर्ष परचाव

इसके जीवनस्तर में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त यह निर्माण कार्यों की दुगुनी प्रगति होने के कारण उपभोक्ताओं को एक बड़े संतोष की आशा है।

उपभोक्ता की दशा में सुधार होना अविकतर कृषि पर निर्भर करता है। ऐसा मनीत होता है कि पिछली योजना के अन्तर्गत निर्धारित निरूप कृषि पदार्थों के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये। यह इससे ज्ञात होता है कि १९६० के लिए निर्धारित अनाज का लक्ष्य १८० मिलियन टन बड़ी है, जो पिछली योजना के लिए रखा गया था। योजना के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अन्न योजना बनाने वालों का अधिक यतीकरण और खादों के अधिक उपयोग पर ही विश्वास है।

अन्त में इतना ही कहना है कि यह योजना लक्ष्यों के अम्पावहारिक होने के कारण असफल रही और भविष्य की योजनाओं के लिए व्यावहारिकता खाने का प्रभाव होने लगा।

सप्तवर्षीय सातवीं योजना (१९५६-१९६५)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनता का जीवनस्तर उन्नत करना था। योजना की अवधि ५ वर्ष से बढ़ाकर ७ वर्ष कर दी गई। इसके अन्तर्गत औद्योगिक और कृषि उत्पादन अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिससे रुढ़ विश्व के राष्ट्रा में सबसे आगे बढ़ जाये।

इस योजना पर होने वाला सरकारी व्यय लगभग इस सारे व्यय के बराबर होगा, जितना पिछले ४० वर्षों में किया गया है। औद्योगिक शिक्षा पर १४८८ से १५१३ यह निर्माण पर ३७५-३८०, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक सुविधाओं पर ७७ हजार मिलियन रूपय व्यय दिये जायेंगे। विभिन्न मंडों पर व्यय और अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार हैं।

मद	व्यय (हजार मिलियन रूपय)	अतिरिक्त उत्पादन प्रतिवर्ष (१९५६ से)
खीर व दूध	१००	६० ;
रसायन उद्योग	१००-१०५	२००
तेल व गैस	१७०-१७३	१३०-१४०
विद्युत्	१२५-१२६	७०
कापड़ा	७४	२० से ६०
उपभोग व स्वास्थ्य उद्योग	८०	५० से १००
कृषि	१५०	७०
रेल	११०-११५	८५-९४
यह निर्माण	३७५-३८०	
सामाजिक कल्याण व सुरक्षा	३६०	

समुक्त राज्य अमरीका से देश का उत्पादन आगे बढ़ाने के लिए १९०० से अधिक कारखाने खोले जायेंगे। उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों का निर्माण किया जायेगा। रासायनिक उद्योग को विकसित करने के लिए २७० बड़े कारखाने खोले जायेंगे। कुल औद्योगिक उत्पादन १९५८ को अपेक्षा १९६२ में लगभग ८०% बढ़ जायेगा। इसके उद्योगों के लिए १५६ नए कारखाने स्थापित होंगे। सूती व ऊनी कपड़े तथा जूते का उत्पादन बढ़ाया जायेगा।

औद्योगिक संगठन में निगिष्टीकरण तथा यन्त्रीकरण से पूरा सहायता ली जायेगी, लागत व्यय में कमी तथा उत्पादन की क्रिम में सुधार करने की भरसक चेष्टा की जायेगी।

यातायात की समस्या इस योजना के अन्तर्गत पूर्ण रूप से हल हो जायेगी। रेल, समुद्र नदी एवं मोटर यातायात के विकास के प्रयत्न किए जायेंगे और मुख्यकर वायु यातायात का विस्तृत विकास किया जायेगा।

मूल्य में कमी तथा वेतन, पेन्शन व सहायता में क्रांति होने से श्रमिका तथा दूसरे कर्मचारियों की वास्तविक आय में वृद्धि हो जायेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन आदि की उचित व्यवस्था की जायेगी।

कृषि-क्षेत्र में यह आशा व्यक्त की गई कि उत्पादन इतना अधिक बढ़ा लिया जायेगा कि जनता के भोजन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकेंगी। उद्यानों के लिए पर्याप्त कच्चा मान भी उपलब्ध हो सकेगा। प्राधुनिकतम यन्त्रा तथा वैज्ञानिक खाद से कृषि क्षेत्रों का विकास किया जायेगा। समूहिक फार्म (Kolkhoz) और राजकीय खेता (Sovkhoz) की विशाल स्तर पर उन्नति की जायेगी। अनाज के उत्पादन का लक्ष्य १६०-१८० मिलियन टन रखा गया है।

पशुपालन विभाग में अत्यधिक उन्नति करने की योजना है। दूध, मांस, अण्डे और ऊन के उत्पादन की विशेष महत्व दिया गया है। चारे के उत्पादन बढ़ाने का भी विशेष प्रयत्न किया जायेगा। बहुत बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर और दूसरे वैज्ञानिक यन्त्रों का निर्माण किया जायेगा। इस प्रकार योजना ने कृषि में महान् परिवर्तन करने की रूपरेखा तैयार की है।

छठी योजना १९६० तक चलने वाली थी, किन्तु १९५८ में उसको स्थगित कर दिया गया। फरवरी १९५६ में कम्युनिस्ट पार्टी के २१वें अधिवेशन में नई योजना के लक्ष्यों को स्वीकार किया गया।

आज रूस संसार का सबसे विस्तृत देश है। उसका क्षेत्रफल ८ मिलियन वर्गमील से अधिक है। वह पश्चिम में फिनलैंड से पूर्व में जापान तक और उत्तर में उत्तरी भुज से एशिया के मध्य तक फैला हुआ है। उसका जनसंख्या १७० मिलियन है, जो कि चीन और भारत के बाद विश्व में सबसे अधिक है। फिर भी वह बेकारी का नाम निगान नहीं है।

इस प्रकार रूस आज पश्चिम को एक आर्थिक चुनौती है। एक पिछड़े हुए देश

से वह युरोप के औद्योगिक दानव के रूप में प्रकट हुआ है। उसके प्रति व्यक्ति के उत्पादन की तुलना अब पश्चिमो देशों में की जाने लगी है। यह आशा व्यक्त की गई है कि १९६२ तक उसका प्रति व्यक्ति उत्पादन वर्तमान युरोपियन उत्पादन से अधिक हो जायेगा तथा अमेरिका के लगभग बराबर हो जायेगा।

इस प्रकार रूस का आर्थिक नक्शा बदल रहा है और रूस वाले नई तांत्रिक शक्ति लाकर विश्व की आर्थिक शक्ति को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं।

रूसी योजनाओं की विशेषताएँ (उनसे शिक्षा)

(Lessons from Russian Plans)

पूर्वोक्त को छोड़ने और पूर्णतया आर्थिक योजना की अपनाने में २ समस्याएँ सामने आती हैं। प्रथम तो देश की आर्थिक व्यवस्था के उचित विकास की और दूसरी कुशल प्रबंध की। रूसी के नेताओं के सामने मुख्य समस्या राबकीय उद्योगों के उचित प्रबंध की थी। इसके लिये ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है, जो योजना के विविध कार्यक्रमों को पूरा होते देखे।

— रूस में योजना का दो पद्धति है—

(१) योजना केन्द्रों का समूह है। सारे देश के लिये एक केन्द्रीय संस्था है, जिसे GOSPLAN कहते हैं और विभिन्न प्रांतों, जिलों और बीस हजार से अधिक आबादी वाले नगरों में योजना आयोग हैं। इन केन्द्रों को किसी भी बात के बारे में पूछताछ करने का अधिकार है, परन्तु योजना की पूर्ति में दखल देने का नहीं।

(२) रूस के मंत्रालयों के अन्तर्गत विभागीय योजना आयोग हैं और उनके विशेष विभाग ट्रस्ट और औद्योगिक संस्थाओं में हैं, जो कि राष्ट्रीयकरण लिये वगैरह उद्योगों का प्रबंध करते हैं। इन दोनों संस्थाओं में पूरा सहयोग है।

रूसी योजनाओं की एक विशेषता यह है कि उनके कार्यक्रमों की पूर्ति पर उचित नियंत्रण रखा जाता है। अच्छी से अच्छी योजना की असफलता अशांत कठिनाइयों और परिस्थितियों के कारण हो सकती है। अतः कोई भी अव्यवस्था का सामयिक ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि रूस में योजना का नियंत्रण और प्रशासन उचित रूप से हो पाता है।

योजनाओं में २ प्रकार का मोड़ पाया जाता है— १ आदेशात्मक और २ प्रेरित। नए विनियोग से सम्बन्धित योजनाएँ प्रेरित होती हैं। जहाँ पर योजना उपभोक्ता के चुनाव की वस्तुओं अथवा स्थानीय पूर्ति से सम्बन्धित है, वह आदेशात्मक की श्रेणी में रखी जाती और केवल सामान्य अनुमान ही लगाये जाते हैं। ऐसी योजनाओं में एक प्रकार की सख्त होती है जिससे कि बाद में कुछ परिवर्तन सम्भव हो सकें।

केन्द्रीय योजना के प्रारम्भिक उद्देश्य निम्नलिखित रहते हैं —

(१) सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के लिये जो अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं, उनका समुचित उत्पादन और वितरण।

(२) योजना में दी गई प्राथमिकता की वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति करना।

(३) राष्ट्रीय प्राथमिकता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में कुछ स्वतन्त्रता देना।

योजनाओं के संचालन में कार्यकुशलता, निर्देशनों के केन्द्रीकरण और प्रशासन के विकेन्द्रीकरण पर ध्यान रखा जाता है। दूसरे शब्दों में उच्च प्रशासन संस्थाओं में हस्तक्षेप और आर्थिक इकाइयों के दिन प्रतिदिन के कार्यों की स्वतन्त्रता के बीच समतुलन रखने का प्रयास किया जाता है।

प्रारम्भ में S E C राज्यीय आर्थिक इकाइयों का प्रशासन करती थी। बाद में यह कॉमिल विभिन्न शाखाओं में विभाजित कर दी गई। १९४० तक ऐसी ३० शाखाएँ थीं, जो राजकीय उद्योगों का प्रशासन करती थीं। लम्बे अनुभव के बाद अब उद्योगों का प्रशासन ३ समूहों में होता है —

1. All Union Industries—इनका उत्पादन सम्पूर्ण देश की राष्ट्रीय योजना के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस समूह में सम्मिलित हैं—पूँजीगत वस्तुओं के निर्माण करने वाले उद्योग और खान आदि के उद्योग। इनका प्रशासन यूनियन के मन्त्रालयों द्वारा होता है।

2. Industries Under Union Republics—कुछ ऐसे बड़े पैमाने के उद्योग हैं जो सारे देश के लिये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये अधिकतर उपभोक्ता की वस्तुओं के उद्योग हैं, जिनका प्रबन्ध यूनियन रिपब्लिक के मन्त्रालय द्वारा होता है। परन्तु इनके कार्यकलापों का समन्वय और धुनियन मन्त्रालय से रहता है। इनकी वस्तुओं के उत्पादन और वितरण का प्रबन्ध रिपब्लिकन अधिकारियों के हाथों में रहता है।

३. लघु उद्योग—तीसरे लघु उद्योग हैं जो स्थानीय कच्चे माल से मुख्यतः उपभोक्ता की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये ही सबसे अधिक सुविधा विकेन्द्रीय प्रशासना की लेते हैं। इनका प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओं द्वारा होता है और इनके कार्यों का समन्वय स्थानीय उद्योग के मन्त्रालय द्वारा होता है।

All Union और Republican उद्योग ट्रस्ट के रूप में संयुक्त होकर मन्त्रालय के अधीन होते हैं। बड़े बड़े उद्योग सीधे मन्त्रालय के अधीन हैं।

आर्थिक योजना की सफलता प्रबन्ध की एकता पर निर्भर है। यह कार्य संचालकों और मुख्य व्यक्तियों को स्वयं जिम्मेवार ठहराना किया जाता है। सबसे छोटी से लेकर बड़ी तक प्रत्येक उत्पादक इकाई में संचालक होता है, जो कि सारी इकाई की व्यवस्था का उत्तर

दायी होता है। किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति उसकी कार्यकुशलता पर निर्भर रहती है। मंचालकों को पूरे अधिकार मिलते हैं, परन्तु जो कार्य सौंपे गए हैं उनको पूरा करने का उत्तरदायित्व भी उनके ऊपर ही है। इन संचालकों के अधिकार पूर्वीवादी देशों की अपेक्षा बहुत अधिक भिन्न हैं—जैसे नियुक्तियाँ करना, स्वतन्त्र रूप से व्यापारिक समझौते करना और समुचित बोझ उठाना आदि। परन्तु उन पर छद्म संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रेस और साक्ष्य संग्रहों का समुचित नियंत्रण रहता है जिससे कि वे कोई अनुचित काम करने में हिचकिचाते हैं।

उत्पादन योजना के साथ साथ ही एक वित्त योजना भी बनाई जाती है। इस योजना में उत्पादन योजना से सम्बन्धित सब प्रकार के व्ययों का ध्येय दिया जाता है। प्रत्येक औद्योगिक इकाई के पास वित्त के २ भाग रहते हैं—(१) स्वयं की पूँजी और (२) वोजित ऋण। दोनों का संचालन GOSBANK द्वारा होता है। पहले के उपयोग पर प्रबन्धकों का पूरा अधिकार रहता है, परन्तु दूसरे का उपयोग वित्त योजना में दिये कार्यक्रमानुसार किया जाता है यदि इसमें किसी प्रकार का विचलन प्रबन्धकों की त्रुटि के कारणों से हुआ तो उसकी सूचना उपयुक्त अधिकारियों को GOS BANK द्वारा दे दी जाती है। यदि अशांत परिस्थितियों के कारण विचलन हुआ है तो GOSBANK वित्त योजना में सुधार के सुझाव अथवा विरोध की प्रतीति व्यक्त कर देती है। यही बैंक अल्पकालीन ऋण की सम्पूर्ण व्यवस्था करता है।

दीर्घकाली ऋण का नियंत्रण भी इस ही प्रकार औद्योगिक बैंक (PROM BANK) द्वारा होता है। बजट ने जिन संस्थाओं को धन मिलता है, उनके व्यय सम्बन्धी प्रस्तावों पर राज्य नियंत्रण मन्त्रालय द्वारा होता है।

योजना की अन्तिम सफलता—असफलता वर्ष के अन्त में इकाइयों के लाभ अथवा हानि द्वारा ज्ञात होती है। इस प्रकार योजना का वृहत् आकार होता है। औद्योगिक इकाइयों के प्रबन्धकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनकी नौकरी से हटाया जा सकता है अथवा दंडित भी किया जा सकता है।

७ मई, १९५७ को श्री गुरुचेव ने रूस के आर्थिक विकास के प्रशासन में विकेंद्रीकरण की घोषणा की, जो भविष्य के आर्थिक विभाग में प्रावश्यक थी। यह विकेंद्रीकरण की योजना रूसी खनिज के प्रत्येक अंग में सम्बन्धित रहेगी। गुरुचेव के अनुसार भूमिगत वन के सटम्पों ने अपने सांस्कृतिक और तांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति में बड़ी उन्नति की है। देश के पास वर्तमान समय में अत्युत्तम सांस्कृतिक धन और तांत्रिक ज्ञान है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक योजना ने रूस को समग्र का एक महान् देश बना दिया है। विश्व में यही एक ऐसा देश है, जहाँ देवारी और उत्पादन का संकट कभी नहीं होता। रूस के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक योजना के अभूतपूर्व गुण विदित हैं।

देश के घन की वृद्धि और प्रत्येक कार्याशील व्यक्ति के उच्च जीवनस्तर के सीधे सम्बन्ध योजना के द्वारा होने के कारण देश में एक समान समाजवादी योजना के प्रशासन में सक्षम व्यक्ति उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं ।

प्रश्न

1. Give the Salient Features of the 1st Five Year Plan of Russia.
 2. What are the main characteristics of Russian Plans ! What lessons do we learn from them.
-

RAJASTHAN UNIVERSITY
FIRST YEAR EXAM. OF THE
THREE YEAR DEGREE COURSES, 1959
Economic Development of U. K. U.S.S.R & India

Max. Marks 100

Answer Five Questions—At Least one and not more than two from each section.

Section A.

1. Explain why the Industrial Revolution made its appearance in Great Britain earlier than in other countries and trace the successive stages of industrial revolution.
2. Examine the industrial effects of the growth of machinery explaining how it has effected the social and economic conditions of the working class in England.
3. Describe some of the effects of the great improvements in transporta on during the nineteenth century in Great Britain.
4. Write short notes on any two:—
 - (a) Factory laws of England.
 - (b) Corn-laws.
 - (c) Laissez Faire.

Section B.

5. Trace the causes which led to the decay of cottage industries in India and discuss the role of cottage industries in India's economic development.
6. Compare the moneylender with a cooperative credit society as a source of rural finance.
7. Describe the importance of Road Development in India and examine the problems of Rail-Road Co-ordination.
8. What are the causes of low yield of agricultural products in India? Mention the possible methods to remove these defects.

Section C.

9. Examine the functions of Soviet Trade Unions & discuss the position of the workers in the present Russian Economic System.
10. Write a short essay on the Soviet First Five Year Plan.
11. Examine the 'New Economic Policy' of 1921 and discuss the reaction against it that had set in immediately following the policy.

1960

Answer five questions. At least one and not more than two from each section :—